hindustantimes.com
@hindustantimes @httweets @hindustantimes @hindustantimes
VOL. C NO. 176

NEW DELHI/METRO
Wednesday, July 24, 2024

Hindustan Times
FIRST VOICE. LAST WORD.

आप की मेहनत रंग लाई, हुआ कमाल !
एम डी एच ने पूरे किये कामयाबियों भरे 105 साल !!



1919·CELEBRATING·2019
1919·शताब्दी उत्सव·2019
100
Years of affinity till infinity
आत्मीयता अनन्त तक

हम अकेले चल दिये थे
जानिबे मंजिल,
लोग मिलते गये
और कारवां बनता गया।


पूज्य माता चन्नन देवी जी

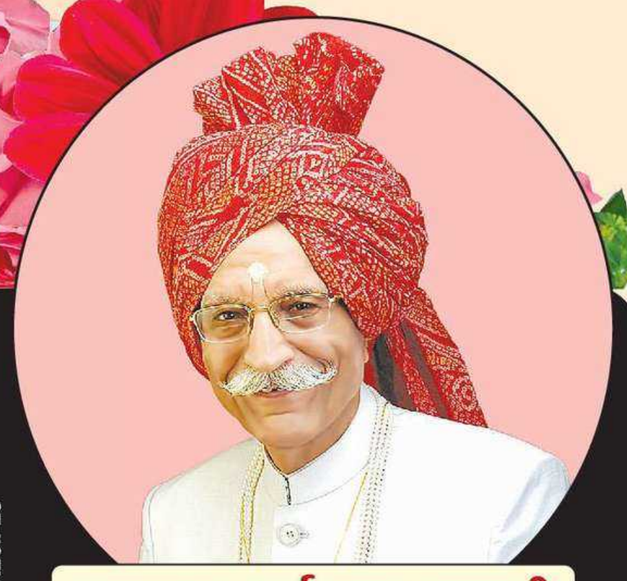
महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लिमिटेड के संस्थापक
महान कर्मयोगी महाशय चूनीलाल जी
138 वें जन्म दिवस पर आपको हमारा कोटि – कोटि नमन्।

138 वें जन्म दिवस 24 जुलाई 2024

आपका प्रताप, आपका आशीर्वाद, ग्राहकों,
उपभोक्ताओं व सहयोगियों की शुभकामनाऐं

हमें निरन्तर मार्गदर्शन व आगे बढ़ते रहने की
प्रेरणा देती रहती हैं।

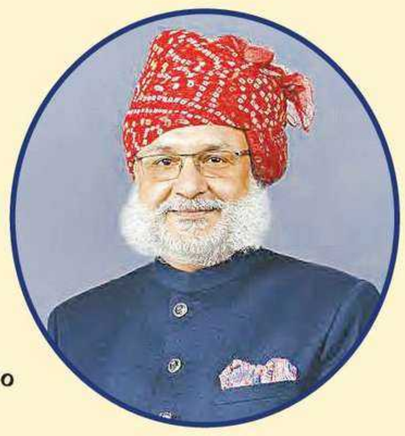
SCAN FOR MDH ORIGINAL RECIPES


महाशय धर्मपाल गुलाटी
संस्थापक चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०

महाशय चूनीलाल धर्मार्थ ट्रस्ट एवं महाशय धर्मपाल धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित एवं संवर्धित संस्थान

० महाशियां दी हट्टी प्रा० लि०, (दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, कुण्डली नागौर) ० सुपर डेलिकेसीज प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली ० माता चन्नन देवी अस्पाताल, (जनकपुरी, नई दिल्ली) ० एम.डी.एच. इंटरनैशनल स्कूल (जनकपुरी एवं द्वारका, नई दिल्ली) ० महाशय चुन्नीलाल सरस्वती बाल मन्दिर (हरी नगर, नई दिल्ली) ० माता लीलावंती सरस्वती विद्या मन्दिर, (टेगौर गार्डन, नई दिल्ली) ० महाशय धर्मपाल विद्या मन्दिर, (बेदगी, कर्नाटक) श्री संजीव गुलाटी चिकित्सालय एवं शोध केन्द्र (ऋषिकेश) ० माता लीलावंती वैदिक संस्कृति प्रशिक्षण केंद्र (उदयपुर, राजस्थान) ० माता चन्नन देवी आर्य कन्या गुरुकुल, (पिल्लु खेड़ा, हरियाणा) ० महाशय धर्मपाल चैरिटेबल सोसाइटी ० महाशय धर्मपाल दयानन्द आर्य विद्या निकेतन (आसाम, एम.पी. झारखण्ड एवं नागालैण्ड) ० एम.डी.एच. गऊशाला (अजमेर, नागौर – राजस्थान) ० माता लीलावंती श्री कृष्ण वैदिक कन्या विद्यालय (खुशीपुरा, मथुरा) ० एम.डी.एच.परिसर निर्वाण न्यास (अजमेर, राजस्थान) ० महाशय धर्मपाल वेद रिसर्च फाउण्डेशन (कालीकट, केरल) ० महाशय धर्मपाल हार्ट इंस्टीट्यूट (जनकपुरी, नई दिल्ली) ० एम.डी.एच. पार्क, (नागौर) ० महाशय धर्मपाल अंतरराष्ट्रीय अतिथि गृह, ग्रेटर केलाश, नई दिल्ली ० महाशय संजीव कुमार धर्मार्थ औषधालय, नालागढ़ (हिमाचल) ० महाशय धर्मपाल यज्ञशाला आर्य समाज, त्रिनगर, नई दिल्ली ० महाशय धर्मपाल स्वावलंबना गृह, सिरसा जेल, सिरसा (हरियाणा) ० महाशय धर्मपाल सर्वोदय विद्यालय मलारना चौड़ (राजस्थान) ० गुरुकुल यमुनावट मंझावली फरीदाबाद (हरियाणा) ० महाशय धर्मपाल सर्वोदय विद्यालय एवं वैदिक शोध केंद्र हल्दीघाटी मार्ग उदयपुर ० महाशय धर्मपाल सर्वोदय विद्यालय एवं वैदिक शोध केंद्र नागौर (राज०) ० श्री सत्य सनातन वेद मंदिर रोहिणी, नई दिल्ली ० स्वामी आत्मानंद वैदिक गुरुकुल मलारना चौड़ जिला सवाई माधोपुर (राजस्थान) ० आर्योदय गुरुकुल संस्थान (जयपुर राजस्थान) ० आर्य समाज कोटपूतली, जिला जयपुर (राजस्थान) ० हवन उत्थान जन कल्याण समिति, मण्डावली, (दिल्ली) ० महर्षि दयानन्द योग धाम, अलवर (राजस्थान) ० सर्वे भवन्तु सुखिनः ट्रस्ट, गाज़ियाबाद (यू० पी०) ० वानप्रस्थ साधक आश्रम (गुजरात) ० आर्य समाज श्री विजयनगर श्रीगंगानगर (राजस्थान) ० आर्य कन्या गुरूकुल शिवगंज, सिरोही (राजस्थान) ० महर्षि पतंजलि इंटरनेशनल योग विद्यापीठ, मुजफ्फरनगर (यू० पी०) ० आर्यवीर दल उत्तर प्रदेश, गुरूकुल विश्वविद्यालय, वृंदावन ० श्री गोपाल गोशाला लोहारू, भिवानी (हरियाणा) ० महाशय धर्मपाल ओपन एअर थियेटर, भिवानी जेल (हरियाणा) ० महाशय धर्मपाल चेरिटेबल ट्रस्ट टंकारा (गुजरात) ० महाशय धर्मपाल चेरिटेबल ट्रस्ट अजमेर (राजस्थान) ० महात्मा रामलाल ट्रस्ट इंदरपुरी (दिल्ली) ० सनातन धर्म मंदिर गुरूग्राम ० महाशय धर्मपाल संस्कृत भवन गुरू विरजानंद संस्कृत कुलम हरी नगर, नई दिल्ली ० युगपुरुष महाशय धर्मपाल गुलाटी (एम.डी. एच.) चेरिटेबल भवन एवं डायग्नोस्टिक सेंटर X-25 कड़कड़डूमा इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली ० युगपुरुष संत महाशय धर्मपाल गुलाटी (एम.डी.एच.) चेरिटेबल कैंसर निदान सहयोग हॉस्पिटल एंव रिसर्च सेंटर X-25 कड़कड़डूमा इंस्टीटयूशनल एरिया, नई दिल्ली ० युगपुरुष संत महाशय धर्मपाल गुलाटी (एम.डी.एच.) आयुर्वेदिक, पंचकर्मा, योग एंव प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य वर्धक एंव रोग निवारण धर्माथ संस्थान, खसरा नं० 259, 275, 276, ग्राम ईशाक नगर, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद यूपी ० विश्वारा कन्या गुरूकुल रुड़की जिला रोहतक (हरियाणा) ० श्री मड्डयानन्द कन्या गुरूकुल महाविद्यालय चोटीपुरा, (उत्तर प्रदेश) ० संजीव गुलाटी स्मृति चिकित्सालय वन्देमातरम कुंज गंगा भोगपुर तल्ला पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखंड) ० महर्षि दयानन्द वेद–विद्या आर्य गुरूकुल नली खुर्द (करनाल) ० श्रीमद् दयानन्द विद्यालय 119, गौतम नगर नई दिल्ली ० श्रीमद् दयानन्द आर्य ज्योतिर्मठ गुरूकुल, पौन्धा, देहरादून (उत्तराखंड) ० बाबा ब्रह्मदास गऊशाला (जीन्द) हरियाणा ० बाबा जमीन नाथ गऊशाला सेवा समिति (जीन्द) हरियाणा ० जय बाबा मन्सानाथ गऊशाला, छात्तर ० जय बाबा धुणेवाला विकलांग गऊशाला समिति (जीन्द) हरियाणा ० श्री कृष्ण गौशाला, नगूरां (जीन्द) हरियाणा ० नन्दी सेवा संघ, उचाना मण्डी (जीन्द) हरियाणा ० श्री गौशाला बाबा फुल्लू साध (जीन्द) हरियाणा ० जय दादा खेड़ा गऊशाला समिति (जीन्द) हरियाणा ० बाबा दलीप गिरी डेरा गऊशाला समिति (जीन्द) हरियाणा ० श्रीमद्वयानंद उत्कर्ष आर्य कन्या गुरूकुल मेरठ ० आर्य समाज विजयनगर (अजमेर)राजस्थान ० महर्षि दयानन्द आर्य गुरूकुल एवं गोशाला भादस जिला मेवात हरियाणा ० आर्यवर्त खेल महासघं जहांगीरपुरी, नई दिल्ली ० महर्षि दयानन्द सेवा समिति (पं.) जनपद एटा, उत्तर प्रदेश ० आर्य समाज निरसा धनबाद ० वेदविद्या शोध संस्थान (न्यास) कुरुक्षेत्र (हरियाणा) ० वेदविद्या आर्य गुरूकुल कन्धमाल (ओडिशा) ० वानप्रस्थ साधक आश्रम साबरकांटा (गुजरात) ० आर्य समाज सैक्टर–11, द्वारका, नई दिल्ली ० सार्वदेशिक आर्य वीर दल, मथुरा (उ.प्र.) ० महर्षि दयानन्द आर्ष कन्या गुरूकुल समिति, शाजापुर (म.प्र.) ० आर्य समाज निरसा, धनबाद झारखण्ड ० आर्य कन्या गुरूकुल, शिवगंज, गुरूकुल – आर्ष कन्या विद्यापीठ नजीबाबाद (उ.प्र.) ० आर्ष गुरूकुल शिक्षा प्रबंध समिति, नोएडा (उ.प्र.) ० गुरू विरजानन्द स्मारक समिति ट्रस्ट, करतारपुर जालन्धर (पंजाब) ० श्रीमती चन्द्रावती कन्या गुरूकुल संस्कृत विद्यापीठ, कासगंज (उ.प्र.) ० वैदिक राष्ट्रनिर्माण गुरूकुल, लखनऊ (उ.प्र.) ० स्वामी कृष्णानन्द आर्य बालाश्रय चैरिटेबल ट्रस्ट वेद मन्दिर ब्रह्मपुरी, दिल्ली ० आर्य समाज पूर्वी पंजाबी बाग, दिल्ली ० आर्य समाज शकरपुर, दिल्ली ० दर्शन योग महाविद्यालय, सुंदरपुर कुटिया, रोहतक ० दर्शनयोग धाम, संस्कृतिवन, गांधीनगर, गुजरात

MDH
निवेदक
महाशय
राजीव गुलाटी
चेयरमैन, महाशियाँ दी हट्टी (प्रा०) लि०



AM/NS INDIA

ArcelorMittal Nippon Steel India

REIMAGINEERING AVIATION
#RE/MAGINEERING BHARAT

SMARTER
STEELS
BRIGHTER
FUTURES

NEW DELHI/METRO
Wednesday, July 24, 2024
■ VOL. C NO. 176

Hindust

Decoding the big numbers in Union Budget 2024-25

The highlights from the budget that sought to emphasise the government's commitment to fiscal consolidation

TOTAL EXPENDITURE
₹48.21 lakh cr
The estimated total expenditure as seen by the government in 2024-25

GROSS TAX REVENUE
₹38.40 lakh cr
The estimated gross tax revenue

NOMINAL GDP GROWTH
10.5% The projected rate of growth for India's nominal gross domestic product (GDP) in the Budget calculations compared to the 6.5-7% real GDP growth projected by the Economic Survey tabled in the Parliament on Monday

Last year's budget had also estimated that the growth in India's nominal GDP would be 10.5%

PERSONAL INCOME TAX (new regime)
₹75,000
(increased from ₹50,000)
Standard deduction for salaried employees

INCOME	TAX RATES
₹0 to ₹3 lakh	NIL
₹3 lakh to ₹7 lakh	5%
₹7 lakh to ₹10 lakh	10%
₹10 lakh to ₹12 lakh	15%
₹12 lakh to ₹15 lakh	20%
>₹15 lakh	30%

CAPITAL EXPENDITURE
₹11.11 lakh cr
Total capital expenditure outlay
17% increase in capital expenditure

AGRICULTURE
₹1.52 lakh cr
Last fiscal, the allotment for agriculture was ₹1.4 lakh crore

RURAL PUSH
₹2.66 lakh cr
The outlay for rural development made in this year's budget

FISCAL DEFICIT
₹16.13 lakh cr
4.9% The proportion of GDP that the government estimates will be the fiscal deficit
4.5% The govt has reiterated its intention to bring fiscal deficit below 4.5% by 2025-26

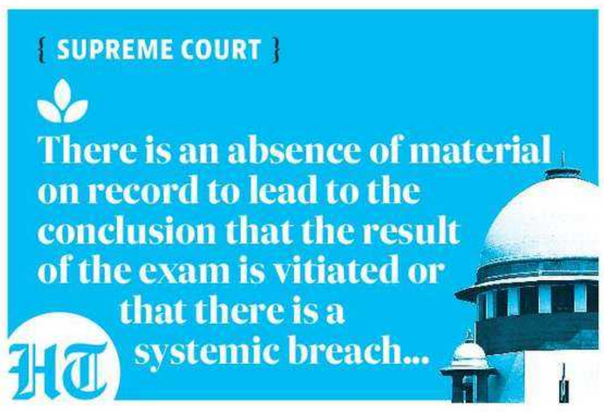
ENERGY
₹68,769 cr
The allotment for energy in the budget this fiscal

DEFENCE
₹6.22 lakh cr
Defence outlay, including pension. This was ₹5.93L-cr in last fiscal

EDUCATION
₹1.26 lakh cr
The allotment for education – a major chunk of which (₹37,500cr) is for Samagra Shiksha Abhiyan

'No evidence leak widespread': SC rules against NEET retest

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com



NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday rejected multiple petitions demanding a NEET-UG 2024 retest because of alleged paper leaks and other malpractices, underlining that the material on record did not show any "systemic breach" that vitiated the exam's sanctity.

Chief Justice of India (CJI) Dhananjaya Y Chandrachud, heading a three-judge bench, pronounced the verdict, addressing the central issue raised by the petitioners — the call for a retest based on claims of a question paper leak and systemic deficiencies in the exam's administration.

"At this stage, there is an absence of material on record to lead to the conclusion that the result of the exam is vitiated or that there is a systemic breach of the sanctity of the exam... Data on record is not indicative of a systemic leak of the question paper, which would indicate a disruption of the sanctity of the exam," held the bench, also comprising justices JB Pardiwala and Manoj Misra.

Adding that probe reports by the Central Bureau of Investigation (CBI) indicate that tainted students (155 in number) could be segregated from the untainted ones, the court clarified that if the probe reveals increased number of beneficiaries, action shall be taken against any such student at any stage notwithstanding the completion of the counselling process. "No student who is revealed to have been in this fraud or a beneficiary would be entitled to claim any vested right in continuance of admission," said the bench.

To be sure, the counselling for NEET-UG is expected to begin on July 24. The Supreme Court's refusal to order a retest came a day before the counselling commences. The bench noted that while the detailed judgment in the matter would

continued on →24

SOLDIER KILLED AS ARMY FOILS J&K INFILTRATION BID

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

JAMMU : A soldier was killed in a gunfight with terrorists as the army thwarted an infiltration bid along the Line of Control (LoC) in the Poonch district of Jammu, officials aware of the matter said on Tuesday, underscoring a spike in terror activities in the erstwhile peaceful region, which continues to be on the edge.

According to officials, security personnel noticed "suspicious" movement along the LoC in the Battal sector of Jammu & Kashmir in the early hours of Tuesday and opened fire. Lance Naik Subhash Chander, a resident of UP, was killed in the gunfight, officials added. →P18

Stay on bail can't be 'mechanical', says SC

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday established stringent guidelines for staying bail orders, emphasising that such orders cannot be issued "casually" or "mechanically" because of their serious implications for human liberty.

The court stressed that high courts and sessions courts should be "very slow in granting drastic interim relief of stay of the order granting bail" owing to the severe implications of staying bail orders without substantial justification. "The reason is that when an undertrial is ordered to be released on bail, his liberty is restored, which cannot be easily taken away for the asking. The undertrial is not a convict," the court noted.

Authored by justice Oka, the landmark ruling underlined the importance of safeguarding the liberty of individuals and aimed to prevent the undue curtailment of this fundamental right during the judicial process. The judgment set clear parameters for when and how courts can stay bail orders, mandating that an interim stay should only be issued in "very rare cases" where a "very strong prima facie case of the existence of grounds for cancellation of bail is made out". The ruling has profound implications for judicial practice across India. →P18

U.S. SECRET SERVICE CHIEF QUITS OVER ASSASSINATION BID ON DONALD TRUMP

WASHINGTON: The director of the Secret Service on Tuesday said she's resigning following the assassination attempt against ex-President Donald Trump that unleashed outcry about how the agency tasked with protecting current and former presidents could fail in its core mission.

Kimberly Cheatle, who served as Secret Service director since August 2022, had been facing growing calls to resign and several investigations into how the shooter was able to get so close to the Republican presidential nominee at an outdoor campaign rally in Pennsylvania.

"I take full responsibility for the security lapse," she said in an email to staff. →P21

Hindustan Times

NEW DELHI
WEDNESDAY
JULY 24, 2024

UNION BUDGET UB 2024-25

Jitters, but markets end flat as budget is tabled

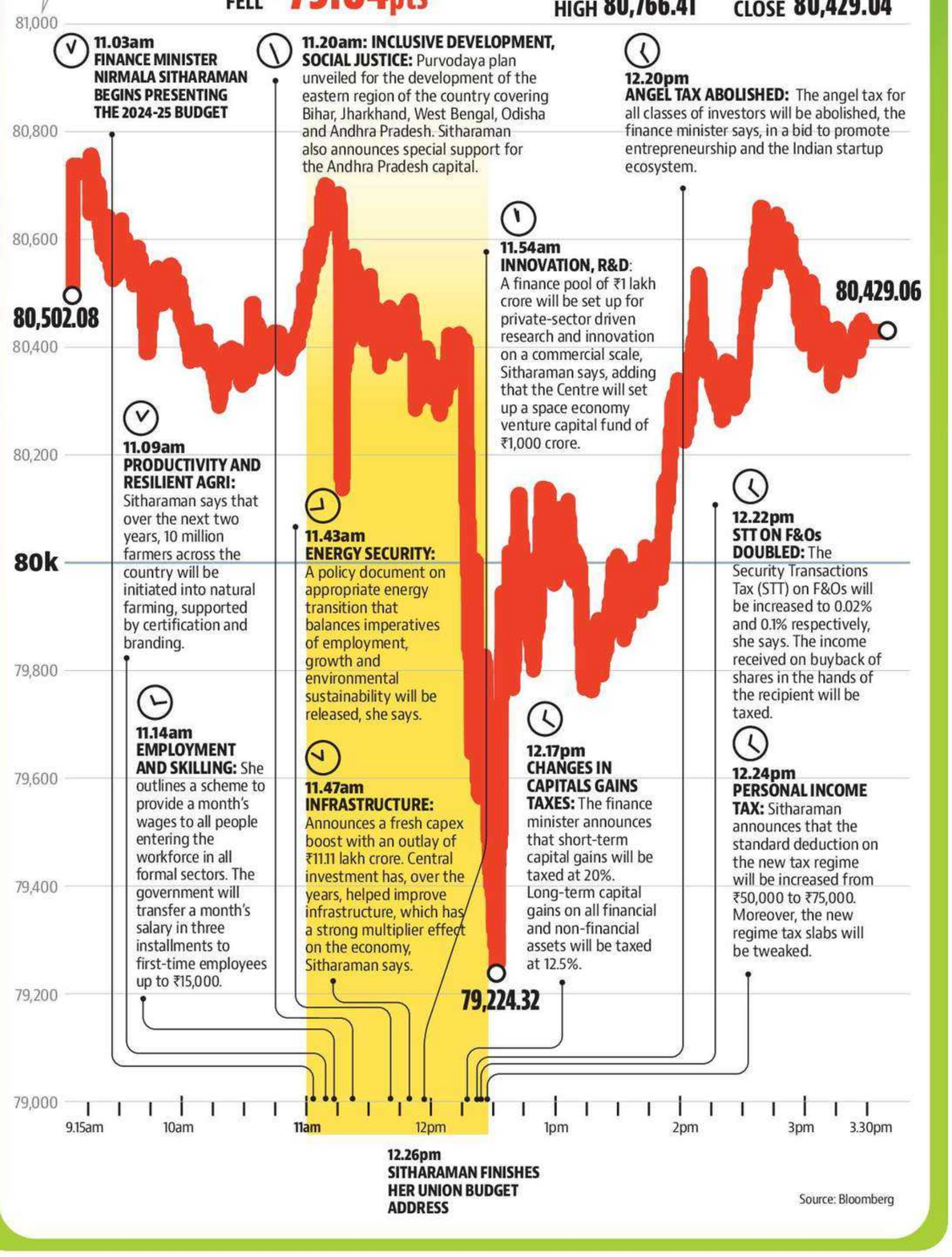
The Sensex settled slightly lower in volatile trade on Tuesday as the Centre proposed to hike securities transaction tax on F&Os in the 2024-25 Budget

HOW MARKETS REACTED

Sensex

SENSEX FELL **-73.04pts**

OPEN **80,724.30**
HIGH **80,766.41**
LOW **79,224.32**
CLOSE **80,429.04**



Source: Bloomberg

WHAT'S COSTLIER

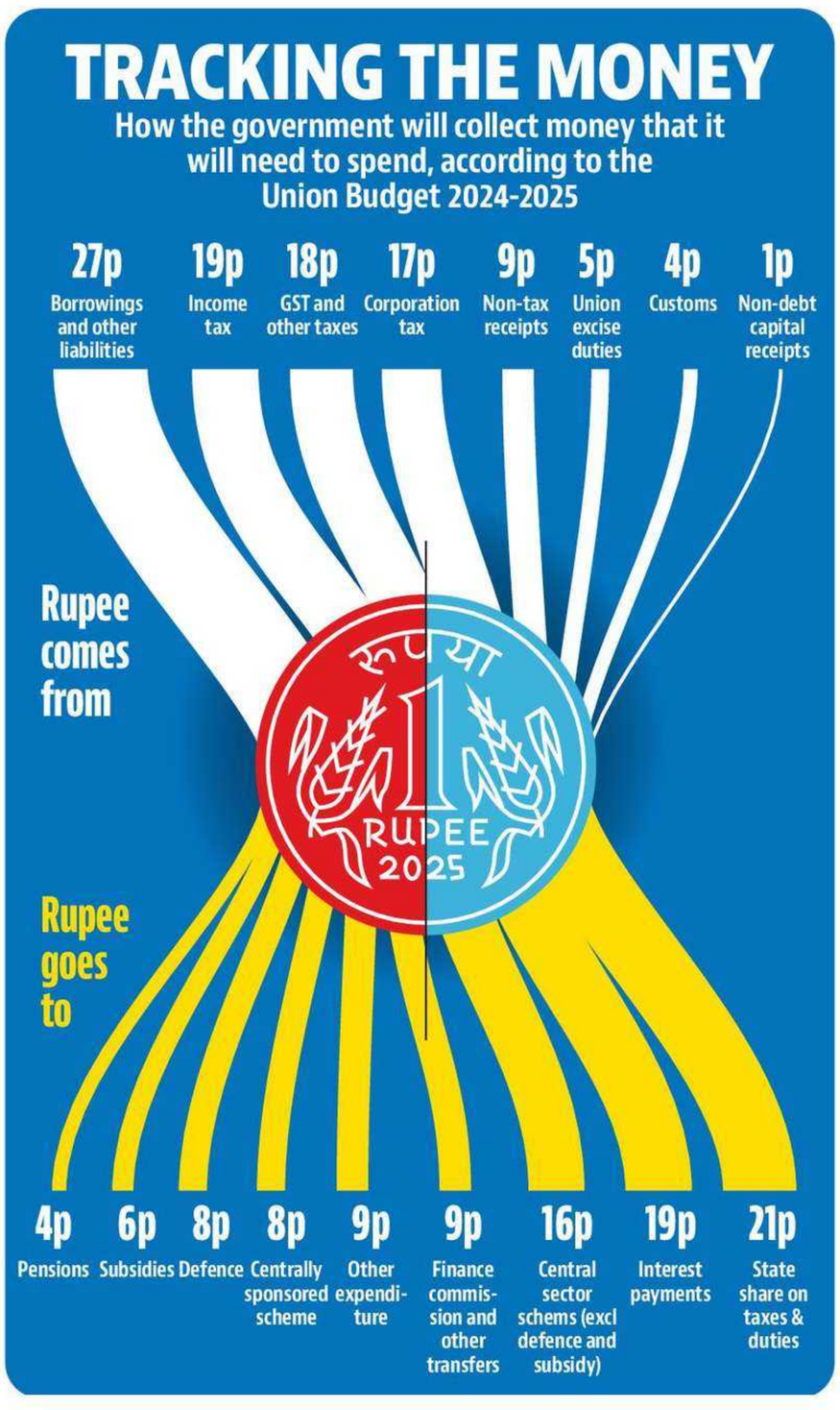
- Equity investments held for less than one year
- Shares held for more than 12 months
- Specified telecom equipment
- Ammonium nitrate
- Non-biodegradable plastics
- PVC flex banners

WHAT'S CHEAPER

- Mobile phones, mobile PCBA and chargers
- Gold and silver
- Platinum
- Three cancer drugs: Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib and Durvalumab
- 25 critical minerals
- Brood stocks, shrimp and fish feed
- Solar panels, solar cells and electric vehicles
- Leather products
- X-ray tubes used in manufacturing of X-ray machines

TRACKING THE MONEY

How the government will collect money that it will need to spend, according to the Union Budget 2024-2025



hindustantimes.com
@hindustantimes @httweets @hindustantimes @hindustantimes
■VOL. C NO. 176 ■PRICE ₹6.00/WITH HINDUSTAN ₹ 10.50 (₹ 9.50 IN FARIDABAD)/WITH MINT ₹ 15.50 ■30 PAGES + 6 PAGES OF HT CITY. AREA SPECIFIC PAGES EXTRA.

NEW DELHI/METRO
Wednesday, **July 24**, 2024

Hindustan Times

FIRST VOICE. LAST WORD.

25 Glorious Years
Indiabulls HOME LOANS
Indiabulls Housing Finance Limited
is now
SAMMAAN CAPITAL

COALITION ECONOMIX

Big push for jobs, changes in direct and capital gains taxes key takeaways from budget, which keeps allies happy with schemes for Andhra and Bihar while staying on the fiscal glide path

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Union Budget on Tuesday unveiled a concerted jobs push and a raft of schemes for young people ranging from internship guarantees to employment-linked incentives even as it laid out a bouquet of sops for critical allies and attempted to balance the exigencies of running a coalition with maintaining fiscal discipline.

Union finance minister Nirmala Sitharaman's second-shortest budget speech, and her seventh overall, also focussed on changes in direct and indirect tax regimes – including a hike in long term capital gains tax for listed assets from 10% to 12.5% , the scrapping of indexation (which took inflation into account while calculating asset values) and introduction of a flat 12.5% rate for real-estate , the removal of the angel tax for all investors, and a sharp reduction in customs duties for items such as gold, silver and mobile phones, which will make these items cheaper for consumers.

She announced some tweaks in the new tax regime that will save taxpayers up to ₹17,500 annually and a review of the income tax act, hinted that the government was moving towards next-generation reforms, and announced that the fiscal deficit stood at 4.9%, keeping India firmly on the fiscal glide path first announced three years ago.

"The #BudgetForViksitBharat ensures inclusive growth, benefiting every segment of society and paving the way for a developed India," Prime Minister Narendra Modi said.

The budget largely steered away from populist announcements, although chunks of the 85-minute budget speech were devoted to schemes and sops aimed at Bihar and Andhra Pradesh, two states governed by allies Janata Dal (United) and Telugu Desam Party (TDP) whose support is crucial for the survival of the National Democratic Alliance (NDA) government.

Sitharaman announced a cluster of projects and packages – roads and highways, airports, flood control, irrigation schemes, tourist hubs, industrial nodes and power projects – totalling roughly ₹59,000 crore for Bihar, which goes to the polls next year.

For Andhra Pradesh, the finance minister announced ₹15,000 crore for the construction of the state capital Amaravati and additional funds if required, completion of the Polavaram dam project and two industrial nodes. "Our government has made

continued on →24

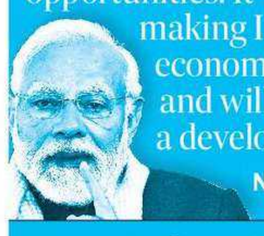
UNION BUDGET 2024-25

Nine priorities for Viksit Bharat goal



1. Productivity and resilience in agriculture
2. Employment and skilling
3. Inclusive human resource development and social justice
4. Manufacturing and services
5. Urban development
6. Energy security
7. Infrastructure investments
8. Innovation, research and development
9. Next generation reforms

The budget has brought new opportunities, new energy, new employment and self-employment opportunities. It will act as a catalyst in making India the third largest economic power in the world and will lay the foundation for a developed India.



NARENDRA MODI, Prime Minister

'Kursi Bachao' Budget. Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states. Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets.



RAHUL GANDHI, Leader of Opposition, Lok Sabha

SMALL REACTORS IN ENERGY MIX

Finance minister Nirmala Sitharaman announced a diversified energy plan, which included small, modular nuclear reactors, rooftop solar plants, and Advanced Ultra Super Critical (AUSC) thermal power plants. →P13

GOVT CUTS FISCAL DEFICIT TARGET

The central government made a downward revision in India's fiscal deficit target for the current financial year, from 5.1% of the gross domestic product (GDP) targeted in the interim budget in January to 4.9%. →P9

FOCUS ON CLIMATE RESILIENT CROPS

The government will ramp up farm research to boost productivity and ability of crops to withstand climate crisis that have upended the country's food supplies, the Union finance minister said on Tuesday. →P12

MULTI-LAYERED MSME PACKAGE

The Union Budget unveiled a revival package for the MSME sector, which included enhanced Mudra loans of up to ₹20 lakh, a collateral-free credit guarantee scheme, and a new assessment model. →P10

Impact on financial markets, real estate after tweak in taxes

mint

MUMBAI/NEW DELHI: The frenzied trading in derivates that alarmed regulators and policy makers is expected to dampen, at least for a while, with the government increasing taxes on transactions in a major blow to investors and traders, and tweaking levies on capital gains in a way that impacted both, the markets as well as the real estate sector.

The changes announced in the Union Budget on Tuesday follow the Economic Survey's warning a day earlier about the sharp increase in retail, or individual, investor participation in the stock markets. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is also planning measures to rein in retail speculation in trading in futures and options.

The budgetary proposals include increased securities transaction tax, or STT, on derivatives as well as higher capital gains levies on listed financial instruments, which market experts say would affect trading volumes, particularly those involving professional high-frequency traders.

The government also scrapped indexation benefit across all asset classes and introduced a flat 12.5% rate for real-estate. The removal of indexation benefit is likely to impact real estate investors the most. Indexation allowed price of acquisition to be as per inflation, helping lower capital gains. →P7,15

CAPITAL GAINS TAX ON REAL ESTATE LOWERED, BUT EXPERTS SAY REMOVAL OF INDEXATION WILL HIT THOSE WITH OLD PROPERTIES

Five major schemes to put young India to work

Zia Haq
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The government announced job-creation plans worth ₹2 lakh crore in its budget for 2024-25, unveiling incentives for firms to raise productivity, programmes to support skilling and broader reforms to spur employment.

Employment-boosting measures announced by finance minister Nirmala Sitharaman include incentives for firms in manufacturing, cheaper loans for higher education, internship programmes and credit flow to small businesses.

By a wide reckoning, India isn't creating enough good-quality jobs for its rising workforce. The unemployment rate in the world's fastest growing economy declined to 3.2% in 2022-23, according to latest official data.

"In this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, the middle class," the finance minister said in her budget speech. The finance minister announced what she called the "Prime Minister's package of five schemes and initiatives" to facilitate employment and skilling opportunities for 40.1 million young people over a five-year period. →P4



Ab hoga har sapna poora sammaan se!

SAMMAAN CAPITAL

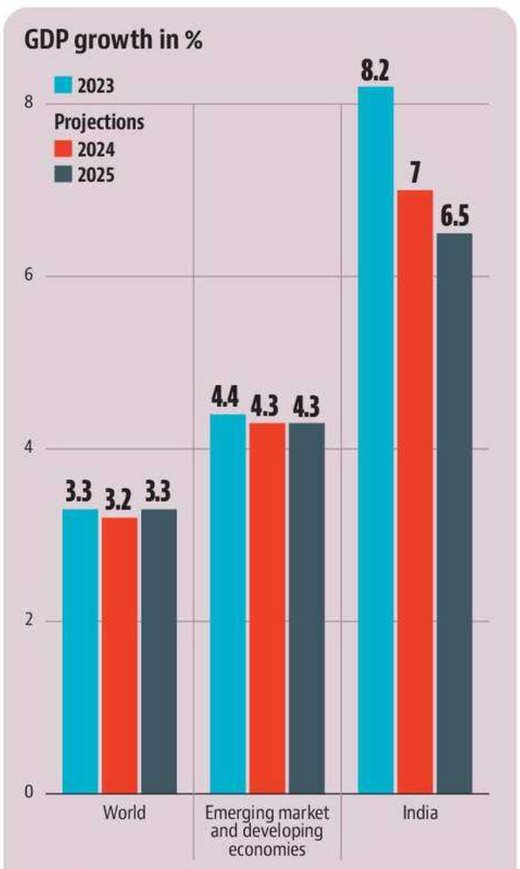
Jiyo Sammaan Se

1800 572 7777 www.sammaancapital.com 8929 899 391 SMS 'HOME' at 56677

Roshan Kishore analyses the impact of the Narendra Modi government's first Budget in his third term, a month after the Lok Sabha elections

HOW THE BUDGET IMPACTS...

...Growth



IMF World Economic Outlook, July 2024

The Economic Survey projecting a more conservative estimate of GDP growth (6.5%-7%) for 2024-25 than even the Reserve Bank of India's projection of 7.2% should have told us that the Union Budget 2024-25 was unlikely to throw the (fiscal) kitchen sink at the economy. In fact, the entire focus of the budget is on boosting India's medium-term to long-term growth prospects rather than short-term quick fixes.

That's partly a reflection of the fact that quick fixes are not required: India already has an edge in terms of growth rate vis-à-vis major global economies and has managed this without a crisis on the inflation front. The budget also suggests that taking India beyond its potential growth rate in a sustainable manner would require more than a one-time fiscal boost to the economy. Here are some elements from the budget which talk about these challenges.

The budget has continued with its focus on capital expenditure which can boost the economy's long-term prospects and also plug supply-side gaps in infrastructure. Capital expenditure allocation has been kept unchanged (from the interim budget) at ₹11.1 lakh crore which is 3.4% of GDP. The effective capital spending figure for 2024-25, including interest free loans provided to states, is expected to be ₹15 lakh crore. While the approach is laudable in principle, it remains to be seen whether it will be able to address the challenge of weak consumption demand, especially at the bottom of the pyramid, which is crucial to a sustained revival of private investment activity in the economy.

To be sure, the budget does have a theoretical road map for boosting incomes in the not-so-rich parts of the Indian economy. For example, it talks about encouraging farmer cooperatives and supply hubs to boost incomes in the agriculture sector. There is also talk about formulating a new National Cooperation Policy. Similarly, there is talk of formulating a Purvodaya (Rise of the East) plan, which will focus on reviving the economic fortunes of Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha and Andhra Pradesh, which are largely poor and resource-starved states and can potentially generate huge tailwinds for overall growth.

₹11.1 L-cr
Capital expenditure allocation, which is 3.4% of GDP, has been kept unchanged (from the interim budget). The effective capital spending figure for 2024-25, including interest-free loans provided to states, is expected to be ₹15 lakh crore.

What does the budget do for India's manufacturing sector? A slew of changes has been announced in customs duty rates, which, the budget has claimed will create the right incentives for domestic manufacturing. How far they go in correcting what industry terms an inverted duty structure for Indian manufacturing will become clear once the fine print is analysed.

There is also a talk about easing capital constraints for MSMEs on many fronts. This includes a credit guarantee of up to ₹100 crore for MSMEs, government subsidies on creation of new jobs in the formal sector at salaries up to ₹1 lakh per month, and revisiting the credit assessment framework for MSMEs. The upgradation of 1,000 new Industrial Training Institutes (ITIs) in a hub-and-spoke network of such centres could be a potential game-changer for easing the supply constraint of skilled labour for India's manufacturing sector. This budget complements this initiative by talking about providing skilling loans up to ₹7.5 lakh for 25,000 students every year. The budget also talks about easing voluntary closure of Limited Liability Partnerships, which could give a nudge to capital rich entrepreneurs to invest money in creating new firms. On the other extreme, it has raised the upper limit for Mudra loans from ₹10 lakh to ₹20 lakh for borrowers who have availed and repaid previous loans. Can these policies catalyse entrepreneurship at the rich and poor ends of the spectrum? The budget is hoping that it will.

As is evident from the discussion above, the budget's approach to boosting India's growth is more about micromanagement of gaps in various sectors of the economy rather than a big bang boost from some major policy announcement. This kind of an approach might work to maintain a growth rate in the ballpark of 7%, which is what the Economic Survey has envisaged as being in the realm of the possible. "In the medium term, the Indian economy can grow at a rate of 7% plus on a sustained basis if we can build on the structural reforms undertaken over the last decade," it says in the chapter on India's medium term growth prospects. However, whether this will generate the required ballast to take care of India's rapidly closing demographic dividend window – India's working age population will peak in the 2040s – is a more difficult question to answer. But then, as the survey points out, the global economic environment has changed for worse at a time when India is making its bid to become an economic superpower. The budget began by reiterating the fact. "Elevated asset prices, political uncertainties and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation," finance minister Nirmala Sitharaman said.

...Politics



Source: PLFS data taken from Economic Survey

An interesting counterfactual as far as the 2024 election results are concerned is whether they would have been different had the interim budget been different. The 2019 comparison is what makes this a very tempting question to ask. The BJP lost the 2018 assembly elections in Madhya Pradesh, Rajasthan and Chhattisgarh in the penultimate round before the 2019 general elections. Rural distress and worsening terms of trade for farmers were seen as a big reason for these losses. The 2019 interim budget announced a direct income transfer scheme for farmers with retrospective effect to nullify this rural anger. While elections are rarely driven by just one factor, the BJP increased its seat tally between 2014 and 2019. The 2024 interim budget, which came in the backdrop of the BJP winning in these three states in 2023, did not do much with an eye on the elections. The BJP saw its seat tally fall from 303 to 240 between 2019 and 2024.

What this budget has not tried to do is undertake the exercise of correcting what could've been a mistake – not doing enough for the elections in the interim budget presented in February. There is no major populist announcement in this budget which can generate low-hanging political fruits for the government in the short term. What the budget has tried to achieve politically is cater to the changed political reality after the 2024 elections. There are two aspects to this political reorientation.

The first is to make sure that the National Democratic Alliance is intact. The BJP, after all, does not have a parliamentary majority of its own. The current NDA government is critically dependent on the support of two of its allies, the Janata Dal (United) and the Telugu Desam Party (TDP), which have 12 and 16 MPs in the Lok Sabha, respectively. Another six MPs from Bihar (five from the LJP and one from HAMS) is what brings the NDA to the halfway mark of 272 in the Lok Sabha. The budget has done its best to cater to the demand of these parties to grant more resources to their states. The finance minister spent a lot of time detailing projects that will be undertaken in both Bihar and Andhra Pradesh.

Bihar, from the optics of the speech, has been given priority given the fact that it goes to polls next year itself. The fact that Bihar and Andhra Pradesh have been prioritised over the poll-bound states of Haryana, Maharashtra and Jharkhand underlines the importance the BJP is giving to keeping the NDA intact even at the cost of suffering potential losses in states where it is in power currently.

To be sure, the budget is not just about keeping the allies in good humour. Another lesson which the 2024 election results have taught the BJP is that political returns from its asset generation-focused welfare programmes are subject to the law of diminishing marginal political utility. Among the most important headwinds for the BJP in these elections was from India's educated unemployed who have been struggling to land well-paying jobs.

The budget, in keeping with the Economic Survey's prognosis, has once again hinted that the mainstay of job-creation will have to be in the realm of the private sector and not the public sector. Where the budget makes a new beginning is in suggesting that the State will subsidise job-creation in the private sector by not just facilitating skill-enhancement, but also sharing a part of the burden of salaries of new recruits. It has not shied away from incorporating some of the ideas from the Congress's manifesto as well such as facilitating internships for young workers. This is in a way the biggest nudge by the government to encourage job-creation in the formal sector.

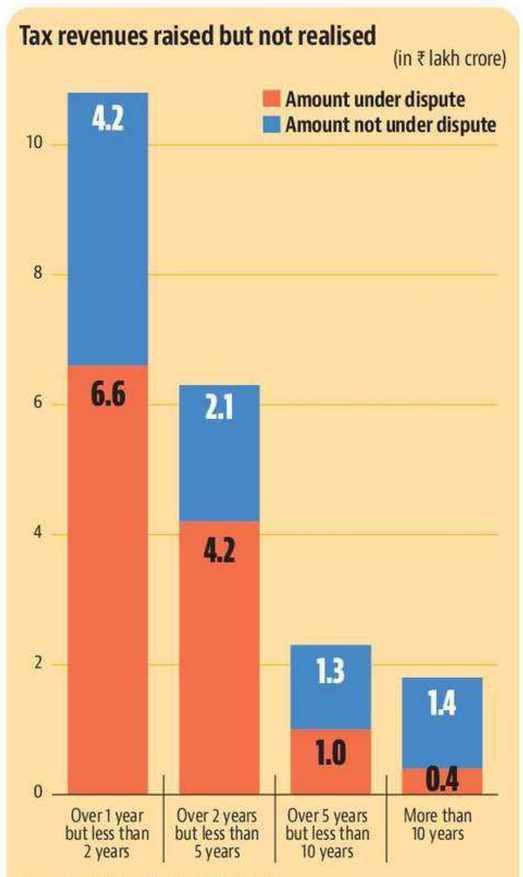
The budget speech has set itself a target of "facilitate[ing] employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a five-year period". The number is almost in sync with the Economic Survey's prescription of the need for generating 7.5-8 million jobs every year.

Will this focus on job-creation help the BJP cultivate a new cohort of "labharthis" or beneficiaries in the labour market before the 2029 general elections? This is the most important political bet in the budget.

To be sure, achieving this objective will be much more difficult than delivering first-generation assets such as LPG cylinders, toilets and piped water to poor households. The biggest reason for this is that the government is expecting (what is at the moment) a demand-deficient private sector to play ball in its job-creation strategy. Also, there is good reason to believe that a large majority of job seekers in India still see low-paying government jobs as the more desired option than blue-collar private sector jobs.

Will the budget's newfound focus on employment generation be able to the counter the Opposition's push for rolling back reforms such as the Agnipath scheme, which has largely done away with permanent jobs in the armed forces or a renewed push for increasing reservations for other backward classes (OBCs) in government jobs? Will these policies generate enough traction for the BJP to do well in the state elections before the 2029 general elections? The BJP is clearly hoping that they will.

...Reforms



Source: Union Budget 2024-25

This is where the budget makes the right noises but has taken an extremely non-confrontational approach. The budget speech of finance minister Nirmala Sitharaman lists next-generation reforms as one of the nine key pillars of the government's economic policy to realise the goal of making India a developed economy by 2047. These reforms, the speech says, will be geared towards factor markets and achieving efficiency gains for the economy. However, it almost immediately adds that such reforms will have to achieved by developing a consensus between the Centre and the states, with the former nudging the latter to move in the desired direction.

To be sure, the speech does give details on desired reforms in land, labour and capital markets. However, they are more in the realm of capacity building and framework development than big-bang announcements. For example, the speech talks about digitising land records in rural and urban areas over the course of next three years. Another reform goal talks about incentivising states with higher stamp duties to bring them down, especially for properties purchased by women.

Similarly, the labour reforms talk in the budget is about facilitating skilling of labour and ensuring ease of compliance for industry and trade rather than making big tweaks to hiring laws or harmonising them across the country, which is what the government intended to achieve via the labour codes.

Enhancing ease of doing business – the Economic Survey flagged it a major concern in attracting investment – has been described as a work in progress under the Jan Vishwas Bill and incentivising states for implementation of their own business reform action plans.

None of the areas listed above is insignificant in nature. In fact, if addressed well, they have the potential of easing significant structural roadblocks to entrepreneurship and investment without the hype around big bang reforms. Having said this, the government's approach of not even talking about relatively more controversial areas of reforms such as the disinvestment of public sector enterprises suggests that the government is in no mood to burn political capital immediately.

The budget speech does hint at some key reforms which are in the works. For example, one of the most awaited reforms in the Indian economy has been the introduction of a new direct tax code. While the budget has made multiple small tweaks to the direct tax slabs, it has also announced a "comprehensive review" of the Income Tax Act within the next six months. "The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the tax payers. It will also bring down the demand embroiled in litigation," the finance minister said.

The speech also suggests that a lot of the direct tax reform might have already happened. "We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and personal income tax. This has been appreciated by tax payers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in financial year 2022-23. Similarly, as per data available till now for the last fiscal, more than two-thirds have availed the new personal income tax regime," the FM added.

On the indirect tax front, the minister reiterated her ministry's commitment to simplify and expand GST's coverage. The latter would entail including petroleum products and liquor under GST. On custom duties, the speech, once again, talks about undertaking "a comprehensive review of the rate structure over the next six months to rationalise and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion and reduction of disputes". On the politically sensitive but fiscally damaging question of reverting to the Old Pension Scheme, the budget suggests that negotiations are still a work in progress and a halfway house is likely to be found.

"The Committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the Staff Side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees have taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens," Sitharaman said.

Another generic but potentially important reform measure which the budget talks about is developing a financial sector vision and strategy document for "meeting financing needs of the economy". This could be an extremely important area for both government and private sector investment. The former plans to undertake a lot of such activity without budgetary allocations and the latter's need are over and above for normal commercial banking channels can provide for. Another major financial sector reform mention in the speech talks about tweaks to the bankruptcy framework and debut recovery tribunals to strengthen and speed up debt recovery.

While this budget's reform quotient is relatively underwhelming, its announcements on initiating a review of income tax laws and customs duties and NPS suggests that there could be major developments on the reform front between now and the next year's budget.

...Stability



Source: Economic Survey

If there is one thing the current government can rightly take credit for, it is India's macroeconomic stability, even if this has come at the cost of political capital. The previous Modi government adopted a retrained fiscal approach to deal with the pandemic's shock to the economy and has not picked quarrel with its monetary policy arm – technically independent – for being hawkish in dealing with inflation in the economy. Both these things might have led to worsening of economic growth as well as sentiment in the short term.

This year's budget shows no intention of departing from this approach even in the aftermath of depleted political capital after the elections. The projected fiscal deficit for 2024-25 is now pegged at 4.9%, 20 basis points lower than what this number was in the interim budget presented in February. One basis point is one hundredth of a percentage point. It also hopes to bring down the fiscal deficit to 4.5% by the next fiscal year. The budget also talks about a fiscal glide path which will keep the debt-GDP ratio under check. "From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government debt will be on a declining path as percentage of GDP," the finance minister said in her speech. This will definitely bring relief to financial markets.

To be sure, the budget has retained policy space to respond to unforeseen global shocks, which it acknowledges pose significant downside risks to growth. "With continued global uncertainty and potential new avenues of conflict still open, prudence demands that the Government retain fiscal flexibility to be able to effectively respond to the potential unforeseen challenges," said the Medium Term Fiscal Policy Cum Fiscal Policy Strategy Statement of the Budget.

The budget's focus on bringing down fiscal deficit and keeping the debt burden under check is also in keeping with the Economic Survey's emphasis on the need for deepening the corporate bond market which will bring an additional source of investment finance over and above banks. "An efficient corporate bond market with lower costs and quicker issuing time can offer an efficient and cost-effective source of longer-term funds for corporates," the Survey said. The government's refusal to make specific concessions to global bond indices and stay focused on attracting them with overall fiscal prudence is definitely a better approach.

4.9%
is the projected fiscal deficit for 2024-25, 20 basis points lower than what this number was in the interim budget presented in February.

To be sure, the budget also takes a more broad-based approach to macroeconomic stability rather than just managing the fisc. Here are two important areas where this approach is clearly visible.

One of the biggest reasons for benchmark inflation staying above RBI's target of 4% in the recent past has been food inflation. The budget takes what will be a more reassuring path to managing food inflation rather than the provocative tone adopted in the Economic Survey. While the latter talked about shifting to an inflation targeting framework which excludes food inflation, the budget strikes a more conciliatory note underlining the importance of developing climate resilient crop varieties and achieving self-sufficiency in key crops such as pulses and oilseeds to mitigate the volatility from international food markets. The budget also reiterates the government's commitment to supply side interventions in food markets to keep food prices under control.

The other, not so explicit, push in the budget towards macroeconomic stability is a subtle effort to discourage speculative and myopic investments in the financial markets. It has raised both short-and long-term capital gains tax on financial assets, in response to the Economic Survey's concern on potential exuberance in the equity markets and its destabilising impact on the economy.

"It is essential to strike a note of caution. The market capitalisation to GDP ratio is not necessarily a sign of economic advancement or sophistication. Financial assets are claims on real goods and services. If equity market claims on the real economy are excessively high, it is a harbinger of market instability rather than market resilience," the Economic Survey said. In taking this approach, the budget has taken a very different route from the political rhetoric of the BJP's top leadership which was talking up the stock markets during the 2024 election campaign. By continuing to prioritise macroeconomic stability, the budget is hoping to achieve two key objectives. One, it is strengthening India's insurance against volatilities in global and domestic financial markets and two, it is also signalling to the world that the losses in 2024 elections have not eroded the confidence of the BJP about being in power for a long time and eying political gains from structural changes in the economy rather than making cyclical or short-term bets. This is the cornerstone of the BJP's macroeconomic approach.

What the tweaks in tax regime mean

Salaried taxpayers shifting to the new tax regime stand to save up to ₹17,500, Nirmala Sitharaman announced on Tuesday. A look at how things change if people opt to file their income tax returns under the new regime

WHAT YOU WILL PAY

Comparison between old and new tax regime

	₹5 lakh		₹15 lakh		₹20 lakh		₹30 lakh		Between old and new tax regime		New regime - Before and after Budget	
	2025-26 (Old Regime)	2025-26 (New Regime)	2025-26 (Old Regime)	2025-26 (New Regime)	2025-26 (Old Regime)	2025-26 (New Regime)	2025-26 (Old Regime)	2025-26 (New Regime)	2025-26 (Old Regime)	2025-26 (New Regime)	2024-25 (Before)	2025-26 (After)
Salary	5,00,000	5,00,000	15,00,000	15,00,000	20,00,000	20,00,000	30,00,000	30,00,000	15,00,000	15,00,000	15,00,000	15,00,000
Less: Standard deduction	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	75,000	50,000	75,000
Net Salary	4,50,000	4,25,000	14,50,000	14,25,000	19,50,000	19,25,000	29,50,000	29,25,000	14,50,000	14,25,000	14,50,000	14,25,000
Loss under the head house property	2,00,000	-	2,00,000	-	2,00,000	-	2,00,000	-	2,00,000	-	-	-
Gross Total Income	2,50,000	4,25,000	12,50,000	14,25,000	17,50,000	19,25,000	27,50,000	29,25,000	12,50,000	14,25,000	14,50,000	14,25,000
80C	1,50,000	-	1,50,000	-	1,50,000	-	1,50,000	-	1,50,000	-	-	-
80D	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	50,000	-	-	-
Total Taxable Income	50,000	4,25,000	10,50,000	14,25,000	15,50,000	19,25,000	25,50,000	29,25,000	10,50,000	14,25,000	14,50,000	14,25,000
Tax (After Rebate u/s 87A)	-	-	1,27,500	1,25,000	2,77,500	2,67,500	5,77,500	5,67,500	1,27,500	1,25,000	1,40,000	1,25,000
Surcharge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Health & Education Cess	-	-	5,100	5,000	11,100	10,700	23,100	22,700	5,100	5,000	5,600	5,000
Tax payable	-	-	1,32,600	1,30,000	2,88,600	2,78,200	6,00,600	5,90,200	1,32,600	1,30,000	1,45,600	1,30,000
Tax Benefit under new tax regime of Section 115BAC	NIL		2,600		10,400		10,400		2,600		15,600	

Credit: **Naveen Wadhwa**, vice president, research and advisory, Taxmann.

"If your annual income is more than ₹14.75 lakh, the new tax regime will be better against ₹4 lakh deduction, while those earning below ₹14.75 lakh should go for the old tax regime. This income threshold comes in at ₹7.75 lakh if you opt for deductions only under Section 80C and 80D."

– Naveen Wadhwa, vice president of Taxmann

"People with an annual income of more than ₹5 crore need not make this comparison. They should always go for the new tax regime, thanks to a lower surcharge rate of 25% applicable in the new tax regime against 37% in the old tax regime."

– Anurag Jain, co-founder and partner at ByTheBook LLP Consulting



UJVN LTD.
H.O.: 'UJJWAL', Maharani Bagh, G.M.S. Road, Dehradun-248006
Telephone: 0135 - 2763808, Fax 0135-2763508
CIN No. : U40101UR2001SGC025866, Website : www.ujvnl.com

Letter No. 625 **DATE EXTENSION E-Notice-1** Dated 23.07.2024

Due to unavoidable reasons date of submission and opening of bids against Tender No: CH(Maint.)-12/2024-25.
Last Date for receipt of bid in portal : 02.08.2024,16:00 hrs.
Last Date of submission of document on website:02.08.2024, 16:00 hrs.
Date of Opening of bid on the website : 03.08.2024, 11:00 hrs.
For further details, kindly visit our website. The tender documents can be downloaded from the Nigam's website www.ujvnl.com.

(Executive Engineer, Maint., Chibro)

"Avoid Wasteful use of Electricity"

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
EXTRA-ORDINARY APPELLATE JURISDICTION
SPECIAL LEAVE PETITION (CIVIL) No. 28449 OF 2018
WITH PRAYER FOR INTERIM RELIEF
WITH
IA NO. 42677/2024
(APPLICATION FOR SUBSTITUTED SERVICE)

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY ... Petitioner(s)/Appellant(s)
VERSUS
SATISH KUMAR AND OTHERS ... Respondent(s)

To,

(1) BHARTI D/O LATE SHIV KUMAR, RZ-96-A, GALI NO. 3, HASTSAL ROAD, UTTAM NAGAR, DISTRICT- WEST *, DELHI

PID: 106778/2024 FOR R[7.4] IN SLP(C) NO.28449/2018 (SEC XIV)

WHEREAS the Petition for Special Leave to Appeal with prayer for interim relief along with application for **SETTING ASIDE AN ABATEMENT, APPLICATION FOR SUBSTITUTION, CONDONATION OF DELAY IN FILING SUBSTITUTION APPLN., APPLICATION FOR CONDONATION OF DELAY IN FILING THE APPLICATION FOR SETTING ASIDE THE ABATEMENT, SUBSTITUTED SERVICE** above mentioned (copy enclosed) filed in the Registry by **Ms. MANIKA TRIPATHY**, Advocate on behalf of the Petitioner(s) above named was listed for hearing before the Hon'ble Judge in Chamber on **20th September, 2021**, when the Court was pleased to pass the following order:-

"Issue Notice on the applications, returnable after two weeks."

AND WHEREAS, the matter above-mentioned was listed before **Ld. Registrar's Court on 29th April, 2024,** When the following order was passed:-

"Despite service of notice on respondent Nos.1 to 5, there is no appearance on their behalf.

Respondent Nos.6, 7.1 to 7.3 and 8 have already filed the counter affidavit.

As per office report, Ld. Counsel for respondent Nos. 9 and 10 have failed to file the counter affidavit within the period stipulated under the rules.

Ld. Counsel for respondent Nos. 9 and 10 submits that he does not wish to file counter affidavit on behalf of said respondents.

MEDIATION

(2) The facility of amicable settlement of disputes by trained mediators in cases pending in the Supreme Court is now available in the Supreme Court.

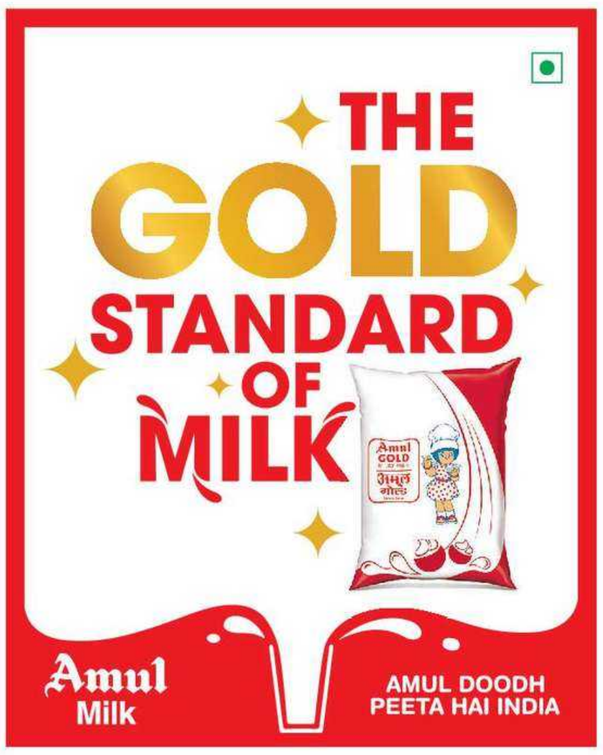
For further information, please contact the Coordinator, Supreme Court Mediation Centre, 109, Lawyers' Chambers, R.K. Jain Block - Near Post Office, Supreme Court Compound, Tilak Marg, New Delhi-110001 (Tel No. 011-23071432)

SALE/RENT

Fully Furnished Building,
New Construction, 1000 mtr. Plot
in Udyog Vihar,
Phase - 1, Gurgaon.

Basement, Stilt (Parking), 1st, 2nd & 3rd Floor • 2 Lifts • Approx. 150 Workstations, Cabins, Reception & Director's Office • Full Power Backup • Air-conditioned Building

9810022492, 9873155611



RAIL LAND DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory Authority under Ministry of Railways, Government of India)
Unit No. 702-B, 7th Floor, Konnectus Tower-II, DMRC Building, Ajmeri Gate, New Delhi-110002 Phone: + 91-11-23232854

REQUEST FOR PROPOSAL THROUGH E-TENDER
(RFP Notice No. RLDA/2024/RFP/CD-34 dated 18.07.2024)

"GRANT OF LEASE FOR COMMERCIAL DEVELOPMENT ON 10834.97 SQM (APPROX.) RAILWAY LAND FOR 60 YEARS AT BHADAU COLONY, VARANASI UNDER LUCKNOW DIVISION OF NR".

Site Description	Approx. area of the Site	FAR	Reserve Price
Bhadau Colony, Varanasi (U.P)	10834.97 Sqm.	2.0 (w.r.t. Complete Land Plot Area)	Rs. 99.50 Crore

Pre-Bid Meeting: 31st July, 2024 at 12:30 Hrs.
(Pre-bid meeting details to be obtained from Joint General Manager/Project-3)
Last Date of Submission of E-bid Online: 09.09.2024 upto 15:00 Hrs.
For Further details of the project, please visit our website www.rlda.indianrailways.gov.in or on e-procurement portal www.tenderwizard.in/RLDA under the heading 'e-tender'
For any clarifications, may please contact :-

Joint General Manager/ Project-3	Chief Project Manager/ Lucknow	Consultant of the Site: Mr. Alok Sinha	For e-bid queries- Mr. Suraj Singh
M: 76781 49900	M: 97948 83330	M: 98182 08062	M: 95996 53865
dgm_p3@rlda.railnet.gov.in	gmrldalko@gmail.com	alok.sinha@in.knightfrank.com	suraj@etenderwizard.com

Note:- Any Corrigendum or Addendum shall be published only on above mentioned websites. JGM/Tender/Expert (M) 9711305031

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

Discussion on
Union Budget 2024-25

July 24, 2024

Venue: Siri Fort Auditorium, New Delhi
Time: 03:00 PM Onwards

Chief Guest
Shri Ravi Agrawal
Chairman, CBDT

Guest Speakers
Shri Raman Chopra, Joint Secretary (TPL-I), CBDT
Shri Pankaj Jindal, Joint Secretary (TPL-II), CBDT
CA. (Dr.) Girish Ahuja, Tax Expert

Torchbearers
CA. Ranjeet Kumar Agarwal, President, ICAI
CA. Charanjot Singh Nanda, Vice-President, ICAI

Organised by
Direct Taxes Committee
Taxation Audits Quality Review Board

Hosted by
Northern India Regional Council of ICAI

Scan & Register

3 CPE Hrs.

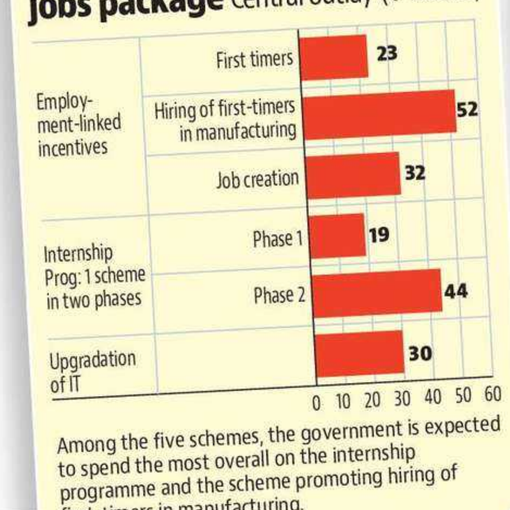
Follow us on: Excellence. Independence. Integrity. Visit: www.icai.org

UNION BUDGET UB 2024-25

THE FIVE-SCHEME JOBS PACKAGE

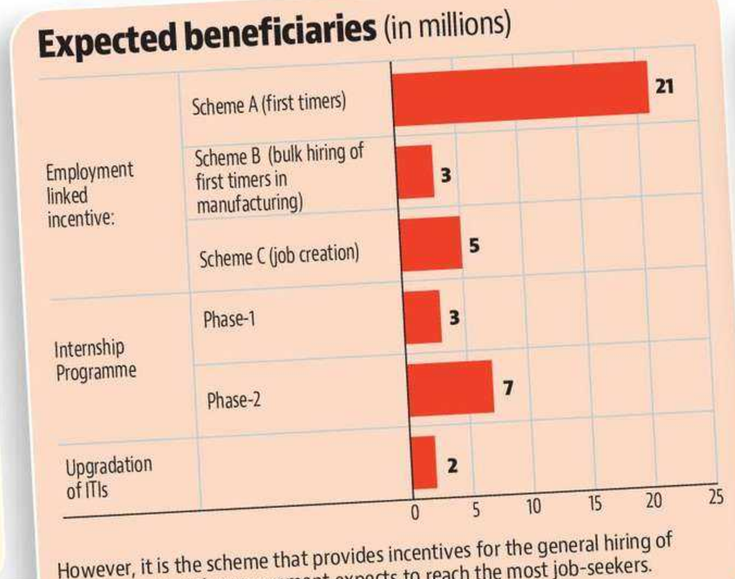
Employment was the key theme of the Budget. One of the biggest announcements on this front was a five-scheme package for jobs, with a total central government outlay of ₹2 lakh crore spread over a five-year period. This package consists of three employment-linked incentives, one internship programme, and a scheme for upgrading ITIs.

Distribution of spending in jobs package Central outlay (₹ '000 cr)



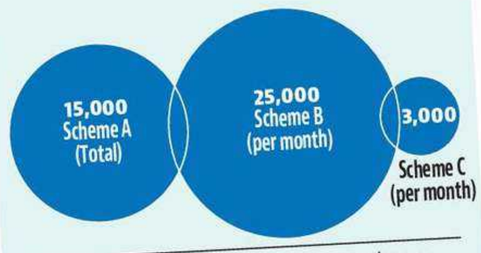
Among the five schemes, the government is expected to spend the most overall on the internship programme and the scheme promoting hiring of first-timers in manufacturing.

Expected beneficiaries (in millions)



However, it is the scheme that provides incentives for the general hiring of first-timers that the government expects to reach the most job-seekers.

Maximum limit of incentive per person (in ₹)



Scheme A: DBT of one-month salary to employees registered in EPFO up to ₹15,000
Scheme B: Contingent on bulk hiring, 24% of salary in the first two years, 16% in third year, and 8% in fourth year, with a max limit of ₹25,000. To be shared equally between employee and employer.
Scheme C: Reimbursement of ₹3,000/month of employer contribution to EPFO contingent of additional hiring

3 EPFO-based schemes among five to help boost jobs for youth

Zia Haq
zia.haq@htlive.com

NEW DELHI: The National Democratic Alliance (NDA) government announced job-creation plans worth ₹2 lakh crore in its Budget for 2024-25, unveiling incentives for firms to raise productivity, programmes to support skilling and broader reforms to spur employment.

Employment-boosting measures announced by finance minister Nirmala Sitharaman include incentives for firms in manufacturing, cheaper loans for higher education, internship programmes and credit flow to small businesses. By a wide reckoning, India isn't creating enough good-quality jobs for its rising workforce. The unemployment rate in the world's fastest growing economy declined to 3.2% in 2022-23, according to latest official data.

However, private estimates tend to show a higher joblessness rate. According to the data firm, Centre for Monitoring the Indian Economy, the country's unemployment rate was 9.2% in June 2024. A weak labour market is said to have cost the BJP a majority in general elections in June.

"In this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs (micro, small and medium enterprises) and the middle class," the finance minister said in her budget speech.

The minister announced what she called the "Prime Minister's package of five schemes and initiatives" to facilitate employment and skilling opportunities for 40.1 million youth over five years.

PM's 5 schemes to boost employment

Target **41** million youngsters
Time period **5** years

Scheme A
First-timers: A month's salary of up to ₹15,000 to be given in three installments to those registered in EPFO

Scheme B
Job creation in manufacturing: Incentive to be given to both employee and employer as per their EPFO contribution in first 4 years of employment

Scheme C
Support to employers: Reimbursement of up to ₹3,000/- month for 2 years towards EPFO contribution of employers, for each additional employee



Skilling
- 2 million youngsters to be skilled
- 1,000 training institutes to be upgraded in hub and spoke arrangements

Internship in 500 top firms
- For 10 million youngsters
- 12-month PM's internship with allowance of ₹5,000/- month

The budget outlined three schemes linked to the Employees' Provident Fund Organisation (EPFO), the state-run retirement fund manager. One, first-time employees entering the workforce in formal sectors will get a month's wage in three instalments as direct benefit transfer, up to ₹15,000. Two, as an additional incentive tied to EPFO contributions, both first-time employees and employers in the manufacturing sector will get funds linked to a specified pay scale. Three, to push firms to hire more, an employer-focused scheme will cover additional employment created in all sectors. All additional employment within a salary of ₹1 lakh a month will be counted.

The government will reimburse employers up to ₹3,000 a month for two years towards their EPFO contribution for each additional staff hired. "The scheme is expected to incentivise additional employment of 50 lakh (5 million) persons," Sitharaman said.

Other job-spurring measures include a revised Model Skill Loan Scheme to offer credit up to ₹7.5 lakh with a guarantee from a government-promoted fund. The government expects this to help 25,000 students every year get employable skills.

The Economic Survey 2023-24 tabled in Parliament on Monday said India needs to create 7.85 million non-farm jobs every year until 2030 to absorb its expanding labour force. "The increase in employment as reflected in the recent RBI KLEMPS data is largely driven by unpaid work and partly because of higher employment in agriculture because of reverse migration to villages," said Ishwar Aravind an economist with Delhi University.

The Survey, authored by the government's chief economic adviser V Anantha Nageswaran, said despite rising profits, companies weren't hiring enough. Citing a survey of 33,000 firms, the review said corporate profits had "quadrupled" between FY20 and FY23 but they had not created enough jobs. "Hiring and compensation growth hardly kept up with it," the survey stated.

Companies may be depending more on capital, known as capital deepening, at the cost of labour, the Survey had suggested.

"Privileging capital over labour is inimical to long-term corporate growth. Businesses have an obligation to themselves to strike a balance between deployment of capital and of labour," it said.

Responding to this imbalance in her budget, Sitharaman said the government's economic policy framework would be geared towards enabling more employment.

"Our government will initiate and incentivise reforms to improve productivity... facilitating markets to become more efficient. These reforms will cover all factors of production... land, labour, capital and entrepreneurship and technology," she said.

₹3L-cr allocated to welfare schemes for women, girls

Fareeha Iftikhar
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: To promote the participation of women in the workforce, the government will set up working women's hostels and creches, finance minister Nirmala Sitharaman said while presenting the budget on Tuesday.

In her budget speech, she announced the allocation of ₹3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. She said that her government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly, farmers, youth, women and the poor.

"We will facilitate higher participation of women in the workforce by setting up working women's hostels in collaboration with industries and the establishment of creches," she said. Sitharaman also said partnerships will be created to organise women-specific skilling programmes.

"To promote women-led development, the budget carries an allocation of more than ₹3 lakh crore for schemes benefitting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development," she said.

> We will facilitate the participation of women in the workforce by setting up working women's hostels.
>
> **NIRMALA SITHARAMAN,** Finance minister

In January, the central government launched inter-ministerial efforts to push for greater female participation in the workforce, with an advisory for employers to promote women's participation by enforcing statutory provisions, release of the national minimum standards and protocol for creches, focus on building more working women's hostels, and a public survey on facilities available for women at workplaces.

According to the budget document, the outlay for the ministry of women and child development seen a marginal increase of 2.5% to ₹26,092.19 crore from ₹25,448.68 crore in revised estimate for 2023-24. The SAMARTHYA sub-scheme, supporting projects such as women's hostels, Swadhar Greh and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana, was allocated ₹2,516 crore, a slight increase from revised budget of ₹2,325 crore last year.

According to the budget document, a large part of the allocated budget of the WCD ministry is directed towards centrally sponsored schemes, which received ₹25,848 crore. Experts welcomed the focus on women. "The announcement regarding the development of hostels and creches in the PPP model is in line with the CII's recommendations on creating a supportive ecosystem for migrant workforce and women to enter the workforce," said Arvind Goel, co-chairperson, CII National Committee on Industrial Relations and Chairman, Tata Autocomp.

Internship scheme sparks row, Congress says govt 'copied' key manifesto promise

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Congress on Tuesday claimed that finance minister Nirmala Sitharaman has a taken a leaf out of the Opposition party's key poll promise of a Right to Apprenticeship Act , after she said in her budget speech on Tuesday that the government would launch an internship scheme for youth in 500 top companies. The scheme will cover 10 million young people over five years, she added.

"They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions and employment opportunities. An internship allowance of ₹5,000 per month along with a one-time assistance of ₹6,000 will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of the internship cost from their CSR funds," Sitharaman said.



The scheme will cover 10 million youngsters over five years, the minister said on Tuesday. HT ARCHIVE

But the Congress was quick to point out that the idea seems to have been borrowed from its manifesto.

Congress leader Jairam Ramesh posted on X: "The Finance Minister has taken a leaf out of the INC's Nyay Patra 2024, with its internship program clearly modelled on the INC's proposed Apprenticeship Program that was called Pehli Naukri Pakki."

Ramesh, however, criticised the NDA's plan and said, "In their trademark style, the scheme has been designed to grab headlines, with arbitrary targets (10 million internships) rather than a programmatic guarantee for all diploma holders and graduates, like the Indian National Congress had envisioned."

In its manifesto for the 2024 Lok Sabha election, the main opposition party said: "Congress guarantees a new Right to Apprenticeship Act to provide a one-year apprenticeship with a private or a public sector company to every diploma holder or college graduate below the age of 25. Apprentices will get ₹1 lakh a year. The apprenticeship will impart skills, enhance employability and provide full-time job opportunities for millions of youth."

The proposed Right to Apprenticeship Act was one of the key highlights of the Congress manifesto and it was seen as an extension of the host of rights-based laws that were enacted during the UPA era.

The Congress also claimed that the Budget announcement to scrap the angel tax and the employment-linked incentive were also lifted from the Congress manifesto. Former Union minister P Chidambaram posted on X, "I was pleased to hear that the FM will abolish the Angel Tax. Congress has pleaded for the abolition for many years and most recently in the Congress Manifesto on page 31."

To be sure, the angel tax, imposed on funds raised by startups from angel investors was introduced in 2012 by the UPA government.

In her speech, Sitharaman announced that "to bolster the Indian start-up eco-system, boost the entrepreneurial spirit and support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors."

According to the IT laws, a startup or an unlisted company has to pay a part of its funding from angel investors as a tax (angel tax) if the total investment value of a firm is more than its Fair Market Value.

The excess amount is seen as "income from other sources", which is taxable.

HT reached out to the government officials for a comment but did not receive a response immediately.

myverdict



{ **GRACEY YADAV** } NEET ASPIRANT, JAIPUR

EXPECTATIONS
Young people should have ample job opportunities in the public and private sectors. I also want the government to consider more intakes in medical colleges to reduce the high competition in NEET, JEE and other similar competitive examinations. I will also like the fuel prices to be lower, which is a huge financial burden on a young person like me.

OUTCOME
There was a negligible allocation for the education sector and this might not be enough to increase the intake in the government colleges, including government medical colleges. Though the government announced a slew of schemes to boost employment in the country, the opportunities which are private-sector-oriented might not open many avenues, especially for students who come from the middle class like myself.

Govt's 3% subvention on loans up to ₹10L for Indian students

Fareeha Iftikhar
letters@hindustantimes.com

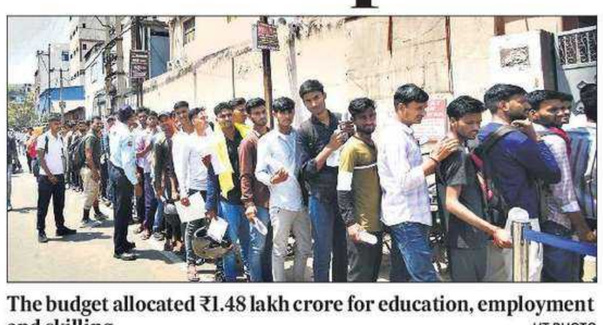
NEW DELHI: Students pursuing higher education within the country will get financial support from the central government in the form of lower interest rates for loans up to ₹10 lakh, the budget proposed on Tuesday.

"E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount," finance minister Nirmala Sitharaman said in her speech. To be eligible for this, the student cannot receive any other benefit under a government scheme or policy. High street banks typically provide education loans at around 11%-12%.

The budget for 2024-25 allocated ₹1.48 lakh crore for education, employment and skilling. Out of this, ₹1.2 lakh crore will be spent on education, representing 2.6% of total budgetary expenditure, which compares with 1.9% for health and 11.3% for transport (highest allocation).

The allocation also represented roughly a 7% decrease compared to the revised estimate for 2023-24, but remained the same as announced in the interim budget. Of the total outlay, the government has set aside ₹73,008.1 crore for schools, a marginal 0.73% increase from the revised estimate for 2023-24, while higher education was earmarked ₹47,619.77 crore, down by a sharp ₹9,600 crore, a reduction of 16.8%.

The funding for the University Grants Commission was slashed significantly by 60.9%, down to ₹2,500 crore for 2024-25 from the revised estimate of ₹6,409 crore in the preceding financial year. This, though was because some central universities funded through UGC last year will receive direct funding this year. Thus, grants for central universities shot up to ₹15,472 crore from the revised estimate of ₹12,000 crore last fiscal year.



The budget allocated ₹1.48 lakh crore for education, employment and skilling. HT PHOTO

The budget also proposed reduced support to the premier Indian Institutes of Technology to ₹10,324 crore, a fall of ₹59.7 crore compared to the revised estimate, but increased to ₹10,384.21 crore for the National Institutes of Technology and Indian Institute of Engineering Science and Technology, a rise of ₹160 crore. Allocations for the Indian Institutes of Management continued to shrink for the second financial year in a row. The allocation declined to ₹212.21 crore for 2024-25, whereas they were ₹608.23 crore and ₹300 crore in two preceding fiscal years. The allocation for R&D has increased to ₹355 crore from ₹193.3 crore shown in the revised estimate of 2023-24.

The government will operationalise the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development, Sitharaman said. "Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of ₹1 lakh crore in line with the announcement in the interim budget," she added.

In school education, allocation for the midday meal scheme, now renamed as PM Poshan, increased to ₹12,467.39 crore for 2024-25 from ₹10,000 crore in 2023-24. The outlay for Samagra Shiksha Abhiyan, a government scheme for universal education, increased to ₹37,499 crore from ₹32,999 crore earlier. The budget also set aside ₹6,050 crore for the Pradhan Mantri Schools For Rising India scheme, under which over 14,500 schools across the country will be upgraded. This has increased from last year's revised estimate of ₹2,800 crore.

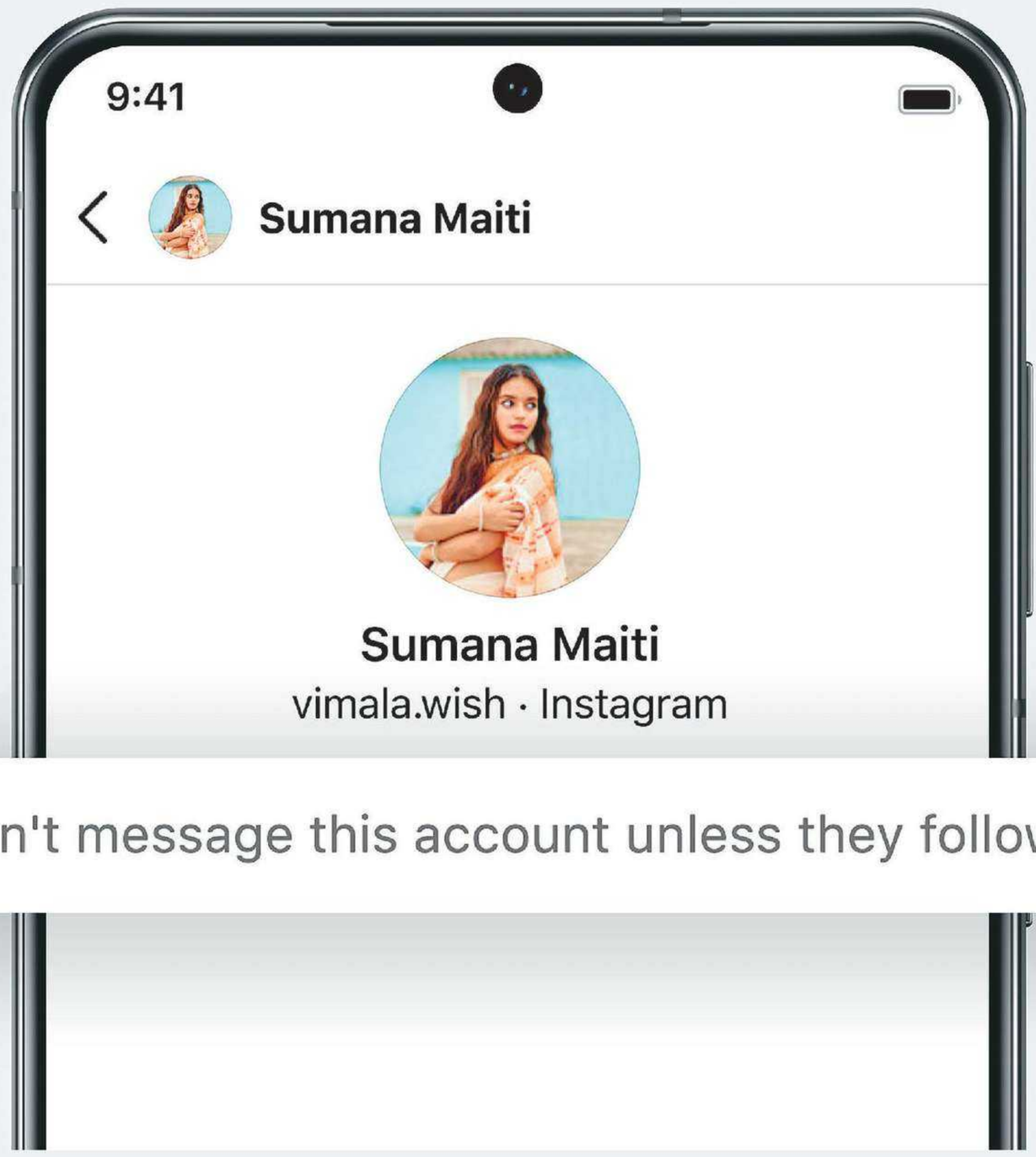
"Prioritizing education, skilling, employment generation, research and innovation like never before, #BudgetForViksitBharat paves the way for strengthening Bharat's credentials...," education minister Dharmendra Pradhan posted on X.

Education loans at lower interest rates were welcomed by educators. "The provision of financial support for loans up to ₹10 lakh for higher education in domestic institutions is a significant step towards making higher education more accessible," said Mahadeo Jaiswal, director at IIM Sambalpur.

Help keep your teen safe online with Instagram's 50+ tools

With Restricted Direct Messages, teens on Instagram can only receive messages from people they follow or are connected to.

Get started with our 50+ tools at **instagram.com/familytools**



Govt. of Haryana



Mahra Haryana Non-Stop Haryana

We Haryanvi Workers

Now receive shagun of up to ₹1 lakh on the marriage of our daughters

1,38,447 families have already received a shagun amount of ₹672 crore directly into their bank account

Now 45 lakh families with annual income of less than ₹1.80 lakh are also included in the scheme

Beti Bachao, Beti Padhao continues



Information, Public Relations and Languages Department, Haryana www.prharyana.gov.in | Follow us on @diprharyana

Time to opt out of old tax regime? Explained

mint

Aprajita Sharma
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The message from Budget 2024 was loud and clear: say goodbye to the old income tax regime. Union finance minister Nirmala Sitharaman proposed three key changes in the new tax regime, while the old one was left untouched.

She tweaked the slab rates. Income up to ₹3 lakh will attract no tax, while it will be 5% for ₹3 lakh-7 lakh, 10% for ₹7 lakh-10 lakh, 15% for ₹10 lakh-12 lakh, 20% for ₹12 lakh-15 lakh and 30% for ₹15 lakh and above.

Standard deduction for salaried employees was increased to ₹75,000 from ₹50,000 earlier.

The limit on an employer's contribution to an employee's National Pension System account, which attracts tax deduction for employees in the new tax regime, has been increased to 14% of the basic salary from 10% earlier.

Considering all these changes, the total tax savings in the new regime will amount to a maximum of ₹17,500.

Does this mean everyone should move to the deduction- and exemption-free simplified regime? Not necessarily. We compared both regimes for different income groups to deduce which one works for whom.

First things first. If your annual income is up to ₹7 lakh, choose the new regime because the tax rebate of ₹25,000 under Section 87A makes your tax liability zero. For the salaried class, the threshold is higher at ₹7.75 lakh, thanks to the standard deduction of ₹75,000, which is not available to the self-employed.

Those with income above the nil-tax threshold need to calculate the total amount of deductions and exemptions they can claim in the old tax regime. We computed the break-even amount for each income level. If your deductions and exemptions exceed the break-even amount, go for the old tax regime, otherwise the new tax regime will be better.

For annual income of ₹10 lakh, the break-even limit is ₹3.5 lakh, assuming tax deduction of ₹4 lakh against investments, donations and insurance premium. Since the deductions are higher than the break-even limit, the old regime will make sense.

If your annual income is ₹15 lakh and you can claim deductions of more than ₹4.58 lakh, you should go for the old regime.

The highest break-even point comes in at ₹4.83 lakh and is applicable for income levels ranging from ₹15.75 lakh to ₹5 crore.

"People with an annual income of more than ₹5 crore need not make this comparison. They should always go for the new tax regime, thanks to a lower surcharge rate of 25% applicable in the new tax regime against 37% in the old tax regime," said Anurag Jain, co-founder and partner at ByTheBook LLP Consulting.

Chartered accountant Naveen Wadhwa calculated the breakeven point by the income threshold and the typical deductions taken. To be sure, people generally opt for deductions adding up to ₹4 lakh - ₹1.5 lakh under Section 80C, ₹50,000 under Section 80D (₹25,000 for self and another ₹25,000 for parents) and ₹2 lakh for interest on housing loan under Section 24 (b).

"If your annual income is more than ₹14.75 lakh, the new tax regime will be better against ₹4 lakh deduction, while those earning below ₹14.75 lakh should go for the old tax regime. This income threshold comes in at ₹7.75 lakh if you opt for deductions only under Section 80C and 80D," said Wadhwa, vice president of Taxmann.

To be sure, about 70% of the taxpayers opted for the new tax regime so far in FY24.

"The proposed changes will provide the necessary impetus for individuals to stick with the new tax regime rather than revert to the old tax regime. It is welcoming as it will bring forth the much-needed change in the mindset that investments must be made keeping personal goals in mind rather than looking at it from a tax-planning angle. The simplified regime will also curtail fraud and litigation," said Jain.



Simplifying the new tax regime



- Standard deduction for salaried employees increased **from ₹50,000 to ₹75,000**
- Deduction on pension for pensioners increased **from ₹15,000 to ₹25,000**

{ TAX 'RATIONALISED' }

Tricky tweaks for capital gains

mint

Neil Borate & Jash Kriplani
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The government has rolled out significant changes to the capital gains tax framework that are expected to impact a wide range of investors.

Beginning 24 July, new tax rates on capital gains for various asset classes will be implemented. Indexation benefits have been removed across all asset classes.

Finance minister Nirmala Sitharaman in her budget for 2024-25 increased the short-term capital gains tax on certain financial assets to 20% from 15%. The long-term capital gains tax on all financial and non-financial assets will attract a tax rate of 12.5%. Mint decodes how different asset classes will be taxed and what the changes means for investors.

Stocks, equity mutual funds

For stocks and equity mutual funds, the short-term capital gains tax rate has been increased to 20% from 15%, while the long-term capital gains tax rate has been increased to 12.5% from 10%. At the same time, the exemption limit has been increased from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh. "The move will nudge more long-term investing in equities as the taxation on short-term capital gains has been increased," said Niranjan Avasthi, head of product and marketing at Edelweiss Asset Management.

Debt mutual funds

Debt mutual funds will continue to be taxed at the slab rate of the investor. The mutual fund industry had hoped for a reversal of last year's budget changes on debt funds that had removed indexation benefits. However, gains from debt funds will continue to be taxed at the slab rate of the investor, regardless of their holding period.

Other mutual funds

The mutual fund industry welcomed the clarity in the budget for fund-of-funds and gold/silver exchange-traded funds, or ETFs. Changes in the previous budget had led to fund-of-funds and gold/silver ETFs getting treated as debt funds for taxation purposes.

Under the new rules, equity fund of funds will be taxed at slab rate of the investor if held for less than 24 months, and the long-term capital gains tax rate of 12.5% will be applicable for those held longer. The new rates will be standard across equity FoFs, gold/silver ETFs, and gold funds. For long-term holding to be applicable, 24 months will be the applicable period. "The requirement of investment of not more than 35% in equity shares has also impacted other funds which are not debt-oriented funds, but invest below 35% in equity shares," read the memorandum of the Union Budget.

"There was an anomaly for fund-of-funds after the previous budget and this clarity is a welcome step," said Swarup Mohanty, chief executive officer of Mirae Asset MF.

"We also see some impact for arbitrage funds as there is a hike in securities transaction tax (STT) on the futures and options segment," said A. Balasubramanian, chief executive officer of Aditya Birla Sun Life Mutual Fund. The STT on options has been increased from 0.0625% to 0.1% and on futures from 0.0125% to 0.02%.

Real estate

The removal of indexation benefit is likely to impact real estate investors the most. Indexation had allowed investors to adjust their acquisition price as per inflation, helping them lower their capital gains for taxation purposes.

"This proposal is going to discourage long-term investment in properties and encourage short-term investment," said Prakash Hegde, a Bengaluru-based chartered accountant. "The saddest part is that people who were already holding it till now will lose the indexation benefit."

Other investments

Unlisted investments such as physical gold will now get the benefit of long-term holding period after two years of holding. This was three years under previous rules. The new rules will also give investors the benefit of the long-term capital gains tax rate of 12.5%, which has been standardized across asset classes.

with inputs from Sashind Ningthoukhongjam

ALL LISTED ASSETS

	Earlier STCG	Now STCG	Holding Period	Holding Changed?	Earlier LTCG	Now LTCG
Stocks	15%	20%	12 months	No	10%	12.50%
Equity Mutual Funds	15%	20%	12 months	No	10%	12.50%
Debt and non-Equity MFs	Slab rate	Slab rate	N/A	No	Slab rate	Slab rate
Bonds (Listed)	15%	20%	24 months	Yes#	10% without indexation	12.50%
REITs/InVITs	15%	20%	12 months	Yes*	10%	12.50%
Equity FoFs	Slab rate	Slab rate	24 months	N.A.	Slab rate	12.50%
Gold/Silver ETF	Slab rate	Slab rate	24 months	N.A.	Slab rate	12.50%
Overseas FoFs	Slab rate	Slab rate	24 months	N.A.	Slab rate	12.50%
Gold Funds	Slab rate	Slab rate	24 months	N.A.	Slab rate	12.50%

Annual LTCG exempt amount hiked from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh for stocks and equity MFs

ALL UNLISTED ASSETS

	Earlier STCG	Now STCG	Holding Period	Holding Changed?	Earlier LTCG	Now LTCG
Real Estate (Physical)	Slab rate	Slab rate	24 months	No	20%**	12.5%
Bonds (Unlisted)	Slab rate	Slab rate	24 months	N.A.	Slab rate	Slab rate
Physical Gold	Slab rate	Slab rate	24 months	Yes*	20%**	12.5%
Stocks (Unlisted)	Slab rate	Slab rate	24 months	No	20%**	12.5%
Foreign equities/debt	Slab rate	Slab rate	24 months	No	20%**	12.5%

*36 months; **With indexation
#12 months
Note: The changes for gold funds, FoFs, feeder funds apply after 1 April 2025
Changes for other asset classes are effective for assests sold after 23rd July 2024

mint

International Financial Services Centres Authority (IFSCA)
(A statutory authority established by the Government of India)
2nd & 3rd floor, savvy Pragya,
Gujarat International Financial Tec-city
Gandhinagar Gujarat - 382355, India
Tel: +91-79-61809800, Web: www.ifsca.gov.in

Tender Notice for Selection of Solution Provider (SP) for Core Supervisory Technology (Core SupTech) System Project of IFSCA

Tender No.: IFSCA/Technology/2024/001

The International Financial Services Centres Authority (IFSCA) intends to select a Solution Provider (SP) for Core Supervisory Technology (Core SupTech) System Project of IFSCA and has issued Request for Proposal (RFP) for the said purpose. The last date for submission of bids has now been revised to **5th August 2024 at 1500 hrs**.

For more details, please refer to IFSCA's e-Procurement Portal (**https://ifsca.enivida.com/**) or the Official Website of IFSCA (**https://ifsca.gov.in/home/TenderList/**).

General Manager-IT
International Financial Services Centres Authority (IFSCA)
CBC 15228/12/0004/2425

एसजेवीएन लिमिटेड SJVN Limited
(भारत सरकार एवं हिमाचल प्रदेश सरकार का संयुक्त उपक्रम)
(A Joint Venture of Govt. of India & Govt. of H.P.)
CIN No. L40101HP1988GOI008409

NOTICE
TRANSFER OF EQUITY SHARES OF THE COMPANY TO INVESTOR EDUCATION AND PROTECTION FUND (IEPF)

Notice is hereby given pursuant to provisions of the Companies Act, 2013 and Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time. The IEPF Rules, amongst other matters, provide that all shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, shall be transferred in the name of Investor Education and Protection Fund (IEPF).

Adhering to the requirements as set out in the IEPF Rules, the Company has also communicated individually to concerned shareholders at their latest available addresses, whose shares are due for transfer to IEPF Authority under the said rules for taking appropriate action.

Further, in terms of relevant IEPF Rules, the Company has also uploaded details (including DP & Client ID/Folio Number) of concerned shareholders whose shares are due for transfer to IEPF on website of the Company (www.sjvn.nic.in) under the Investor Relations Section. The details uploaded by Company on its website should be regarded and shall be deemed as adequate notice in respect of transfer of shares to IEPF.

Shareholders are advised to claim the unclaimed dividend amount from the Financial Year 2016-17 onwards immediately by sending a formal letter mentioning their beneficiary account no. or folio number along with self – attested copy of PAN card and address proof immediately to Alankit Assignments Limited, Registrar and Share Transfer Agent of the Company by 26th October, 2024.

In case the Company / Registrar & Share Transfer Agent does not receive any communication from the concerned shareholders claiming dividend of any of the past Seven Financial years by 26th October, 2024 or such other date as may be extended, the Company shall proceed to transfer the shares in respect of which dividend has not been paid or claimed by the shareholders for seven consecutive years or more, without any further notice as per procedure set out in IEPF Rules.

Shareholders may please note that the shares and unclaimed amounts transferred to the IEPF can be claimed back from the IEPF after following the procedure prescribed under the Companies Act, 2013 and IEPF Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed amount and shares transferred to IEPF pursuant to provisions of said rules, as amended from time to time.

For any queries or clarifications on the subject matter, shareholders may contact:

Company Secretary, **SJVN Limited,** **SJVN Corporate Office Complex,** **Shanan, Shimla – 171006** **Tel: 0177 - 2660075** **Email: investor.relations@sjvn.nic.in**	**Alankit Assignments Limited** **Alankit Heights, 4E/2,** **Jhandewalan Extension,** **New Delhi – 110055.** **Tel: 011 - 42541957** **Email: rameshk1@alankit.com**

Place: Shimla
Date: 24.07.2024

For SJVN Limited
Sd/-
Soumendra Das
Company Secretary

Regd. Office: SJVN Corporate Office Complex, Shanan, Shimla – 171006 (HP)
Tel: 0177- 2660070, Email: investor.relations@sjvn.nic.in, Website: www.sjvn.nic.in

PUBLIC NOTICE
GOVERNMENT OF HARYANA
EXCISE & TAXATION DEPARTMENT

NOTICE FOR INVITING e-TENDERS FROM GENERAL PUBLIC FOR ALLOTMENT OF REMAINING RETAIL LIQUOR ZONES IN TEN (10) DISTRICTS IN THE STATE OF HARYANA FOR THE EXCISE POLICY YEAR 2024-25.

1. It is notified for the information of general public that e-tenders for allotment of 13 retail liquor zones of country liquor and Indian Made Foreign Liquor vends (L-2/L-14A) in 10 districts in the State of Haryana are hereby invited for the excise policy year 2024-25. The district wise detail of zones available for e-bidding is as under:-

Sr. No.	Name of District	Zone Code	
1.	Faridabad	ZFBD73	
2.	Gurugram (East)	ZGRE08	
3.	Hisar	ZHSR01	ZHSR07
4.	Jhajjar	ZJHA22	
5.	Kurukshetra	ZKKR01	
6.	Narnaul	ZNNL19	ZNNL28
7.	Panipat	ZPNP16	
8.	Rewari	ZRWR31	
9.	Rohtak	ZRTK05	ZRTK18
10.	Sirsa	ZSRS14	

2. The schedule for submission of e-bids for these zones and evaluation thereof shall be as under:-

Starting date and time for placing e-tenders	From 25th July, 2024 (9.00 AM)
Closing date and time for placing e-tenders	Till 25th July, 2024 (04.00 PM)
Evaluation of e-tenders	25th July, 2024 (5.00 PM)

3. The reserve price and quota of these 13 zones for the purpose of e-tendering has been decided as per the provisions of clause 2.16 and other relevant provisions of the Haryana Excise Policy 2024-25.
The zone-wise detail of reserve price and quota of these 13 zones shall be displayed in the excise arrangement.

4. The e-tenders for these zones can be submitted online through the official website of the department i.e. **www.haryanatax.gov.in**. The remaining terms and conditions of e-tenders and allotment of zones shall be same, as informed vide the Public Notice, published in leading newspapers on 18th May, 2024, for inviting e-tenders for allotment of retail liquor zones of all districts in the State of Haryana. The copy of Public Notice dated 18th May, 2024 is also available on the official website of department i.e. **www.haryanatax.gov.in**. The detailed procedure of registration for participation in the allotment process and submission of e-tenders is also available on the official website.

5. The excise arrangements of these zones containing number of vends, liquor quota, location of vends, command area as applicable and reserve price thereof, as well as the venue for evaluation of e-tenders shall be conspicuously displayed in the office of DETCs (Excise) and DETCs (ST) of the districts concerned. These details shall also be available on the official website i.e. **www.haryanatax.gov.in**.

6. All allotment(s) and grant of licence(s) shall be subject to the provisions of the Haryana Excise Act, 1914, the rules framed thereunder, orders/instructions issued by the competent authority and the Excise Policy for the year 2024-25. Any clarification regarding the procedure may be obtained from the office of DETCs (Excise) in any of the districts. The copy of Haryana Excise Policy for the year 2024-25 is available on official website of the department.

7. All allotments of licenses are subject to the approval of the Excise and Taxation Commissioner (Financial Commissioner). The ETC (FC) may reject, without assigning any reason, any allotment in public interest as the case may be, within 10 days of the date of allotment. In case no decision of Excise and Taxation Commissioner (FC) is conveyed within the stipulated period of ten days, the allotment shall be deemed to have been approved by the ETC(FC).

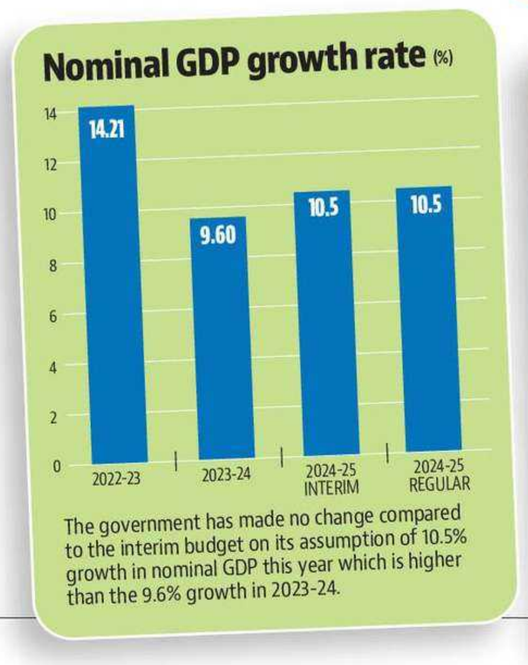
Excise and Taxation Commissioner
RO No. 1037/11/236/2025/28127/19/7 **Haryana**

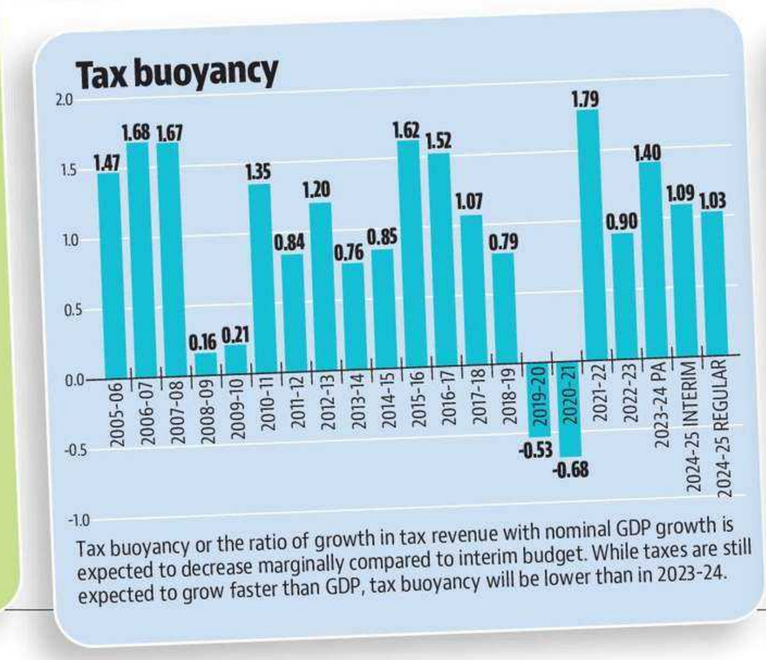


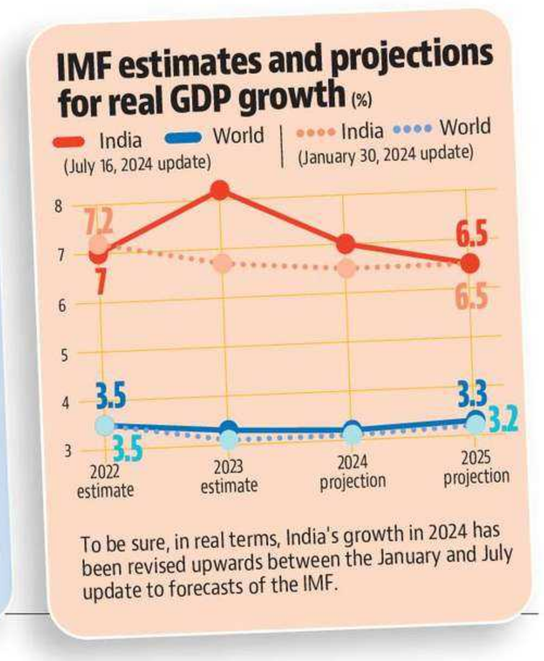
UNION BUDGET UB 2024-25

KEY ASSUMPTIONS IN BUDGET MATHS

All budgetary maths depends on two key assumptions and estimates: the nominal growth rate of GDP and the buoyancy of taxes. The regular budget for 2024-25 has assumed a nominal GDP growth of 10.5% and tax buoyancy of almost 1, the former same as in the interim budget and latter slightly lower. These assumptions were made amid an IMF forecast for 7% growth this year, compared to a 6.5% forecast in January.







Nitish hails progressive Bihar package, RJD 'disappointed'

Ruchir Kumar and Arun Kumar
letters@hindustantimes.com

PATNA: Bihar chief minister Nitish Kumar on Tuesday welcomed the Union Budget as "progressive" — it earmarked several schemes for the state, from roads to tourism to irrigation to infrastructure to health care — even as the leader of Opposition in the state assembly, Tejashwi Yadav, described the measures as a "letdown".

The announcements by Union finance minister Nirmala Sitharaman highlighted the importance of the Janata Dal (United) in the new National Democratic Alliance (NDA) regime at the Centre, and Nitish took credit for pushing for his state's demands.

"I have continuously spoken for this. I told them to give us either a special status or a special package. As a follow-up, they have announced aid for a lot of things. We were speaking of special status and a lot of people said that the provision for special status has been done away with much earlier. So, instead of that, aid should be given to help Bihar. They have now started it," Nitish told reporters in Patna.

Deputy chief minister and state BJP president Samrat Choudhary, who also holds the finance portfolio, said the Centre had "opened the coffers (*khazana khol diya*)" for Bihar. "It is a historic budget for which PM Narendra Modi deserves kudos. The state will see expressways, new power plants, and a medical college. Every aspect, including flood control and development of tourism, have been taken care of," he said.

Bihar secured ₹26,000 crore for road connectivity projects, new airports and sports infrastructure. It will also get ₹11,500 crore for flood mitigation, a major demand by the state.

But Tejashwi, who has not attended the assembly in recent days, said that the budget lacked a revival plan for the state, which was in dire need of a special status and a special package. "The Centre must not insult the people of Bihar by presenting routine outlays as something out of the ordinary. We shall not retract, even by an inch, on the demand for special status which is required to eradicate backwardness of the state from where young people are forced to migrate in search of a better future," the RJD leader added.

Former chief minister and RJD leader Rabri Devi, described the announcement of ₹26,000 crore of support to Bihar for the development of crucial projects, including road connectivity and infrastructure, as a "jhunjhuna" (toy).

Experts and stakeholders in the state, however, welcomed the measures.

Bihar Industries Association president KPS Keshri called it a "developmental budget" — one that was "commendable from Bihar's point of view and would boost the state's infrastructure".

Bihar Chamber of Commerce and Industries president Subhash Patowari thanked the Centre for having given to the state a "surfeit of schemes to boost infrastructure and irrigation facilities, besides mitigating the miseries of perennial floods in north Bihar".

The president of Bihar Motor Transport Federation, Uday Shankar Singh, said: "The special package should be implemented in the right manner with all stakeholders getting benefit of it. It would only help the faster development of the state."

Bihar will face assembly polls next year.



Budget only aims to save chair, not need-based: Oppn

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The INDIA group of opposition parties slammed the budget presented by finance minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Tuesday, alleging the government led by the Bharatiya Janata Party has merely tried to save itself through this exercise.

The budget for 2024-25 was disappointing, Congress president Mallikarjun Kharge said. "The budget distribution is not need-based, but only to save the chair," he said. "The budget has pleased just two people, while ignoring the interests of 140 crore Indians."

He was obliquely referring to the chiefs of Telugu Desam Party of Andhra Pradesh and Janata Dal (United) of Bihar, key allies of the Bharatiya Janata Party.

Leader of the opposition in the Lok Sabha Rahul Gandhi termed it as a "kursi bachao (save chair)" budget. "-Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states. - Appease Cronies: Benefits to AA with no relief for the common Indian. - Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets," he posted on X.

Kharge claimed that the budget ignored significant sections of the population that included the middle class, farmers, youth, scheduled castes and tribes. "The BJP government had tried to settle scores with the SCs, STs and backward classes as most of them had voted for the INDIA bloc this time," Khagre said, pointing out that the budget failed to address "the issue of rising prices under which the entire country was reeling and people were suffering."

"The party had expected the budget to address the long pending issues of the farmers including the legal guarantee for the MSP (minimum support price), subsidy on fertilisers and other things," he said. "But none of these things were mentioned in the budget."

Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav said, "In the eleventh budget, the issues of unemployment, inflation, farmers, women and youth have vanished. This budget is also a bundle of despair. Thankfully, people are still alive in these conditions."

"There is no provision in the budget for the safety of women," SP MP and Yadav's wife Dimple Yadav told the media. "The kitchen has not been taken care of because the government does not want to take any step regarding inflation."

"Modi government has not been able to fulfill its promise of providing employment. No new solutions are invented to provide employment...," Nationalist Congress Party (Sharad Pawar) posted on X. "Now the youth of Maharashtra will not rest without teaching a lesson to the BJP in the coming assembly elections." Maharashtra is scheduled to elected a new assembly later this year.

"This time the share market has gone down after the budget was presented. This means that the market did not like this budget," AAP's Sanjay Singh told reporters.

Congress CMs, Stalin to boycott Niti Aayog meet

Meanwhile, Congress general secretary KV Venugopal said the party will not send its chief ministers in the upcoming meeting of the NITI Aayog's governing council on July 27. "The Union Budget was extremely discriminatory and dangerous...In protest, INC CMs will be boycotting the NITI Aayog meeting," he said.

Tamil Nadu CM MK Stalin will also give the NITI Aayog meeting a miss. "There was no mention of Tamil or Tamil Nadu" in the speech, he said.

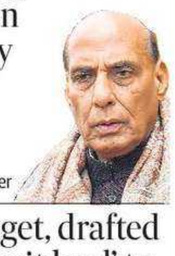
MINISTERS SPEAK

Harnessing the power of Bharat's youth, Nari Shakti and farmers, the budget fuels the nation's pace on the path of emerging as a developed nation by ushering in a new era of employment and opportunities... my heartfelt gratitude to PM and FM...



AMIT SHAH, Home minister

Inspired by PM Modi's vision of inclusive and fast-paced development, this budget will accelerate India's economic transformation... it will go a long way in making India a $5 trillion economy by 2027.



RAJNATH SINGH, Defence minister

The budget, drafted with 'Amrit kaal' to 'Mission 2047' in mind, ensures comprehensive development across sectors such as agriculture, rural development, education, and health care.



JYOTIRADITYA SCINDIA, Communications minister

I think this is a budget for new India. It is taking India in the Amrit Kaal rapidly, progressing towards a developed nation by 2047.



PIYUSH GOYAL, Commerce and industry minister

In the past 10 years, we have laid a very strong foundation for our economy... the work done in 10 years, the continuity of that effort is reflected in today's budget



ASHWINI VAISHNAW, I&B minister

Bolstering NDA in focus as 2 states get lion's share

Rajeev Jayaswal and Smriti Kak Ramachandran
letters@hindustantimes.com

THE GOVERNMENT ACCOMMODATED THE WISHES OF ITS TWO MAIN ALLIES — TDP AND JD(U) — THAT RUN GOVTS WITH THE BJP IN ANDHRA PRADESH AND BIHAR

NEW DELHI: The generous financial assistance announced for Andhra Pradesh and Bihar by finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday while presenting her seventh Union budget should reaffirm the stability of the Bharatiya Janata Party-led National Democratic Alliance government.

The BJP, which fell short of a majority in the Lok Sabha in its third straight term, relies on 28 lawmakers of the Telugu Desam Party and Janata Dal (United) in addition to representatives from a clutch of other parties.

The government accommodated the wishes of its two main allies that run alliance governments with the BJP in Andhra Pradesh and Bihar. Both partners had sought special category status or special packages to meet infrastructure needs in their states.

Bihar secured ₹26,000 crore for road connectivity projects, new airports and sports infrastructure. It will also get ₹11,500 crore for flood mitigation, a major demand by the state. The Bihar government had asked the Centre to provide funds to build infrastructure projects such as barrages and river-linking projects to prevent losses due to recurring floods, HT reported on Sunday.

"Bihar has frequently suffered from floods, many originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Programme and other sources, will provide financial support for projects with an estimated cost of ₹11,500 crore," Sitharaman said while announcing allocations for Bihar, which will elect a new assembly in 2025. "Additionally, a survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken."

The Centre will support the development of an industrial hub at Gaya on the Amritsar-Kolkata industrial corridor in Bihar to catalyse the development of the eastern region, she added.

The budget announcements for Bihar are "just the beginning" and the provisions for infrastructure projects, the power plants and other projects will be a "game changer" for the state, JD(U) working chief Sanjay Jha said. "We are particularly happy at the mention of the critical pain point for Bihar about the flood control structures in Nepal. Over the years, under the visionary leadership of chief minister Nitish Kumar, I have constantly pursued this matter — as an MLC, water resources minister and then as Rajya Sabha MP."

In Andhra Pradesh, where chief minister N Chandrababu Naidu had put on record the need for special assistance to build capital Amaravati, the budget proposed a package of ₹15,000 crore for the same. Sitharaman announced that her government is also committed to ensure the completion and financing of Polavaram irrigation project, she added.

"Under the AP Reorganisation Act, for promoting industrial developments, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads and also grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasam North coastal Andhra Pradesh, as stated in the Act will be provided," she said.

"On behalf of the people of Andhra Pradesh, I thank the Hon'ble Prime Minister, @narendramodi Ji and Hon'ble Union Finance Minister, @nsitharaman Ji, for recognising the needs of our State and focusing on a Capital, Polavaram, industrial nodes and development of backward areas in AP in the union budget of FY 24-25," Naidu said in a post on X. "This support from the Centre will go a long way towards rebuilding Andhra Pradesh..."

Opposition parties, however, called it a disappointing budget.

"This budget of the finance minister was very disappointing... It was to give priority to two states and two particular political parties, because the government has to save its chair. There was nothing in it for the middle class, farmers and the unemployed. But there was a lot in it for those industrialists who donate to BJP," said Congress' deputy leader in the Lok Sabha Gaurav Gogoi.

Andhra gets ₹15k-cr boost for Amaravati

Srinivasa Rao Apparasu
letters@hindustantimes.com

HYDERABAD: A special financial support of ₹15,000 crore to develop the capital city at Amaravati, release of adequate finances for early completion of the Polavaram irrigation project on the Godavari river and provision of funds for essential infrastructure in two major industrial corridors were some of the measures proposed by finance minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget presented in Parliament on Tuesday.

"Our government has made concerted efforts to fulfil the commitments in the Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2024," Sitharaman said while making a special mention of the law in her speech.

Andhra Pradesh is ruled by the National Democratic Alliance comprising the Telugu Desam Party, Jana Sena Party and Bharatiya Janata Party.

Recognising the state's need for a capital, the Centre will facilitate special financial support through multilateral development agencies, Sitharaman said. "In the current financial year, ₹15,000 crore will be arranged, with additional amounts in future years."

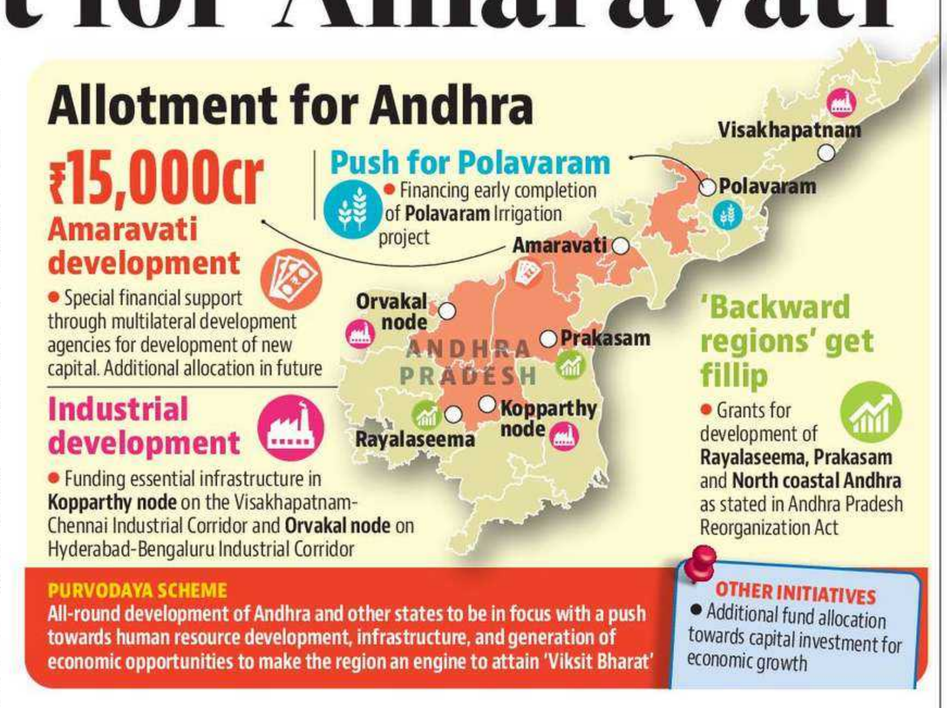
Although the budget text did not specifically mention the mode of financial support for Amaravati, it would imply that the Centre would stand a guarantee to the long-term lending by multilateral development agencies like the World Bank, Asian Development Bank and other financial institutions, TDP spokesperson G Deepak Reddy said. "We are yet to get finer details about the pattern of financing. But getting ₹15,000 crore in the first year itself would go a long way in the construction of the capital city," he said. "It is a good beginning."

The Amaravati capital city project, initiated by TDP president and chief minister N Chandrababu Naidu in 2015, was abandoned by the YSR Congress Party government in 2019 after over ₹9,000 crore was spent on various work. The Centre had sanctioned ₹2,500 crore for this purpose, of which ₹1,500 crore was released. The balance grant got lapsed due to change of government in the state in 2019.

Another major announcement made by Sitharaman was the Centre's commitment to complete the Polavaram irrigation project on Godavari river. "Our government is fully committed to financing the early completion of the Polavaram irrigation project – which is the lifeline of Andhra Pradesh and its farmers," she said, adding it would facilitate the country's food security as well.

The finance minister further announced that funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways and roads in Kopparthy node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Orvakal node on Hyderabad-Bengaluru Industrial Corridor.

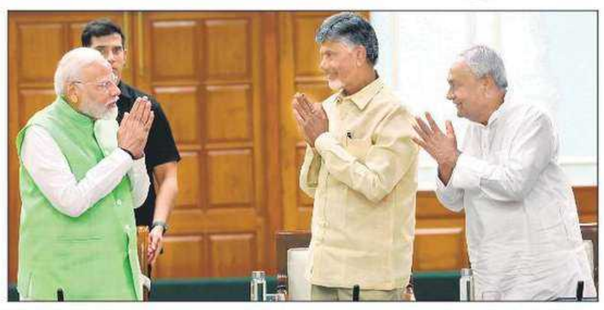
"An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth," Sitharaman said.



{ ALLY FRIENDLY ALLOCATIONS }

Coalition dharma focus of post-election budget

Smriti Kak Ramachandran
letters@hindustantimes.com



PM Narendra Modi meets NDA partners Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu and Bihar CM Nitish Kumar, on June 5. ANI

NEW DELHI: The Bharatiya Janata Party (BJP) made an attempt to keep its National Democratic Alliance (NDA) partners and core supporters happy by ensuring that the Union Budget had something for the allies, critical for the stability of the government, and for four segments — poor, farmers, women and the youth — that are key for electoral success.

The Union Budget was careful to address the concerns of key allies Telegu Desam Party and Janata Dal United.

"The party has ensured that it walked the talk on coalition dharma...we have been saying that the BJP does not desert its allies and this budget proves it," said a senior party functionary, requesting anonymity. He dismissed the allegations of the Opposition that in trying to "save the government" the finance minister overlooked the concerns of other states.

"There is something for everyone...the focus on Andhra Pradesh and Bihar is because these were pressing demands, much needed for infrastructure development," the functionary said.

Party chief JP Nadda referred to the "first budget of Modi 3.0" as "a testament to India's inclusive growth, sustainable development and economic resilience".

"This visionary budget not only addresses the immediate needs of the nation but also lays down a robust framework for long-term prosperity, while also prioritising infrastructure development, technological innovation and social welfare. It paves the way for a more prosperous and equitable India," he said.

After it failed to secure a majority on its own and won 240 seats, the BJP is dependent on the 14-party NDA. Andhra Pradesh was allocated ₹15,000 crore for building its capital Amaravati, and a commitment to the completion of Polavaram irrigation project; Bihar secured ₹26,000 crore allocation for road connectivity projects, new airports and sports infrastructure. The state will also get ₹11,500 crore for flood mitigation projects.

The government's move drew a sharp response from the Opposition. In poll-bound Maharashtra, Shiv Sena (UBT) leader Aaditya Thackeray took a pot shot at the government and said other states were neglected.

"I can understand the BJP wanting to save its government and giving Bihar and Andhra Pradesh a huge sum of the budget...But what is Maharashtra's fault? That we are the largest taxpayer? What did we get against what we contribute? Was Maharashtra even mentioned once in the budget?" he asked. The BJP and the Sena, which later split into two factions, parted ways in 2019 over power sharing.

In Odisha, where the BJP ousted the Biju Janata Dal from power in June, resentment at being overlooked for special assistance was articulated by the Opposition. "I feel disappointed at the continued neglect of Odisha while the state contributes so much to the country," BJD president and former CM Naveen Patnaik said. His party colleagues in the Rajya Sabha walked out when the budget was presented.

While Odisha, Andhra Pradesh and Bihar were asked for special category, the two states got special additional funds while Odisha's demand was not considered. "Probably this is the punishment meted out to Odisha for electing 20 Lok Sabha BJP MPs out of 21 MPs from Odisha and the reward to the BJP allies from Bihar and Andhra Pradesh," BJD leader Sasmit Patra said.

Unfazed by the criticism, the BJP asserted that the focus on employment generation, skilling, micro, small and medium enterprises, and boost agriculture will put the country on the path of economic growth. "What is purvodaya... it is our commitment to the development in the eastern states including Odisha (Bihar, Jharkhand, West Bengal and Andhra Pradesh being the other states), the Opposition has no reason to complain," the functionary quoted above said.

The offshoots of the Rashtriya Swayamsevak Sangh, the BJP's ideological mentor, also supported the budget. "The budget is slated to be a great leap towards employment generation and skill development. It's an employment centric budget and the government has addressed many of our concerns and demands," said Ashwani Mahajan of the Swadeshi Jagran Manch.

Ghanshyam Oza of the Laghu Udyog Bharti, the offshoot that works with MSMEs, also welcome the attention given to the sector. "There has been a lot done for the MSMEs and we are hopeful that the FM will heed our demand to divert labour engaged in MNREGA works to work in the MSME sector to meet the labour shortfall and also give a one time exemption for technical faults that arose in filing GST between 2017 to 2022," he said.

FM lowers fiscal deficit target to 4.9% for FY25

Rajeev Jayaswal
letters@hindustantimes.com



NEW DELHI: Union finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday made a downward revision in India's fiscal deficit target for the current financial year from 5.1% of the gross domestic product (GDP) targeted in the interim budget in January to 4.9% on prudent expenditure management and buoyant revenue receipts. "The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach a deficit below 4.5% next year. The Government is committed to staying the course," she said in her budget speech in Parliament.

Sitharaman also hinted at a newer way to benchmark fiscal management. "From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the Central Government debt will be on a declining path as percentage of GDP." While the full budget for 2024-25 has not provided rolling targets for the next two years, it envisaged that "an active and nimble fiscal policy strategy is a pre-requisite for smooth fiscal policy operations".

Explaining this strategy, finance secretary TV Somanathan said, "Hereafter, it is not the intention to focus on the deficit number, but rather to look at what will keep reducing — the debt to GDP ratio in normal years."

"The reason for this is, a fixed figure, which historically was enshrined in the FRBM Act in past, does not take into account the specific debt dynamics of a fast-growing economy like India," he added. The Fiscal Responsibility and Budget Management Act (FRBM Act), 2003 (as amended) became effective from July 5, 2004. It mandates the Central government to reduce fiscal deficit to an amount equivalent to 3% of GDP. It also prescribes the format for the medium-term fiscal policy statement to be presented to Parliament along with the annual financial statement.

Somanathan, who is also the expenditure secretary, said the figure of 3% "correctly or wrongly" came from Europe. "But the growth rates of those countries are very low. So, what is sustainable in a fast growing economy is very different from the debt which is sustainable in a slow growing economy. So, India is today the fastest growing large economy in the world. The deficit, which we can support in a particular year without expanding our debt, is not necessarily 3%. It is much more than 3%."

"Yes, it is a new approach that the government has spoken about. And so each year's calibration will be based on what will be a percentage which will keep our debt on a reducing path," Somanathan said.

According to the budget, for the year 2024-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at ₹32.07 lakh crore and ₹48.21 lakh crore respectively. The net tax receipts are estimated at ₹25.83 lakh crore. And the fiscal deficit for FY25 is estimated at 4.9% of GDP.

While presenting the interim budget for FY25 on February 1 this year, finance minister Nirmala Sitharaman revised the fiscal deficit estimate for previous financial year (FY24) from 5.9% of GDP to 5.8% and set a target of 5.1% for the current financial year. But, according to data released by the Controller General of Accounts (CGA) on May 31, India's fiscal deficit for 2023-24 came in at 5.63%, substantially below the revised estimate (RE) made in the budget on February 1. Besides, about ₹2 lakh crore dividend from the Reserve Bank of India (RBI) gave the government significant headroom to reduce fiscal deficit target despite raising capital expenditure.

DK Srivastava, chief policy adviser, EY India said the government has accelerated the process of fiscal consolidation. "An important implication is that GoI's gross and net market borrowings would be reduced in terms of magnitude which would now amount to ₹14.01 lakh crore and ₹11.63 lakh crore respectively in 2024-25. This turnaround will facilitate a reduction in policy interest rates and encourage private investment."

The discussion about doing away with a specific fiscal deficit target suggests that the government is thinking about implementing recommendations of the 2017 FRBM Review Committee report which was chaired by N K Singh. The report argued for "a move to public debt to GDP ratio as a medium-term anchor for fiscal policy in India".

The report had categorically recommended repealing the FRBM Act of 2003 and FRBM rules of 2004 and adopting "fiscal deficit as the key operational target consistent with achieving the medium-term debt ceiling".

FM SPEECH TAKEAWAYS

For the year 2024-25, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at ₹32.07 lakh crore and ₹48.21 lakh crore respectively.

The net tax receipts are estimated at ₹25.83 lakh crore.

The gross and net market borrowings through dated securities during 2024-25 are estimated at ₹14.01 lakh crore and ₹11.63 lakh crore respectively. Both will be less than that in 2023-24.

From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the Central Government debt will be on a declining path as percentage of GDP.



NIRMALA SITHARAMAN, Union finance minister

DEFENCE SERVICES OFFICERS INSTITUTE (DSOI)
H-Block, Palam Vihar, Gurgaon-122017

RENOVATION FACADING AT REZANGLA URC CANTEEN, C/O DSOI, PV, GURGAON

Renovation of FACADING work will be carried out a Rezangla, URC, C/o DSOI, PV, Gurgaon. The same can be inspected from 29 July 2024 to 08 Aug 2024. Tenders are invited in two Bid system (Technical & Commercial Bid) from experienced Firms to carry out the above works in Defence Services Officers Institute (DSOI), PV, Gurgaon 122017. Application Forms (RFP) indicating terms & conditions will be available at the DSOI Office on all days except Tuesdays between 1000 hrs to 1600 hrs on payment of Rs 1,000/- +GST from 29 Jul to 08 Aug 2024. Application form duly completed in all respect should reach DSOI Office by 10 Aug 2024 (5:00 PM). Pay Order/Demand Draft of Rs 50,000/- on account of Earnest Money Deposit for above work of any Scheduled Bank to be raised in favour of DSOI, Gurgaon

FOR ANY QUERY CONTACT- 0124-4554700 & 2365228

"मेरी सड़क" ऐप डाउनलोड कर, फीडबेक देकर राष्ट्र के विकास में सहयोग दें।

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY
(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
3rd Floor, Vikas Bhawan, Arera Hills, Bhopal (M.P.)
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)

No. 9158/22/D-12/SQC-Brg./24 Bhopal, Dated : 23.07.2024

SQC CONSULTANCY OF BRIDGES
(E-Procurement Notice)

Online Bids are invited through e-procurement portal **http://mptenders.gov.in** from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Bridge works being constructed on Rural Roads for the following packages :

- **No. of Packages - 02**
- **No. of Bridges - 21**

Total Estimated Construction Cost – Rs. 37,45,94,000/-

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in from 17:30 hrs. on 25.07.2024.**
2. Last date of Submission of bid is date **20.08.2024 upto 17.30 hrs.**

Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Bridge works June, 2021 on our Website **http://mptenders.gov.in**.

CHIEF GENERAL MANAGER
M.P. Madhyam/115506/2024 (TENDER)

GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
Navyug Market, Opp. Old Bus Stand Ghaziabad 201001, UP
E-mail:gzb.nagar.nigam@gmail.com
Website: www.ghaziabadnagarnigam.in

E-Tender

निविदा नोटिस संख्या:448 / स्वा0 / 2023–24 दिनांक: 23.07.2024

1	Name of the Bid	Selection of agency for procuring & recycling the collected and confiscated single Use mixed plastic material from GMC
2	Contract Period	01 YEAR
3	Earnest Money Deposit	Rs. 50,000.00 (Rupees Fifty thousand Only) to be paid on E-tender website i.e. https://etender.up.nic.in
4	Tender Fee	Rs. 5900/- including GST (Five Thousand Nine Hundred Rupees including GST) to be paid on E-tender website i.e.https://etender.up.nic.in
5	Bid System	Two Bid System (Technical & Financial)
6	Name of the Authority & Official	Municipal Commissioner Municipal Corporation Ghaziabad Gzb.nagar.nigam@gmail.com
7	Bid Validity Period	180 Days
8	Bid Language	English
9	Bid Currency	INR
10	**Key Dates**	
	Uploading of bid	25.07.2024
	Last Date of bid submission on e-portal	09.08.2024, 02:00 PM
	Date of Technical bid opening	09.08.2024, 04:00 PM

Municipal Commissioner
Municipal Corporation Ghaziabad

HT Education

SRM UNIVERSITY
DELHI-NCR, SONEPAT
NAAC ACCREDITED A+ GRADE

20+ Disciplines & 70+ Programs across UG, PG & Ph.D.

EARN UPTO 100%
MERIT BASED SCHOLARSHIP

APPLY NOW
SEATS FILLING FAST!

From Average to EXTRA Ordinary:
Transform your career with a
MANAGEMENT DEGREE

- M.B.A.
- B.B.A.
- B.B.A.
With specialization in Business Analytics (in association with IBM)

HIGHLIGHTS:
- Dual Specialisation
- Exposure to foreign languages
- Financial Modelling with latest Technologies (Artificial Intelligence/ Blockchain/ PowerBI)
- Semester Exchange: Collaboration with 50+ International universities

GATEWAY TO SRM SONEPAT
APPLY NOW

Scores accepted: SRMHCAT | CUET | CAT | MAT | UGAT | NMAT



University Address:
39, Rajiv Gandhi Education City,
Delhi-NCR, Sonepat, Haryana

Delhi Admission Office:
79+80, 1st Floor, Pocket D12, Sector 8,
Next to Rohini East Metro Station, New Delhi

Email: admissions@srmuniversity.ac.in
Website: www.srmuniversity.ac.in

ADMISSION HELPLINE
+91 95417 79883 / 88160 33301 / 02 / 03 / 04 / 05

CHAT ON WHATSAPP
88160 33306

SRM/rapidexadvertising/0724

Sushant University
soaring high
Golf Course Road, Gurugram, NCR Delhi

- UGC Recognized
- Approved by COA | BCI | PCI | ITPI, Govt. of Haryana etc.
- Industry Collaboration with upGrad / Samatrix.io / ImaginXP / ICRI and many more...
- Strong International Collaborations over many Foreign Universities of USA, UK, Italy, France etc.

ADMISSIONS OPEN 2024-25

CUET/JEE/NEET/CLAT/ NATA
Based Scholarship upto 100%

School of Art and Architecture
B.Arch. | B.F.A. | M.Arch. | M.Plan

School of Design
B.Des. | M.Des.

School of Engineering & Technology
B.Tech (Hons.) - CSE & CE | BCA (Hons.)
M.Tech - CSE | CE | MCA

Vatel Hotel & Tourism Business School
BHM | Diploma in Culinary Arts

School of Business
BBA (Hons.) | B.Com. (Hons.)
MBA - (Dual Specialization) with International Immersion & Industry Connect

School of Health Sciences
B.Pharm. | B.Optom. | B.Sc. CVT | Psychology | Clinical Research | MLT | MRIT | M.Optom. | M.Sc. Clinical Research

School of Law
BA LL.B. (Hons.) | BBA LL.B. (Hons.) LL.B. (Hons.) | LL.M.

Ph.D. & Research in all Schools

Lateral Entry in All Programmes

ASU Arizona State University | Berkeley University of California | Domus Academy Milan | The University of Adelaide | Arts University Bournemouth | Vatel Hotel & Tourism Business School

Call: 8448221265 | 9650087257
Toll Free: 1800-2705-520
www.sushantuniversity.edu.in
admissions@sushantuniversity.edu.in
Scan to Apply



Top Reasons to Join SU
- Faculty from prestigious institutions like IIM, IIT, BITS, NLU, AIIMS etc.
- Top Awards, Rankings & International Collaborations.
- Global Alumni Network & 100% placement assistance.
- Industry focused contemporary curricula with multiple specializations.
- Soft skills training spread across all semesters by Industry Trainers.
- Hands on Industrial training and certifications.
- 5 Minutes walking distance from Rapid Metro Station.

- One text book allowed in Exam.
- Give Exam in Hindi or English.



26.5 LPA
Ms. Oorja Ganga Singh
B.Tech. - Zscaler

70% Placement to all Eligible Students. Average Package 6 LPA

Admission / Counseling available on all 7 days of the week

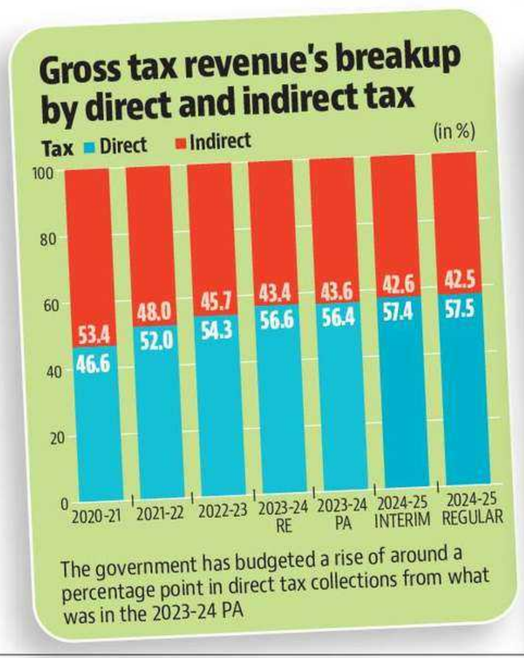
HAVE FUN
WITH FACTS ON SUNDAYS

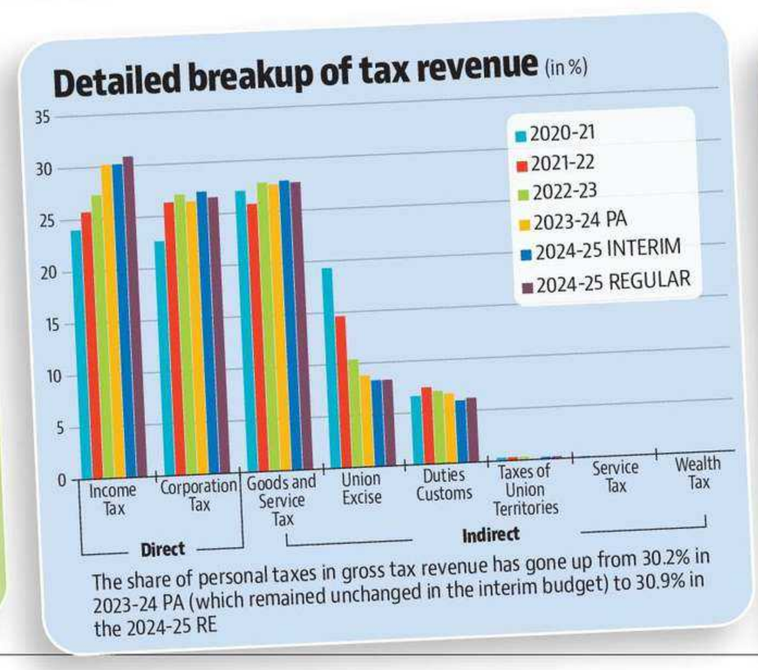
Catch the latest column of
HT TWTW
THE WEEK THAT WAS
A quiz on the week's development.

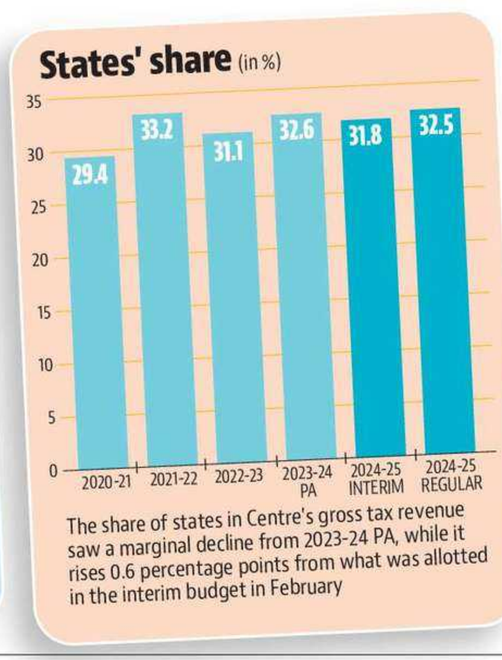


HOW THE TAX BURDEN HAS CHANGED

Tax-GDP ratio is budgeted at 11.8% this year, the highest since 2007-08. This will be driven by direct taxes, whose share is estimated to increase in gross tax revenue. Since direct taxes increase with income, GTR will be more progressive than in recent years. However, it is the personal rather than corporate taxes that will drive this progressive turn.







Customs duties cut, more rate tweaks soon: Nirmala

Rajeev Jayaswal
letters@hindustantimes.com


The reduction in levy covered a range of products from medicines to rare earth minerals. SHUTTERSTOCK

NEW DELHI: The budget on Tuesday tweaked customs duties on several items to provide relief to people, boost domestic manufacturing and promote export competitiveness covering a range of products such as life-saving medicines, rare earth minerals and precious metals, including gold and silver.

Speaking about duty rationalisation, Union finance minister Nirmala Sitharaman said she would also undertake "a comprehensive review" of the rate structure over the next six months to rationalise and simplify them for ease of trade, removal of duty inversion and reduction of disputes.

She exempted cancer medicines such as Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab from import duty and reduced basic customs levies on x-ray tubes and flat panel detectors for use in medical x-ray machines. The duty reduction of medical equipment was undertaken under the phased manufacturing programme, so as to synchronise them with domestic capacity addition, she said.

The move removed duties on all types of polyethylene for use in manufacture of orthopaedic implants and special grade stainless steel, titanium alloys, cobalt-chrome alloys, and for use in manufacture of other artificial parts of the body.

In order to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, she reduced basic customs duties on their inputs. "My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation, while keeping the interest of the general public and consumers surmount," she said.

The minister announced reductions in customs duties on precious metals, including gold, silver and platinum to boost gem and jewellery industry, a labour-intensive sector. While levy on gold and silver was reduced from 15% to 6%, it was brought down from 15.4% to 6.4% on platinum.

Speaking about a steep reduction in customs duty on gold, revenue secretary Sanjay Malhotra said the decision is mainly aimed at boosting India's gem and jewellery industry. "The sector is very important for us as it contributes approximately over 8% of our total exports and employs approximately 55 lakh people. We have reduced import duty [on gold and other precious metals] keeping this in mind," he said. The reduction in duty may also curb gold smuggling.

The budget also slashed the levy on mobile phones. The last six years have seen a three-fold increase in domestic production of mobile phones and almost a hundred-fold jump in exports of mobile phones.

She also announced full exemption of customs duties on 25 critical minerals and reduced the levy on two of them. This will benefit sectors like space, defence, telecommunications, high-tech electronics, nuclear energy and renewable energy, where these minerals are critical, she said.

The 25 minerals are Antimony, Beryllium, Bismuth, Cobalt, Copper, Gallium, Germanium, Hafnium, Indium, Lithium, Molybdenum, Niobium, Nickel, Potash, REE, Rhenium, Strontium, Tantalum, Tellurium, Tin, Tungsten, Vanadium, Zirconium, Selenium, Cadmium, Silicon other than Quartz and Silicon Dioxide. Earlier, they attracted customs duty ranging from 2.5% to 10%.

Duty on agricultural products such as shea nuts has been reduced from 30% to 15%, prawn and shrimp feed and fish feed from 15% to 5%. The inputs required for manufacture of prawn and shrimp feed or fish feed such as mineral and vitamin pre-mixes have been exempted from the levy.

The levy on capital goods for use in petroleum exploration operations is exempted from tax. Capital goods used in manufacture of solar cells and modules reduced from 7.5% to zero.

The budget raised customs duty on ammonium nitrate from 7.5% to 10%, PVC flex films/flex banners from 10% to 25% and laboratory chemicals from 10% to 15% to check dumping and encourage domestic manufacturing.

Duties have been raised on solar glass for manufacture of solar cells or modules from zero to 10% with effect from October 1, 2024. Similarly, tinned copper interconnect for manufacture of solar cells or modules would attract a 5% duty from October 1.

"Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar glass and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of customs duties provided to them," the minister said.

Tushar Aggarwal, co-founder, Tattvam Group, said: "This exemption on specified capital goods used in the manufacturing of solar panels and solar cells marks a pivotal step towards bolstering India's renewable energy sector... By exempting specified capital goods from customs duty, the government has taken a crucial step towards incentivising domestic production, which will significantly reduce our industries' dependency on imports of solar panels and cells."

"The customs duty rate changes proposed in the Union Budget 2024 are designed to boost exports, enhance local value addition and domestic manufacturing, encouraging growth and sustainability," said Ranjeet Kumar Agarwal, president of ICAI.

MSMEs get special attention in budget

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com



NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman announced a revival package for the MSME sector that will include enhanced Mudra loans of up to ₹20 lakh, a collateral-free credit guarantee scheme to help purchase machinery and equipment, and a new assessment model to help unlisted enterprises access bank credit, among other measures.

Sitharaman announced that the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the TReDS platform will be reduced from ₹500 crore to ₹250 crore to help MSMEs finance trade receivables. She declared a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during stress. "Turning attention to the full year and beyond, in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class," the finance minister announced.

The MSME sector is the largest employer after agriculture in India and has 35% share in India's manufacturing output.

Sitharaman announced that the budget provides "special attention to MSMEs and manufacturing" and said, "We have formulated a package covering financing, regulatory changes and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally."

"For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide, to each applicant, guarantee cover up to ₹100 crore, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on reducing loan balance," she said.

On the new mechanism to help MSMEs get credit during stress, she said, "While being in the 'special mention account' (SMA) stage for reasons beyond their control, MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee from a government-promoted fund."

The budget provided for a 100% hike in Mudra loans, one of the popular avenues to get collateral-free credit for small entrepreneurs. "The limit of Mudra loans will be enhanced to ₹20 lakh from the current ₹10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the 'Tarun' category," Sitharaman announced.

A new credit assessment model has also been envisaged in the budget that aims to remove one of the key stumbling blocks for the sector. "Public sector banks will build their in-house capability to assess MSMEs for credit, instead of relying on external assessment," the finance minister announced.

She also announced more SIDBI branches in MSME clusters to serve all major clusters within 3 years, and provide direct credit to them. "With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters," Sitharaman added.

The budget also earmarked financial support to set up 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector and the government will facilitate setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation.

Tamal Sarkar, senior adviser to the Foundation for MSME Clusters, said, "This budget has given a lot of weightage in terms of developmental issues like a technology upgrade fund, investment-grade energy audit, special promotion of food processing clusters and the overall promotion of MSMEs through clusters by SIDBI, which had several decades of experience in cluster-based promotion of MSMEs."

He added that "the new credit assessment tool that will give high weightage to digital footprint may take into account carbon footprint too and give special support to carbon-neutral and carbon-negative investment."

With digital crop survey, govt to expand DPI to agri

Aditi Agrawal
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced that the government will use digital public infrastructure (DPI) to conduct a digital crop survey (DCS) in 400 districts for the kharif season this year.

A DCS creates "one verified source of truth" about a farmer and his crops, which can be used by multiple departments and stakeholders (such as insurance companies and banks). It involves creating a registry of geo-fenced plots that includes details about the owners, details about which crop is sown and when, what is the expected and actual yield, etc.

The use of DPI for agriculture is not new — the pilot DCS was conducted in 12 states for the 2023 kharif season, then agriculture minister Narendra Singh Tomar informed Lok Sabha in August 2023.

"Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with states, will facilitate the implementation of DPI in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, DCS for kharif using DPI will be taken up in 400 districts. The details of 60 million farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth-based Kisan Credit Cards will be enabled in five states," Sitharaman said.

States such as Tamil Nadu and Karnataka have created their own websites and apps for DCSs. Madhya Pradesh CM Mohan Yadav in June had announced a DCS for this kharif season.

Sitharaman said that DPIs also are planned in areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME, services delivery, and urban governance. She proposed the development of DPI applications at "population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector".

To be sure, digital payments infrastructure such as UPI and e-commerce protocols like Open Network for Digital Commerce are considered DPI and/or digital public goods by the government and have already been implemented.

Phones, peripherals set to get cheaper after customs duty cut

Aditi Agrawal
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced a slew of measures to strengthen India's electronics industry, including reduced basic customs duty on mobile phones, mobile printed circuit board assembly (PCBA) and mobile chargers from 20% to 15%, and increased duty on PCBAs of some telecom equipment from 10% to 15%.

The budget also proposed to exempt 25 critical minerals and rare earth elements from custom duties and reduced basic duty on two of them to secure their availability for strategic sectors such as telecommunications, electronics, energy, space, defence, renewable energy and nuclear energy.

"With a threefold increase in domestic production and almost 100-fold jump in exports of mobile phones over the last six years, the Indian mobile phone industry has matured," Sitharaman said in her budget speech in Parliament.

To boost value addition in the domestic electronics industry, the government also proposed reduced BCD on oxygen-free copper used to manufacture resistors from 5% to nil, and BCD on specified goods for use in manufacture of connectors from 5% or 7.5% to zero.

The India Cellular and Electronics Association welcomed the announcements. "It will further embolden the industry and its competitiveness," chairperson Pankaj Mohindroo said.

myverdict



{ BHAVIK KHERA } CONVENER, CII GUJARAT MSME PANEL

EXPECTATIONS
The 2024 Budget must prioritise MSME growth. We expect investment in workforce upskilling, especially in AI and data analytics. Continued support for ECLGS and PCGS is crucial, with streamlined credit access. We need simplified regulations, uniform GST registration, and funding for digital transformation...Infrastructure investments in logistics and tech integration are vital. The budget should create an ecosystem for MSMEs to upskill, innovate, and scale efficiently, boosting economic growth and job creation.

OUTCOME
MSMEs, crucial for economic growth and employment, received insufficient attention. There were no significant initiatives aimed at enhancing MSME export competitiveness or addressing their unique challenges. The budget's emphasis was more on broad economic areas and large sectors, rather than providing targeted support for MSMEs to increase their export potential. This is possibly something which may pan out with a detailed review of the Budget as MSMEs play a vital role in driving innovation and employment. While there were tax reforms and incentives to boost investment... there was insufficient focus on measures specifically designed to support MSMEs.

Ending angel tax, reducing unlisted LTCG tax hailed

mint

Ranjani Raghavan
letters@hindustantimes.com

MUMBAI: Amid a funding winter, venture capital and private equity investors have secured two long-standing demands from the Union Budget: the abolition of angel tax and the reduction of long-term capital gains tax for unlisted securities.

The measures are expected to boost domestic capital investment in the Indian startup ecosystem, said investors.

Dismantling the entire angel tax provision is a bold move, said Gopal Srinivasan, founder and managing partner, TVS Capital. Tuesday is "a red letter day" also because of the new tax slab for long-term capital gains that brings parity between public and private investors, he added.

The erstwhile angel tax under section 56(2)(viib) of the Income Tax Act applied to unlisted companies on issuing securities to investors at a premium to their fair market value. The difference was considered as "income" for the company and subject to tax.

"The removal of angel tax sans conditions must be celebrated as a major win," said Siddarth Pai, co-founder of venture capital firm 3one4 Capital.

Finance minister Nirmala Sitharaman's decision to abolish angel tax won't be applied retrospectively: it comes into effect from April 1, 2024.

For long, private Indian investors have been paying a 20% tax on long-term capital gains in unlisted securities. For the same securities, foreign investors paid 10% tax on long-term gains. Public market investors were also paying a 10% tax. Now, all asset classes will be taxed at 12.5% for long-term captial gains. "Aligning the tax rates will result in more funding into Indian startups," Pai said.

However, investors won't be motivated by tax for their asset purchases, said Subramaniam Krishnan, partner, EY. "They will look at the asset class based on their risk-return profile and make investment decisions. However, foreign investors will pay marginally more tax on long-term capital gains (albeit on foreign currency gains where applicable). There is now almost total parity between residents and non-residents on long-term capital gains tax rates."

This move to even-out the disparity in long-term capital gains tax will inevitably boost the PE-VC industry, which currently stands at ₹2.5 trillion, only a "tenth of the Indian equity mutual fund pool," said TVS Capital's Srinivasan.

The budget also introduced the concept of variable capital company (VCCs) at the Indian Financial System Code IFSC-Gift City, which could promote the ease of doing business. "Trusts were not conceived for the complex operations of VC/PE funds and the VCC structure will make GIFT IFSC even more attractive," Pai said.

{ INTERVIEW } NIRMALA SITHARAMAN

'Our aim is to give more opportunities to talented Indian youth within the country'

The basic custom duty reduction or elimination of duties announced in the budget will help Indian labour-intensive manufacturing industries export more, finance minister Nirmala Sitharaman said in an interview with Doordarshan. That, in turn, will create more job opportunities. "That is the primary and only reason why this custom duty reduction has been done." **Edited excerpts:**

This budget is big on employment generation. What was the thinking behind it?

Today, the youth of India is working in important positions in industries across the world. Global companies are looking purely at talent and hence prefer the youth of India. But the opportunities they should get within India are not at the level they should be. That is why we have launched five schemes with a corpus of ₹2 lakh crore to be spent over the next five years. It will benefit 4.1 crore (41 million) youth. This includes first-time employees, as also those who shift jobs. The employers also get benefitted from it so they are encouraged to hire more and also to retain them for at least two years. For skilling, there is a lack of wherewithal and machinery in ITIs (Industrial Training Institutes) across the country which are managed by the states. There has not been that much investment here in the last 20-30 years, but right now there is a demand for skilling and for ITIs to be ready for Industry 4.0, so the money will go towards that. On top of this 1 crore (10 million) youth will benefit from the internship scheme and we will be talking with 500 top companies.

You have given a provision of ₹1.52 lakh crore for the agriculture sector and ₹2.66 lakh crore for rural development. How does this meet the goal of making agriculture an engine of growth?

There's one thing I want to dispel. When we talk about these numbers, people don't realise that there are multiple schemes that are ongoing for which provisions have already been made. We need to reach the farmers with such inputs which are worthy for them to toil in the soil. Farmers need high-quality seeds. I have spoken about 109 varieties of climate-resilient seeds, which we will soon take to the farmers. We are looking at giving input support to the farmers, and more than 50% of their input cost should be met by the amounts we give them.

Rural development is not just building homes or new roads. Over and above this, we are looking at hard infrastructure in rural areas, be it power and smart meters in villages.

You have said women-led development will see an allocation of over ₹3 lakh crore. How will this money be spent?

We have been emphasising on how more women being a part of productive activities has to be continued. Women's participation in the workforce has been highlighted in the Economic Survey. We have come a long way since "beti bachao, beti padhao andolan". We have emphasised on land and property registration in the name of women in this budget.

You have not talked much about existing schemes like MGNREGA (Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme), etc. Can you clarify that these will continue?

Absolutely. Today my speech lasted... nearly one-and-a-half hours. How much can I cover in this time? A lot of people also said I haven't talked about many states. But that does not mean that money will not flow to those states. Every scheme is being implemented—central as well as centrally sponsored schemes, and besides that projects from the World Bank and ADB (Asian Development Bank), etc. For example, the country's largest port worth ₹76,000 crore is coming up in Vadhavan in Maharashtra. It wasn't mentioned in the last speech or this speech, but it is happening. So, I wish to dispel this doubt that schemes like MGNREGA or some other scheme like PM Swanidhi scheme or Mudra; such schemes will always continue. Just because they don't find mention in the speech doesn't mean they are being discontinued.

You have mentioned new airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar, and there's plenty of allocation for Andhra Pradesh in the Budget. Are there some special messages that you're sending out here?

No. First of all, the Andhra Pradesh Reorganisation Act required all this to be done anyway. In the first 10 years after the AP Reorganisation Act came into being, the two states were bifurcated; we have been giving money for the backward district programme, with institutions such as AIIMS (All India Institute Of Medical Sciences) and IIT (Indian Institute of Technology) which have been taken. There are certain projects which are getting staggered. Polavaram is one of the biggest national irrigation projects, with the dam storage capacity being immense. Godavari waters are being kept there and from there it is going into the fields. This is a national project. We will certainly support it, and that is what I have emphasized. Similarly, there is backward region development in Andhra Pradesh, such as Rayalaseema and north coastal Andhra Pradesh. We are only definitely assuring the newly elected government in Andhra Pradesh that we will stand by them.

How will these e-commerce hubs that are being set up in public private partnership work? You also talked about this plug-and-play industrial parks in 100 cities. Could you expand on them?

On the e-commerce and MSME (micro, small and medium enterprise) front, look at the example of what ONDC, or the Open Network for Digital Commerce, is doing. It's actually given at the cost of the government, meaning they don't have to pay any charge. It gives access to MSMEs to reach the global market. ONDC has proven to be a very, very powerful catalyst. Now, when you form e-commerce hubs, you're making sure that because of these digital assets that we have, MSMEs in particular can benefit from them. It's somewhat like creating a special economic zone but you're creating it in the digital world, so that these MSME can be onboarded, either by sector or by some kind of a common denominator, and we will be able to give them access to the overseas market. That is a facility which the government will spend on so that MSMEs don't have to invest in them, and we give them the access for it.

The plug-and-play concept for industrial parks is that big investments for creating such hubs don't come easily. We want the industry also to participate with us. So when you set up a hub in one place, this becomes the mother centre, and smaller centres can benefit by attaching themselves like a spoke to the hub.

You have talked about reviewing the Income Tax Act, 1961, in the next six months. Are we moving towards a direct tax code?

Absolutely. We are consistently moving towards simplifying the tax structure. As it is we moved away from the old tax regime and created a new tax regime to facilitate those who do not need exemptions. They can opt for the new tax regime where the tax is also low. After the launch of the new regime, people said at least give us standard deduction, so we gave ₹50,000 and now we have raised it to ₹75,000 so that there is more money in the hands of the people. We have also further simplified the rates and even reduced it, so that the middle class get some relief in income tax and they think that we have done something to put more money in their hands. When we talk of reviewing the Income Tax Act, the intention is to simplify the structure. I have given one example of old and new tax regimes, but there are other things too that need to be simplified. We will keep working on that so that the Income Tax Act which is such a bulky book today becomes a simple form that is easy to fill and follow. And just like we have introduced pre-filled forms, we will continue to use technology and keep lowering the rates to give relief to people.



The changes that you've announced for customs duties... to what extent do they keep us away from the China conundrum?

First of all, if you look at the selection of items for which I have given a basic customs duty reduction or elimination of duties, they are the essential inputs for labour-intensive manufacturing industries. So these are the gems and jewellery, gold or raw diamonds, leather-related, shrimp-related and textile sectors. These are sectors where you have intensive labour employed. When you bring raw material for cheap, their expansion plans, their plans to export whatever they produce, will all go through a positive change. Because of that, employment will also improve. That is the primary and only reason why this custom duty reduction has been done.

On overall tax proposals, you talk about a revenue foregone of about ₹7,000 crore. So is this a shortfall?

The way in which we have decided to spend money in building capacities, in making sure there are more efficiencies or productivity increase, and making sure youth trained properly to get into good quality jobs, all this will generate economic activity which will give me that comfort to make up for that revenue foregone. We can hope, because of the ways in which we are bringing in factors for productivity gains will help us. Other than that, of course, we also make sure that the tax net is widened, through non-tax revenues in rural and urban areas. So I mentioned about land-related reforms, labour-related reforms, capital-related reforms and entrepreneurship, of course through MSMEs and training, which is happening. So, for land, what kind of reforms, digitisation can we bring in? We are making sure that land records are maintained digitally, stamp duty reduction happens for which we are working with the states. Similarly, for labour reforms, we have exhaustively mentioned in the budget speech.

You have spoken about first-time employees getting into the formal sector. Could you elaborate on this?

I have mentioned this as Scheme A in my speech; when a fresh first-time employee is recruited by somebody for a salary up to ₹1 lakh, the government will give ₹15,000 as one-month wage, which will be spread across three instalments. The employer also receives this because he will register him as an EPFO (Employees Provident Fund Organisation) employee. Both employer and employee will benefit through this incentive, in this case involving a first-time employee. The second scheme looks at first-time employees and for anyone else who gets a job; we will give allowances to both employer and employee. However in this scheme, if the employer doesn't retain him for two years and removes him before that, every incentive given to the employer will have to be refunded or paid back.

We are making sure that under each scheme, there are more and more new people coming in and fresh appointments happen. Companies will be incentivised to grow. Suppose you are already running a company with 100 people, you can scale up. Besides these two, there is ITI and the fourth one is the internship. We intend to seriously implement each of them.

You talked about developing a taxonomy for climate finance and enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. What is this taxonomy?

Taxonomy is when you start classifying and is an expression used for various other things which are developing. So, in climate-related matters, how do you tax certain things? Taxonomy is what kind of items come into certain kinds of green energy and what is counted as green. How do you calculate the emission count, and on the basis of that, how do you bring the carbon market to efficiently function? Those are not clear yet for India itself. So, we need to have enough work done through, let's say, domain experts to understand what is the classification we need. Going forward, for instance, carbon trading will depend on what kind of classifications we make.

What was the thinking behind raising capital gains tax? Are you worried about futures and options trading in the country?

I want to clarify that our intention was not to generate more revenue by increasing capital gains tax. We assessed all the use cases of indexation across asset classes and found that nobody got less than 13.5% (of tax incidence) anywhere. So, we kept it at 12.5% so nobody gets taxed more without indexation. The intention was to simplify taxation and increase convenience for the assessee. There should be no confusion over this. If the intention were to raise revenue, I would have put the rate even higher.

Our intention was not to generate more revenue by increasing capital gains tax. We assessed all the use cases of indexation and found that nobody got less than 13.5% anywhere. Out intention was to simplify taxation and increase convenience for the assessee. There should be no confusion over this. If the intention was to raise revenue, I would have put the rate even higher.

{ BUDGET SPEECH }

Word cloud highlights govt's focus



{ MODI CALLS BUDGET VISIONARY } 'WILL LAY SOLID FOUNDATION FOR DEVELOPED INDIA'

Budget will make us No. 3 economy: PM

Smriti Kak Ramachandran
letters@hindustantimes.com

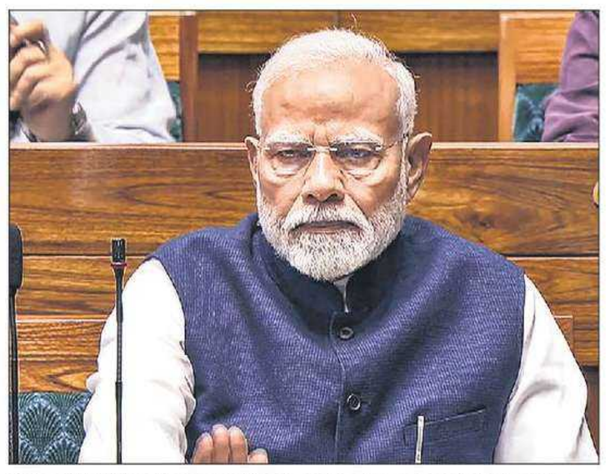
NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi on Tuesday said the Union Budget brought "new opportunities and new energy" and will act as a "catalyst" in the process of making India the third largest economic power in the world.

"Today's budget has brought new opportunities, new energy, new employment and self-employment opportunities. It has brought better growth and a bright future... it will act as a catalyst in making India the third largest economic power in the world and will lay a solid foundation for a developed India," he said.

In a televised address soon after the budget was presented by Union finance minister Nirmala Sitharaman, the PM said the budgetary provisions will lay a solid foundation for a developed India. "I congratulate all my countrymen on this landmark budget, poised to propel our nation to unprecedented heights of progress," Modi said, adding that the "visionary budget will uplift and empower every stratum of society, paving way for a brighter future for all."

Hailing the economic policies of the government over the last decade, he said, "Over the last 10 years, 25 crore individuals have come out of poverty. Building on this momentum, this budget will further energise the aspirations of our neo-middle class. Our young generation will have unprecedented opportunities. Education and skills development will achieve a new scale, fuelling our nation's growth. This budget will empower the middle class like never before."

Budget provisions, he said, will drive economic growth and empower the poor and the marginalised. "We will create entrepreneurs in every city, every village and every home... For this purpose, the limit of Mudra loans without guarantee has been increased from ₹10 lakh to ₹20 lakh. This will boost self-employment among small businessmen, especially women, Dalit, backward and tribal families," he said.



Prime Minister Narendra Modi during the presentation of the Union Budget in Lok Sabha on Tuesday. PTI

"The Union Budget gives a fillip to manufacturing as well as infrastructure," Modi said.

He referred to the success of the PLI scheme and highlighted the Employment Linked Incentive scheme, which he said will create millions of jobs.

"Under the scheme, the first salary of the first job of a youth will be borne by the government. Working in top companies under the scheme, the young interns will find new avenues of possibilities," he said.

The budget presents opportunities for India's start-up and innovation ecosystem, he said.

He said this year's budget consists of numerous provisions to create an aatmanirbhar (self-reliant) defence sector. He said government policies in the last decade ensured tax relief for the poor and the middle class, while decisions were made in this year's budget to reduce income tax, hike standard deduction and simplify TDS rules.

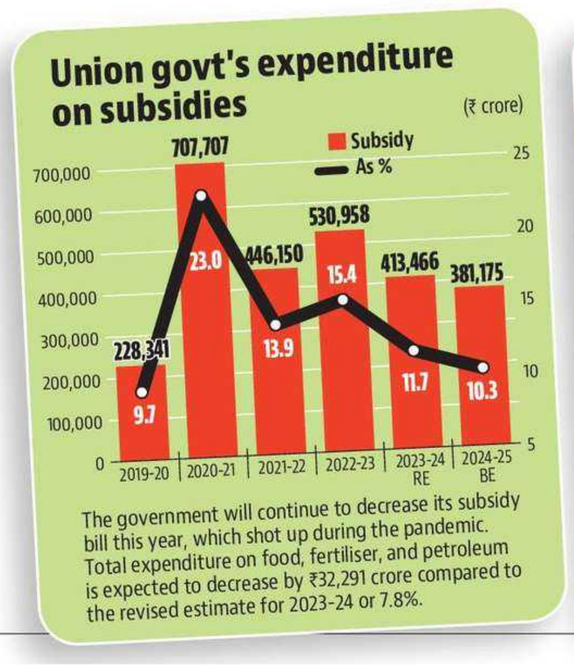
"A big focus of this budget is the nation's farmers. After the world's biggest grain storage scheme, now vegetable production clusters are being introduced, which will help both the farmers and the middle class," he said.

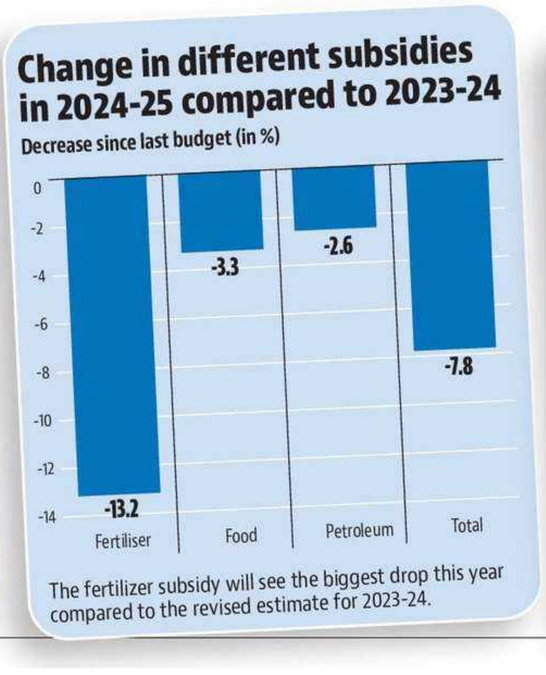
The PM also referred to the nearly 30 million houses for the poor as well as the Janjatiya Unnat Gram Abhiyan that will link 50 million tribal families to basic facilities.

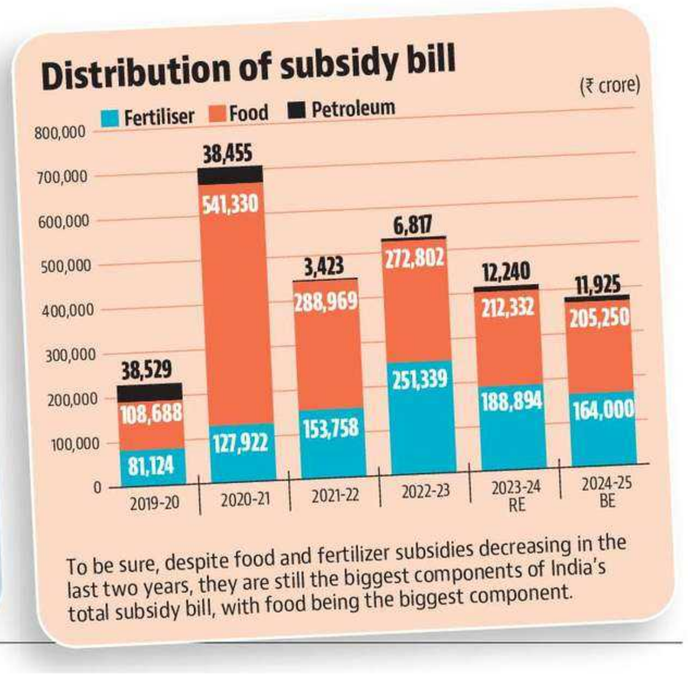
UNION BUDGET UB 2024-25

A CONTRACTING SUBSIDY BILL

Revenue expenditure of the government (less interest payments) is expected to increase by 2.5% this year compared to the 2023-24 RE, much slower than government's overall expenditure growth of 7.4%. The slower growth in revenue expenditure is partly because of a contracting subsidy bill. The government intends to do this mainly by decreasing the fertilizer subsidy this year.







Crop productivity, climate resilience in focus

Zia Haq
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Union government will ramp up farm research to boost productivity and ability of crops to withstand climate challenges that have upended the country's food supplies, Union finance minister Nirmala Sitharaman said while unveiling the budget, her seventh in a row.

Identifying agriculture as one among nine top priorities, Sitharaman said there would be a "comprehensive review of the agriculture research set-up" to raise productivity and develop "climate-resilient varieties".

The government was allocating ₹1.52 lakh crore for agriculture and allied sectors, she said. For agriculture alone, the budget has provisioned ₹1.32 lakh crore, up from the interim budget's allocation ₹1.27 lakh crore.

However, the capital expenditure allocation for the department of farm research stood at ₹6.5 crore out of a total of ₹9,941 crore, which means the bulk of the outlay will go towards revenue expenditure. The revised estimates for 2023-24 showed the government had spent ₹9.96 crore as capex for the farm research department.

While it spent ₹40 crore on climate-resilient agriculture initiative in 2022-23, there has been no allocation for it since 2023-24. Sitharaman, however, said funding will be provided to bolster agricultural research. "Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector," she said. "Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research."

The government will introduce 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops, Sitharaman said. Among major schemes, the budget allocated ₹60,000 crore for the PM-Kisan, a cash-transfer scheme, the same as revised estimates in the previous financial year.

In the past five years, agriculture has grown at an average 4.18%, but during 2023-24, it expanded just 1.4% on the back of a poor monsoon. The farm sector employs nearly half the population but is marked by low productivity levels, fragmented landholdings and inadequate marketing infrastructure, the Economic Survey 2024 said on Monday.


Union finance minister Nirmala Sitharaman said the government will introduce 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticulture crops. PTI FILE

The government also plans to set up clusters of vegetable farms around large cities to boost supplies and enhance market access. Efforts are on to raise the output and marketing of pulses and oilseeds for self-sufficiency, she said.

The budget proposal to link digitised land records with farmers' database on an agri stack will help farmers get loans in a matter of hours, agriculture minister Shivraj Singh Chouhan commented. "To increase productivity as well as to reduce input costs, minimum support prices are being continuously increased," Chouhan said.

The budget had ignored the demand of cultivators for guaranteed prices, farm organisations said. "While farmers have been asking for a legally guaranteed price support, with C2 as the cost component to calculate 50% margin over cost of cultivation, nothing has been provided for this by the government," Kiran Vissa of the Alliance for Sustainable and Holistic Agriculture. C2 is a broader measure of agricultural costs incurred by farmers than the one used by the government.

The government is also pushing farmers towards more chemical-free agriculture for which allocation for the National Mission on Natural Farming for 2023-24 (budget estimates) was ₹459 crore. The revised estimate for the year came to ₹100 crore, pointing to low utilisation of funds.

Given that spending on natural farming was low, the budget has allocated ₹365 crore for natural farming for 2024-25. "In the next two years, one crore farmers will be initiated into natural farming," Sitharaman said.

New announcements in the budget included Jan Samarth-based Kisan Credit Card in five states, assured financing for shrimp farming and exports as well as for setting up a network of nucleus breeding centres for shrimp.

The government will introduce a national cooperation policy to boost the rural economy, Sitharaman said. The Centre will also push digital public infrastructure for agriculture in partnership with states.

The details of 60 million farmers and their land records will be entered into an agri stack database over the next three years, the minister said. Digital technologies for crop estimations will be undertaken in 400 districts from the current summer season.

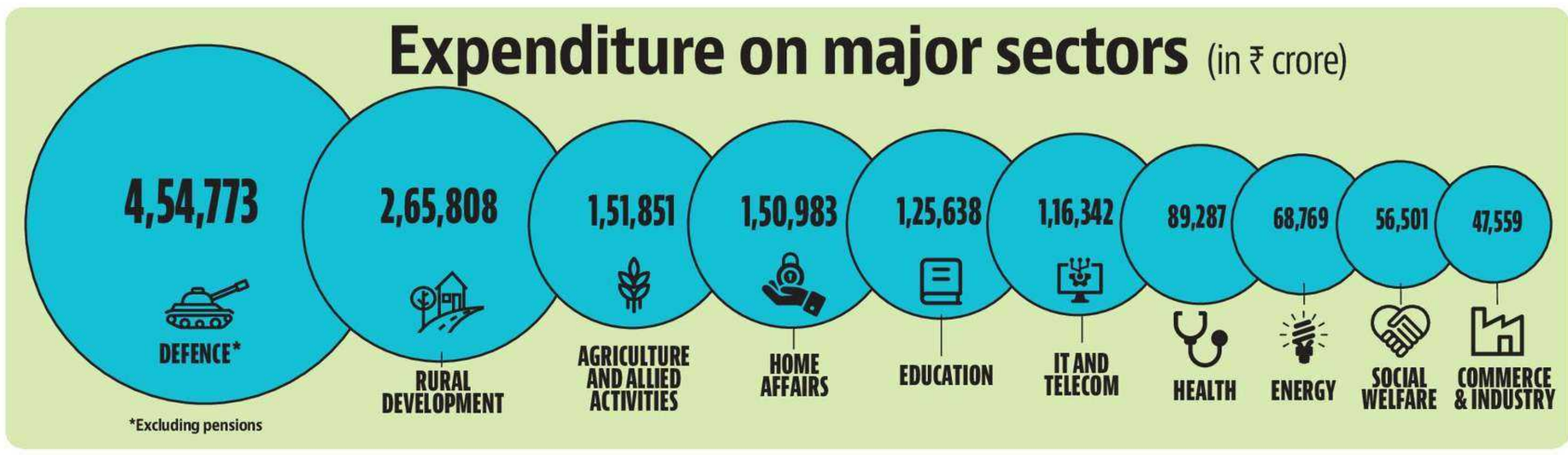
While agriculture tends to swing from one problem to the other, India's 140 million farmers are increasingly battling extreme weather said to be linked to climate change.

Heatwaves shriveled wheat crops in the world's second-largest grower in 2022 and 2023, stoking food prices. In June, food prices rose a sharp 9.6%, official data show.

A landmark study by Indian Council for Research on International Economic Relations in 2018 found that every ₹10 lakh invested in farm research potentially pulled 328 people out of poverty, while only 26 people were helped by the same amount spent on subsidies. Likewise, every ₹1 spent on agricultural research increased farm GDP by ₹11.2, the study showed.

The budget kept the fertiliser subsidy at ₹1.64 lakh crore, the same as proposed in the interim budget and lower than the ₹1.88 lakh crore in 2023-24 (revised estimate).

Food subsidy has been set at ₹2.05 lakh crore, the same as in the interim budget, but lower from the revised estimates of ₹2.12 lakh crore during the last financial year.



₹10L-cr set aside to boost urban housing scheme

Soumya Chatterjee
letters@hindustantimes.com

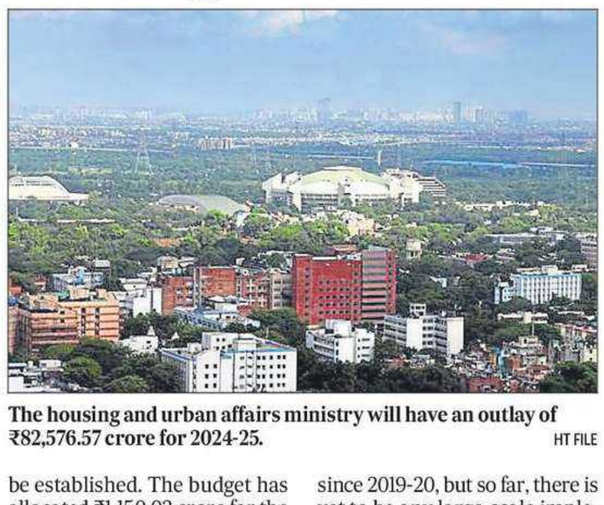
NEW DELHI: Urban development is one of the nine priorities through which the government will help develop cities as growth hubs, finance minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday as she announced a clutch of measures that included a transit-oriented development framework for 14 large Indian cities, dormitory rental housing for industrial workers, brownfield redevelopment of 100 large cities and 10 million new houses for the urban poor.

Her seventh budget proposed an investment of ₹10 lakh crore to push 10 million affordable urban housing units under the Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0, including ₹2.2 lakh crore central funding, in the next five years.

Sitharaman said, "Under the PM Awas Yojana-Urban 2.0, the housing needs of one crore poor and middle-class families will be addressed with an investment of ₹10 lakh crore. This will include the central assistance of ₹2.2 lakh crore in the next five years."

In all, the ministry of housing and urban affairs will have an outlay of ₹82,576.57 crore for 2024-25, compared to ₹69,270.72 crore in the year ended March, marking an increase of 19.2%.

In a related announcement, the finance minister said land records in urban areas will be digitised with GIS mapping. An IT-based property record administration, updating and tax administration system will also be established. The budget has allocated ₹1,150.02 crore for the national urban digital mission. The allocation to central government schemes, including programmes such as PMAY(Urban) and Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation, has been increased to ₹29,961.30 crore from ₹27,074 crore earlier.


The housing and urban affairs ministry will have an outlay of ₹82,576.57 crore for 2024-25. HT FILE

The transit-oriented development plans – an integration of land-use plans with transportation planning to reduce commutes by building mixed-use neighbourhoods near transit hubs – will be prepared for 14 of the largest cities with a population of over three million, she said. This policy is likely because Indian cities already have 905km of Metro networks and construction of another 900km is underway.

This framework as an urban planning concept has been mentioned in five budget speeches since 2019-20, but so far, there is yet to be any large-scale implementation, said Rutul Joshi, senior associate professor at CEPT University in Gujarat. "TOD policies are often not integrated with the master plans, urban local bodies may not have funds to kick-start such projects, and this budget does not give any specific allocation for the same," he said, pointing to the example of the state-led Karkardooma TOD project in Delhi worth ₹1,200 crore that is yet to be completed after 12 years.

The Union government will ensure the development of 100 weekly markets in some cities in the next five years as an extension of the PM Svanidhi scheme, Sitharaman said.

While the idea of weekly haats (markets) was good, the scale was far too small, according to Aravind Unni, an expert on urban poverty alleviation.

myverdict



{ JAGTAR SINGH } FARMER, MEHMASARJA, BATHINDA

EXPECTATION
There needs to be some special income incentive for alternative crops other than wheat and paddy. Like the pay commission for government employees, we need regular agriculture commission to work on the needs of farmers and offer them the best remunerative price. The budget should focus on promoting cultivation of pulses, as the government is spending ₹60-70,000 crore annually on import of pulses. I suggest a separate agriculture budget as large share in country's GDP is from agriculture sector.

OUTCOME
The overall increase in budget for agriculture sector is 4.14% which when compared to inflation is very less. There has been no increase in minimum support price as Union finance minister Nirmala Sitharaman has said that the government is already giving best prices possible. As against the demand for waiver of Goods and Services Tax on farm implements and rationalising subsidies, there is no announcement of relief to farmers. Farmers need support of market intelligence in the agricultural sector... there was no mention that it might at least come as a policy decision by the Centre.

Rural housing push with 68% hike in funds

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The central government will help build an additional 30 million houses in both urban and rural areas under the PM Awas scheme, finance minister Nirmala Sitharaman announced in her seventh budget speech in Parliament, allocating an additional 68% funds for rural areas compared with the revised estimates of the previous budget.

"Three crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made," Sitharaman said on Tuesday. "The government allocated ₹54,000 crore for the rural housing programme in the FY 24-25 budget as against ₹32,000 crore in the revised estimates in the last budget."

Under the rural housing scheme, the government has constructed 2.63 crore dwelling units against a target of 2.94 crores. In the past few years, all PMAY (Grameen) houses came with cooking gas, water and power connections.

Presenting the interim budget in February this year, Sitharaman had announced: "Despite the challenges due to Covid, implementation of PM Awas Yojana (Grameen) continued and we are close to achieving the target of three crore houses. Two crore more houses will be taken up in the next five years to meet the requirement arising from increase in the number of families."

On June 10, the government gave approval to a cabinet proposal to construct a total of 3 million houses in the next five years, of which 20 million will be in rural areas, and 10 million in urban areas across the country.

The housing programme has worked well politically and as a developmental intervention, experts said.

There was no discrimination among the beneficiaries and it addressed the multidimensional poverty by creating durable assets of brick and mortar houses. The extension is much-needed as it will cater to new families in a number of states, an official said.

Under the central government, all new PMAY (Grameen) houses are provided with a cooking gas connection under the Ujjwala scheme and electricity connection under the Saubhagya scheme.

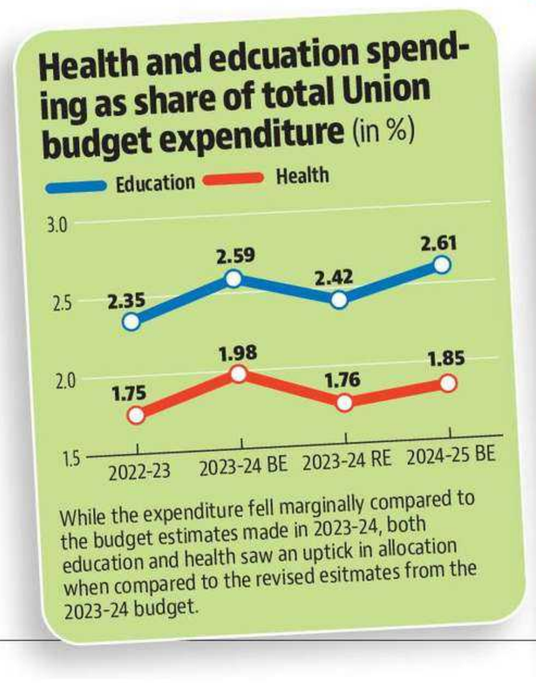
In her address to the joint sitting of both Houses in the last session of 17th Lok Sabha, President Droupadi Murmu had said, "Construction of pucca houses under the PM Awas Yojana has enhanced the social status and dignity of the beneficiary families and giving over seventy per cent houses under PM Awas Yojana in rural areas to women as sole or joint owners have enhanced their dignity."

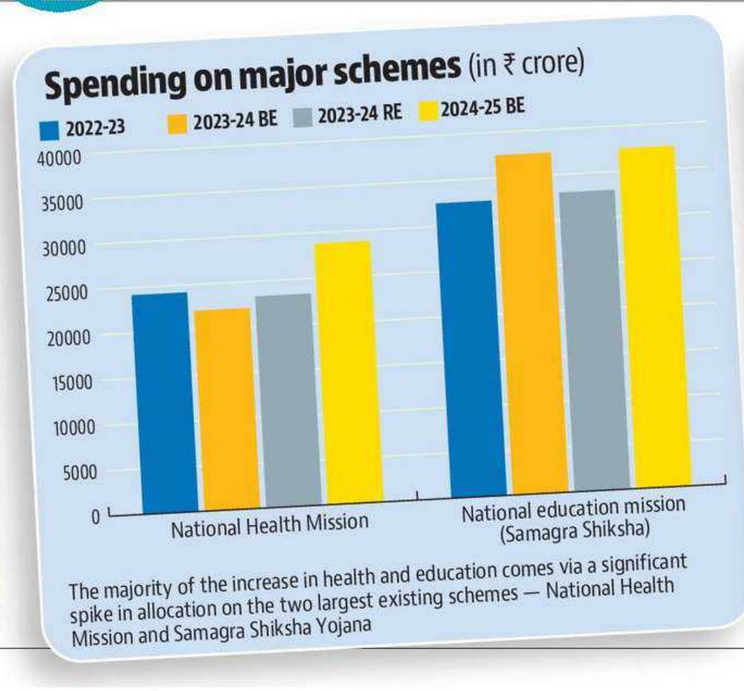
Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Rajasthan are among the top states in completing the construction of these houses.

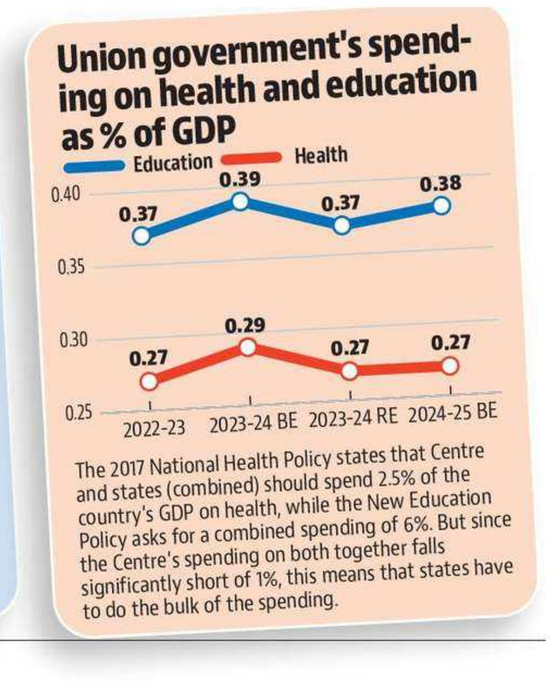

On June 10, the government approved a cabinet proposal to construct three million houses in the next five years. PTI FILE

HEALTH AND EDUCATION

In the 2024-25 Union budget, the central government has increased spending on health and education, both in absolute terms as well as in terms of proportion in the budget compared to the revised estimates of the 2023-24 budget.







Climate finance taxonomy on cards

Jayashree Nandi
letters@hindustantimes.com


The budget expanded list of exempted capital goods for use in manufacture of solar panels. HT ARCHIVE

NEW DELHI: India will develop a taxonomy for climate finance to enhance availability of capital for climate adaptation and mitigation, Union finance minister Nirmala Sitharaman announced on Tuesday, adding that the move will support the achievement of country's climate commitments and green transition.

According to the International Finance Corporation, clear climate finance taxonomies are like a referee in a football match – they make sure everyone agrees on what constitutes a true "green" investment. These rules are essential for creating a level playing field that attracts investors, helps the climate finance pie grow, and advances progress towards a sustainable future.

Climate finance taxonomy is a classification system that defines criteria for economic activities that are aligned with a net zero trajectory, and broader environmental goals.

It has been a point of contention and debate in UN climate negotiations, with India demanding a multilaterally agreed definition. By developing its own climate finance taxonomy, India can ensure investors identify activities, assets, and/or project categories that deliver on key climate, green, social or sustainable objectives. The European Union, for example, has its own climate finance taxonomy.

The Economic Survey released on Monday highlighted that India has achieved two of its nationally determined contributions (NDCs) under the Paris Agreement, years ahead of schedule, and is the only G20 nation in line to be compliant with the Paris Agreement's goal to keep global warming under 2 degrees Celsius.

The preliminary estimates of the overall resource requirement, as stated in the country's NDC, is $2.5 trillion for 2015-2030. The Long-Term Low Emission Development Strategy submitted by the country highlighted that financial resources of the order of tens of trillions of dollars would be required by 2050 for India's transition towards a low-carbon development pathway. India's first Adaptation Communication (AC) submitted to UNFCCC mentioned the cumulative need for expenditure for adaptation to be ₹56.68 trillion by 2030.

Last year, Union environment minister Bhupender Yadav made an intervention at a high-level ministerial dialogue on climate finance at COP28, saying that the lack of definition of climate finance also leads to a lack of trust and transparency among parties. "The issue is that most of the money categorised as climate finance are often loans or business investments and no grants which increases the debt burden of developing countries," he said at the time.

The government undertook issue of sovereign green bonds amounting to ₹16,000 crore in January-February 2023 to raise proceeds for public sector projects that would help reduce intensity of emissions, followed by ₹20,000 crore raised through sovereign green bonds in October-December 2023.

The Union Budget on Tuesday also proposed to exempt customs duty on critical minerals required for energy transition to nuclear and renewable energy and to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country.

"Minerals such as lithium, copper, cobalt and rare earth elements are critical for sectors like nuclear and renewable energy, space, defence, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on two of them. This will...help secure their availability for strategic sectors," Sitharaman said.

"CII commends the government's initiative to develop a taxonomy for climate finance. This will facilitate greater investments towards climate-friendly projects; enhance transparency and consistency in climate finance reporting; help India's transition to a low-carbon economy and mobilise resources for climate change adaptation and mitigation efforts," the Confederation of Indian Industries wrote on X after the announcement.

Meanwhile, the budget for Union environment ministry was increased marginally to ₹3,330.37 crore.

"The budget implicitly acknowledges that the lack of a taxonomy for climate finance is a barrier for enhancing availability of climate finance for mitigation and adaptation. Many investors and institutions want to invest in climate aligned activities. But absence of a clear guidance on what constitutes such activities impedes allocation of capital to climate policy aligned activities. Such a taxonomy will help government and stakeholders measure flow of climate finance and assess progress on climate finance provision across years. Once taxonomy and measurement is clear, the government could also report India's domestic climate finance contribution in its annual budgets. This critical announcement in the current budget creates a foundation for the same," said Vaibhav Chaturvedi, senior fellow, CEEW.

Outlay hiked for nuclear, thermal and solar power

Jayashree Nandi
letters@hindustantimes.com

Budget addresses not only India's clean energy ambitions but also ...targets broader implications of India's green industrialisation.

NIRMALA SITHARAMAN, Union finance minister

NEW DELHI: Union finance minister Nirmala Sitharaman, in her budget speech on Tuesday, announced a diversified energy plan for India focussed on small, modular nuclear reactors, rooftop solar plants, and the development of indigenous technology for Advanced Ultra Super Critical (AUSC) thermal power plants with much higher energy efficiency.

Sitharaman said nuclear energy is expected to form a significant part of the energy mix for Viksit Bharat or developed India, adding that the government will partner with the private sector to set up Bharat Small Reactors, research and development (R&D) of Bharat Small Modular Reactor, and R&D for newer technologies for nuclear energy. "The R&D funding announced in the interim Budget [in February] will be made available for this sector."

India has an installed nuclear energy capacity of 7.48 GW (gigawatts) which is slated to increase to 13.08 GW by 2029, with the addition of seven more reactors.

Sitharaman said PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 10 million households to get free electricity up to 300 units monthly. She added the scheme has generated a remarkable response with over 12.8 million registrations and 1.4 million applications. "...we will further encourage it."

Sitharaman said the development of indigenous technology for AUSC thermal power plants with much higher efficiency has been completed. "A joint venture between NTPC [National Thermal Power Corporation] and BHEL [Bharat Heavy Electricals Ltd] will set up a full-scale 800 MW commercial plant using AUSC technology," she said. "The government will provide the required fiscal support."

She said a roadmap for moving the "hard to abate" industries from "energy efficiency" targets to "emission targets" will be formulated.

Sitharaman also announced the development of a taxonomy for climate finance to enhance the availability of capital for climate adaptation and mitigation. "This will support [the] achievement of country's climate commitments and green transition."

"The 2024 Budget has several promising provisions to build a sustainable economy. It addresses not only India's clean energy ambitions (with a focus on rooftop solar and pumped hydro storage) but also outlines actions on water treatment, air quality, and recovery from riverine floods. In parallel, it targets broader implications of India's green industrialisation, how MSMEs—the backbone of India's industry—will transition, and importance of a Critical Mineral Mission. These elements are peppered through, but looked at together they form a significant push for a greener economy," said Arunabha Ghosh, CEO, Council on Energy, Environment and Water (CEEW) in a statement.

"Each of these provisions—from clean energy markets, to green industry, to quality of life—can benefit from a focus on loss prevention from climate events, promoting new business models for households and small industry, a circular economy of resources, and innovative financing beyond budgetary support. In that regard, the Budget's proposal to define climate finance is a positive step towards mobilising capital for sustainability. These measures can lay strong foundations for a sustainable and prosperous India, with energy transition as the fulcrum on which public policy can be leveraged for a wider economic transformation," he added.

International development consulting IPE Global's sector head (climate change and sustainability) Abinash Mohanty said the Budget outlays a clear intent to bring climate finance from margins to the mainstream through a financial taxonomy. "The Budget stands true to India's climate commitments and recognises the dire need to step up climate actions."

Mohanty called promises to mitigate flood risks through climate-resilient infrastructure development across flood hotspots such as Bihar, Assam, and other Himalayan states in the Budget speech laudable.

Mohanty said the Budget, however, lacks focus on improving the climate data and information infrastructure and making it more people-centric, especially when India is losing millions in loss and damage due to climate extremes.

The 2023-24 Economic Survey said India will target a diversified set of sources for energy security with a significant place for thermal power and coal to provide base load, and minimise risks associated with systems in line with national commitments.

₹1,000 cr VC fund for space economy

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com


The budget allocates ₹10,088 crore for space technology and ₹1,612 crore for space applications. AP

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman unveiled a set of forward-looking initiatives as part of the budget proposals on Tuesday, operationalising a ₹1 lakh crore research fund that experts said will help work in next generation technologies and announce a new fund for innovation in the space sector.

The budget, presented for the fiscal year 2024-25, also has plans to expand digital infrastructure, advance nuclear technology, and secure critical minerals essential for high-tech manufacturing.

"We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realising their life goals and aspirations," Sitharaman said, setting the tone for a budget focused on long-term growth and innovation.

Part of this push was in the space sector, which appears to capitalise on India's recent successes in space exploration. The government earmarked funds to dramatically expand the country's space economy.

"With our continued emphasis on expanding the space economy by five times in the next 10 years, a venture capital fund of ₹1,000 crore will be set up," Sitharaman declared.

Winnie Shekhar, partner at INDUSLAW, said the "₹1,000 crore venture capital fund will significantly impact India's space sector by providing essential financial support for research and development of advanced space technologies".

"This move is expected to boost private sector participation, create high-skilled jobs, and drive innovation across various industries (space and beyond), positioning India as a major player in the global space economy," Shekhar added.

The budget allocates ₹10,088 crore for space technology and ₹1,612 crore for space applications, demonstrating a substantial increase in funding for the space sector over the previous financial year, when, according to revised estimates, ₹8,180 crore and ₹1,526 crore were allotted to the sector.

The minister's plans also appeared to target critical minerals in order to secure the future of tech manufacturing.

"We will set up a Critical Mineral Mission for domestic production, recycling of critical minerals, and overseas acquisition of mineral assets," Sitharaman stated. The mission's mandate will include technology development, skilled workforce creation, an extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism.

These initiatives are crucial for ensuring a steady supply of minerals essential for high-tech manufacturing, including semiconductors, batteries, and renewable energy technologies.

Hitesh Garg, VP and India managing director, NXP Semiconductors, welcomed what he said was "strong support for the semiconductor and electronics manufacturing sector". "The government's significant increase in funding for semiconductors, along with the enhanced PLI allocation under Meity, shows a strong commitment to fostering a thriving ecosystem for technological progress," Garg said.

For development of semiconductors and display manufacturing ecosystem, the budget proposed to allocate ₹6,903 crore, as compared to ₹1,503 crore allotted in the previous financial year, according to revised estimated. In the 2023-24 period, the government had initially budgeted ₹3,000 crore but appeared to have utilised half the amount for the purpose.

Sitharaman announced decision to operationalise "Anusandhan National Research Fund", which was unveiled as part of a law on national research enacted in 2023 for basic research and prototype development. "Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of ₹1 lakh crore in line with the announcement in the interim budget," the finance minister said.

Experts hailed this move and said some of these will go to future technologies. "Though there are multiple announcements which will benefit the startup ecosystem, the industry was hoping for more a dedicated focus for AI and deep tech which will hopefully now come from the R&D initiatives that have been announced," said Ranjana Adhikari, partner, INDUSLAW.

myverdict



{ SAUMYA MAHAJAN } PSYCHOLOGY TEACHER, LUCKNOW

EXPECTATIONS
Adequate resources, support systems, emphasis on advancing technology in the education sector is what I had hope for from the Union Budget of 2024... I strongly believe that an environment that fosters effective teaching and enhances overall job satisfaction at the workplace is the basic requirement for educators, being shapers of the future.

OUTCOME
The Union Budget of 2024, especially to do with the education and jobs has met my expectations. The budget has also taken initiatives for skill development and vocational training which aligns education with industry needs, and will also enhance employability.

Allocation for health ministry rises by 12.59%

Rhythma Kaul
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Union finance minister Nirmala Sitharaman announced a full exemption from customs duty for three key cancer drugs that oncologists said will significantly benefit patients. According to experts, the overall cost of the three drugs could come down by up to 20% because of the exemption.

The health ministry received ₹90,658.63 crore, a 12.59% increase from last year (as measured by the revised estimates for the 2023-24 fiscal), and the Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission (PMABHIM) saw an allocation of ₹3,200 crore.

The drugs that have received exemption — Trastuzumab Deruxtecan, Osimertinib, and Durvalumab — are used as targeted cancer therapy in certain types of cancers. Of the ₹90,958.63 crore, ₹87,656.90 crore has been allocated to the department of health and family welfare and ₹3,301.73 crore to the department of health research.

"All imported life-saving drugs are costly and the same goes for cancer drugs, so customs duty exemption is a welcome step. Since patients require long-term treatment, all steps to bring the cost down are very welcome," said Dr Shyam Aggarwal, chairman, medical oncology, Sir Ganga Ram Hospital.

Trastuzumab Deruxtecan is an antibody-drug conjugate used primarily to treat HER2-positive breast cancer that has spread to other parts of the body (metastatic). It is also being studied for use in other types of cancer, such as gastric cancer.

Osimertinib is a targeted therapy used to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) with specific mutations in the EGFR gene. It is particularly effective against cancers that have developed resistance to earlier generations of EGFR inhibitors.

Durvalumab is an immunotherapy drug that works by blocking the PD-L1 protein, helping the immune system attack cancer cells. It is used to treat non-small cell lung cancer (NSCLC) and urothelial carcinoma (bladder cancer).

"The exact reduction in cost will depend on the current customs duty rates and other associated costs such as import taxes and logistics. Exemption from basic customs duty could potentially reduce the price by 10-20%, making these treatments more affordable for patients," said Mandeep Singh Malhotra, director, surgical oncology at CK Birla Hospital.

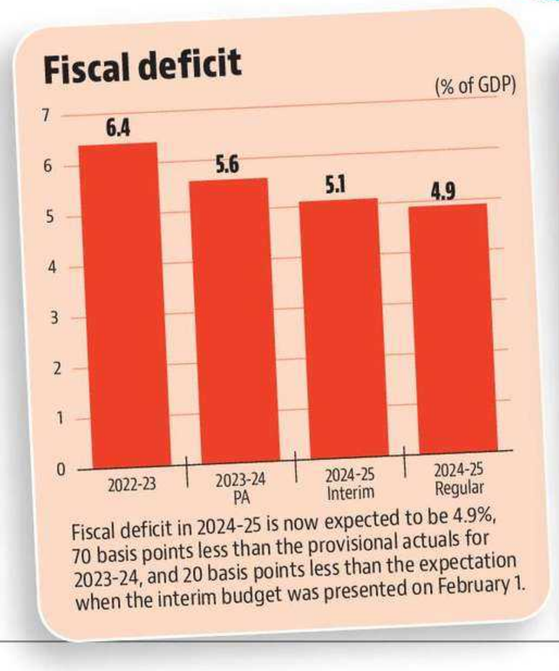
Along with cancer drugs, the finance minister also announced the exemption of customs duty on components of X-ray tubes and digital detectors. "Since there are no domestic manufacturers available for these two components, the relief is appreciable," said Rajiv Nath, forum coordinator, Association of Indian Medical Device Industry.

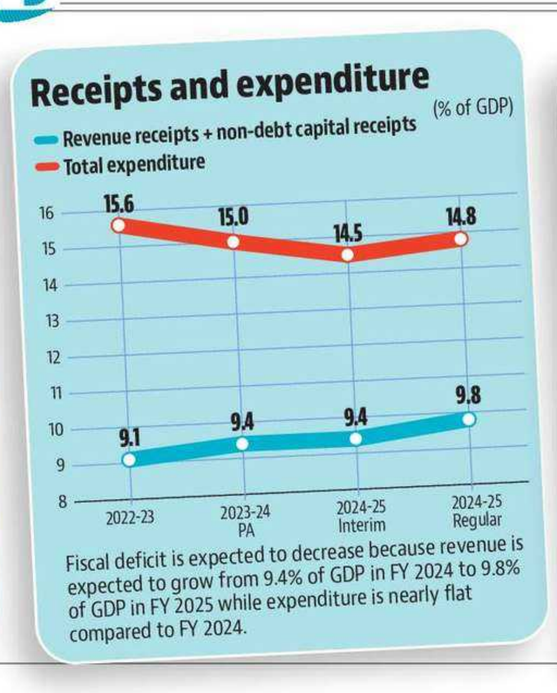
UNION BUDGET UB 2024-25

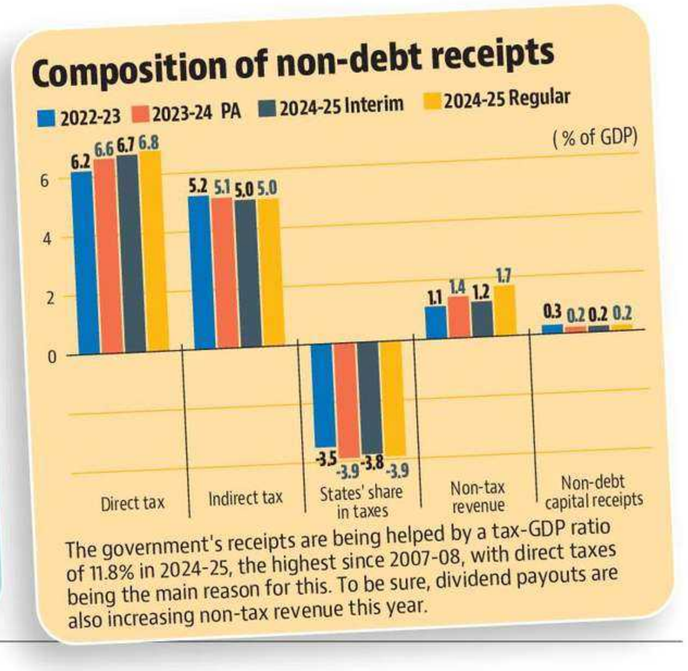
OTHER KEY SECTORS

GOVT'S FISCAL CONSOLIDATION CONTINUES

The 2nd Modi govt followed a strategy of aggressive fiscal consolidation despite the economic disruption caused by the pandemic. The new government is continuing on this path. While the assumed GDP growth of 10.5% and flat expenditure (as a share of GDP) are a factor in this, fiscal consolidation this year is also being helped this year by direct tax collections and higher than usual dividend payouts.







With ₹6.22L-cr for defence, focus on 'Atmanirbharta'

Rahul Singh
rahul.singh@hindustantimes.com

NEW DELHI: India on Tuesday set aside almost ₹6.22 lakh crore for spending on defence in the Union Budget 2024-25, with the chunk of the outlay allocated for buying modern weapons, systems and equipment from domestic suppliers to achieve the larger goal of Atmanirbharta or self-reliance.

The allocation is 4.79% higher than what it was in the budget estimates (₹5,93 lakh crore) for financial year 2023-24, but a fraction lower than last year's revised estimates (₹6.23 lakh crore), budget documents show. The allocation is ₹400 crore more than what it was in the interim budget announced in February.

This year's allocation (₹6,21,940.85 crore) includes a revenue expenditure of ₹2.82 lakh crore, a capital expenditure ₹1.72 lakh crore, and a pension outlay of ₹1.41 lakh crore. The capital outlay includes ₹1.05 lakh crore for domestic procurement, and the revenue outlay consists of ₹92,088 crore for sustenance and operational readiness.

In all, the defence ministry has earmarked 75% of the total modernisation budget for domestic procurement during 2024-25. "This will have a multiplier effect on GDP, employment generation and capital formation, thus providing a stimulus to the economy," the defence ministry said in a statement.



The revenue expenditure includes almost ₹6,000 crore for the Agnipath scheme, up from ₹4,266 crore and ₹3,518 crore in the budget and revised estimates for 2023-24. HT PHOTO

The defence budget accounts for 12.9% of the total government budget and 1.9% of the country's projected gross domestic product (GDP) for 2024-25.

"The allocation is aimed to promote Atmanirbharta in defence technology and manufacturing and equipping the armed forces with modern weapons/platforms along with creation of job opportunities for the youth," the ministry said in the statement, soon after finance minister Nirmala Sitharaman presented the budget in Parliament.

To be sure, she did not spell out the defence allocation in her speech.

It stood at ₹6,21,540.85 crore in the interim budget announced in February, then accounting for 13.04% of the total government budget.

"While maintaining the allocation made to the defence ministry during interim budget, the government has made an additional allocation of ₹400 crore on innovation in defence through the ADITI scheme," the statement said. ADITI stands for Acing Development of Innovative Technologies with iDEX (Innovations for Defence Excellence).

The capital outlay (for modernisation) stood at ₹1.62 lakh crore in 2023-24, and was revised to ₹1.57 lakh crore.

"In absolute terms, budgetary allocation under capital head to the defence forces for FY 2024-25 is ₹1.72 lakh crore, which is 20.33% higher than the actual expenditure of FY 2022-23 and 9.40% more than the revised allocation of FY 2023-24. The allocation is aimed to fill the critical capability gaps through big ticket acquisitions in current and subsequent FYs," the statement said. To be sure, the capital budget is 5.8% more than the budget estimates for 2023-24.

The enhanced allocation for 2024-25 will help the armed forces strengthen their capabilities with new military hardware to stay prepared for security challenges. India is modernising its military with fighter jets, helicopters, warships, tanks, artillery guns, rockets and missiles, unmanned capabilities and other combat systems, at a time when it is locked in a military standoff with China in eastern Ladakh.

"The enhanced budgetary allocation will fulfil the requirement of annual cash outgo on planned capital acquisitions aimed at equipping the armed forces with state-of-the-art niche technology, lethal weapons, fighter aircraft, ships, submarines, unmanned aerial vehicles, and specialist vehicles," the statement said.

The revenue expenditure includes almost ₹6,000 crore for the Agnipath scheme, up from ₹4,266 crore and ₹3,518 crore in the budget and revised estimates for 2023-24.

Revised estimates in the budget documents show that the armed forces were unable to spend ₹5,372 crore of last year's capital outlay of ₹1.62 lakh crore.

Govt fillip to pitch India as global tourist destination

Vrinda Tulsian
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday announced a series of steps, ranging from building temple corridors and wildlife sanctuaries to pitching India as a global destination, as part of the government's efforts to provide a fillip to the tourism sector.

The minister said tourism plays an intrinsic role in India's cultural fabric. "The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and all-round prosperity... tourism has always been a part of our civilisation. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments and unlock economic opportunities for other sectors," she said.

According to the budget, the government plans for comprehensive development of the Vishnupad temple and Mahabodhi temple corridors, at Gaya and Bodh Gaya, respectively, on the lines of the Kashi-Vishwanath temple corridor. A similar plan has also been devised for the Nalanda-Rajgir corridor.



Nirmala Sitharaman said that the Mahabodhi Temple at Bodh Gaya has immense spiritual significance. HT PHOTO

Besides promoting Nalanda as a centre for tourism, Sitharaman also announced plans to revive the Nalanda University to its "glorious stature" — a month after Prime Minister Narendra Modi inaugurated the varsity close to the site of the ruins of Nalanda during his Bihar visit.

"Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Munisuvrata temple in the Jain Temple complex is ancient. The Saptharishi or the seven hotsprings form a warm water Brahmakund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken," she said.

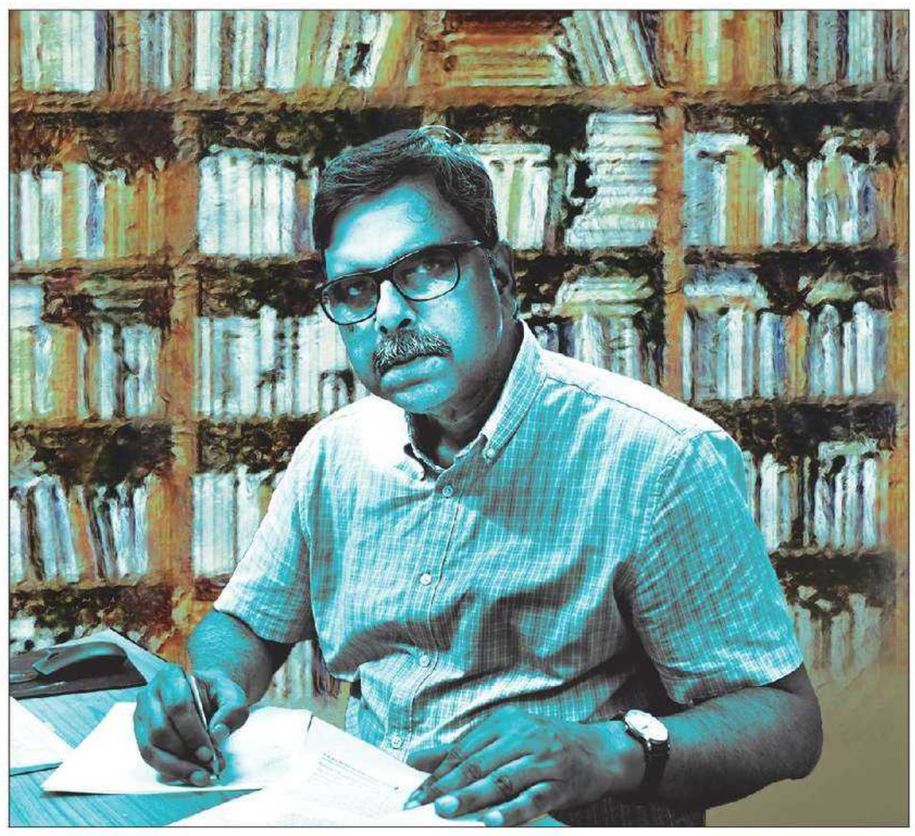
The government also stressed on Odisha's scenic beauty, highlighted by the state's temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes and pristine beaches, "making it an ultimate tourism destination".

The finance minister added there was tremendous potential for cruise tourism in India. "To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country," she said.

Some stakeholders in the tourism industry, however, said they were "disappointed" with the budget announcements, as their recommendations to boost the industry have been sidelined.

"It hurts more as the government's objective is to boost employment generation, and no industry comes closer to it in terms of the potential of employment generation," Indian Association of Tour Operators president Rajiv Mehra said.

myverdict



{ ASHUTOSH KUMAR } POLITICAL SCIENCE PROFESSOR, PANJAB UNIVERSITY

EXPECTATIONS
Rising prices of food items and other stuff has hit the middle classes hard. The government should provide some relief for the tax-paying middle class also. The present regime has been widely seen, rightly or wrongly, as catering either to the poor or rich. Middle class weighs much more than the actual number indicates. And it needs attention in the budget.

OUTCOME
The announcement to directly transfer to the first-time employee a maximum of ₹15,000 should be seen as a populist measure... The middle class... has been sought to be placated by the relief in the form of the revised tax structure in the new tax regime. Pro-reform middle class... would be enthused by the announcement of the creation of new satellite townships, new transit plans, lower stamp duties for women, less customs duty on mobile phones, etc.

FUNDING FOR MHA RESEARCH, TRAINING LOGS 3-FOLD INCREASE

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The budget allocation for the Ministry of Home Affairs (MHA) under the Education Training and Research expenditure increased to ₹1348.35 crore — a three-fold increase from the revised estimate (RE) 2023-24 of ₹440.8 crore.

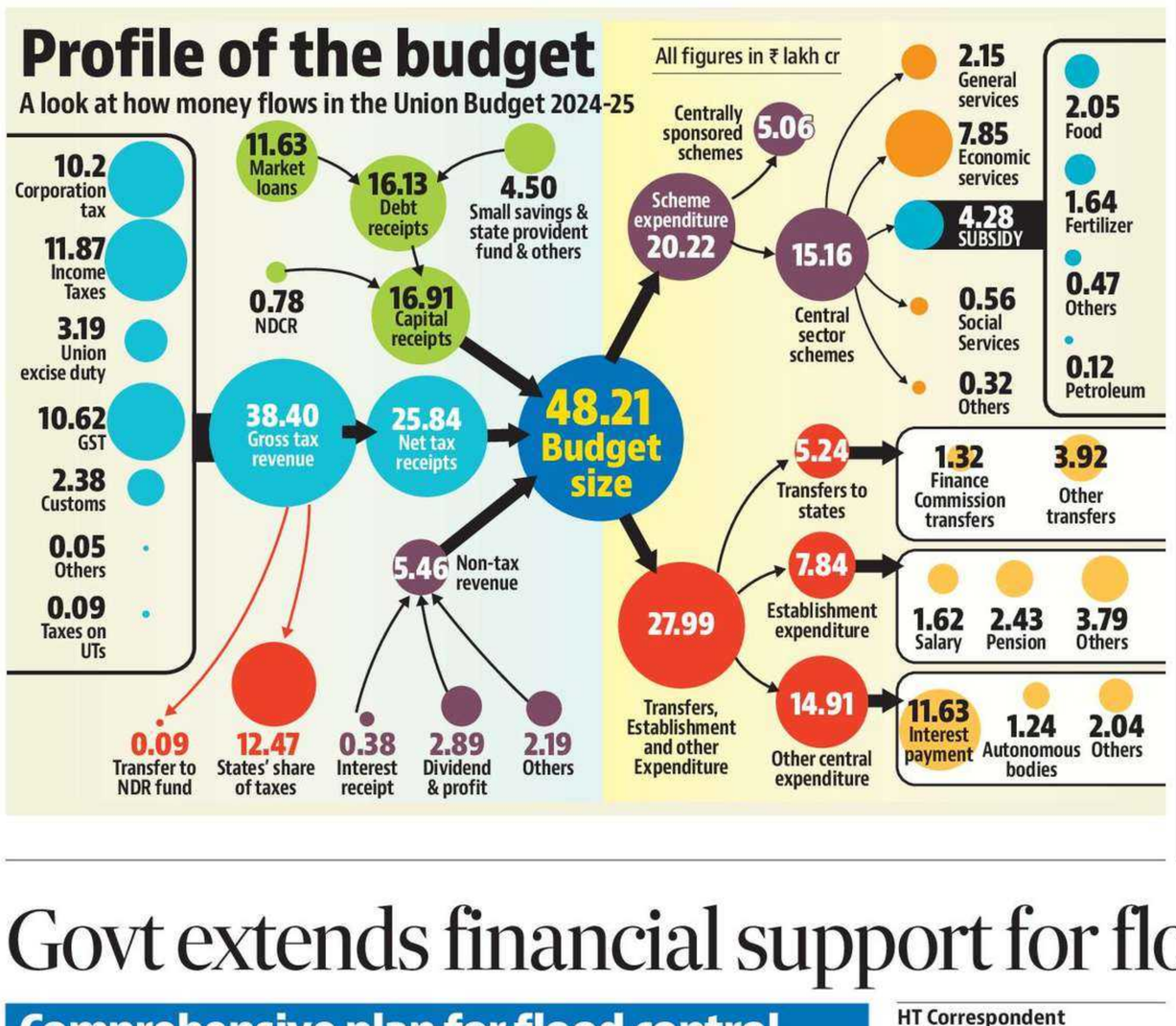
With the implementation of the three new criminal laws and states adopting the new judicial process, different research and training institutions under the Centre are involved in improving the infrastructure and training of police personnel.

The amount covers expenditure on the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, Central Detective Training School, National Institute of Criminology and Forensic Science, North-East Police Academy, Central Academy of Police Training, Central Detective Training School, Bureau of Police Research and Development (BRRD) and Central Armed Police Forces Institute of Medical Science. The provision is also for the BPRD's training intervention, research and development projects for better efficiency and public reach out.

BPRD officials said the bureau has already completed the training of trainers for all state police forces across the country.

For modernisation of state police forces and connecting CCTNS budget increased to more than twice from ₹221 crore (RE 2023-24) to ₹520 crore. CCTNS connects police stations across the country on one platform.

Even as all states have adopted the new criminal laws, the bureau is continuing to hold trainings for personnel, who are yet to be trained by the trainers.



Govt extends financial support for flood mitigation in five states

Comprehensive plan for flood control



Bihar
₹11,500 crore for Kosi-Mechi intra-state link and 20 other flood management and irrigation projects

Assam
Centre to help manage floods caused by the Brahmaputra Rriver and its tributaries

Uttarakhand and Sikkim
Central assistance after recent spate of floods and landslides

Himachal Pradesh
Centre to help with the reconstruction and rehabilitation following damage caused by floods last year

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Union finance minister Nirmala Sitharaman announced financial assistance for Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand and Sikkim for the damage caused by floods and other natural calamities.

Delivering her budget speech on Tuesday, she said, "Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Programme and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of ₹11,500 crore such as the Kosi-Mechi intrastate link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement and irrigation projects."

In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken, she said.

For Assam, which is hit by floods every year by the Brahmaputra and its tributaries, originating outside India, she said, "We will provide assistance to Assam for flood management and related projects. Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance." The floods in Assam this year has claimed at least 80 lives, uprooted 45,000 people from their homes. It affected at least 27 of the 35 districts in the state.

Uttarakhand and Sikkim, which suffer losses due to cloud bursts and flash flood too, will be provided aid, she said. At least 44 people, including 23 army personnel, died after a cloudburst that triggered flood in north Sikkim in October last year. While over 50 people went missing, the flood affected over 30,000 people.

Union home minister Amit Shah posted on X, "The Budget 2024–25 stands out for the healing touch it serves to the people of the states affected by floods. Providing much-needed relief to flood-affected Bihar, Assam, Himachal Pradesh, Uttarakhand, and Sikkim, the budget sets out to reshape the dreams of people by rejuvenating the affected areas and making adequate provisions for flood prevention."

Union Budget moves to tame frenzied trading in derivatives

mint

Dipti Sharma
letters@hindustantimes.com



The Bombay Stock Exchange building in Mumbai, India, on Tuesday. HINDUSTAN TIMES

MUMBAI: The frenzied trading in derivates that alarmed regulators and policy makers is expected to dampen, at least for a while, with the government increasing taxes on transactions in a major blow to investors and traders.

The changes announced in the Union Budget on Tuesday follow the Economic Survey's warning a day earlier about the sharp increase in retail, or individual, investor participation in the stock markets. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) is also planning measures to rein in retail speculation in trading in futures and options.

The budgetary proposals include increased securities transaction tax, or STT, on derivatives as well as higher capital gains levies on listed financial instruments, which market experts say would affect trading volumes, particularly those involving professional high-frequency traders.

Finance minister Nirmala Sitharaman in her budget for 2024-25 proposed raising the STT on the sale of options from 0.0625% to 0.1% of the premium, and on futures from 0.0125% to 0.02% of the trading price.

She also raised the short-term capital gains tax on listed financial instruments from 15% to 20%, and the long-term tax from 10% to 12.5%.

For options traders, the securities transaction tax will increase by about 60%, said Roop Bhootra, chief executive officer of investment services at Anand Rathi Shares and Stock Brokers.

"This move would definitely have a negative impact on professional traders who are trading more on intraday basis and generating exceptionally high-volume trades as it will increase their trading costs," he said.

The securities transaction tax was introduced in 2004 to rein in speculative trading and rake in revenue from the financial markets. Investors and traders must pay STT regardless of whether they make a profit or a loss.

On expected lines

Average daily turnover in equity futures on the National Stock Exchange increased by 1.5 times between 2018-19 and 2023-24, and in options by 18 times, said Krishna Rao, managing director and co-head, equity broking, at JM Financial Services Ltd.

Data on NSE, the world's largest equity derivatives marketplace, show that the notional turnover of equity derivatives jumped to ₹79,928 trillion in 2023-24 from ₹3,445 trillion in FY20.

"The increase in STT on derivatives was on expected lines and a right step so as to limit the F&O transactions by the high-frequency traders," Rao said.

High-frequency traders usually work with thin profit margins and at very low cost. The higher STT is expected to adversely affect such traders, forcing them to slash volumes in the near term. Some market experts, however, believe these traders would adjust their strategies and not be discouraged in the long term.

"HFTs may cut back on their volumes immediately (post 1 October) as their spreads will get narrower due to the hike in STT," said Dhiraj Relli, managing director and chief executive of HDFC Securities Ltd.

But if the stock markets continue to be volatile, especially on the bullish side, these traders may seek to compensate with higher volumes, he said.

Ajay Menon, MD and CEO, broking and distribution, at Motilal Oswal Financial Services Ltd, said the higher STT will impact profitability for F&O traders.

"We may see the volumes getting impacted in the near term, particularly for clients who were trading in thin margin spreads," he said. "For positional traders, there will be some impact but we expect volumes to recover gradually."

Curbing the retail frenzy

Relli of HDFC Securities said traders would have to also wait for the outcome of the consultation paper to be floated by Sebi, which will outline measures to address the retail frenzy in F&O trading.

"If other steps to curb F&O volumes are taken then it may cumulatively impact the F&0 volumes and even HFTs will have to adjust to this new norm," he said.

On Monday, the Economic Survey for 2023-24 said the sharp rise in retail investors in the stock market warranted careful consideration. "This is crucial because the possibility of overconfidence leading to speculation and the expectation of even greater returns, which might not align with the real market conditions, is a serious concern," the survey said.

Derivatives trading seems to be fuelling the surge in active retail participation, it added.

"Derivatives trading holds the potential for outsized gains. Thus, it caters to humans' gambling instincts and can augment income if profitable," the Economic Survey said, adding that a major stock market correction could lead to more substantial losses for retail investors involved in derivatives trading.

Controversial e-commerce levy that led to a tiff between India and US scrapped

mint

Gireesh Chandra Prasad
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A controversial levy India imposed four years ago on digital services rendered to Indian businesses by offshore technology firms, leading to a tiff between New Delhi and Washington, has been scrapped.

The Finance Bill 2024 presented by finance minister Nirmala Sitharaman proposes to scrap from August 1 the 2% equalisation levy on a wide array of services rendered by offshore tech firms including cloud services and e-commerce services.

The move comes as a big relief to global e-commerce players, especially US-based ones, as many businesses were facing tax disputes on account of this levy, experts said.

India had in 2020 expanded the scope of its equalisation levy, first introduced in 2016 on offshore firms hosting advertisements targeted at Indian consumers, to include other e-commerce services by offshore entities.

According to a report by the US Trade Representative (USTR) in 2021, which described the expanded form of the levy discriminatory against the US, a large number of services including software as a service, platform services, data-related services, cloud services, financial services, education services and digital sales of a company's own goods are covered under the 2% levy.

The idea has been to tax payments made to offshore entities by Indian consumers of these services as the technology service providers may not have a physical presence here and therefore the income tax department cannot subject such income earned from India to tax. The Finance Bill said that some stakeholders raised concerns that the scope of the 2% levy was ambiguous and as a result, lead to compliance burden.

"In view of this it is proposed that this equalisation levy at the rate of 2% shall not be applicable to consideration received or receivable for e-commerce supply or services, on or after the first day of August, 2024," said the Union budget documents.

The levy which was originally applicable to online advertisements hosted on platforms run by offshore entities was at the rate of 6%. This, however, stays.

Only the 2% levy on other e-commerce services that was rolled out in 2020 which led to friction with the US has been rolled back, explained Amit Maheshwari, tax partner at AKM Global, a tax and consulting firm. "Since, its introduction from April 1, 2020, the equalisation levy on digital services created controversies with respect to classification of services to determine if these would be subject to this levy or could be taxed as royalty or fee for technical services," said Maheshwari.

"The tax department and foreign companies are not always aligned even if the foreign companies discharged the obligation of payment of this levy. Its removal will put to rest such disputes and will simplify the compliance burden for the foreign companies providing such services," said Maheshwari.

Although the USTR had said the levy was actionable under US laws — such as withdrawing trade benefits and imposing duties or import curbs — the two countries agreed on a transitional deal similar to what the US had reached with countries like Austria, France, Italy, Spain, and UK.

Budget proposes reduction in customs duty on gold, silver

Asian News International
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Finance minister Nirmala Sitharaman on Tuesday proposed to reduce customs duties on gold and silver to 6% and on platinum to 6.4%to enhance value addition in precious metal jewellery.

"To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewellery in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that on platinum to 6.4%," Sitharaman said while presenting Union Budget 2024-25 in the Lok Sabha.

Referring to other metals, she said steel and copper are important raw materials.

"To reduce their cost of production, I propose to remove the BCD (Basic Customs Duty) on ferro nickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap," she said.


Gold necklaces are displayed inside a jewellery showroom in Kolkata. REUTERS

In the beginning of her budget speech, Sitharaman said that the people of India have reposed their faith in the government led by Prime Minister Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. "We are grateful for their support, faith and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender and age, make substantial progress in realising their life goals and aspirations," she said.

The minister said that the global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. "Elevated asset prices, political uncertainties and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation."

She said India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. "India's inflation continues to be low, stable and moving towards the 4% target. Core inflation (non-food, non-fuel) currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach market adequately," she said.

The minister said that the government will undertake a comprehensive review of the agriculture research setup to bring focus on raising productivity and developing climate resilient varieties.

'OVER ₹1 LAKH CR DEDICATED FOR RAIL SAFETY'

Neha LM Tripathi
neha.tripathi@htlive.com

NEW DELHI: Union railways minister Ashwini Vaishnaw announced on Tuesday that out of the total budget of ₹2,62,200 crore, a record ₹1,08,795 crore will be dedicated to safety measures.

Indian Railways will allocate a significant portion of its budget to improve train safety and introduce the "Kavach" automatic train-protection system.

"A big chunk of this allocation; ₹1,08,795 cr is for safety-related activities, which include, replacement of old tracks, improvement in the signalling system, construction of rail over and rail under bridges, and to install Kavach," Vaishnaw said.

The government allocated a record Capex to ₹2,62,200 crore for Railways.

Vaishnaw said that installation of Kavach was on the top of the priority list for the government.

CSIR-Indian Institute of Petroleum
(Council of Scientific & Industrial Research)
P.O. IIP, Mohkampur, Haridwar Road Dehradun - 248005 (Uttarakhand), INDIA, Website: www.iip.res.in
Creating Future Fuels

Recruitment Advt. No. 05/2024

Walk-in-Interview for the temporary Positions of "Project Scientist I/II" "Senior Project Associate" "Project Associate-II" "Project Associate-I" & "Laboratory Assistant"

Position & Eligibility	Maximum Age limit (As on the date of walk-in-interview)	No. of Positions	Date of Walk-in-Interview
(A) Project Scientist I/II [Stipend Rs. 56,000/ 67,000/- per month plus HRA*]			
(i) **Essential Qualification:** **For Project Scientist-I-** Doctoral Degree in Science or Master's Degree in Engg. or Technology from a recognized University as per subjects mentioned in the detailed advertisement available on the CSIR-IIP Website. **OR** **For Project Scientist-II** – Doctoral Degree in Science or Master's Degree in Engg. or Technology from a recognized University as per subjects mentioned in the detailed advertisement available on the CSIR-IIP Website with three years of relevant experience in R&D. **Desirable:** Candidates having Experience in at least one LCA tools e.g. Sima Pro, GREET, Open LCA. Experience in GHGH accounting, GHG inventory preparation will be preferred.	35 Years OR 40 Years	01	**01.08.2024 (Thursday)**
(ii) **For Project Scientist-I-** Ph.D. in Metallurgical and Materials Engg./ Science from a recognized university. OR **For Project Scientist-II-** Ph.D. in Metallurgical and Materials Engg./ Science from a recognized university with three years of relevant Experience in R&D.	35 Years OR 40 Years	01	**02.08.2024 (Friday)**
(B) Senior Project Associate [Stipend Rs 42,000/- per month plus HRA*]			
(i) **Essential Qualification:** B.E./B.Tech. in Science/ Engg. from a recognized University as per subjects mentioned in the detailed advertisement available on the CSIR-IIP Website with four years of relevant experience in R&D. OR Ph.D. in Science/ Engg. from a recognized university as per subjects mentioned in the detailed advertisement available on the CSIR-IIP Website.	40 Years	01	**01.08.2024 (Thursday)**
(ii) **Essential Qualification:** B.E./B. Tech. in Mechanical Engg. from a recognized university with 4 years of relevant experience. OR Ph.D. in Metallurgical and Materials Engg. from a recognized university.	40 Years	01	**02.08.2024 (Friday)**
(iii) **Essential Qualification:** Ph.D. in Chemistry from a recognized university. Desirable: R&D Experience in the area of bio-fuels, bio-surfactants, Value addition of vegetable oil and LCA analysis.	40 Years	01	**07.08.2024 (Wednesday)**
(C) Project Associate-II [Stipend Rs 28,000 / 35,000/-# per month plus HRA*]			
(i) **Essential Qualification:** B.E./B. Tech. (Mechanical Engg.) from a recognized university with two years or relevant experience.	35 Years	02	**02.08.2024 (Friday)**
(D) Project Associate-I [Stipend Rs 25,000/ 31,000/- per month plus HRA*]			
(i) **Essential Qualification:** B.E./B. Tech. (Chemical Engg.) from a recognized university.	35 Years	01	**07.08.2024 (Wednesday)**
(ii) **Essential Qualification:** B.E./B. Tech. (Mechanical Engg.) from a recognized university.	35 Years	02	**02.08.2024 (Friday)**
(iii) **Essential Qualification:** B.E./B.Tech. in Electrical Engg. / Electronics & Communication Engg./ E.E.E./ Electronics Engg. from a recognized university.	35 Years	01	**08.08.2024 (Thursday)**
(E) Laboratory Assistant [Stipend Rs 20,000/- per month plus HRA*]			
(i) **Essential Qualification:** B.Sc. (IT/Computer Science) OR BCA from a recognized university.	50 Years	01	**08.08.2024 (Thursday)**

Note: Where Ph.D. is essential qualification, the Ph.D. submitted candidates are not eligible to apply.
*HRA will only be given if there is a provision of HRA in the Concerned Project.
All the interested candidates may visit Institute website **www.iip.res.in** for detailed advertisement and application proforma and eligible candidates may appear for Walk-in-Interview/Written test on the above-mentioned dates. The positions are purely on temporary basis and are co-terminus with the project, Number of positions may vary.

Administrative Officer

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(Ministry of Ports, Shipping and Waterways, Govt. of India)
Head Office: A-13, Sector -1, Noida – 201301 (U.P.), Phone: 0120 – 2527667

Press Note

Under the visionary leadership of Hon'ble Prime Minister and able guidance of Hon'ble Minister of Ports, Shipping and Waterways, the Inland Waterways Authority of India (IWAI) is taking several steps to promote Cargo Transportation using Waterways, which is considered as safe, cheap & environment friendly mode of transportation as compared to Rail/Road. As a result, the Cargo Transportation through Waterways has reached 133 million tonnes during 2023-24 as compared to 18 million tonnes a decade ago.

The IWAI, in continuation of its efforts to promote National Waterways, took several landmark decisions during its Board Meeting held on 19.07.2024, which shall have a long-lasting impact on Inland Water Transport (IWT) Sector in the country.

To give further boost to IWT, IWAI approved Draft Regulations for providing "No Objection Certificate" (NOC) for development of "Inland Waterways Terminal" on or along National Waterways. This will enable development of network of IWT Terminals for commercial use with the participation of private sector, public sector entities and enhance the modal share of cargo transportation through waterways in the overall transport chain.

IWAI approved the action plan for Dredging in the North Eastern Region (NER) to provide seamless movement of Cargo/Passenger Vessels in NW-2 (Brahmaputra) from Dhubri to Dibrugarh, NW-16 (Barak), NW-37 (Dhansiri) & NW-57 (Kopili) in NER through Dredging/Bandalling. This will provide seamless connectivity to NER from Varanasi on NW-1 to Kolkata/Haldia to NW-2 & NW-16 through Indo-Bangladesh Protocol Route.

IWAI approved the proposal of development of Fairway near berthing area and excess channel of Haldia Multi-Modal Terminal through Shyama Prasad Mookerjee Port Authority, Kolkata. This will enhance the trade potential in the region, especially EXIM Trade with Bangladesh.

IWAI also decided to procure 5 Amphibian Dredgers to provide requisite depth near the 60 Community Jetties developed along NW-1 (Ganges) in the States of UP, Bihar, Jharkhand & West Bengal. These jetties will be utilised by the local communities for their day-to-day movement along with movement of their cargo to nearby markets.

The proposal to engage Indian Port Rail & Ropeway Corporation Ltd. (IPRCL) for providing Rail connectivity to Multi-Modal Terminal at Varanasi, Sahibganj & Haldia was also approved. This will ensure modal shift of cargo 'to IWT and full utilisation of these Terminals.

In accordance with the commitment of the Government to reduce carbon footprints, first Hydrogen Fuel Vessel has been introduced in Varanasi. IWAI is in the process to procure more such vessels. To generate and provide green fuel to these vessels, it was decided to engage Sagarmala Development Co. Ltd., a PSU under MoPSW, to set up a Hydrogen Plant, Storage & Dispensation facility at MMT, Varanasi.

With the enhancement of NWs from existing 5 to 111 in Yr 2016, there was a long-felt requirement to re-structure IWAI in keeping with the operational requirements. The Board decided to engage National Institute for Smart Government for re-structuring of IWAI. This shall augment the operational efficiency and Human Resource capabilities of IWAI to undertake necessary developmental projects along all National Waterways.

MUNICIPAL CORPORATION MANESAR

पब्लिक नोटिस

नगर निगम मानेसर के गांवों की आबादी देह/लाल डोरा स्थित सम्पत्ति मालिकों को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि लाल डोरा के अन्दर पड़ने वाली सम्पत्तियों का डाटा जो कि सर्वे के दौरान प्राप्त हुआ था, को नगर निगम मानेसर की वैब–साइट **ulbharyana.gov.in** पर दिनांक **23-07-2024** को अपलोड कर दिया गया है। इन सम्पत्तियों के डाटा में वर्णित नाम,पता, ऐरिया, उपयोग तथा मोबाइल नम्बर व अन्य किसी तथ्य पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो **ulbharyana.gov.in** पोर्टल पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, जिसको निपटान हेतू संबंधित गांव की वार्ड कमेटी के समक्ष मामला रखा जायेगा और उसका निपटान वार्ड कमेटी द्वारा नियमानुसार किया जायेगा। अतः ऐसे सभी दावाकर्ताओं को इस नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है कि वे अपने–अपने दावे तथा आपत्तियां दिनांक **22-08-2024** तक पोर्टल पर दर्ज करवा सकते हैं।

आयुक्त
नगर निगम,मानेसर।

SEARCH FOR MISSING BOY



General public is here by informed that one boy (depicted in the Photo) **Namely:** Azhaan Akhtar **S/o:** Sh. Khalid Akhtar, **R/o-** L-58 Venus Apartment Abul Fazal Enclave Part-1 Shaheen Bagh Delhi **Age:** 19 Years, **Height:** 5'5", **Complexion:** Fair, **Face:** Round, **Built:** Normal, **Wearing:** Black Color T-Shirt & Grey Track Pant & Gray Color Slipper In Feet Missing Since 21.06.2024 by 10.00 AM from last seen at the shop under area of P.S Shaheen Bagh, Delhi.
In this regard a **FIR No. 194/2024 U/s 365 IPC dated 15.07.2024** has been registered at P.S. Shaheen Bagh, Delhi.
Sincere efforts have been made by local police to trace out information about this person but no clue has come to light so far.
Any person having any information or clue about this person kindly inform to the following.

SHO
P.S.- Shaheen Bagh, Delhi
Ph. 011-26940691, 8750870926
E-Mail: cic@cbi.gov.in
Website: http://cbi.nic.in
Ph: 011-24368638, 9667341024
DP/9383/SE/2024

UPDCC

Office of DGM-01, PIU Song Dam, UPDCC Ltd.
Ground Floor, Lakhwad Field Hostel,
Yamuna Colony, Dehradun-248001
E-Mail ID: songproject.gm@gmail.com

National Competitive Bidding
e-Tender Notice

Office of the DGM-01 (Civil), Song Dam Project, UPDCC Limited (A Govt. of Uttarakhand Construction Corporation), Yamuna Colony (Dehradun), invites online bids from interested parties. Brief summary of bid is given as below:

Owner's Engineer & Project Management Consultancy Services for Dam Contract, Construction and Quality Control of Song Dam Drinking Water Project, Dehradun, Uttarakhand
Bid Identification No:02/DGM-01/PIUS/UPDCC/2024-25

Bid Security (in lacs)	64.86
Date of availability of bid document on website	24.07.2024 11:00 AM onwards
Date of Pre-Bid Meeting	27.07.2024 12:00 PM onwards
Last date for submission of bids on website	07.08.2024 till 03:00 PM
Date of opening of Technical Bids	08.08.2024 3:00 PM

For full & further details, kindly visit e-procurement portal **"http://uktenders.gov.in"**

Deputy General Manager-01 (Civil)

The Hindustan Times
ESTABLISHED IN 1924

{ OUR TAKE }

Continuity and employment

Budget retains welfare-with-prudence focus. Govt heeds electoral lesson on need for jobs

Ahead of Budget 2024, the big question was whether the Bharatiya Janata Party's (BJP) sub-par performance in the summer's national election would push the government into unveiling a populist budget, especially with assembly elections due in Maharashtra, Haryana, and Jharkhand later this year. The budget presented by finance minister (FM) Nirmala Sitharaman has answered this question in the negative by shunning populism in favour of the government's templated approach of welfarism, reforms, and fiscal prudence, but, despite the length of the FM's speech — it was her second shortest budget speech after her speech while presenting the interim budget on February 1 this year — still sought to create a positive political narrative, a big theme that touches lives, make a real difference, and which the government can speak about.

The big theme of Budget 2024 is jobs, or employment. Mrs Sitharaman announced a bouquet of five schemes, with an aggregate spend of around ₹2 lakh crore, aimed at incentivising companies to create jobs, and at training young people to be ready for jobs (including an apprenticeship programme that can expose young people to the biggest and the best companies in the country). Irrespective of data, it was clear that India was not creating as many jobs as it needed, nor providing young people with the required skills to be employable, and this is perhaps the first budget to attempt to solve both problems, and in scale. Much (as it always does) will depend on the implementation, but this is, on paper, exactly the kind of intervention the most populous country in the world (and also the one with the largest working-class population, a distinction India will hold till 2049) needs. It is also a more productive response to the angst that was perhaps responsible for the BJP's performance in the Lok Sabha elections; after all, more jobs is exactly what India needs at the moment. But the BJP's choice of employment as its big theme for the budget suggests that it also believes it can build a political narrative around it. To be sure, there are other things it can do between now and the elections that could also help — for instance, in the case of Haryana, a tweak in the Agniveer recruitment scheme for the armed forces.

There are other political exigencies that the budget has responded to more traditionally. With the BJP dependant on Andhra Pradesh's Telugu Desam Party, and Bihar's Janata Dal (United) — both are senior partners in the respective National Democratic Alliance governments in the two states — for its majority in the Lok Sabha, it was a given that the budget would announce a package of some sort for both. It has done just that, with an emphasis on infrastructure, and the first reactions of the two partners indicates that they are satisfied, at least for the moment. That should remove any question marks (if indeed, any existed) over the stability of the BJP-led NDA government.

The budget has generated a lot of conversation around taxes; it has made more changes in direct and indirect ones (the duty inversion in customs duties of several products has been addressed, making local manufacturing more competitive) than many budgets in recent years. Stock market investors are unhappy about the increase in long term capital gains tax to 12.5% from 10%; and real estate investors are happy at the reduction in the same tax from 20% to 12.5%, but unhappy that the benefits of indexation (it increased the acquisition value of the asset by taking inflation into account) have been scrapped; and some middle-class taxpayers who have opted to be taxed under the new tax regime are cheering the slight changes in the definition of income slabs, and the increase in standard deduction, but there is a larger message behind these changes in taxes. Read along with the FM's statement that suggests that a new direct tax code is in the works (or will soon go into the works), there is clearly a move towards simplification of the tax framework.

And, finally, the economics of the budget show that the government has, in reality, not moved away from its established template. This is not a contractionary budget, so the focus on welfarism continues; as does the emphasis on capital expenditure (it remains at 3.4% of GDP). But neither has come at the cost of busting the bank. The budgeted fiscal deficit, at 4.9% (lower than the 5.1% mentioned in the interim budget) is a sign of fiscal prudence and macroeconomic stability that has become characteristic of the Indian economy under this government. Continuity is good, as long as the jobs get created.

The Indian middle class expected more

Continuity, capex, jobs and capital gains taxes lie at the heart of this year's Budget



The worry of economists that India is in a phase of jobless growth found place in the budget that had a slew of proposals to boost jobs ANI


Monika Halan

Budget 2024 came at a rare moment in the history of Indian budgets. Tax revenues are up, bank and corporate balance sheets are cleaned up, reserves are looking good and a surprise bonus from the Reserve Bank of India has bolstered the ability of the government to spend without compromising the fiscal consolidation process. But there are two clouds on the horizon — slowing consumption growth and tepid private sector investment. There was a third issue in front of the government — the middle class wanted a break from the increased taxation it has faced over the years. While Budget 2024 has not addressed all these issues to everybody's satisfaction, it has started the walk on the path that does.

The lower end of the middle class has got a tax break with the tax slabs and standard deduction going up in the new tax regime. Slab levels are up by a lakh up to the ₹12 lakh slab level. Standard deduction is up from ₹50,000 to ₹75,000. The total benefit of these changes is a maximum of ₹17,500 for the taxpayer. The old tax regime under which people can claim a multitude of deductions saw no change.

The big changes have been in the capital gains space. Capital gains, or profits from assets, are taxed differently depending on how you hold and for how long you hold them. It is messy and complicated. A promise has been made to clean it up and the direction seems to have been set. As suggested in an earlier column in these pages *(https://www.hindustantimes.com/opinion/eat-the-rich-but-do-it-in-a-logical-way-101719846246923.html)*, the direction is to standardise the rates and the holding periods eventually. In this process, listed stocks and equity mutual funds have been hit by an increase in both the short- and long-term capital gains tax which now stand at 20% and 12.5%, up from 15% and 10%, respectively. Looking out for the small investor, the tax-exempt profit has been hiked from ₹1 lakh to ₹1.25 lakh in a year.

Real estate has both won and lost. Its long-term rate has dropped from 20% to 12.5%, but it has lost the indexation benefit. Indexation allows the investor to inflation-adjust the buying price thereby reducing the profit and hence the taxation. Debt fund profits continue to be taxed at slab rate but there is a window till April 1, 2026, to rethink this and standardise the rates with other asset classes.

The government and regulators are worried about the runaway futures and options (F&O) market that might be causing the tail to wag the dog. The worry is that large hedge funds with smart algorithms and technology are earning millions of dollars sitting outside the country at the cost of the tiny Indian retail investor who sees the F&O market as a casino and is losing money.

The securities transaction tax (STT) has been hiked on both futures and options to dampen the interest. More steps are awaited from the Securities and Exchange Board of India to put in place a framework that is fair and discourages investors from unsuitable products while allowing the F&O market to hedge the risks as is its primary mandate.

The worry of economists that India is in a phase of jobless growth found place in the budget that had a slew of proposals to boost jobs. Mostly aimed at first time workers, the government is willing to spend money to move people into formal employment as reflected in the Employees Provident Fund Organisation (EPFO) employment numbers. But there are lots of hoops to jump through before this money will be given. One of which is that the employee must go through a financial literacy course before she can claim the next instalment of a promised handout! Another route is to nudge the top 500 companies to hire interns for a year with the government paying for most of the cost, with the cost of training and 10% of the stipend coming from the firm's Corporate Social Responsibility money. This is a voluntary scheme for companies. It might be a good idea for those firms who find it difficult to get skilled workers — an incentive scheme like this might allow them the runway to find, train and then hire these workers.

From 35,000 feet, the Budget 2024 story is this: The government will continue to tax the top 10% of the population heavily. It will tax assets and income and luxury goods and services. Despite a big middle class push this year for tax breaks, the government has not blinked — it might pay a political price, but that is five years later. The government is going to continue on the prudent path of sensible borrowing — this means keeping deficits gliding down and spending borrowed money largely on capital investment.

It has taken note of the issue of jobs and is trying to incentivise the private sector to hire more and the workers to go to work. So, the big picture looks good, but it is the details that will tell the real story.

Monika Halan is the author of the Let's Talk Money book series. The views expressed are personal

The elusive quest for jobs in Viksit Bharat

"We particularly focus on employment, skilling, MSMEs". Finance minister (FM) Nirmala Sitharaman's opening statement, as she presented the first full budget of the newly elected government, clearly indicates that, Prime Minister (PM) Narendra Modi and his government have finally acknowledged that without quality jobs, the path to Viksit Bharat will remain elusive. But in its prescriptions, the budget lays bare the unresolved tensions in economic policy making that brought us to such a pass. These tensions may not be new, but they have sharpened in the last decade. And this budget offers little by way of solutions.

The first is the formal versus informal economy, and the role of government in enabling transition pathways for better quality jobs. The Economic Survey highlights that corporate profits have nearly quadrupled between FY20 and FY23. In sharp contrast, the recently released Annual Survey on Unincorporated Sector Enterprises for roughly the same period, shows a decline in the growth of enterprises in manufacturing, and with it, a decline in employment, from 2015-16. These two contrasting facts highlight the reality of India's growth model — a model that favoured growth via the small formal, corporate sector, leaving unincorporated enterprises that make up the informal economy, where the bulk of India is employed, to bleed. This is India's K-shaped economy — actively facilitated by policy missteps of the last decade from demonetisation to the Covid lockdowns, which exacerbated the jobs challenge.


Yamini Aiyar

The budget's big ticket interventions — the Employment Linked Incentive (ELI) schemes, the internship programme and skilling — taken on their face value may well be reasonable interventions. But like previous budgets of the Modi government, they cater to the formal sector — the ELI incentives are linked to EPFO, the internships are in 500 top companies — leaving unaddressed the vast informal economy where the real distress is. Not only does the budget ignore distress in the informal sector, it also doesn't recognise the need to devise transition pathways to formalisation in the long term. Nothing has been learnt from the havoc caused by forced formalisation of the last decade. Rather than a policy road map and transition pathways, we got new schemes and some political squabbling over who owns the idea, the Congress or the Bharatiya Janata Party!

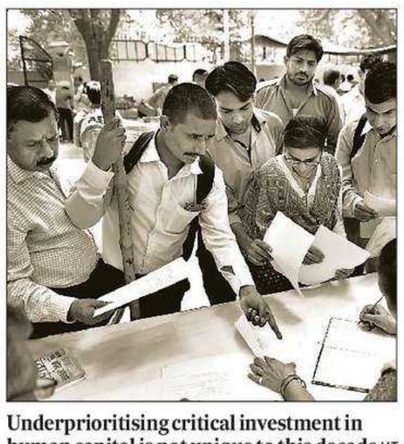
Two important elements of such a road map did find mention in the budget: MSME's and urbanisation. For MSMEs, there is old wine in the form of credit guarantees and factor market reforms. And for the urban transition, housing (Pradhan Mantri Awas Yojana allocations increased by 18% over FY23 revised estimates) is prioritised along with a commitment to develop cities as growth hubs. But, as economist Amit Basole reminds us, the binding constraint for MSME growth is poor quality infrastructure, particularly in the small and census towns (local roads not highways, transport, power). This reality has been forgotten in the rush to formalise via blunt policy instruments, including those deployed in the proposed ELI. To get there, we needed a new policy imagination. One that, as Basole argues, prioritises capital expenditure for local roads and railways rather than highways and Vande Bharat. Moreover, we need to refocus social policy such that it addresses vulnerabilities of urban workers, including via an urban employment guarantee and enhanced portability of safety-nets like cash transfers. None of this is on the agenda.

The second tension relates to welfare policy. This budget offers no directional change. Allocations for key welfare schemes remain stagnant, as they did in the interim budget. Its welfarist stance notwithstanding, the Modi government, in its successive avatars, has been a conservative welfare spender. Between 2015-16 and 2024-25, social sector spending as a proportion of total government expenditure fell from 23% to 19%. Fiscal space for Modi ki Guarantee was squeezed out of health, education, and nutrition.

Underprioritising critical investments in human capital is not unique to this last decade. However, technology created a new site of tension between human capital and cash transfer. DBT-based transfers sold as "guarantees" are far more visible and therefore electorally salient than investments in the public system needed for delivering health and education. Indeed, Samgra Shiksha, the flagship scheme for school education, saw a slight drop in allocation over the interim budget. The windfall from the Reserve Bank of India could have been used effectively, but that requires a policy imagination that goes beyond tinkering with deficit targets. We will continue on the path of skilling on the back of an education system where 50% children in standard 5 can barely read a standard 2 text!

The third is Centre-state tensions. In the Economic Survey and budget speech, the need to work in coordination with states to achieve the next generation of reforms found repeated mention. However, this requires a commitment to federalism, missing in this government's DNA. The ruling parties in Bihar and Andhra Pradesh extracted their pounds of flesh, but that is the price of coalition politics. For the rest, devolution to states as a percentage of gross tax revenue is stuck at 33%, a far cry from the 15th Finance Commission recommendation of 41%. There remains no foundation for cooperative, competitive federalism, and the blame game will continue

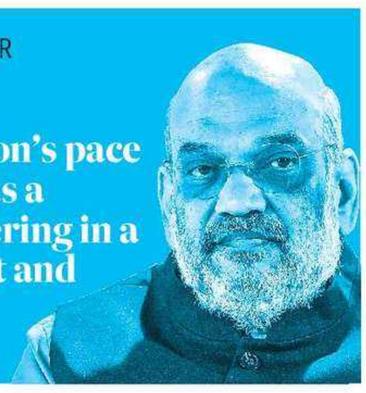
In her speech, the FM promised to formulate an economic policy framework. But if this framework continues to paper over the challenges, and refuses to confront the role that policy missteps of the last decade played in exacerbating the jobs challenge, we will get an economy that will continue to hobble, stuck in a K-shaped Viksit Bharat.


Underprioritising critical investment in human capital is not unique to this decade HT

Yamini Aiyar will be a visiting senior fellow at Brown University from 2024-25. The views expressed are personal

{ AMIT SHAH } UNION HOME MINISTER

The budget fuels the nation's pace on the path of emerging as a developed nation by ushering in a new era of employment and opportunities



The budget echoes the Developed India vision

Finance minister Nirmala Sitharaman has meticulously assessed India's economic vitality. Her seventh consecutive budget demonstrates this amply. There is a marked focus on uplifting the disadvantaged sections, including the poor, women, youth, and farmers.

Budget 2024 unveiled a comprehensive strategy built on nine foundational pillars — agriculture, employment, inclusive development, manufacturing and services, urban development, energy, infrastructure, innovation/research and development, and next-gen reforms. These pillars will serve as guiding principles aimed at fostering broad-based opportunities and sustainable progress across the country.

Central to the budget's agenda is the enhancement of agricultural productivity and resilience to achieve $100 billion from agricultural exports. A significant allocation of ₹1.52 lakh crore has been made to the agriculture and allied sectors, underscoring the government's commitment to modernising farming practices and bolstering rural economies. The budget introduces three pivotal employment schemes linked to enrolment in the Employee Provident Fund Organisation (EPFO). These initiatives include a Direct Benefit Transfer equivalent to one-month salary for first-time employees (up to ₹15,000), incentives for manufacturing job creation, and employer subsidies on EPFO contributions for additional employees over a two-year period.


Nilesh Shah

Youth empowerment and skill development feature prominently among the budget's initiatives, with provisions for subsidised education loans up to ₹10 lakh and a 3% interest subvention for higher education (only for domestic institutions). Furthermore, internship programmes have been launched to bridge the gap between academic learning and practical skills, enhancing employability across diverse sectors.

Small and medium enterprises (MSMEs), particularly those in labour-intensive manufacturing, receive targeted support. The budget raises the Mudra loan limit to ₹20 lakh for entrepreneurs who have successfully repaid loans under the Tarun category, aiming to stimulate entrepreneurship and economic resilience.

Under the PM Awas Yojana Urban 2.0, ₹10 lakh crore has been earmarked for addressing the housing needs of one crore urban poor and middle class families. Additionally, reducing the stamp duty for properties purchased by women is aimed at empowering them economically and socially. This will help inculcate a sense of security among the women of the country, which may appear small but is a very important step, from the point of view of furthering social progress. Infrastructure development, crucial for economic growth, retains a substantial allocation, of ₹11.11 lakh crore or equivalent to 3.4% of the GDP.

The budget also emphasises enhancing tourism infrastructure. Tourism will act as a catalyst in overall development of the economy as it will support local entrepreneurs; developing good roads, air connectivity and allied infra shall boost activity. This is expected to create jobs at the grassroots level.

The states of Bihar and Andhra Pradesh were the biggest beneficiaries in terms of development initiatives and infrastructure projects; hence, they may attract tourists from around the globe. Foreign tourists shall also help bring in much-desired forex flows, helping narrow the current account deficit. The budget also prioritises rationalising taxation policies to simplify compliance and reduce litigation. This budget has tried to rationalise tax rates with an increase in standard deduction for salaried employees, and benefits in tax slab in new tax regime.

The budget aimed at standardising the definition of long-term and short-term assets across various asset classes. It has tried to standardise the long-term capital gains (LTCG) tax at 12.5% and the short-term capital gains tax at 20%. However, the indexation benefit, that allows for inflation adjustment, has been removed from LTCG computation.

The budget has simplified the tax system to a large extent and also tried to reduce the tax burden on an overall basis. However, there is a marginal increase in equity tax. The reduction in import duty on gold and silver to 6% will make the imports cheap and is seen as a welcome move by the consumers.

Social security benefits are strengthened through increased deductions for National Pension System (NPS) contributions, incentivising savings and ensuring financial security for employees across private and public sectors. This move is expected to attract sustainable investments in debt and equity markets, fostering long-term economic growth.

In conclusion, the Union Budget for this fiscal presents a holistic approach to economic development, balancing fiscal prudence with targeted interventions for inclusive growth. By addressing various facets of the economy and prioritising social welfare, the budget sets a bold trajectory towards a prosperous and resilient India, echoing the vision of Viksit Bharat by 2047.

Nilesh Shah is managing director, Kotak Mahindra Asset Management. The views expressed are personal

R. N. I. No. 503/1957 ● Postal Reg. No. DL(ND)-11/6058/2018-19-20 'Licensed to post without prepayment' LICENCE No. U(C)-113/2006-08, AIR SURCHARGE: Raipur and beyond by Rail or Road - Re 5/-, Ahmedabad, Bangalore, Coimbatore, Chennai, Cochin, Goa, Hyderabad, Khajuraho, Mumbai, Trivandrum, Visakhapatnam, Vijayawada and beyond by Rail or Road - Rs. 10/-;

PRINTED & PUBLISHED BY MANHAR KAPOOR for and on behalf of HT Media Ltd. 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001 and printed at HT Media Ltd. Presses at Plot No.-8, Udyog Vihar, Greater Noida, Distt. Gautam Budh Nagar. (UP). Pin-201306.
BOARD: (011)23361234 ● EDITORIAL: (011)66561234 Extn. 1254, 1268 ● CIRCULATION: (011)66561111 ● ADVERTISING: (011)66561389 ● FAX: (011)66561270.

EDITOR: KUNAL PRADHAN

Moving forward with nine levers of growth

Budget 2024 lays the ground for delivering on the promises of progress made to all Indians, sans any differentiation

The New York Times, long considered a cheerleader of the select global club sceptical of India's exponential phy-gital (physical and digital) capabilities build-up in recent years, acknowledged the same, writing in late June how "positive vibes" from India are making it a preferred destination for marquee American and European conglomerates, accentuating a clear shift away from mainland China.

The budget presented on Tuesday, a record seventh (including February's interim budget) for the current finance minister, cements the idea of competitive capacity and capability building through putting in place nine enablers or levers that ensure the incremental centricity of the country in the rapidly changing global production and supply chain ecosystem. It does this by focussing on relevant skill sets, enhancing female participation in the workforce while formalising the labour force, simultaneously anchoring upliftment of MSMEs and boosting capex and education. It also seeks the rationalisation of taxes with long-term imperative, which has the potential to structurally change the way financialisation benefits both savers and users without being susceptible to shocks embedded in the global financial system.

Given the change in food intake/nutrition habits with rising income and education levels, the announcements with regards to usage of digital public infrastructure (DPI) to include the holdings of 60 million farmers in digital registries can revolutionise the delivery of agri-credit and strengthen market infrastructure through loops of forward and backward linkages. Additionally, digital crop surveys and creating clusters of vegetable production near major consumption centres can blunt volatility in key inflation components. Self-sufficiency in oil seed production will further reduce imports while stability on the pulses front, along with a nudge to farmers on adopting natural farming practices, augurs well.



Soumya Kanti Ghosh

However, for agriculture to become sustainable, policy makers and regulators would do well to revisit the recommendations of the committee on Agri Value Chain Financing headed by C S Shetty of the State Bank of India, to enable the desired transition. The report was submitted in 2021 and is still awaiting implementation.

The three-pronged approach to enhance formalisation of employment generation, through incentivising all stakeholders, should upend the changing labour landscape, while ensuring benefits are reaped over a long term, most handsomely by those who are fresh entrants to the country's job markets.

Increasing participation of women, apart from helping the cause of gender diversity, should broaden the skill sets of the entire workforce. A great example is the country's flourishing self help group (SHG) landscape, which shows how enhanced market access at the local level can work wonders for strengthening the rural economy in particular. Financing skills acquisition through a guaranteed loan, as also financial support through e-vouchers for education loans, are both good schemes.

Bringing a clutch of resource-rich eastern states into the mainframe through targeted corridor development schemes augurs well for a holistic vision of national development. MSMEs, which have a pivotal role in India's ascent to developed nation status by 2047, will be benefitting significantly through the guarantee scheme for the purchase of machinery and equipment without collateral/third-party guarantee up to ₹100 crore, while usage of alternative data viz. tax and other digital footprints for delivering in-time and just credit (initiated by SBI last month) can be a game changer given rising integration with platform-based initiatives such as OCEN and ONDC that promise to democratise the existing architecture. They will also benefit from the enhanced latitude of TReDS platform, dedicated coverage of MSME clusters through localised SIDBI branches, and creation of e-commerce export hubs in the PPP mode.

On the taxation front, the intent of the government is noteworthy as it has taken bold initiatives to smoothen asymmetries in taxation of various asset classes.

However, some clarification is needed on taxation aspects of capital gains from non-financial assets, notably ancestral properties where indexation and grandfathering benefits seem fair for genuine cases. While the proposed taxation ensures that end usage of funds will be assured across same asset classes transfer, to leverage the tax benefits and discourage cross-usage of gains for speculative purposes (also bolstered by higher taxation on F&O), there is also a possibility of increased usage of cash in real estate transactions.



Digital crop surveys and creating clusters of vegetable and fruit production near major consumption centres, as the budget has proposed, can blunt volatility in key inflation components PTI

Further, there is a genuine need to offer tax incentives to bank deposits to keep them competitive. Currently, bank deposits are subject to taxation of interest income at accrual level, and we must appreciate that banks in India largely fund themselves through retail deposits rather than wholesale funding as seen in other regions (which has been a clear and frequent source of contagion). Clearly, banks which are the custodians of large deposit franchise in the country, deserve better. India has limited social security and interest from bank deposits are often used by senior citizens for offsetting consumption expenditure. The good thing about an increase in capital gains tax could be a temporary interest in bank deposits in the interregnum, but that could fizzle out soon sans structural optimal parity.

Finally, adhering to the path of sound fiscal management, fiscal deficit for FY25 is estimated at the 4.9% of GDP as against 5.8% of GDP in revised estimate of FY24. The nominal GDP for FY25 is estimated at ₹326 lakh crore, a 10.5% growth over FY24. With RBI growth projections at 7.2% for FY25 (SBI's 7.5%), we believe that this is a conservative estimate. In such a case, the budget numbers could throw up a positive surprise at the end of the fiscal. We believe that cost of borrowing of the government is likely to decline as budgeted borrowing numbers are lower than FY24 estimates by ₹20,000 crore.

To sum up, this is a budget that lays the groundwork to deliver on promises that benefit each and every Indian, sans any differentiation. Therein lies its simple magic.

Soumya Kanti Ghosh is group chief economic advisor, State Bank of India, and member, 16th Finance Commission. The views expressed are personal

Mobilising forces for Viksit Bharat, with a focus on productivity and employment

Finance Minister Nirmala Sitharaman's seventh budget articulates a bold, even radical vision for sustaining India's fast growth in an uncertain world. At its heart are measures to make the best use of India's demographic dividend, which is what lies at the core of India's vision of its Amrit Kaal, the centenary of its Independence. The most visible dimensions of this strategy are the multiple initiatives in the budget to stimulate employment in the formal sector. This is rightly seen as the most reliable way to boost labour productivity.

Equally significant, though less prominent, is a fundamental repositioning of the role to be played by the private sector in all its dimensions: farmers, MSMEs, Self Help Groups (SHGs), the large scale corporate sector, and foreign multi-nationals. They represent the demand side of the labour market and have an equally important role to play. Given the sheer scale and diversity of India's potential labour force, new institutions to match demand and supply are also being devised.

India has maintained a long-term average growth rate of 6% for three decades since the 1991 reforms. With slowing population growth, per capita growth has been even stronger. This impressive rate of sustained growth over the last few decades speaks of the maturity of institutions and decision-making structures, which express themselves in rising productivity — what economists call supply-side growth. India's Gross National Income (GNI) per capita for 2023, as reported by the World Bank, is $2,540, which places it firmly in the lower middle-income category. A country that is just above the World Bank's high-income threshold of $14,005 is Chile with a reported Gross National Income per capita of $15,820. The challenge for India is to prepare itself for the transition to middle-income status ($4,516 by World Bank metrics) and to keep growing fast as a middle-income country, as China and Korea have before it.



Suman Bery

This is an ambitious goal, and there is no sure way to plan for a 25-year horizon: There are too many uncertainties. Yet private investors, both domestic and foreign, do need long-term guidance. Also, in a democracy, a given Parliament cannot bind its successors. What can reasonably be done is to announce broad directions of policy, enshrine these in legislation and aim for a few early wins in an effort to establish momentum.

Commendably, employment incentives and skilling are at the core of the budget. Three schemes for employment generation are part of the package that, for the first time, includes a wage subsidy for new entrants. To further push the agenda of women-led development and to improve the female labour force participation, several notable initiatives including setting up of working women hostels, establishing creches, organising women-specific skilling programmes and promoting market access for women led SHGs/enterprises, are laid out in the budget.

Preparing the labour force to be more productive has no point without a receptive private sector. The budget reimagines the private sector in a comprehensive manner, recognising the equal importance, not only of large scale corporate but also start-ups, farmers and MSMEs. To this end, the budget incorporates relevant measures to bolster the health of agricultural sector and MSMEs. The strategies to attain *atmanirbharta* for oil seeds and pulses and creation of large-scale clusters for vegetable production close to major consumption centres, all by acknowledging the role of Farmer Producer Organisations (FPOs), cooperatives and start ups, is reflective of this.

The commitment to review the direct tax code could also make an enormous difference to ease of doing business. Underlying these policies are two deeper shifts. First, the lead on investment will shift from the public to private sector with the government playing a facilitating role. An important example in the budget is the commitment to allow the private sector into the nuclear power sector, as well as the development of a taxonomy for green investment. Also relevant is the commitment for a vision for the financial sector which can mobilise long term resources for India's investment requirements.

As the third largest economy in the world, India will inevitably get deeply engaged with the world economy. What India enjoys is scale. This budget seeks to harness underutilised domestic resources and capabilities to establish a virtuous cycle of rising productivity, increased savings and lower cost of capital. This strategy will become clearer in the course of the year as various policy papers are finalised, but the direction of change is obvious and welcome. The job-rich growth strategy should innovate itself to be inclusive, but historic, geographic and social circumstances will remain pervasive for some time to come. Successful programmes such as the Aspirational Districts Program and the most recent Aspirational Blocks Program will continue to play an important role. It would be ideal if the lessons from these new skilling initiatives could in time be brought into these schemes as well.

Suman Bery is vice-chairman, NITI Aayog. The views expressed are personal

Budget 2024's botched borrowing of ideas leaves India without the impetus it needs

The Union Budget is not merely a statement of accounts — it is a declaration of the nation's economic priorities. By this yardstick, this budget reflects poorly on the Narendra Modi-led government and bodes ill for India's political and economic future.

The budget highlighted the government's preference for politicking over nation-building. States where the National Democratic Alliance did well in the Lok Sabha Elections — Andhra Pradesh and Bihar — were massively preferred over states where the Opposition did well, e.g., Maharashtra and Haryana. Natural calamity relief flows to Bihar, Assam, Sikkim and Uttarakhand, all NDA-ruled; only Congress-ruled Himachal Pradesh is the exception. The government's duty is to provide support to all of India based on objective criteria rather than to single out states where it is in power.

The budget speech made no mention of the Railways. At a time when there have been several tragic incidents and railway services are in shambles, this should have been top priority.

Rural India did not get its due. MGNREGA's budget has remained stagnant at ₹86,000 crore despite huge demand for work, indicating significant unemployment and economic distress. Allocations for crop insurance and urea subsidy have been reduced. Agriculture's share in the overall budget has declined from 4.97% in 2019-20 to 2.74% in 2024-25. Lofty commitments such as extending natural farming to 10 million farmers and using digital public infrastructure for agriculture are hardly likely to yield substantial, tangible results. The Prime Minister (PM)'s promise of doubling farmers' incomes remains a distant dream.

A key budget priority is 'Inclusive Human Resources Development.' Yet welfare is glaringly neglected. The word "children" was not mentioned once. Health expenditure as a proportion of the GDP remains stagnant; the government is far from the goal of spending 2.5% of the GDP on health. Food subsidy has also been reduced.



Rajeev Gowda

Skilling initiatives were highlighted. However, so far, various skilling initiatives have failed to deliver. There was no mention of primary or higher education in the budget speech. Sad, given that 3.5 million children dropped out in the academic year 2021-22. Without investing in social welfare and human development, how is the government to transform future generations, another of the budget's priorities?

The budget's most important achievement is that it signifies the return of unemployment as a focus of the government's policy making. Bizarrely, unemployment has been missing from the agenda for the last few years — it has rarely shown up in budget documents, the BJP's election manifestos, or the PM's speeches. The debacle of June 4 appears to have stirred the government to pay attention to this challenge.

Two key initiatives have been borrowed from the Congress's Nyay Patra for the 2024 Lok Sabha elections: the internship programme, and Employment Linked Incentives. Unsurprisingly, both have been adopted rather poorly.

The Nyay Patra envisioned a Pehli Naukri Pakki scheme, which guaranteed a year-long paid apprenticeship to all college graduates and diploma holders. The budget's internship programme, which promises to deliver internships to 10 million young people at 500 top companies over the next five years, is inspired by this idea. But it botches up the policy. Rather than make the scheme a universal guarantee for educated youth, it promises 10 million internships — simply for the gimmick value of the number. Similarly, rather than taking a comprehensive economy-wide approach, it needlessly limits itself to the top 500 companies. These top 500 companies are not the only ones who can provide quality apprenticeships — nor are they the ones actually in need of interns. Further, allowing firms to redirect Corporate Social Responsibility (CSR) funds towards partial funding of internships will save the government some funds, but it detracts from those corporations' other responsibilities to society. Employment Linked Incentives were also proposed in the Nyay Patra 2024, as a way for "corporates to win tax credits for additional hiring against regular, quality jobs."

The budget adopts the idea, but rather than delivering ELIs through tax credits, delivers them through reimbursements for EPFO contributions. This delivery mechanism is effectively a subsidy on wages for these employed workers. Employment-linked rebates on taxes — rather than the blanket corporate tax cuts which were announced a few years ago and failed to deliver investment or jobs — would have been a more compelling incentive for firm owners and proprietors to expand hiring.

The middle class did not get much of a respite. The budget only tinkers with and has made no major changes to the income tax slabs. This ignores the increasing inflation burden faced by the average taxpayer over the last decade. Removal of indexation is an unnecessary intervention that will hurt millions of families who invested in real estate assets over the years.

There are a few silver linings. The scrapping of the angel tax will help our start-ups. Unachievable disinvestment targets were left out. Rhetorically, MSMEs have returned to the government's agenda.

Overall, this budget can be termed a *kursi bachao* budget and a Congress manifesto "copy-paste". It shows that the Modi government has again failed to put its finger on the pulse of Indians who are hurting. It is a massive let down from a government that is running out of steam.

Rajeev Gowda is a former member of Parliament, and chair, AICC Research Department The views expressed are personal

A missed opportunity on kickstarting farm reform

In a departure from earlier years, finance minister Nirmala Sitharaman acknowledged the importance of agriculture for the rural economy, inflation (management) and the country's food security at the beginning of her speech. She did well to highlight the urgent need to develop climate-resistant varieties of seeds, touching upon the importance of driving agri-productivity and resilience. The Economic Survey for 2023-24, too, highlighted the contradictions and challenges confronting the agriculture sector, underscoring the threat of the climate crisis. One would be forgiven for assuming such concerns indicated a reforms push. Serious reforms in the agri-food sector have been debated for a long time. But the government led by Prime Minister Narendra Modi has barely made any progress, even in important areas such as fertiliser subsidy, seamless movement of agri-produce across the states, and crop diversification in Punjab and Haryana.



Budget 2024 did little to stem the backsliding of liberalisation in some areas of the agri-economy REUTERS

Budget 2024 too has failed to present a road map for such reforms. The government may have realised that it needs to take the states on board and reach a consensus before it can do this.



Siraj Hussain



Shweta Saini

Liberalisation in some areas of the agriculture and food economy has taken a backward step. For instance, the export of wheat, rice, sugar and onions is almost fully canalised through National Cooperative Export Limited (NCEL), and only cooperatives are eligible to supply to NCEL. This is similar to the United Progressive Alliance (UPA) government's policy of canalisation of wheat and rice export through Public Sector Undertakings such as the STC, PEC, and MMTC. The budget says nothing about engaging with private trade for export of agricultural produce.

Even the free movement of produce across states faces restrictions (from state governments) from time to time. At present, West Bengal traders are finding it hard to transport potato to other states. A central law for inter-state trade of agricultural produce is long overdue.

Compared to the interim budget, allocations to various agri-related ministries have changed marginally. The allocation to the department of agriculture has increased by ₹5,000 crore, primarily due to an additional ₹4,700 crore for Pradhan Mantri Annadata Aay SanraksHan Abhiyan (PM Aasha), the umbrella scheme for price support to farmers. It is good that the government realises that market forces alone can't give farmers a fair deal. It will be good if the money is utilised to procure pulses and oilseeds during peak arrival so that prices do not fall below the minimum support price (MSP). Due to a good monsoon, the sown area under pulses has gone up; so, the government must ensure prices do not crash. Distribution of pulses procured under PM Aasha has been allocated ₹300 crore.

The department of consumer affairs receives ₹10,000 crore for the Price Stabilisation Fund. This amount can be used to purchase an agri-commodity at MSP or an even higher price, if the government expects the price to rise. It is a good decision to provide such funds for the PSF, given only a token allocation was provided in the last two years.

There were expectations of investment in creating infrastructure for the Agricultural Produce and Livestock Market Committee (APMCs) so that farmers get access to better cleaning, grading and storage facilities. APMCs already have sufficient land and it is not difficult to create high-quality cold chain infrastructure within their premises. A private-public partnership (PPP) model could have been considered for this. It seems that the government has not yet made up its mind about the role it wants APMCs to play.

The allocation to the ministry of food processing industries remains unchanged at ₹3,290 crore. This is despite the realisation that if the losses in supply chain are to be reduced, more private investment is needed, especially in developing the cold chain.

The allocation to the department of agricultural research and education, the nodal department of the Indian Council of Agricultural Research (ICAR), has been increased by just ₹65 crore over the previous fiscal year. In fact, the budget for the ICAR headquarters has been reduced. This overhead takes care of, inter alia, the salaries of ICAR scientists and staff.

The allocation to the ministry of cooperation remains unchanged at ₹1,183.39 crore, as does the allocation to the department of food and public distribution at ₹213,019.75 crore. The budget retains the allocation of ₹450 crore made in the interim budget for an interest subvention scheme targeting sugar mills that enhances their ethanol production capacity.

A critical observation in the Economic Survey was that food gets very high weightage in the consumer price index, and the interventions of the Reserve Bank of India (RBI) to check inflation ultimately result in targeting food inflation. This results in lower prices received by farmers. The survey recommends that "India's inflation targeting framework should consider targeting inflation, excluding food" as higher food prices are very often not demand-induced but supply-induced.

If this recommendation is actually accepted, a rate cut may come sooner rather than later.

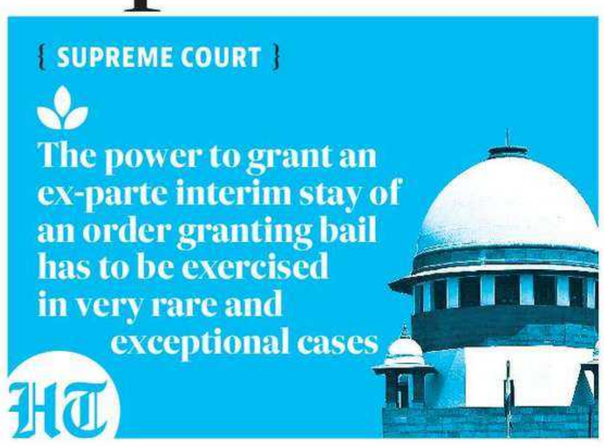
The Indian agriculture sector is in dire need of reforms. The budget sets the tone for this, but on actual impetus for such reforms, it leaves too much unaddressed for the agriculture minister to strategise, prioritise, design and implement.

Siraj Hussain is former agriculture secretary, GoI, and Shweta Saini is an agriculture economist and promoter of Arcus Policy Research. The views expressed are personal

'Can't stay bail casually': SC cites implications for liberty

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

{ SUPREME COURT }



NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday established stringent guidelines for staying bail orders, emphasising that such directives cannot be issued "casually" or "mechanically" because of their serious implications on human liberty.

"When a person is arrested, the rights guaranteed by Article 21 (life and liberty) of the Constitution of India get substantially curtailed. The effect of the grant of bail is that the liberty of the undertrial accused is restored pending the trial, subject to the accused complying with the conditions of bail. When the high court or sessions court stays such an order, it amounts to taking away the liberty granted under the order of bail," highlighted a bench of justices Abhay S Oka and Augustine George Masih.

The court stressed that high courts and sessions courts should be "very slow in granting drastic interim relief of stay of the order granting bail" owing to the severe implications of staying bail orders without substantial justification.

"The reason is that when an undertrial is ordered to be released on bail, his liberty is restored, which cannot be easily taken away for the asking. The undertrial is not a convict," it noted.

The court explained: "When a court finds the accused entitled to be enlarged on bail, unless the said order is set aside on the limited grounds of cancellation available under subsection (2) of Section 439 of CrPC or any other proceedings, the accused cannot be normally deprived of his right to liberty guaranteed under Article 21." The bench pointed out that an application for cancellation of bail does not become moot just because a stay is not granted immediately.

Authored by justice Oka, the landmark ruling underlined the importance of safeguarding the liberty of individuals and aimed to prevent the undue curtailment of this fundamental right during the judicial process.

The judgment set clear parameters for when and how courts can stay bail orders, mandating that an interim stay should only be issued in "very rare cases" where a "very strong prima facie case of the existence of grounds for cancellation of bail is made out". Illustrating the proposition with examples, the court referred to cases where bail is granted by a "very cryptic order without recording any reasons" or where there is evidence of the accused tampering with witnesses or misusing their liberty.

The court also outlined that in situations warranting a stay, the reasons for granting such an order must be explicitly recorded while also advising against granting ex-parte stays - orders given without hearing the other party- as a standard practice. "The power to grant an ex-parte interim stay of an order granting bail has to be exercised in very rare and exceptional cases where the situation demands the passing of such an order," it held.

This ruling has profound implications for judicial practice across India. By setting a high bar for staying bail orders, the Supreme Court aimed to balance the need for judicial oversight with the protection of individual liberty. It underscored that liberty, once granted, should not be taken away without compelling reasons and due process.

In the present case, an individual named Parvinder Singh Khurana was granted bail by a Delhi court on June 17, 2023, in connection with a money laundering case. After the Enforcement Directorate filed an appeal, the Delhi high court on June 23, 2023, stayed the bail order but did not give any reason. The bail order remained stayed for a year before a vacation bench in the Supreme Court stepped in on June 7 to direct that the accused will be released forthwith.

Setting aside the HC order that stayed Khurana's bail, the bench noted that the ex-parte order passed without considering merits cannot continue to operate for one year without Khurana getting a hearing on the issue.

"Whether such an approach violated the fundamental right to liberty of the appellant is a serious question we must ask ourselves. Except for stating that this is a sorry state of affairs, we cannot say anything further as we must show restraint...All courts have to be sensitive about the most important fundamental right conferred under our Constitution, which is the right to liberty under Article 21," it emphasised.

During the hearing of the matter on July 12, ED contended that staying bail orders was an established practice among several courts since the power to cancel bail would include the power to stay such orders. The submissions had prompted the bench to assert that the practice of casually staying bail orders is wrong, adding the top court will put an end to such a practice because of its "disastrous" implications for human liberty.

The top court's stance comes against the backdrop of a recent controversy involving Delhi chief minister Arvind Kejriwal, who is in judicial custody in connection with alleged illegalities in the framing of the 2021-22 excise policy.

On June 21, the Delhi HC stayed the bail granted to Kejriwal by a trial court in a money laundering case linked to the excise policy case.

{ JAMMU & KASHMIR }

Soldier killed as army thwarts infiltration bid

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com



Army personnel outside a hospital after a soldier was injured in an exchange of fire with terrorists in Poonch on Tuesday. PTI

JAMMU: A soldier was killed in a gunfight with terrorists as the army thwarted an infiltration bid along the Line of Control (LoC) in the Poonch district of Jammu, officials aware of the matter said on Tuesday, underscoring a spike in terror activities in the erstwhile peaceful region, which continues to be on the edge.

According to officials, security personnel noticed "suspicious" movement along the LoC in the Battal sector of Jammu & Kashmir in the early hours of Tuesday and opened fire.

"There was suspicious movement by two terrorists at around 3am. They were fired upon by the soldiers. However, Lance Naik Subhash Chander soldier suffered serious injuries in the exchange of fire. He later succumbed," an official said, requesting anonymity. A resident of Hathras in Uttar Pradesh, he was posted with the 7 Jat Regiment.

"All Ranks of White Knight Corps salute the supreme sacrifice of braveheart L/Nk Subhash Chander, who laid down his life in the line of duty. White Knight Corps offers deepest condolences and stands firm with the bereaved family in this hour of grief," the White Knight Corps posted on X.

There has been around a dozen infiltration attempt in Jammu since January this year amid a spate of terror attacks, raising concerns over the region emerging as the new hub of violence, where tens of thousands of people have died in extremist attacks since the 1990s.

The gunfight broke out a day after terrorists attempted separate attacks on an army post and the house of a Village Defence Group in Rajouri district. The surge in terror strikes in Jammu & Kashmir in recent weeks was discussed at a meeting of the crucial Cabinet Committee on Security chaired by Prime Minister Narendra Modi in New Delhi last Thursday.

Gunfight breaks out near army camp in Kupwara: Officials

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

SRINAGAR: An encounter broke out between security forces and terrorists near an army camp in the Kupwara district of Kashmir on Tuesday, officials aware of the matter said.

The gunfight was underway at the time of going to print.

Speaking on condition of anonymity, officials said that the encounter broke out near the army's Divar camp, which keeps a watch on the movement of extremists in the district's Lolab valley. The gunfight started after the army and J&K Police established contact with the terrorists in the forests of Trimukha Top, the officials added.

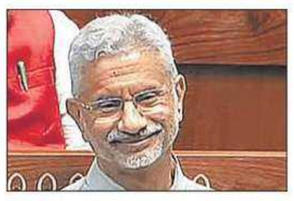
"Security forces have established contact with terrorists near Trimukha Top, Lolab, Kupwara. Operation in progress," J&K Police posted on X.

The Trimukha forest area connects Lolab with Bandipora and Baramulla districts and has been used by the terrorists to sneak from one district to another after infiltrating from across the Line of Control (LoC), the officials added.

The gunfight broke out days after the army foiled an infiltration bid in the Keran sector and killed two terrorists. On July 14, three terrorists were killed as security forces foiled an infiltration bid in the Keran sector.

The region has been on alert amid an increase in terror attacks, with the army using drones, quadcopters, and human intelligence to track the movement of terrorists and thwart infiltrations. Keran has earlier been used as a regular infiltration route.

In April, the army killed two infiltrators in Uri near Rustam post. It was the first infiltration attempt of the year, which was averted by the alert forces.



S Jaishankar

EAM TO VISIT LAOS, JAPAN FOR QUAD, ASEAN MEETINGS

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: External affairs minister S Jaishankar will make back-to-back visits to Laos and Japan this month to attend meetings related to the Association of Southeast Asian Nations (Asean) and the Quad that are expected to focus on the Indo-Pacific region.

Jaishankar will travel to Vientiane, the capital of Laos, during July 25-27 to participate in foreign ministers' meetings under the Asean framework. This includes meetings of Asean-India, the East Asia Summit and the Asean Regional Forum (ARF). He is also expected to hold bilateral meetings with his counterparts from other countries in Vientiane on the margins of the Asean-related meetings, the external affairs ministry said on Tuesday.

Jaishankar is visiting Vientiane at the invitation of Saleumxay Kommasith, deputy prime minister and foreign minister of Laos, the current chair of Asean.

This year marks a decade of India's "Act East" policy, which was announced at the 9th East Asia Summit in 2014.

Jaishankar will then travel to Japan during July 28-30 to participate in a meeting of the Quad foreign ministers in Tokyo on July 29 along with his counterparts from Australia, Japan and the US.

Navy chief reviews damage to warship as search for missing sailor continues

Yogesh Naik
letters@hindustantimes.com



INS Brahmaputra tilted to its side on Monday. ANI

MUMBAI: Indian Navy Chief Admiral Dinesh Tripathi on Tuesday reviewed the damage to frontline warship INS Brahmaputra at the Mumbai naval dockyard, a day after it experienced "severe listing" to one side, with authorities struggling to bring it back to an upright position.

Listing refers to a vessel tilting to one side after taking water in. Tripathi met senior officers and discussed steps forward, even as officials said that an inquiry has been ordered into the accident.

A fire was reported on board the frigate on July 21 when the ship was undergoing a refit at the dockyard, which the Navy said, was brought under control by the ship's crew with the assistance of firefighters and other ships in the harbour by the morning of July 22. On Monday afternoon however, the ship experienced severe listing to one side, and despite efforts, could not be brought upright. One junior sailor also went missing.

Officials said on Monday that while the cause of the vessel tipping over towards port, or the left was not immediately known, fire-fighting units had pumped huge quantities of water to douse the flames. The 3,850-tonne multi-role frigate, the lead warship of the Brahmaputra class, suffered extensive damage and is likely to be out of action for several months, said one of the officials, who asked not to be named.

Navy officials said on Tuesday said that there was some preliminary evidence of mishandling the fire-fighting operations. "The water should have been removed to balance the ship." A search is also underway for the missing junior sailor who is missing, with several diving teams pressed into rescue operations.

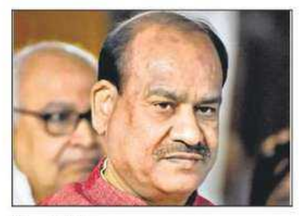
Speaking to PTI in Goa, Vice admiral Krishna Swaminathan said, "A lot of water was used to douse the fire, and perhaps the ship's stability was upset because of this, and it tilted to one side and is resting on the jetty," he said.

INS Brahmaputra was commissioned in 2000 and is designed to carry a team of 40 officers and 330 sailors, has medium-range, close-range and anti-aircraft guns, surface-to-surface and surface-to-air missiles and torpedo launchers. It can also carry Sea King and Chetak helicopters. This is not the first time such an accident has occurred at the naval dockyard. In December 2016, INS Betwa tipped over and crashed on its side in the naval dockyard, killing two sailors. Fourteen other people in the dockyard were injured.

With PTI inputs

HC orders removal of 'objectionable' posts against Speaker's kin

Press Trust of India
letters@hindustantimes.com



Om Birla

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday directed X Corp and Google Inc to remove alleged objectionable social media posts against Indian Railway Personnel Service (IRPS) officer and Lok Sabha Speaker Om Birla's daughter Anjali Birla.

Justice Navin Chawla, in an interim order, also restrained unknown parties from directly or indirectly posting, circulating, communicating, tweeting or retweeting the alleged defamatory content mentioned by Anjali Birla in her defamation suit.

The high court, which said Birla has been able to make out a prima facie case in her favour, added the social media posts shall be removed by the intermediaries within 24 hours, and in case the plaintiff comes to know of any other similar posts, she shall inform X and Google about it.

"Having considered the contents of the suit and having heard the counsel for plaintiff, I am of the opinion that the plaintiff has been able to make out a prima facie case in her favour. Balance of convenience is also in favour of the plaintiff and against the defendants," Justice Chawla said.

The court was of the opinion that the social media posts Birla had complained about did not appear to have been made after due verification.

"The plaintiff was appointed to IRPS in 2021. The purpose of posting the impugned social media posts in 2024 and in the language they have been posted do not appear to be bonafide," it noted.

RUCKUS IN ODISHA HOUSE OVER 'LACK' OF ACTION AGAINST GOVERNOR'S SON

BHUBANESWAR: The Odisha assembly was adjourned twice on Tuesday following a ruckus as the opposition demanded a statement from chief minister Mohan Majhi over the lack of action against governor Raghubar Das's son for allegedly assaulting a government official earlier this month.

As soon as the House assembled for Question Hour, opposition chief whip Pramila Mallik demanded a statement from Majhi.

"An ASO (assistant section officer) was assaulted by the governor's son on July 7 but he hasn't been provided justice so far. Both the governor and CM held discussions with the victim but what transpired between them didn't come out," alleged Mallik.

ASO Baikunthanath Pradhan was allegedly assaulted by governor's son Lalit Kumar and five of his associates on the Raj Bhavan premises in Puri on July 7.

Amid repeated adjournments, BJD MLA Dhruba Sahoo climbed the Speaker's podium and broke the microphone. HTC

NCPCR summons Netflix over accessibility of sexually explicit content to minors

NEW DELHI: The National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) has summoned Netflix officials on Monday for allegedly showing "sexually explicit content" that is accessible to minors on the platform. In a letter to Netflix officials on Tuesday, the NCPCR said "unrestricted accessibility of explicit content" on Netflix to minors constitutes a violation of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act-2012.

HC grants interim stay on order permitting Indrani Mukerjea to travel abroad

MUMBAI: The Bombay HC on Tuesday granted an ad-interim stay on a special court order allowing former media executive Indrani Mukerjea, who is accused of killing her daughter Sheena Bora in 2012 and is currently out on bail, to travel to Europe. The CBI's advocate told the court that Indrani is a prime accused in a murder case, the trial of which is ongoing. Hence, it would not be appropriate to let the accused leave the country at this stage, he argued.

SC bars Aravalli states from granting mining lease renewal

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday said Aravalli hill range states will remain barred from granting final permission for renewal of mining leases without obtaining prior approval of the apex court. The Aravalli range is spread across Delhi, Haryana, Rajasthan and Gujarat. While hearing two fresh pleas for renewal of mining licences, the top court directed the state governments concerned to process the proposals for renewal of leases including obtaining statutory clearances from various authorities.

Khedkar fails to report to training academy

Shrinivas Deshpande
shrinivas.deshpande@htlive.com



Puja Khedkar

PUNE: Probationary IAS officer Puja Khedkar, who was instructed by Mussoorie-based Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration (LBSNAA) officials to join the institute by July 23, did not report on Tuesday, officials familiar with the matter said.

The Maharashtra government in its July 16 order had relieved Khedkar from her district training programme after LBSNAA recalled her for "further necessary action". "By 5.30 pm on Tuesday, Puja Khedkar has not reported at the academy," LBSNAA officials said.

Khedkar faces a raft of allegations, including of misuse of her power and privileges, disability and Other Backward Class (non-creamy layer) quotas to secure her candidature in the civic service exam, apart from manipulation of her identity to take the exam beyond permissible attempts. The Union Public Service Commission (UPSC) has registered a criminal case against her for "misrepresenting and falsifying facts".

The Centre has instructed the Pune police to provide information on Khedkar's parents' marital status. It is alleged that she obtained the OBC non-creamy layer quota advantage by falsely claiming her parents were separated.

SC bench split on GM mustard release, seeks national policy

Utkarsh Anand
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Supreme Court on Tuesday delivered a split decision regarding the environmental release of genetically modified (GM) mustard, even as it directed the Union government to formulate a national policy on stringent and transparent biosafety protocols for genetically modified organisms (GMOs).

The two-judge bench, comprising justices BV Nagarathna and Sanjay Karol, presented divergent views while emphasising the need for comprehensive biosafety measures. Justice Nagarathna raised significant concerns about procedural lapses, potential environmental and health impacts with regard to open field trials of GM mustard whereas justice Karol affirmed the adequacy of the existing regulatory framework.

While the unanimous view of the judges regarding the necessity of a national policy on GM crops following a national consultation in the next four months reflects the apex court's recognition of the need for a comprehensive and transparent approach to GM crop regulation in India, the dissenting opinions on the open field trials of GM mustard underscore the complexities surrounding the environmental release of GM crops in India.

Given the split decision on the GEAC's approval for GM mustard, the matter will now be placed before the Chief Justice of India, who will constitute a larger bench of three judges to reconsider the issue afresh.

Points of difference

Justice Nagarathna's opinion was a scathing critique of procedural lapses in the approval process for the GM mustard variety DMH-11 as it quashed the government's decision to allow the environmental release of GM mustard. This decision by the Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) in October 2022 sparked a nationwide debate on the safety, necessity and potential impact of GM crops on biodiversity, human health and agricultural practices.



Concerns were raised over the environmental impacts of GM mustard.

According to justice Nagarathna, the decision was vitiated on grounds of lack of effective consultation and disregard of the principles of public trust doctrine. The judge also criticised the Centre for showing "undue haste" in getting the GEAC to approve the decision on the conditional release of GM mustard, highlighting significant procedural lapses and the critical importance of adhering to statutory protocols.

Justice Nagarathna pointed out the absence of representatives from the Indian Council of Medical Research (ICMR) and the ministry of health at the crucial 147th meeting of the GEAC on October 18, 2022. This omission led to an inadequate consideration of the potential adverse effects on human health, animals, and other plants, she opined.

Additionally, she criticised the GEAC for ignoring the recommendations of the court-appointed technical expert committee (TEC) and constituting another expert committee based on a letter from professor Deepak Pental to the Union minister of environment, forest and climate change in May 2022. According to the judge, this intervention resulted in the approval of the DMH-11 hybrid mustard without adequate precautionary measures and in bypassing the decision of GEAC in its meeting held in March 2019 to further defer field demonstration studies on transgenic mustard.

"I am of the view that the GEAC approval dated 18.10.2022 and the consequent decision dated 25.10.2022 regarding the environmental release of transgenic mustard hybrid DMH-11 is vitiated. I also find that the impugned approval was in gross violation of the principle of public trust," justice Nagarathna held.

Dissenting with her views, justice Karol focussed on the adequacy of the assessment and approval procedures for GM crops, asserting that the regulatory framework in India is robust and sufficient. "Even if the TEC and parliamentary standing committees have found certain issues with the procedures governing GM crops, that cannot automatically lead to the conclusion that gaps in the impugned procedures result in a violation of Part III of the Constitution of India (fundamental rights) and must be invalidated or that the impugned action be stalled." he maintained.

Points of consensus

Despite their divergent opinions, justices Nagarathna and Karol agreed on the need for a national policy on GM crops. Recognising the complexities and potential risks associated with GMOs, they directed the Union government to develop a comprehensive national policy on GM crops. This policy should be formulated in consultation with all stakeholders, including agricultural experts, biotechnologists, state governments and farmers' representatives, said the judges, stressing importance of transparency and public involvement in this process.

Badal dissolves SAD core committee amid rebellion by leaders

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com



Sukhbir Singh Badal

NEW DELHI: Shiromani Akali Dal (SAD) chief Sukhbir Singh Badal on Tuesday dissolved the party's core committee in the wake of a rebellion by a section of senior leaders who were part of the body.

The decision was made public by the party's senior vice president Daljit Singh Cheema. "The working committee of the party has authorised the SAD President S Sukhbir Singh Badal to reorganise the party organisation. In this regard, the party president discussed in detail with his senior colleagues in a meeting held at Chandigarh today (Tuesday). It was decided to dissolve the core committee of the party. It will be reorganised shortly," Cheema announced in a post on X.

Many of the party's senior leaders had demanded the resignation of Badal as Shiromani Akali Dal chief following the drubbing in the 2024 Lok Sabha elections in Punjab. Last week, the rebellious senior leaders had launched the 'Shiromani Akali Dal Sudhar Lehar' to resuscitate the party following the recent spate of losses in parliamentary and assembly polls.

The members of the core committee included party patron Sukhdev Singh Dhindsa, former president of Shiromani Gurdwara Parbandhak committee (SGPC) Jagir Kaur, ex-MP Prem Singh Chandumajra, former ministers Parminder Singh Dhindsa, Sikandar Singh Maluka, Surjeet Singh Rakhra and Baldev Singh Mann and former MLA Gurpartap Singh Wadala.

"Behave or be banished, the message is loud," said a party leader on the condition of anonymity to the rebel leader. "It is not possible to tread on two boats."

"It is to be seen what happens to them when the core committee is recast," said Badal's principal Harcharan Bains.

He also said that the rebels are behaving like a separate party and are openly speaking against Badal.

Meanwhile, the rebels also held a meeting on Tuesday, in which they finalised a 13-member presidium to support Wadala as the convener of Sudhar Lehar.

Minister lauds NEET order; revised results out in 2 days

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com



Students protest over alleged irregularities in the conduct of NEET-UG 2024, at Jantar Mantar in Delhi on July 7. HT PHOTO

NEW DELHI: Union education minister Dharmendra Pradhan on Tuesday hailed the Supreme Court's decision on the National Eligibility cum Entrance Test undergraduate (NEET-UG), adding that the revised results in accordance with the top court's judgement will be released within two days.

The apex court dismissed pleas seeking cancellation and a retest of the controversy-riddled 2024 NEET-UG, holding that there was no evidence on record to conclude that the sanctity of the exam has been violated.

Speaking to the media, Pradhan welcomed the Supreme Court's decision and said that the "truth has prevailed".

"We have been saying this from the beginning — our priority is the students of this country. The government's priority has always been to see that there should be no tampering with students' futures. For the last 2-2.5 months, the government's stand has been that there has not been any large-scale breach. Today, the Supreme Court has upheld that in its final judgment," he said.

The education minister also slammed the Leader of Opposition (LoP) in Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi for calling the country's examination system "rubbish", and said he and the opposition should apologise to the students and parents of the country.

"When the NEET matter came to light, the Opposition's role became clear after the Supreme Court's judgment today. The attitude that the Lok Sabha LoP had adopted until yesterday, invalidating the examination system of the country and calling it 'rubbish' proves his mental status...Criticising this, Rahul Gandhi ji has criticised India," he said.

"Misleading the students of the country, creating confusion and provoking them for social tensions were all planned as part of his politics. By rejecting the electoral results in the country, anarchy and civil unrest have become a part of his strategy. I appeal to him and all people of the Opposition who were involved in such irresponsible actions that they should apologise to the students, youth and parents of the country... The country will not forgive you. Political rivalry can be different, but students belong to everyone," he said.

On Monday, the first day of the monsoon session, the NEET controversy dominated discussions, with Opposition leaders, including Leader of the Opposition (LoP) Rahul Gandhi and Samajwadi Party (SP) MP Akhilesh Yadav vociferously attacking the government. They called for the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan. The uproar forced the government to defend its position and the measures it had taken to address the situation.

Pradhan rejected allegations that widespread paper leaks had vitiated the exam, asserting that there was no evidence of paper leaks in the last seven years.

Pradhan said the government has promised the Supreme Court that it will be committed to have a transparent, tamper-proof and zero-error examination system. "Taking this commitment forward, we announced a high-level committee for a complete revamp of NTA. That committee is working dedicatedly. The committee has collected expert opinions and studied various models...They will submit a report soon," he said.

The education ministry had last month formed a seven-member committee, headed by K Radhakrishnan, to ensure transparent, smooth and fair conduct of examinations through the NTA.

"I would like to assure the youth and students of the country that we are committed to making the NTA an error-free organisation. In this process, all those involved in these irregularities will not be spared," the education minister said.

He also assured that anyone who has been found guilty in the entire NEET-UG issue will not be spared and strict action will be taken against them. "If anybody is found involved in exam irregularities, they will not be spared. Zero tolerance for any kind of breach; the sanctity of exams supreme for us," Pradhan said.

Mamata hits out at guv over warning to impose fine on two TMC MLAs

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A day after West Bengal Governor CV Ananda Bose warned that he would impose a fine of ₹500 per day on two Trinamool Congress (TMC) legislators who were administered the oath on July 5 by the Speaker of the Assembly, chief minister Mamata Banerjee accused him of "bias", calling the fine a "colonial law".

The oath taking of Sayantika Banerjee and Reyat Hossain Sarkar, who won the bypolls from Baranagar and Bhagwangola in June has been shrouded in controversy after they demanded that they be administered the oath of office in the House rather than at Raj Bhavan, triggering another prolonged stand-off between the Raj Bhavan and the ruling TMC.

A letter sent by the Raj Bhavan to the two legislators on Monday said, "As such their making and subscribing oath or affirmation before the Speaker has no legal sanction and is nothing but Constitutional transgression, which would attract the penal provisions as container under Article 193 of the Constitution of India." Article 193 of the Constitution suggests that if a person either sits or votes in the legislative assembly before taking oath or affirmation, they are liable to pay a penalty of ₹500 for each day.

> Are you in desperate need of money? Do you need money for tiffin? You may tell me. I can arrange
>
> **MAMATA BANERJEE,**
> West Bengal chief minister

Banerjee on Tuesday, however, attacked Bose in the Assembly and said, "Are you in desperate need of money? Do you need money for tiffin? You may tell me. I can arrange... Don't go off the tracks. You can't be biased towards any political party. Who will pay the penalty imposed on you? Imposing a penalty of ₹500 is a colonial law," she said.

There was no immediate reaction from Raj Bhavan.

Meanwhile, Speaker Biman Banerjee on Tuesday administered oath to four new TMC MLAs — Supti Pandey, Madhuparna Thakur, Mukutmani Adhikari and Krishna Kalyani (Raiganj) — who were elected in the July 10 bypolls. Bose, who was in Delhi, met Vice President Jagdeep Dhankhar on Tuesday.



HC grants bail to two accused in Kalburgi murder

BENGALURU: The Karnataka high court on Tuesday granted bail to two accused in the murder case of scholar MM Kalburgi. Justice M G Uma observed that the prosecution could not provide a definite timeline for the trial's conclusion.

Lalu admitted to AIIMS Delhi

NEW DELHI: RJD chief Lalu Prasad Yadav was admitted to AIIMS Delhi on Tuesday night after his health suddenly deteriorated, people aware of the details said. At the time of filing, his condition was stable. Yadav's family were also present at the hospital.

Man held for bid to bury paralysed mother alive: Cops

GUWAHATI: A tea garden worker in Assam's Tinsuka district was arrested on Tuesday for allegedly trying to bury his paralysed mother in the backyard of their house. Locals informed the police about the incident that took place on Monday. The mother was later rescued by the locals, said officials.

K'taka HC stays FIR against two ED officials

BENGALURU: The Karnataka high court on Tuesday stayed an FIR filed against ED officials over a complaint of a social welfare department officer who alleged he was harassed to take the name of CM, deputy CM and others in government in the Valmiki case.

{ ON GALLANTRY AWARDS }

MHA seeks clarification over Haryana's proposal

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

CHANDIGARH: The Union ministry of home affairs has sought a clarification from the Haryana government after the state administration had proposed awarding gallantry medals to six police officers for an operation to stop protesting farmers at the Shambhu and Khanauri borders in February.

The MHA has said that personnel of several paramilitary forces were also involved in the operation and were not mentioned in the recommendation. Farmer groups in the region, however, have raised objection to the recommendation of the gallantry medals in light of the death of Shubh Karan Singh, a farmer who died in the alleged police firing on February 21.

In a July 8 communication, the MHA said, "It has been noticed that personnel of Rapid Action Force (RAF), Central Reserve Police Force (CRPF), Border Security Force (BSF), Indo-Tibetan Border Police (ITBP) and Sashastra Seema Bal (SSB) also participated in the action but were not recommended." It pointed to a guidelines issued on October 16, 2023, which had said that in case of joint operations of different units of forces, their roles must be properly highlighted.

In July 2024, the Haryana government had proposed the names of three IPS officers — Inspector General of Police, Ambala Range Sibash Kabiraj, the then Ambala Superintendent of Police Jashndeep Singh Randhawa and Jind Superintendent of Police Sumit Kumar — and three Haryana Police Service (HPS) officers Narender Singh, Ram Kumar and Amit Bhatia for the medals.

SC/ST funds for cows, religious sites as per population: MP official

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

BHOPAL: The Madhya Pradesh government on Tuesday said it has provided funds from scheduled caste (SC) and scheduled tribe (ST) sub-plans for cow conservation and development of religious places for 2024-25 financial year as per proportion of SCs and STs to the state's total population, similar to the provision made in the previous financial year.

Reacting to a HT story about the matter on Tuesday, an official from the state's public relation department said a provision of 16% and 21% for scheduled caste and schedule tribe, respectively, was provided in the budget.

Of the ₹252 crore fund for cow and animal conservation, ₹156.24 crore was allocated from the general category, ₹40.32 crore from the SC sub-plan and ₹55.44 crore was from ST sub-plan.

The allocation from the SC and ST sub-plan is 16% and 22%, respectively, which is as per proportion of SCs and STs to Madhya Pradesh's total population.

The official added that a similar provision of ₹90 crore for cow conservation was also made in the budget last year.

With regards to the development of five religious places including the Atal Bihari Vajpayee Memorial in Gwalior, the department said 16% from the SC sub-plan and 23% from ST sub-plan was provided in budget for 2024-25.

A similar budget provision was made for the previous fiscal year, the official added.

The department also said that the MP government was committed towards the welfare of SC and ST communities and has provided ₹27,900 crore and ₹40,804 crore in the 2024-25 budget.

UK foreign secy to push for reset of partnership during India visit

Rezaul H Laskar
letters@hindustantimes.com



David Lammy

NEW DELHI: British foreign secretary David Lammy will push for a reset of the India-UK partnership during his visit to New Delhi this week by reinforcing Britain's commitment to securing a free trade agreement (FTA) that benefits both countries.

The FTA, negotiations for which began in January 2022, is set to top the agenda for Lammy's visit beginning on Wednesday. Lammy, who is travelling to India within a month of taking over his position, will meet external affairs minister S Jaishankar and commerce minister Piyush Goyal.

Lammy will tell Jaishankar that he wants to "drive forward greater growth for both countries", said a statement from the British high commission. He will also highlight the importance of a new partnership with India that focuses on economic, domestic and global security.

"Our FTA negotiations is the floor not the ceiling of our ambitions to unlock our shared potential and deliver growth, from Bengaluru to Birmingham. We have shared interests on the green transition, new technologies, economic security and global security," Lammy said ahead of the visit.

Lammy, who described India as the "emerging superpower of the 21st century", will push for a reset of the India-UK partnership, including through reinforcing Britain's commitment to securing an FTA that benefits both sides, the statement said.



रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 REGD. NO. D. L. - 33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी-डी.एल.-अ.-03072024-255100
CG-DL-E-03072024-255100

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3 - Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2438] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 2, 2024/आषाढ 11, 1946
No. 2438] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 2, 2024/ASHADHA 11, 1946

MINISTRY OF RAILWAYS
(Railways Board)
NOTIFICATION
New Delhi, the 1st July, 2024

S.O. 2573(E).—WHEREAS by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), vide number S.O.3812 (E), dated the 22th August, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 25th August, 2023, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of Special Railway Project, namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Meerut in the State of Uttar Pradesh;

AND WHEREAS, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Hindustan Times" and "Dainik Jagran", dated the 9th September, 2023, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

AND WHEREAS, no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

AND WHEREAS, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), and in pursuance of sub-section (2), of section 20E of the said Act, the Central Government, -

(i) upon receipt of the said report of the competent authority, hereby declares that the lands specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; and

(ii) hereby declares that on publication of this notification, the lands specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely upon it free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for Special Railway Project of Eastern Dedicated Freight Corridor in the District of Meerut in the State of Uttar Pradesh.

DISTRICT: Meerut

Sr. No.	Tehsil	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Khasra No.	Area in (Hect.)	Name of the Land Owner/ Intersted Person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Sadar	Uplehda	Private	Agriculture	314	0.0258	Sanjay Kumar,Rajeev Kumar S/o Late Sheeshpal Singh, Satyapal Singh S/o Daryav Singh, Praveen Kumar, Naveen Kumar, Arun Kumar and Jitendra Kumar S/o Harpal Singh.
2			Private	Agriculture	317	0.0190	Dharambir S/o Baljeet Singh.
3			Private	Agriculture	318	0.0138	Munesh Kumari W/o Lokesh Kumar, Omvati W/o Yashkumar, Lokesh S/o Braham Singh, Dhari Devi W/o Late Braham Singh.
4		Chajjupur Urf Chhajmalpur	Private	Agriculture	400	0.0180	Jaiprakash S/o Shankar, Arjun Kumar Agarwal S/o Bhagwat Prasad.
5			Private	Agriculture	344	0.0080	Arun Kumar S/o Harpal Singh, Geeta Rana W/o Sanjay Rana.
6			Private	Agriculture	343	0.0100	Islamuddin, Ali Mohammad, S/o Chhote.
7			Private	Agriculture	342	0.0085	Vijaypal S/o Aman Singh, Seema W/o Naveen Kumar,NaveenKumar, Jitendra Kumar S/o Harpal Singh, Brijpal, Madanpal, Vedpal, Brijveer Singh S/o Jaipal, Premvati W/o Late Jagpal Singh, Pawanveer, Karanveer, Ajayveer Singh S/o Jagpal Singh, Rampal, Ashok s/o Sukhvir, Sunita W/o Madanpal, Mansi, Miss Nancy (minor 15 years old) D/o Madanpal guardian mother, Siddharth (minor 13 years old) S/o Madanpal guardian mother, Anil Kumar and Devendra Kumar S/o Sukhveer, Arun Kumar S/o Harpal, Bijendri W/o Sohanveer.
8			Private	Agriculture	341	0.0040	Ompal Singh & Rajveer Singh S/o Nawab Singh.
9			Private	Agriculture	338	0.0148	Narendra Kumar & Subhash Chand S/o Kundanlal, Vasudev Chaudhary & Arjun Singh S/o Ompal Singh, Omveer Singh, Omprakash, Sardar Singh & Samay Singh S/o Nawab Singh.
10			Private	Agriculture	337	0.0173	Narendra Kumar & Subhash Chand S/o Kundan.
11			Private	Agriculture	332	0.0030	Manjoor Ahmad, Noor Ahmad, Khaleel Ahmad, Ahmad Hasan S/o Masoom Ali urf Mousam Ali.
12			Private	Agriculture	317	0.0200	OmpalSingh & Rajveer SinghS/o Nawab Singh.
13			Private	Agriculture	316	0.0198	Vijaypal, Gajraj & Trilokchand S/o Narayan Singh, Ankur S/o Vedprakash, Kamlesh W/o Vedprakash, Rashmi Upadhyay W/o Amit Kumar.
14			Private	Agriculture	318	0.0080	Omveer Singh & Omprakash S/o Nawab Singh, Dhari Devi W/o Late Braham Singh, Ankur S/o Vedprakash, Kamlesh W/o Vedprakash.
15			Private	Agriculture	319	0.0055	Lokesh Kumar S/o Braham Singh, Dhari Devi W/o Late Braham Singh.
16			Private	Agriculture	329	0.0037	Omprakash adopted S/o Ramsharan.
17			Private	Agriculture	327	0.0142	Narendra, Jitendra Sharma, Satendra Sharma, Neeraj Sharma & Raju S/o Kanti, Maya Devi W/o Late Kanti, Veernarayan, Rameshchand & Kailash Chand S/o Saggan, Omwati Sharma W/o Ranveer Sharma.
18			Private	Agriculture	299	0.0114	Mahendri Devi W/o Mahavir Singh, Chaudhary Adesh Kadiyan & Pradeep Chaudhary S/o Mahavir Singh, Raj veer Singh, Rajendra Kumar, Shyamveer Singh & Rajkumar S/o Tikam Singh, Pavitra W/o Rajendra Kumar, Shashi W/o Shyamveer Singh.
19			Private	Agriculture	297	0.0015	Lokesh Kumar S/o Braham Singh, Fayyaz & Abdul Hameed S/o Wazir, Shafiq Ahmed, Ahmed Hasan, Aas Mohammad, Hasan Mohammad, Shakeel Ahmed & Aaqib Ali S/o Rafiq Ahmed, Mehboob Ali, Saleem Khan S/o Abdul Rashid & Naushad S/o Jamiluddin, Salma W/o Late Jamiluddin, Shaheeda W/o Yasin, Irshad Ali, Dilshad & Farman Khan S/o Yasin.
20		Govindpur Urf Ghasouli	Private	Agriculture	91	0.0120	Rakesh,Manbir Singh & Dinesh Kumar S/o Sukhpal Singh.
21			Private	Agriculture	107	0.0018	Smt. Shrimati W/o Asharam.
22		Jangethi	Private	Agriculture	358	0.0210	Sukhpal, Raghubar & Shauraj S/o Late Ramsharan, Indro Devi W/o Mohanlal.
23			Private	Agriculture	357	0.0092	Mahavir Singh S/o Balwant, Devendra S/o Latur Singh, Mohanlal S/o Mukhtyar Singh.
24			Private	Agriculture	359	0.0192	Rajrani W/o Naresh Kumar, Savitri W/o Meer Singh, Vimal Kumar S/o Meer Singh, Bijendra Kumar, Rajendra Kumar, Jitendra Kumar, Naresh Kumar & Krishna Kumar S/o Rupram, Babita W/o Billu.
25			Private	Agriculture	367	0.0750	Virendra Singh,Surendra Singh, Ravindra, Shripal & Rishipal S/o Kanval Singh, Jagpal Singh, Ashok Pal, Satish Kumar,Harendra Kumar, Bijendra Kumar & Bintu S/o Ilam Singh.
26			Private	Agriculture	108	0.0040	Virendra Singh, Surendra Singh, Ravindra, Shripal & Rishipal S/o Kanwal Singh, Jagpal, Ashok Pal,Satish Kumar, Harendra Kumar, Bijendra Kumar & Bintu S/o Ilam Singh.
27			Private	Agriculture	104	0.0342	Virendra Singh, Surendra Singh, Ravindra, Shripal & Rishipal S/o Kanwal Singh, Jagpal, Ashok Pal, Satish Kumar, Harendra Kumar, Bijendra Kumar & Bintu S/o Ilam Singh.
28			Private	Agriculture	103	0.0154	Mahesh S/o Nepal, Usha W/o Mukesh, Deepak Kumar S/o Mukesh, Vinod Kumar, Subhash, Kuljeet, Amrish Kumar, Raju S/o Kaluram.
29			Private	Agriculture	101	0.0077	Baldev S/o Dharma.
30			Private	Agriculture	417	0.0250	Shimla W/o Deepak Kumar, Yashlok & Abhishek S/o Deepak, Kuldeep Kashyap S/o Shauraj Singh, Sudesh S/o Richpal, Shokindra S/o Rohtash.
31			Private	Agriculture	386	0.0305	Ramchandra S/o Baddal.
32			Private	Agriculture	382	0.0195	Anil Kumar S/o Vijaypal Singh, Meenu W/o Late Vipin Kumar, Rajbiri W/o Late Vijaypal Singh.
33			Private	Agriculture	381	0.0163	Chaman Singh son of Harpal Singh.
34			Private	Agriculture	380	0.0425	Anil Kumar S/o Vijaypal Singh, Meenu W/o Late Vipin Kumar, Rajbiri W/o Late Vijaypal Singh, Chaman Singh S/o Harpal.
35			Private	Agriculture	377	0.0375	Satyendra Kumar & Pawan Kumar S/o Jaipal Singh, Himanshu Chaudhary S/o Ravindra Kumar.
36			Private	Agriculture	376	0.0600	Satyendra Kumar & Pawan Kumar S/o Jaipal Singh, Himanshu Chaudhary S/o Ravindra Kumar, Madan Singh urf Madanpal S/o Hukum Singh, Satyapal S/o Sukkhe, Malkhan Singh, Samay Singh, Balwan Singh, Ramkripal Singh & Yogendra Pal S/o Harveer, Shripal, Sheeshpal, Sohanveer Singh S/o Mukhtiyar.'
37			Private	Agriculture	99	0.0745	Mahesh Kumar s/o Nepal, Usha W/o Mukesh, Deepak S/o Mukesh, Subhash, Kuljeet, Amrish Kumar & Raju S/o Kaluram, Pradeep Panwar & Sandeep Panwar S/o Shaudan Singh, Pradeep Kumar S/o Saudan Singh.
38			Private	Agriculture	95	0.0663	Chhatarpal Singh S/o Kishna, Ashwani Kumar & Ashish Kumar S/o Jagat Singh, Pramila Devi W/o Jagat Singh, Deepak S/o Ome, Km. Komal D/o Ome
39			Private	Agriculture	91	0.0135	Chhatarpal Singh S/o Kishna, Ashwani Kumar & Ashish Kumar S/o Jagat Singh, Pramila Devi W/o Jagat Singh, Deepak S/o Ome, Km. Komal D/o Ome.
40			Private	Agriculture	90M	0.0146	Saroj W/o Mahesh, Tinku Singh, Lucky Kumar & Kunwarpal S/o Kiranpal, Gyanwati W/o Jograj, Arun Kumar S/o Lahari Singh.
41			Private	Agriculture	89	0.0120	Azad Singh S/o Kale.
42		Matour	Private	Agriculture	721	0.0225	Brajpal Singh, Satyapal Singh, Sushil Singh, Sunil & Yogendra Singh S/o Ranjeet Singh.
43	Sardhana	Kanoda	Private	Agriculture	46	0.0216	Jaiveer Singh S/o Balmukund, Rakesh Sharma S/o Rambharoselal Sharma, Sunil Gaur & Sanjeev Gaur S/o Gyanprakash Sharma.
44			Private	Agriculture	48	0.0195	Amardev, Jagdev, Jaidev & Shadev S/o Jaipal, Phoolvati W/o Jaipal.

[F. No. 2024/LML-II/12/2/EC/2473]
PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि.
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत वितरण मण्डल
हाईडिल कलोनी रानीखेत- 263645 (जि.-अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड) दूरभाष : 05966-220620

पत्रांक : 2116/वि.वि.म.(रा)/ई-निविदा

ई-निविदा सूचना

दिनांक : 23.07.2024

विद्युत वितरण मण्डल रानीखेत निम्न ई-निविदा आमंत्रित करता है :-

क्र0 सं0	ई-निविदा संख्या	कार्य का नाम	ई-निविदा क्रय/जमा करने की ऑनलाइन अन्तिम तिथि एवं समय	ई-निविदा (भाग-1) खुलने की ऑफलाइन/ऑन लाइन तिथि एवं समय
1	वि0वि0म0(रा0) 06/2024-25	वि0प0ख0 अल्मोडा के अधीन वि0वि0ख0, अल्मोडा के अन्तर्गत के0सी0सी0/नॉन के0सी0सी0 (05 KW and above) उपभोक्ताओं की एम0आर0आई0 सम्बन्धी कार्य।	13.08.2024 15:00 बजे तक	14.08.2024 12:00 बजे
2	वि0वि0म0(रा0) 07/2024-25	वि0प0ख0 अल्मोडा के अधीन वि0वि0ख0, बागेश्वर के अन्तर्गत के0सी0सी0/नॉन के0सी0सी0 (05 KW and above) उपभोक्ताओं की एम0आर0आई0 सम्बन्धी कार्य।	13.08.2024 15:00 बजे तक	14.08.2024 12:00 बजे
3	वि0वि0म0(रा0) 08/2024-25	वि0प0ख0 अल्मोडा के अधीन वि0वि0ख0, अल्मोडा के अन्तर्गत के0सी0सी0/नॉन के0सी0सी0 (05 KW and above) उपभोक्ताओं की एम0आर0आई0 सम्बन्धी कार्य।	13.08.2024 15:00 बजे तक	14.08.2024 12:00 बजे
4	वि0वि0म0(रा0) 09/2024-25	वि0वि0ख0 रानीखेत के अन्तर्गत कर्मचारी कार्योजित किये जाने सम्बन्धी कार्य।	13.08.2024 15:00 बजे तक	14.08.2024 12:00 बजे

उक्त ई-निविदाओं की अन्य नियम व एवं शर्तें वैबसाईट www.uktenders.gov.in पर देखी जा सकती है। उक्त ई-निविदाओं का शुद्धि पत्र/विस्तारीकरण/निरस्तीकरण आदि की सूचना वैबसाईट www.uktenders.gov.in में ही प्रकाशित / उपलब्ध होगी।

''राष्ट्र हित में बिजली बचायें''
Customer Toll Free No- 18004190405

अधीक्षण अभियन्ता

MORADABAD SMART CITY LIMTED
Office of the CEO/ Municipal Commissioner,
Peeli Kothi, Water Works Compound, Pili Kothi, Civil Lines, Moradabad 244001
Contact. No.: 0591-2971001
E-Mail: moradabadsmartcitylimited@gmail.com

NOTICE INVITING E-TENDER

Open Tender 3036/MSCL/2024 Dated:23/07/2024

The C.E.O of Moradabad Smart City Limited (MSCL) invites e-tenders for the following works:

1) **Name of the Work: Request for Proposal for Publishing Gazette 2.0 Book Under Cultural Events, Promotions, Festivals, Promotion Handicraft mela for Brass promotions Project work**

Specification of the Gazette Book:

1. **Colored pages will be 84 and will be spread over the book; they will be placed after specific black and white pages.**
2. **Gazetter will be hardbound. It will be bound in 2.2mm kappa board with a multicolored laminated paster on 150 gsm Art Paper. Jacket printed in multicolor on 170 gsm Art paper with matt lamination, spot UV and hybrid will be put to cover the book.**

Tender Fee Rs. 11,800.00/- (Rs. Eleven Thousand Eight Hundred Only/-)
Start Date and time for downloading of bid **24th of July 2024 and 16:00 Hrs.**
Period of Last date and time for submission of bid **31th of July 2024 and 16:00 Hrs.**
Opening of bid **31th of July 2024 and 17:00 Hrs.**

The bid forms and other details are available on website **https://etender.up.nic.in/** and can only be submitted through https://etender.up.nic.in/. Any corrigendum regarding this would be published only on the above mentioned wesite.

C.E.O./Municipal Commisioner
Moradabad Smart City Limited

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सैक्टर-ओमेगा-1 (पी-2) ग्रेटर नौएडा
Toll Free No. 18001808296 वेबसाइट: www.yamunaexpresswayauthority.com

पत्रांक :- वाई0ई0ए0/भूलेख/577/2024

सार्वजनिक सूचना

दिनांक: 22.07.2024

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजित क्षेत्र में आपसी सहमति के आधार पर निम्न काश्तकारों से भूमि क्रय किया जाना प्रस्तावित है–

सैक्टर–29 ग्राम तिरथली व सैक्टर–32 ग्राम चकवीरमपुर

क्रम सं0	ग्राम का नाम/सैक्टर	खाता संख्या	गाटा संख्या	खसरे का कुल क्षेत्रफल (हे0 में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1.	सैक्टर–29 तिरथली	187	629	0.7140	तौकीर व सलाउददीन पुत्रगण नन्नू खाँ व मौविना पत्नी नन्नू खाँ नि0 ग्राम तिरथली, पर0 व तह0 जेवर, गौतमबुद्धनगर हाल निवासी बी–113, गली नं0–6, चांद बाग करावल नगर, दिल्ली	855/7140 भाग	0.0855
2.	सैक्टर–29 तिरथली	187	629	0.7140	जफरूददीन पुत्र गफूर वेग नि0 ग्राम तिरथली, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर हाल निवासी बी–113, गली नं0–6, चांद बाग करावल नगर, दिल्ली	855/7140 भाग	0.0855
3.	सैक्टर–29 तिरथली	292	683	1.0300	रफीक उर्फ रफीक अहमद पुत्र युसूफ खान निवासी ग्राम नगला हॉडा माजरा कुरैब, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर व असलम पुत्र दाउद निवासी ग्राम नगला हॉडा माजरा कुरैब, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर हाल निवासी हाउस नं0 166, सबजी मंडी के पास, अज्जी कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	1/4 भाग	0.2476
4.	सैक्टर–29 तिरथली	360	159	0.5240	विनीत प्रजापति पुत्र रमेशचन्द प्रजापति निवासी सी0 85/2 गली नम्बर 8, मोहनपुरी दिल्ली हाल निवासी फलैदा बांगर, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर	1/2 भाग	0.2620
5.	सैक्टर–29 तिरथली	360	159	0.5240	प्रकाश उर्फ प्रकाश चन्द प्रजापति पुत्र शिवलाल निवासी फलैदा बांगर, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर	1/2 भाग	0.2620
6.	सैक्टर–29 तिरथली	62	387	0.5570	अजीज फात्मा पत्नी शफीक अहमद निवासी ग्राम तिरथली, पर0 व तह0 जिला गौतमबुद्धनगर	1/3 भाग	0.1857
7.	सैक्टर–29 तिरथली	321	661	3.0180	सईद पुत्र अल्लादिया निवासी ग्राम नगला हाण्डा माजरा, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर	1/16 भाग	0.1886
8.	सैक्टर–32 चकवीरमपुर	100	258	1.9590	अवन्तिका देवी ऐजूकेशन सोसायटी द्वारा प्रबन्धक हर्षद पुत्र पवन कुमार निवासी ग्राम चकवीरमपुर, पर0 व तह0 जेवर, जिला गौतमबुद्धनगर	5060/19590 भाग	0.5060

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण के कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

पत्रांक :- वाई0ई0ए0/भूलेख/803/2024 दिनांक: 23.07.2024

निम्नलिखित भूमि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति के आधार पर काश्तकारों से क्रय किया जाना प्रस्तावित है। क्रय हेतु काश्तकार द्वारा तहसील से गाटा संख्या, क्षेत्रफल व काश्तकार का हिस्सा सम्बन्धी आख्या उपलब्ध कराई गई है, जिसका विवरण निम्नलिखित तालिका में अंकित है–

ग्राम धनौरी, सैक्टर–18

क्रमांक	ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा संख्या	खसरे का कुल क्षे0 (हे0 में)	खातेदार का नाम व पता	तहसील से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर काश्तकार का हिस्सा (हे0 में)	काश्तकार का विक्रय हेतु क्षेत्रफल (हे0 में)
1	धनौरी (सै0–18)	256	973मि	1.0000	हरिओम पुत्र हरकरन नि0 ग्राम	1/4 भाग	0.2500 हे0

उपरोक्त भूमि क्रय किये जाने में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह लिखित रूप में 15 दिन के अंदर अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

डिप्टी कलेक्टर
यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मास्टर प्लान के अतिरिक्त प्लॉटिंग/हाउसिंग/कॉलोनी या किसी भी प्रकार का अन्य निर्माण पूरी तरह से अवैध है। सामान्यजन इस प्रकार की खरीद – फ़रोख्त से पूर्णतः सचेत रहें तथा कॉलोनाइजर के भ्रामक विज्ञापनों से बचें। अधिक जानकारी के लिए प्राधिकरण की वेबसाइट www.yamunaexpresswayauthority.com देखें।

Have fun with facts on Sundays

Catch the latest column of
HT TWTW
THE WEEK THAT WAS
A quiz on the week's development.



PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
Reg: Office: PSEB, Head Office, The Mall, Patiala-147001
Dy. Chief Engineer/O&M/MM-II, GHTP, Lehra Mohabat-151111 (Bathinda)
M No. 96461-17607, E-mail: se.mm2.lehra@gmail.com
Corporate Identity Number: U40109PB010SGC033813
Website: www.pspci.in

Tender Enquiry No.: 82/CHP/HEMC-308-Vol-XI **Dated:-** 23.07.24

Dy Chief Engineer, Mechanical Mtc. Circle-II/GHTP, Lehra Mohabbat invites E-tender for the work of "AMC to attend various Routine, Preventive and Break-Down Mechanical maintenance work of all the Heavy Equipment under HEMC/CHP, GHTP, Lehra Mohabbat (Wagon Tipplers, Stacker Reclaimers, Primary & Secondary Crushers, Dust Suppression System, Dust Extraction System, Ventilation System and Crusher/Grinder of coal sampling lab of coal handling plant Stage-I&II etc.) on lump sum basis for a period of one year at GHTP."

For detailed NIT & tender specification please refer to **https://eproc.punjab.gov.in** from 23.07.24 at 17.00 onwards.

Note: Corrigendum and addendum, if any will be published online at **https://eproc.punjab.gov.in**

GHTP-61/24 35955

Rajasthan State Mines & Minerals Limited
(A Government of Rajasthan Enterprise), 4, Meera Marg, Udaipur – 313001, Phone: (0294)2427177, 2428763-67, Fax (0294) 2428768,2428739, Email:- contractsco.rsmml@rajasthan.gov.in

Detailed Notice Inviting Tender Date - 22.07.2024

NIT No. & Date	Description of Work
e-Tender no. Cont- 07/2024-25 dated 22.07.2024 UBN No. MML2425WSOB 00071	Production of Low Silica High Grade Limestone Gitti by Deployment of HEMM equipment etc for Mining of Limestone, commissioning, operation & maintenance of Crushing & Screening Plant & Other related job & Services, construction of infrastructure facility at mines like explosive storage buildings, mine approach & link road, site office & store, weigh bridges, land reclamation, plantation, mine planning, statutory compliances, compliances etc work at UNROI-1 & UNROI-2 SMS Grade Limestone Mine, Sub Tehsil: Ramgarh, Tehsil Sam, District Jaisalmer and Loading of limestone gitti at mines & its transportation from mines to railway siding at Sanu railway station & its unloading, proper stacking at siding platforms etc work. Contract value Rs. 857.00 Crore, EMD in Rs. 17.00 Crore, Tender Fees Rs. 4720/-Rs. 3.63 Lacs, Tender Fees Rs. 4720/-

Other terms & conditions have been given in detailed tender for which please visit us at our website **www.rsmm.com or www.sppp.rajasthan.gov.in or eproc.rajasthan.gov.in** or Manager (Contract) on above address. **Raj.Samwad/C/24/2625** **Dy. General Manager (P&A)**

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
हरिद्वार
पिन कोड- 249404

पत्रांक :: 24/65/उ.कु.प्रसा./स0रा0(सिविल/प्रवर) अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024/गोपन–3/2024–25 दिनांक : 23 जुलाई, 2024

विज्ञप्ति

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है **दिनांक 14 जुलाई, 2024** को आयोजित **उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024 के प्रारंभिक परीक्षा के प्रथम प्रश्नपत्र–सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय प्रश्नपत्र–सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)** की चारों सीरीज (A, B, C & D) की उत्तरकुंजी को उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रसारित कर दिया गया है। यदि किसी अभ्यर्थी को चारों सीरीज के किसी प्रश्न एवं उत्तर विकल्प पर कोई आपत्ति है तो वह आयोग की वेबसाईट पर **Online Answer Key Objection** हेतु दिये गये लिंक पर जाकर अपनी आपत्तियों को आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार **दिनांक : 24 जुलाई, 2024 से 30 जुलाई, 2024 (समय रात्रि के 23:59:59 बजे तक)** तक दर्ज करा सकते हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा।

आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध लिंक **Online Answer Key Objection** के अतिरिक्त ई–मेल, डाक अथवा अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा अन्तिम तिथि के उपरान्त प्रेषित आपत्तियों तथा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान नहीं किये जाने की दशा में प्रस्तुत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। उत्तर कुंजी के सापेक्ष आपत्ति दर्ज किये जाने से पूर्व आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध दिशा–निर्देश सम्बन्धी विस्तृत विज्ञप्ति **पत्रांक :: 23/65/उ.कु.प्रसा./स0रा0(सिविल/प्रवर) अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2024/गोपन–3/2024–25 दिनांक : 23 जुलाई, 2024** का अध्ययन अवश्य कर लें।

(गिरधारी सिंह रावत) सचिव।

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON
See Section 82 Cr. P. C.

Whereas a complaint has been made before me that accused person namely **Zulfiqar Ahmed S/o Sh. Zafar** R/o House No.2979/XI, Kuncha Neelkanth, Darya Ganj, Delhi, who have committed (or is suspected to have committed) the offence under **FIR.No. 42/24 dt.12.01.2024 U/s 420 IPC.,** has been registered at **P.S. Darya Ganj Delhi** and it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said, **Zulfiqar Ahmed** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said, **Zulfiqar Ahmed** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant). Proclamation is hereby made that the said accused **Zulfiqar Ahmed of FIR. No. 42/24 dt. 12.01.2024 U/s 420 IPC., registered at PS. Darya Ganj, Delhi** is required to appear before this court to answer the said complaint on or before **03.10.2024.**

By Order
Sh. Raj Kumar Singh, Ld. MM, Central-05,
Room No. 241, 2nd floor, Tis Hazari Courts, Delhi

DP/9476/CD/2024

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF PERSONS ACCUSED
(See Section 82 Cr. PC)

Whereas complaint has been made before me tha two accused person namely **(1) Sanjeev Gupta (2) Rajeev Gupta C/o Sumit Jewellers & M/s Vaibhav Enterprises, 1-2, Chitra Gupta Road, Paharganj, New Delhi-110055 and R/o I-1806, Chitranjan Park, New Delhi and R/o M/s Viabhav Enterprises, 1574, Outram Line, Mukherjee Nagar, Delhi** has committed (or is suspected to have committed) the offence in case **Ct. Cases No. 531107/2016 U/s 200 Cr.P.C. IPC at PS: Kotwali, Delhi** and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said accused **(1) Sanjeev Gupta (2) Rajeev Gupta** can not be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused **(1) Sanjeev Gupta (2) Rajeev Gupta** has absconded (or is concealing themself to avoid the service of the said warrant). Proclamation is hereby made that the said accused **(1) Sanjeev Gupta (2) Rajeev Gupta of Ct. Cases No. 531107/2016 U/s 200 Cr.P.C. of PS: Kotwali, Delhi is required to appear before this court to answer the said complaint on or before 24.08.2024.**

By order
Sayesha Chadha
Metropolitan Magistrate-08
Room No.272
Tis Hazari Courts, Delhi

DP/9401/N/2024

235 NOTICES SENT TO EDU INSTITUTES OVER MOSQUITO BREEDING: MCD

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The public health department of the Municipal Corporation of Delhi (MCD) sent 235 legal notices and issued 67 prosecutions against educational institutions over mosquito breeding measures as part of a special drive last week said the civic body in their statement on Tuesday. Under this drive, the civic body conducted inspections at 2,370 educational institutes for detecting mosquito breeding and mosquitogenic conditions at 15% of the sites across the city.

The week-long drive carried out in all 12 zones of Delhi, aimed to check both private and government schools and other educational institutes for mosquito breeding, they said in an official statement. "All the MCD schools have also been inspected. Out of a total of 2,370 educational institutes, the breeding of mosquitoes was detected in 360 places. The larvae were destroyed using insecticides," they added.

A senior public health department official said that letters have been sent to all educational institutes, urging them to take preventive measures to control mosquito breeding. "We have also provided homework cards to encourage students to check and report any stagnant water pools around their houses and schools," the official added.

According to MCD data, Delhi reported 246 dengue cases in first six months of 2024, the highest in at least last decade.

Waterlogging, loose wire leads to electrocution of 26-year-old

Jignasa Sinha and Jasjeev Gandhiok
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A 26-year-old man was electrocuted to death after coming into contact with an iron gate during heavy rain in Patel Nagar, central Delhi, on Monday, police said. The man may have slipped on the waterlogged street and grabbed the gate for support, and was electrocuted due to an exposed motor wire, they said.

The deceased was identified as Nilesh Rai, an aspirant for the Union Public Service Commission (UPSC), who died just 50 metres from his paying guest accommodation. The incident took place around 2.40pm on Monday and an FIR was lodged, police said.

Deputy commissioner of police (central) Harsha Vardhan said, "We received a call at 2.43pm. A person was found stuck to an iron gate near the Patel Nagar Metro station due to an electric current in the gate. There was waterlogging on the road. The victim was taken to RML hospital, where he was declared dead."

Rai is survived by his two sisters and parents, who live in Ghazipur, Uttar Pradesh. His father Narender Rai is an advocate and his mother Neelam Rai is a primary school teacher. Rai completed his engineering from Bengaluru, but later decided to pursue becoming a civil servant.





The victim, Nilesh Rai; (left) the gate in Patel Nagar, which he touched and suffered the electric shock. SANCHIT KHANNA/HT

Rai's landlord, Atul Dua, said his wife called him at 2pm, telling him that a man was stuck to the gate. Dua used a scooter and plastic pipes to rescue Rai. "It was difficult to rescue him since the religious thread on his wrist was stuck to the gate. When I finally managed to pull him, I saw his face and was shocked. It was Nilesh..." Dua said.

The landlord said that Rai was returning from a library, and stopped to have tea at a stall in the vicinity before heading home.

A day after the incident, the street was still inundated with water and the entire lane was filled with exposed wires lying around the ground or hanging from poles. The iron gate, where Rai died, was surrounded by multiple wires, including those used for earthing.

At RML hospital, Rai's cousin, Indu Bhushan, a lawyer, said, "We are all shocked. He was the only son. He had appeared thrice for the UPSC exams and was finally able to clear the prelims test. We were all happy for him. How could this happen? Why were these exposed wires close to the house? We want police to investigate the case and make arrests."

A TATA Power DDL official attributed Rai's death to leakage of current from a damaged motor wiring. "Upon receiving the information, our breakdown team promptly arrived at the site. We urge the public to follow safety guidelines during monsoon," the spokesperson said.

Public outcry

Residents' welfare associations (RWAs) said they should be brought on board to coordinate with local discom teams given that monitoring loose wires is the need of the hour. "Every monsoon, we see such instances across Delhi. There is a need for greater accountability from all parties concerned, be it the road or landowning agency and the discom," Atul Goyal, president of the United Residents Joint Action (URJA), an apex body of over 2,500 RWAs in Delhi, said.

Aam Aadmi Party leader and Rajya Sabha MP Swati Maliwal, posted on X: "A UPSC student died after getting electrocuted on the road following rain in Delhi's Patel Nagar. This is not an accident, it is a murder caused by the failure of the government system. Is there no value for the lives of common citizens? What answer will that child's parents get? He died while walking on the road, sorry?..."

The Delhi unit of the Bharatiya Janata Party (BJP) also held the government responsible for the death. Praveen Kapoor, Delhi BJP spokesperson, said Rai died due to the negligence of AAP and demanded a compensation of ₹1 crore to the family.

The incident was the third rain-related electrocution death in the last month, since monsoon hit the national capital. On June 28, when Delhi received over 200mm of rainfall, a 39-year-old man was electrocuted in Rohini's Prem Nagar after he came in contact with a live wire on a waterlogged road.

On July 13, a 34-year-old woman was electrocuted on a waterlogged road in the Bhajanpura locality.

A BSES spokesperson said: "Safety inspections are being carried out on electrical equipment, including substations, feeder pillars, distribution boxes, and fencing across BSES areas to identify and rectify hazardous conditions, if any, and ensure the safety of the infrastructure."

The spokesperson said illegal wires were being removed and jumbled cables on electricity poles were also being sorted.

Man strangles brother-in-law, sets body on fire

Debashish Karmakar
letters@hindustantimes.com

GURUGRAM: A 21-year-old man was arrested for allegedly strangling his brother-in-law to death and setting his body afire using turpentine at an under-construction house in Sector 15, Part 1, for ostensibly mistreating his ailing sister, police said.

The incident took place on the intervening night of July 18 and 19. The suspect, identified as Rajesh Kumar alias Chotu, worked as a guard at the house.

He was arrested from Sector 29 on Sunday night and booked under sections 103 (1) (murder) and 3(5) (common intention), 238 (a) (causing disappearance of evidence) of the Bharatiya Nyaya Sanhita at Civil Lines police station, on a complaint filed by the contractor. He was remanded to police custody.

Inspector Arvind Kumar, station house officer (SHO) of Civil Lines police station, said that the deceased was identified as 32-year-old Gore Lal, who was from Chattarpur, Madhya Pradesh. "Kumar had tried to make Lal understand on multiple occasions to take care of his sister but the deceased didn't change his behaviour," he said.

The police were informed about the body on July 19 by workers at the site, who also said that the guard was missing.

Police said that Lal worked for a building contractor and lived with his wife, who was around 29 years old, in Sector 43. They had married around eight years ago and the woman was suffering from multiple medical complications for the past two months.

According to their enquiries, police said they found that Lal used to spend money on liquor instead of medications for his wife and also assaulted her, due to which her brother confronted him. As part of his plan, Rajesh Kumar invited Lal to dinner at the work site and got him drunk, following which Kumar allegedly strangled him.

Kumar then poured a can of turpentine oil and set the body afire, police said.

74-year-old run over by car in W Delhi, dies

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: A 74-year-old woman was mowed down, allegedly by a speeding car, in Rajouri Garden, west Delhi on Tuesday, said police. The driver of the Hyundai i20 car fled the scene, leaving the vehicle behind, investigators said.

No arrest was made till Tuesday night, and police were working to trace the accused.

Deputy commissioner of police (west) Vichitra Veer said that the accident took place on Najafgarh Road on Tuesday morning.

According to locals, the elderly woman was walking on the main road when she was struck by the speeding car. She was thrown on to the windshield and then on to the road. The driver did not stop and later abandoned the car.

Locals took the victim to a nearby hospital, where doctors declared her dead.

The deceased, identified as Amarjeet Kaur, was a widow and had recently lost her husband, Hardeep Singh, in January. She was a homemaker residing in Nihal Vihar, said police.

DCP Veer said, "The vehicle has been seized. The owner of the car has been identified as Geeta Malik from Rajouri Garden. Her house was locked. The car was either driven by her or her husband, Vijay Malik. Efforts are being made to trace the accused."

Pune man held from Kolkata for ₹92L fraud in Noida

Arun Singh
arun.singh@hindustantimes.com

NOIDA: A Pune-based man, who allegedly duped a Noida businessman of ₹92 lakh on the pretext of getting him sanctioned a loan of ₹60 crore from a Singapore-based bank, was arrested from Kolkata airport when he was about to flee the country, senior Noida police officers said on Tuesday.

The police added that the suspect was booked on charges of fraud at the Phase 2 police station on March 10, on a complaint from a resident.

"Complainant Hetal Verma, a resident of Sector 56, runs an export business in Noida's Sector 80. Verma complained to police that when he was looking for a business loan, he came in contact with suspect Abhishek Goyal through an acquaintance. Goyal promised to get him sanctioned a loan of ₹25 crore from a Singapore-based bank,"said Vindyachal Tiwari, the station house officer of Phase 2 police station in Noida.

"The suspect took all necessary documents from Verma and asked him to pay him 5% of the loan amount as fee. On September 28, 2023, Verma received a WhatsApp message mentioning that the bank had sanctioned him a loan of ₹60 crore." said Tiwari.

Later, Goyal asked Verma to buy e-stamp paper with a value of ₹3 crore to register an investment agreement.

The station house officer (SHO) said, "On the pretext of processing the ₹60 crore loan, Goyal duped Verma of ₹92 lakh. But when Verma did not receive a loan and found that the entire process was fake, the victim confronted the suspect. But Goyal threatened Verma with dire consequences if the matter was reported to the police."

"On a complaint by Verma, a case of fraud under relevant sections of the Indian Penal Code and IT Act was registered against Goyal at Phase 2 police station on March 10, and multiple teams were formed to nab him," said Tiwari, adding that a lookout notice was also issued against him.

On the night of July 20, Goyal was identified at the Kolkata airport, and Noida police were alerted.

"A team was sent to bring Goyal here and he was produced before a court in Kolkata for transit remand," said Tiwari, adding that Goyal was planning to leave the country and was travelling to Bangkok in Thailand.

Investigation also revealed that the suspect was jailed by Pune police in 2019 in a similar case of fraud, said police, adding that he was out on bail in that case.

"On Tuesday, he was produced before a court in Surajpur, and further investigation is underway," said Tiwari.

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ
जल संसाधन विभाग
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना – 01SBD/2024–25
शुद्धि–पत्र
(Email Id- wwaysmohania@gmail.com)
Mob :- 7463889406

पत्रांक 866

इस कार्यालय का पत्रांक 848 दिनांक 15.07.2024 द्वारा निविदा आमंत्रण सूचना संख्या 01SBD/2024–25 जिसका PR-004027 (WRD) 2024-25 है, अपरिहार्य कारण से उक्त प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना में निम्न संशोधन किया जाता है:–

क्र0सं0	विवरणी	पूर्व में निर्धारित तिथि	संशोधित तिथि
01	निविदा कागजात डाउनलोड एवं अपलोड करने की अवधि	दिनांक 22.07.2024 से 29.07.2024 को 3:00 बजे अपराहन तक केवल वेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर	दिनांक 25.07.2024 से 01.08.2024 को 3:00 बजे अपराहन तक केवल वेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर
02	प्री बीड मीटिंग की तिथि समय एवं स्थान	दिनांक 23.07.2024 को 3:00 बजे अपराहन में सिंचाई भवन, पटना के सभाकक्ष (जल संसाधन विभाग, पटना) में।	दिनांक 26.07.2024 को 3:00 बजे अपराहन में।
03	तकनीकी बीड खोलने की तिथि एवं समय	दिनांक 31.07.2024 के अपराहन 3:30 बजे केवल बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर	दिनांक 03.08.2024 के अपराहन 3:30 बजे केवल बेवसाईट www.eproc2.bihar.gov.in पर

निविदा में प्रकाशित अन्य नियम एवं शर्त पूर्वतः रहेंगे।

कार्यपालक अभियंता
सिंचाई प्रमंडल, भभुआ

PR. No. 004448 (WRD) 2024-25

नशे से बचने का है एक ही उपचार, दृढ़ संकल्प और परिवार से प्यार।

UNION TERRITORY OF JAMMU & KASHMIR
OFFICE THE EXECUTIVE ENGINEER PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR, JAMMU

NOTICE INVITING TENDER
e-NIT No. 17 of 2024-2025 Dated 20.07.2024

For and on behalf of the **Lieutenant Governor, Union Territory of Jammu and Kashmir** e-tenders are invited on **percentage basis** from approved and eligible Contractors registered with Union Territory of J&K, CPWD, Railways, MES and other State/Central Governments for each of the following works:-

S. No	Name of Work	Name of Division	Advertised Cost (Rs. in lacs)	Cost of document (in Rs.)	Earnest Money (in Rs.)	Time Allowed for completion	Time and date of opening of tender	Class of Contractor
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Construction of Auditorium and Cafeteria including Parking Store lift and Ramp etc at CD Hospital Jammu Balance work	PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu	112.00	3000	2% of Advertised Cost	06 Months	**06.08.2024 (12.00 Pm)**	"A" Class

Position of AAA: Accorded
Position of TS: Sanctioned
Position of Funds: Not Available

The Bidding documents Consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Drawings, bill of quantities (B.O.Q), Set of terms and conditions of contract and other details can be seen/downloaded from the departmental website **http://jktenders.gov.in** as per below schedule :-

1	**Date of Issue of Tender Notice**	**20.07.2024**
2	**Period of downloading of bidding documents**	**From 20.07.2024 to 05.08.2024 upto 1800 Hrs**
3	**Date, Time and place of pre-bid meeting**	**XXXXXXXX at XXXX Hrs. in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu**
4	**Bid submission Start Date**	**20.07.2024**
5	**Bid Submission End Date**	**05.08.2024 upto 1800 Hrs**
6	**Date & time of opening of Technical Bids (Online)**	**06.08.2024 on or after 1200 Hrs in the Office of Executive Engineer PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu**
7	**Date & time of opening of Financial Bids (Online)**	**To be notified after technical bid evaluation is completed**

1. Bids must be accompanied with cost of Tender document in shape of **e-challan through Treasury indicating Treasury Voucher No. & date, e-NIT No. and name of work duly crediting to MH 0059 (Revenue) favoring Executive Engineer PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu and upload the same i.e treasury challan/receipt,** Earnest money/Bid security in shape of **CDR/FDR/BG** pledged to **Executive Engineer PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu**. The CDR/FDR/BG shall be valid for 45 Days beyond the bid validity period. The original instruments in respect of cost of documents, EMD and relevant documents of **L1** be submitted to the **Executive Engineer PWD (R&B) DIVISION BAKSHI NAGAR Jammu** at the time of allotment.

No.:- EE/R&B/BN/2832-51 Dated:- 20.07.2024

(Er. Amit Sharma)
Executive Engineer
PWD (R&B) Division
Bakshi Nagar, Jammu

DIP-J-3258-24

Government of Union Territory Jammu & Kashmir
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER MECHANICAL AND HOSPITALS DIVISION SRINAGAR
Telefax:- 0194-2496089, Email ID:- xenmhchdk@yahoo.in

GIST of e-tender

e-NIT No: M&HD/TS /2024-25/48/ e-tendering **Dated: 20.07.2024**

For and on behalf of the Lt. Governor of Jammu and Kashmir UT, e-tenders, valid for 180 days, are invited from eligible Registered, reputed & experienced firms as detailed in the NIT for below mentioned works:

Name of Work	Est. Cost (Rs. in Lacs)	Cost of T/Doc. (In rupees)	Time of completion (in months)	Earnest Money Deposit (In Lacs)	Position of Funds
1	2	3	4	5	6
1. Upgradation of Infra structure for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar by way of Design, Supply, Installation, Testing and Commissioning of Modular Operation Theatres Along With MGPS & HVAC system and CMC for one year of MOTs post one year warranty period for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar.	105.7	5000	06 months	2.11	Available with the intending department

o **Authorization conveyed Vide Principal, GMC Srinagar vide Order No:- 32 MCS of 2022, Dt: 20.08.2022 and Executive Engineer R&B Division Karanagar Srinagar's letter No. EE/R&B/KNR/CS/782-84, Dated:- 11.05.2024**

o **Technical Sanction: Accorded vide No: MHED/K/TS/10 , Dt:- 12.06.2024**

The Bidding documents consisting of qualifying information, eligibility criteria, specifications, Drawings, bill of quantities (B.O.Q) set of terms and conditions of contract and other details can be seen /downloaded from the website **www.jktenders.gov.in** as per the below schedule:

1.	Date of issue of Tender Notice	20.07.2024
2.	Period of downloading of the bidding document	From 20.07.2024 (1800 HRS) to 01.08.2024 (1200 HRS)
3.	Bid Submission Start Date	From 20.07.2024 (18.00 HRS)
4.	Bid Submission End Date	01.08.2024 (1200 HRS)
5.	Cost of Bidding Document	**Rs. 5000/- For Upgradation of Infra structure for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar by way of Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Modular Operation Theatres Along With MGPS & HVAC system and CMC for one year of MOT's post one year warranty period for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar.**
6.	Tender document fee to be deposited in	**In the shape of e-challan in account Account no:-0005010100005109. Name :- Executive Engineer M&HD Srinagar. Name of the Bank:- Jammu & Kashmir Bank. Branch Name:- Residency Road Srinagar. Branch Code:- CHINAR IFSC Code:- JAKA0CHINAR MICR CODE:- 190051066 or by uploading a copy of treasury challan/receipt in favour of the Executive Engineer, M&HD, Srinagar to be deposited in Major Head 0059.**
7.	Earnest Money Deposit	**Rs 2.11 Lacs (For Upgradation of Infra structure for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar by way of Design, Supply, Installation, Testing & Commissioning of Modular Operation Theatres Along With MGPS & HVAC system and CMC for one year of MOT's post one year warranty period for ENT Extension Block at SMHS, Hospital, Srinagar). In case of unsuccessful bidder, the EMD shall be released immediately after issuance of Award Of Contract to the successful bidder and in case of successful bidder the same shall be released after submission of Performance Guarantee of 05% of advertised cost in the shape of FDR/BG.**
8.	Date and time for opening of the Technical Bids online	01.08.2024 at 1400 HRS in the office of **Executive Engineer, M&H Division, Srinagar**
9.	Date & Time of opening of the Financial Bids (online)	To be notified after technical bid evaluation is completed

No: M&HD/TS/2331-35
Dated: 20.07.2024
DIPK-3328-24

Sd/-
Executive Engineer
M&HD, Srinagar

BSES Yamuna Power Limited

BSES Yamuna Power Limited, Delhi
... A joint venture with Govt. of NCT of Delhi

NOTICE INVITING TENDER **Date: 24.07.2024**

E-tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) are invited as per the following details:

NIT No.	Tender Description	Estimated Cost (₹)	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
CMC/BY/24-25/RS/SkS/MD/24	Supply of Single phase 11 kV insulated type drop out fuse unit.	2.50 Crore	5.00 Lakhs	13.08.2024 14:00 Hrs	13.08.2024 15:00 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SkS/MD/25	Supply of 33KV & 66KV Outdoor CT & PT of various ratings.	1.10 Crore	2.20 Lakhs	13.08.2024 14:00 Hrs	13.08.2024 15:00 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SkS/MD/26	Supply of 33KV & 66KV Outdoor CVT	0.60 Crore	1.20 Lakhs	13.08.2024 14:00 Hrs	13.08.2024 15:00 Hrs
CMC/BY/24-25/RS/SvS/AS/27	Award of work for Servicing / Repairing of Distribution Transformers of various ratings at BYPL's Workshop for 2 Years	3.60 Crore	7.20 Lakhs	14.08.2024 11:00 Hrs	14.08.2024 11:30 Hrs

Cost of each Tender Document: **₹1,180/-**
For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents, corrigendum etc. please visit our website **www.bsesdelhi.com --> BSES YAMUNA POWER LTD--> Tenders-->Open Tenders.**

Head (Contracts & Materials)

Regd.Off: BSES Yamuna Power Ltd, Shakti Kiran Building, Karkardooma, Delhi-110032 | CIN: U40109DL2001PLC111525
Website: www.bsesdelhi.com

Development Support Agency of Gujarat
(D-SAG)
An autonomous Society promoted by **Tribal Development Department,** Government of Gujarat

Request For Proposal

Development Support Agency of Gujarat (D-SAG) had invited Expression of Interest (EoI) from Applicants for implementing "Vocational Training Centres" through leading Employer Organizations".The R.F.P document was published on dated 04/02/2024. Regarding the same **Revised R.F.P. Document** can be downloaded from the websites www.dsag.gujarat.gov.in and www.dsagsahay.gujarat.gov.in from **24/07/2024, 12:00 PM** Hours onwards.

Important Dates:	
R.F.P. Downloading Date/Time	**24/07/2024, 12.00 PM**
Last Date/Time for Submission of EoI	**31/12/2024, 05.00 PM**

Interested applicants are requested to download the R.F.P document from the above-mentioned websites. Completed proposals can be submitted **on any working day after the start of application process.**

Further details can be obtained from the office of Development Support Agency of Gujarat (D-SAG) Third Floor, Birsa Munda Bhavan, Gandhinagar. Gujarat- 382010. Phone : (079) 232-58617.

Chief Executive Officer
Development Support Agency of Gujarat
Gandhinagar

INF/567/24-25

F. No. 13/03/2024-EC
Ministry of Power
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg
New Delhi-110001
VACANCY CIRCULAR

Bureau of Energy Efficiency (BEE) is a statutory body under the Ministry of Power, Government of India, established under the provisions of Energy Conservation Act, 2001 to promote energy efficiency in the country. The Director-General is its Chief Executive Authority and is responsible for the successful implementation of the objectives of the Bureau of Energy Efficiency.

It is proposed to fill up one (01) vacant post of Director General, in Bureau of Energy Efficiency (a non-CSS post) in Level-15 of pay matrix on Deputation (including Short Term Contract) basis. The details like general conditions of service, Eligibility Criteria, Age limit, proforma of application form etc. are available on the website of Ministry of Power and Bureau of Energy Efficiency at the links **https://powermin.gov.in/** & **https://beeindia.gov.in/en**. The application forms **(only in the prescribed proforma)** along with copy of all the necessary documents in support of their claim for age, educational qualification(s) and experience(s) may be submitted to the Director (EC), Room No. 201-F Wing, Second Floor, Nirman Bhawan, New Delhi-110011 through Speed post/Registered Post only within **45 days** of publication of this advertisement in the Employment News.

Under Secretary (EC, ET & EV)
Ministry of Power

CBC 34101/11/0004/2425

NEW DELHI, **WEDNESDAY, JULY 24, 2024**

TO BOOK YOUR AD CALL **0120-4834999 (9 am to 9 pm, Everyday)**
OR E-MAIL **htclassifieds@hindustantimes.com**

HT Classifieds {Wednesday}

SCAN THE CODE TO BOOK YOUR ADS ONLINE

www.htclassifieds.com

EDUCATION/ADMISSIONS

Bharatiya Vidya Bhavan
Promoting SANSKRIT & SANSKRITI Since 1938

ADMISSION OPEN

The Best Professional Job Oriented Courses (Evening Classes)

- PG DIPLOMA IN MASS COMMUNICATION AND JOURNALISM
- PG DIPLOMA IN PUBLIC RELATIONS AND EVENT MANAGEMENT
- PG DIPLOMA IN MARKETING AND ADVERTISING
- PG DIPLOMA IN MARKETING AND SALES MANAGEMENT

Forms Available Upto 31.07.2024 | Classes From: 12.08.2024 | Eligibility: Graduation

BHARATIYA VIDYA BHAVAN SP COLLEGE OF COMMUNICATION & MANAGEMENT
Mehta Sadan, Room Number- 7, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110001
TEL: 011-23389942 9818452917, 7838811279, 8882808482
Website: www.bvbdelhi.org / Email: spccm@bvbdelhi.org

बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटेक्निक
BABA SAHEB AMBEDKAR POLYTECHNIC
BSAP AICTE APPROVED AFFILIATED TO HSBTE CODE-467
राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित
AFFILIATED TO STATE BOARD OF TECHNICAL EDUCATION & APPROVED BY AICTE, GOVT. OF INDIA

DIPLOMA
1st YEAR/ LATERAL ENTRY (2 YEARS) FOR 10+2

MECHANICAL ENGG. | ELECTRONICS ENGG.
ELECTRICAL ENGG. | AUTOMOBILE ENGG.
COMPUTER SC. & ENGG. | CIVIL ENGG.
MEDICAL LAB TECHNICIAN

Kindly refer website: www.bsates.com
Certification: Successful candidates will be awarded Diploma by BTE (Approved by AICTE, Govt. of India) which are applicable for all Central/ State Govt. posts and services.
Age: As prescribed for the course applied.
Eligibility: 10th pass for 1st Year /12th OR ITI pass for Lateral Entry
Scholarships: Candidates belonging to SC/ST category and having valid Income Certificate, may apply for Scholarship Scheme of Govt. of India.

Plot No.13, Bodhella, Vikaspuri, New Delhi-110018
7703917546, 7011331839, 7011291459

MEWAR INSTITUTE
Affiliated to C.C.S. University, Meerut
App. by Bar Council of india, N.Delhi
Admission 2024-25 Estd 1997
Premier Institute in NCR

LLB | BA-LLB | BBA | BCA | B.Com | B.Ed

Other courses available:
B.Sc (Math), M. Sc. (Bio-Tec), LLM, BTC

Sec-4C, Vasundhra, Ghaziabad
0120-2698218/19/20, 9818511145

To place a Classified ad
Log on to htclassifieds.com or Scan QR code

BE INDUSTRY READY

MCA
SPECIALISATION : • DATA SCIENCE • ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)

MBA 15th Batch
SPECIALISATION : MKT., HR, FIN., IT, IB, Operation •Advance EXCEL •Digital Mktg. •Supply Chain •Mandatory Internship
ADMISSION OPEN | Placement Upto 80%
Highly Qualified Faculty from DU/PU/AMU/IPU/Corporates
Issued 207 Offer Letters in a Single Day at HBS Campus Noida in MEGA JOB FEST 2023
www.hierank.in

BBA 19th Batch
• TALLY & GST • DIGITAL MARKETING
• ADV. EXCEL • REASONING & APT.
120 hrs. module with Univ. Syllabus

BCA Internship Mandatory 117 Recruiters | ADMISSION OPEN
• FULL STACK • WEB DESIGNING
• ARTIFICIAL INT. (AI) • ADV. EXCEL
Oldest B.School Providing Industry Ready Degree Since 2006

HIERANK BUSINESS SCHOOL
Enhancing Competence
• Affiliated to NAAC A++ AKTU, CCSU
• Approved by AICTE
A-42, Sector-62, Noida (Opp. 63 Metro Stn.)
Call: 96508 48777 • 99101 72577
www.hierank.org

HT Classifieds


Image by Freepik

Advertising Rates
HT City Delhi (NCR) CD/Block : ₹150/- per sq.cm. (B/W Color)
Publication Date : 28 July 2024
Booking deadline 26 July 1:00 PM sharp.

To book your ad, contact us:
NORTH DELHI: Vishal Sachdeva: 9910249013
EAST & CENTRAL DELHI: Sumit Negi: 9899268321
WEST DELHI & FARIDABAD: Ranjeet Singh: 9911819105
SOUTH DELHI & GURGAON: Abhishek Tiwari: 9899865804
NOIDA & GHAZIABAD: Gaurav: 8630242501 | Telebooking: 1800-103-1800
+GST as applicable | *T&C Apply

TRAVEL & TOURS

NORTH INDIA'S BEST COMPANY
CAAN Wings Consultants Pvt. Ltd.
License No. 301MC-1MA
329, New Jawahar Nagar, Jalandhar (Also In Delhi B-Block GK1)

AUSTRALIA
491 VISA GRANTS
11 SKILLED MIGRANT VISA GRANT IN 1 DAY



ALSO APPLY STUDY/ PR VISA
CANADA- USA-UK-EUROPE
7701 88 76 76, 87250-55656

PUBLIC NOTICES

PUBLIC NOTICE

This notice is hereby given to the general public at large that Late Sh. Harbans Rai Wadhwa S/o Late Sh. Bansi Lal Wadhwa had died on 21st January, 2012 and Late Smt. Santosh Kumari w/o Late Sh. Harbans Rai Wadhawa resident of H.No. 3125, Sector 40-D, Chandigarh died on 1st February, 2024 intestate leaving behind only three daughters (hereinafter referred to as my clients) namely 1) **Smt. Meenu Gupta W/o Sh. Ajay Gupta D/o Late Sh. Harbans Rai Wadhwa** presently residing at Group Housing 4, Flat no 231 Sector 24 Panchkula 134116, permanent resident of 4 Greybox St Box Hill, NSW 2765- Australia, 2) **Smt. Mona Nanda W/o Sh. Arun Nanda D/o Late Sh. Harbans Rai Wadhwa** presently residing at House No. 3096, Sector 40-D, Chandigarh, permanent resident of 21 Heavey Street Werrington Sydney- 2747 and 3) **Smt. Jyoti Jasuja W/o Sh. Pawan Kumar Jasuja D/o Late Sh. Harbans Rai Wadhwa** resident of Flat No. 2130, Catiana Tower, Mahagan Moderne, Sector-78, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar-201301 UP who have mutually and voluntarily entered into a family settlement on 13th day of February 2024 which has been reduced into writing by way of memorandum of family settlement on this 12th day of July 2024 admitting and accepting 1/3 share for each sisters in all the moveable and immovable properties of their deceased parents being their only class-1 legal heirs. Details of the immovable properties are as under: -

a) Property/ plot bearing no: 848, Sector-9, Gurgaon which is in the name of the mother of the parties namely late Smt. Santosh Kumari.

b) Property/ house bearing no:677, Sector-4, Panchkula which is in the name of the mother of the parties namely late Smt. Santosh Kumari.

c) Property bearing no: 3125, Sector- 40-D, Chandigarh which is in the name of the father of the parties namely late Sh. Harbans Rai Wadhwa.

Any person and / or persons having any right, claims, interest or otherwise are requested to inform the same in writing along with the proof regarding the same to the undersigned within 15 days from the date of publication of this notice failing which the claim(s) if any of such person(s) shall be deemed and treated to have been waived in all respects and not binding upon my clients.

Place: Panchkula
Date: 12.07.2024
Shakti Paul Sharma, M.A, LL.B, LL.M (Advocate)
Office-cum-resi: # 116, Sector-7, Panchkula, Haryana, 134109
Mobile: 9216734709
Tele Fax: 0172-4634709
E-mail: indiancourts@gmail.com

EDUCATION

9210027962 , 9810582924
LLB (3/5Yrs), LLM, P.HD
B.ED, M.ED, JBT
MBA, MCA, M.SC
D. PHARMACY, B. TECH, M. TECH
BA, B.COM, BBA, BCA, B.SC
MA, M.COM, MPT, BPT
Library Course, Yoga & Naturopathy
Fine Arts, Journalism & Mass Comm
10th &12th(OPEN SCHOOL)
RBA COLLEGE
E- 44, Nehru Ground NIT Faridabad

ADMISSIONS

LL.B(3/5 YRS) CH. Charan Singh University, No Age Limit, Flexibility in Attendance, (BA,B.COM,MBA,B.ED in distance mode Available) Legal Professional Academy M: 8287845744

PROPERTY

WEST DELHI

Commercial
Lease/Sale
Location:
Shivaji Enclave (Near Raja Garden Terminal/ Shivaji College)
Plot size: 360 sq. yd.
Built-up: 6 Floors
Ground 2916,
1st/2nd/3rd 2808 sft.
with Basement,
Stilt parking, Lift
Excellent Connectivity
Call: 9810057795

CHANGE OF NAME

I, SANDEEP Ahlawat S/o Sh. Karam Veer Singh R/o H. No. 280-B, Subhash Nagar, Rohtak declare that I have changed my minor daughter name from Prisha to Prisha Ahlawat. In future she will be called by the name of Prisha Ahlawat for all Purposes.

I, AARTI Tandon (Indian Passport No: Z5310647) D/o Rajnish Rai Tandon, R/o C-2/52, Sec-31, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201303, after my divorce, have changed my minor daughter's name from Mysha Khan to Mysha Tandon for all future purposes.

I, MADHURIMA Tatia, W/o Shri Rajendra Mal Tatia, R/o 143-D, Pocket B, Mayur Vihar Phase-2, Delhi 110091 have changed my name from Madhurima Mehta to Madhurima Tatia for all purposes.

I, MEGHA Mendiratta W/o Shri Nitin Mendiratta R/O House No.3D/57, BP Block-D, NIT-3, Faridabad, Haryana-121001 have changed my name from Megha Gulati to Megha Mendiratta for all future purposes.

CHANGE OF NAME

I, YOGESH s/o Sh. Ram Ratan Sharma R/o Mata Wali Gail, Village Tilpat, Amar Nagar, Faridabad, Haryana-121003, I have Change my name from Yogesh to Yogesh Sharma, Yogesh and Yogesh Sharma both are my names, my name Yogesh Sharma for all Purposes in Future.

I, JANKI Prasad S/O Karan Singh R/O H.No. A-118, Gali No.3, Prem Vihar, Karawal Nagar, North East Delhi-110094, have changed my name from Janki Prashad to Janki Prasad. For all future puposes.

I, AARTI Tandon (Indian Passport No: Z5310647) D/o Rajnish Rai Tandon, R/o C-2/52, Sec-31, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201303, after my divorce, have changed my minor daughter's name from Nousha Khan to Nousha Tandon for all future purposes.

I HITHERTO known as Sunila Dutta D/o Prem Prakash Dutta W/o Atul Khullar R/o C-58 Chattarpur Enclave Phase 2, New Delhi-110074 have changed my name after marriage and shall hereafter be known as Sunila Khullar for all future purposes. It is certified that I have complied with other legal requiremenmts in this connection.

I, JAGMOHAN Singh Gusain S/o Raje Singh Gusain R/o TA-156, Third Floor, Right Side Front, Gali No.3, Near Gurudwara, Tughlakabad Extn., New Delhi-110019 declare that my name is wrongly mentioned as Jagmohan Singh in my educational certificate. My correct & actual name is Jagmohan Singh Gusain & I should be known as Jagmohan Singh Gusain for all future purposes. I also declare that my father's name is wrongly mentioned as Raje Singh in my educational certificate, My father's correct name is Raje Singh Gusain & it is correctly written as Raje Singh Gusain in my Aadhar Card 700990287088 & my Pan Card BCGPS9745D.

I, LOKESH Mittal S/o Shri Ram Pratap Mittal R/o Flat No.201, Tower-D1, SRS Royal Hills Apartments, Sector-87 Faridabad, Haryana-121002 have changed my name from Lokesh to Lokesh Mittal for all future purposes.

I, SRISHTI Gupta Mittal w/o Harsh Dev r/o 15, Inder Enclave, Rohtak Road, New Delhi - 110087 inform that after marriage I have changed my name from Srishti Gupta to Srishti Gupta Mittal residing at above address, for all future purposes.

I TALVINDER Kaur Popli W/o. Harnam Singh Popli R/o 2/417, Subhash Nagar, New Delhi-110027 have changed my name to Tanu Popli for all future purposes.

I, PRIYA Verma D/o Sh. Bharat Bhushan R/o 2128, Rani Bagh, Delhi-110034, I have changed my name to Priya Rekhi for all future purposes.

I, PARVEEN Kumar S/o Shri Mool Chand R/o E-127, Sector-27, Noida, Distt. Gautam Budh Nagar, UP-201301 state that Parveen Kumar, Praveen Sharma, Praveen Kumar Sharma & Parveen Kumar Sharma these names are the same & one person but I will be known as Praveen Sharma for all future purposes.

CHANGE OF NAME

I, BHAWNA W/o Rubal Chhabra R/o Farm No. 5A, Westend DLF Chattarpur Farms, South Delhi-74, have changed my name to Bhawna Chhabra for all future purposes.

I, RIZVANA Khatoon W/o Shakil Ahmad, R/o H. No. G-581, Gali No. 12, Janta Enclave, Prem Nagar-III, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, declare that my name is wrongly mentioned in my son's school record as Rijwana Khatoon. I.e. Rizvana Khatoon & Rijwana Khatoon are one & same person.

I, MANU S/o Mangalananda Panicker R/o 1630, GF, HBC, Sector 29, Faridabad, hereby declare that the name Manu appears in my school/ college documents, while other documents mention my name as Manu Panicker. I declare that Manu Panicker is my true name for all future purposes. I further declare that Manu and Manu Panicker refer to the same person.

I, SUBHASH Chander Batra S/o Shri Dina Nath Batra R/o H.No.1457, Sector-16, Faridabad (Haryana) 121002 have changed my name from Subhash Batra to Subhash Chander Batra for all future purposes.

I RAPINDER Kour W/O, Harmeet Singh R/o 1204 - Nova West, Supernova, Sector-94, Noida, Uttar Pradesh have changed my name to Rapinder Kaur, for all future purposes.

I DENCI Mol Augusthy W/O Jaimon John R/o Ekta Apartments, Flat No.203, Plot No.90, Ward No .2, Mehrauli, New Delhi - 110030.\r\n have changed my name from Denci Mol Augusthy to Denci Mol Jaimon.

I, AARTI Tandon (Indian Passport No: Z5310647) D/o Rajnish Rai Tandon, R/o C-2/52, Sec-31, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201303, after my divorce, have changed my minor son's name from Aamish Khan to Aamish Tandon for all future purposes.

I, KULDEEP S/O Sh. Amar Singh R/O H-1/28, First floor, Front Side Gali No.-27,Rajapuri Uttam Nagar West Delhi-110059 declare that my minor Daughter's and wife name wrongly mentioned in daughter school records that is Anshika and Renuka. But my Daughter and wife correct name is Anshika Dahiya D.O.B. 27-11-2010 and Renuka Kumari which may be amended accordingly.

I, AARTI Tandon (Indian Passport No: Z5310647) D/o Rajnish Rai Tandon, R/o C-2/52, Sec-31, Noida, Gautam Budh Nagar, UP-201303, after my divorce, have changed my minor daughter's name from Takisha Khan to Takisha Tandon for all future purposes.

I, SHAKIL Ahmad S/o Khalik Ahmad, R/o H.No. G-581, Gali No. 12, Janta Enclave, Prem Nagar-III, Kirari Suleman Nagar, Delhi-110086, declare that my name is wrongly mentioned in my son's school record as Md Shakeel. I.e. Shakil Ahmad & Md Shakeel are one & same person.

I, SUNIL Kumar Ved S/o Rajay Singh R/o 319, Sector-2, R.K. Puram, Sec-5, New Delhi-110022, have changed my minor son's name from Vyom Vedh to Vyom Vaid for all future purposes.

CHANGE OF NAME

I, KUMUD Pradeep Diwan W/O Pradeep Diwan born on 01/04/1961 residing at C-73 Anand Niketan, ND 21, have changed my name to Kumud Diwan vide affidavit dated 22/07/24 at Delhi

LOST & FOUND

I RITU khanna (Ritu Batra - after my marriage) have lost share certificates of ESCORTS KUBOTA LIMITED bearing certificate Nos. 952034to 952036 and distinctive Nos from 38395038 to 38395187. If anyone happens to find these physical share certificates these may please be returned to me at my address 5/3 Teg Bahadur Road, Dalanwala. Dehradun 248001 - Uttarakhand

I, SAURABH Srivastava S/o Late Rameshwar Dayal Srivasatav R/o H.No. C-482 Defence Colony, New Delhi-110024 have lost my property documents Khewat No.66, Barkaba 2686,property registration dated 19.06.1985 Registration No.2881 Goan Moja Kot Faridabad. Finder may contact on residence address.

I, AKSHAY Sabharwal, S/o Mr. Manjeet Sabharwal, have lost allotment letter of my flat No. 12, Gr. Flr, EWS, Heritage Max, Sector-102, Dwarka Expressway, Gurgaon. finder please. call 9599999132.

I, BIJU John S/o Sh. C.J John have lost original possession Letter/H/T Over of Flat No. C-303, Om Satyam CGHS Ltd, Plot No. 13, Sector-4, Dwarka, N.D. Finder Pls Contact:9350657360

I, DALVINDER Singh Sodhi S/o Kashmir Singh Sodhi R/o B-2/6 First Floor, Vasant Vihar, New Delhi-110057, Have Lost / Misplaced Original Sale deed, Registered Documents of property no DSS-1, Sector 46, Gurugram, Haryana, finder may Contact: 9968007800

PERSONAL

I, NIDHI Singh D/o Kanwar Pratap Singh R/o 38-A Vijay Block Laxmi Nagar Delhi-110092 had changed my name to Nidhi Soni W/o Akhil Soni after my marriage. Now I have again changed my name back to my maiden name Nidhi Singh D/o Kanwar Pratap Singh. From today I will be known/ called as Nidhi Singh D/o Sh Kanwar pratap singh R/o 38-A Vijay Block Laxmi Nagar Delhi-110092

HT Classifieds
WISH TO PLACE AN AD WITH US
E-MAIL OR CALL US

counterclassifieds @ hindustantimes.com
1800-103-1800
STAY HOME STAY SAFE

TENDER NOTICE

DELHI CONSUMER'S COOPERATIVE WHOESALE STORE LIMITED
(APEX LEVEL COOPERATIVE ORGANISATION, UNDER GOVT. OF NCT OF DELHI)
KARAMPURA ROAD, MOTI NAGAR, NEW DELHI – 110015. PH. 9871003343
E-PROCUREMENT
TENDER NOTICE
TENDER I.D. NO. 2024_DCCWL_259572_1.

E-Tender are invited from leading contractors for sale of lifting of empty cartons of IMFL/IFL/Beer/Country Liquor from the Liquor Vends of DCCWS Ltd. situated in Delhi/New Delhi for the period of one year from 05/08/2024. Tender Forms can be downloaded from the website http://govtprocurement.delhi.gov.in upto 2.00 p.m. on 30/07/2024.

Schedule of E-tender is as under:
1. Last Date & Time of submission of bid on 30/07/2024 upto 2.00 p.m.
2. Date & Time for opening of Technical bid on 30/07/2024 upto 3.00 p.m.
3. Date & Time for opening of Financial bid on 02/08/2024 upto 3.00 p.m.

MANAGER (C.T.)
DCCWS LTD.

PUBLIC NOTICES

Public Notice

Sub: Transfer of ownership in respect of B-34 Omaxe RPS Green Valley, Sec 41-42, Faridabad-121010, Haryana, consequent upon the intestate death of Joint owner Late Shri Uddalak Gupta S/o Late Ashok Gupta. Late Shri Uddalak Gupta who was the joint owner of the subject of the cited property as per record died on 15.10.2022 leaving behind the following legal heirs Smt. Ruhani Kaur (wife) and Idha Gupta (daughter). Ruhani Kaur w/o Late Shri Uddalak Gupta who is already the joint owner of the cited property intends to apply for transfer of the said property in her and her daughters favour being the legal heirs and requests for re-allotment in the name of Smt. Ruhani Kaur and Idha Gupta. If any person is having any objections against the transfer of the said property, he/she can submit objections in writing to the Estate Officer, HUDA, Faridabad, along with supporting documents within 30 days of the publication of this notice, otherwise the Estate officer may accord permission to transfer/ re-allot the said property as per Huda Policy and many not entertain subsequent claim if any.
Legal Heir Smt. Ruhani Kaur & Idha Gupta

Public Notice

Subject: Transfer of ownership in respect of House No. 306 Sector- 38 HUDA Urban Estate Gurugram -2 Haryana Consequent upon the intestate death of Late. Shri. Govind Prasad Mundhra S/O Late Sh. Madan lal Mundhra as per records, died on 19.05.2023 , leaving behind the following legal heirs:- 1. Manju Mundhra (Wife) 2. Abhinav Mundhra (Son), 3. Amrita Mundhra (Daughter)

Manju Mundhra W/o Late Sh. Govind Prasad Mundhra R/o House no.306 Sector 38 Gurgaon Haryana intends to apply for the transfer of the said in her favour though the legal heirs and request for re - allotment in the name.

If any person is having any objection to the above transfer of the said house, he/she/they can submit objections to The Estate Officer 2, HSVP, Sector - 34 Gurugram along with the supporting documents within 30 days of publication of this notice. Otherwise the Estate Officer may sanction mutation of the property as per HSVP policy and may not entertain subsequent claims if any.
Manju Mundhra (Legal Heir)On behalf of Estate officer- 2

PUBLIC NOTICES

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership in respect. of House No. 446 , Surya Nagar Phase -2, Sector-91 MCF Office Tilpat Faridabad in respect of 100% share upon the death of **Smt Rani Bhardwaj W/o Sh Hariom Bhardwaj**.

Smt Rani Bhardwaj was the owner of the subject cited property to the extent of 100% share as per record has died on 05-05-2021. She had not unregistered WILL & Leaving behind the following legal heirs, Hariom Bhardwaj (Husband) Piyush Bhardwaj(Son), Sh Devansh Bhardwaj (Daughter), there are no other legal heirs. Now **Sh. Hariom Bhardwaj S/o Late Sh Sh Ganga Sahai** R/o H.No. 446 Surya Nagar Part -2 Sector -91 MCF Office Tilpat Faridabad, intends to apply for the transfer said property in favour of legal heirs. If any person is having the transfer of house they can submit objections in writing to the Joint Commissioner (MCF) Old Faridabad. along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice. Otherwise said officer may sanction mutation of the property as per MCF policy & may not entertain subsequent claim if any.
Legal Heir : Hariom Bhardwaj

PUBLIC NOTICE

Subject:- Transfer of ownership in respect of H.No.2352, Sector-9, in Urban Estate Faridabad, Haryana in Death Case.

Sh. Prem Parkash Gandhi S/o Late Sh. Ushnak Rai Gandhi R/o H.No. 2352, Sector-9, Faridabad, Haryana, who was the Owner/allottee of 100% share of the subject cited property as per HSVP record. Sh. Prem Parkash Gandhi S/o Late Sh. Ushnak Rai Gandhi has died on 10.06.2018, have no registered or un-registered will, leaving behind legal heirs namely (1) Neelam Gandhi (Wife) (2) Rashi Khosla (Daughter) (3) Rachit Gandhi (Son) (4) Shanti Devi (Mother).

Now **Smt. Neelam Gandhi W/o Late Sh. Prem Gandhi @ Prem Parkash Gandhi R/o H.No. 2352, Sec-9, Faridabad, Haryana,** intend to apply for the transfer of 100% share of the said property in her favour being the legal heirs. If any person is having any objection against the transfer of ibid/above house/property, he/she can submit objections in writing to the Estate Officer, (Haryana Sahri Vikash Pradhikaran) HSVP, Faridabad, Haryana along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice, otherwise the Estate Officer, HSVP, Faridabad, Haryana may accord permission to transfer of the said property as per HSVP policy and may not entertain subsequent claim, if any.
Legal Heir- Smt. Neelam Gandhi

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership of House No. 601 Sector-19, Faridabad in respect of 100% share upon the death of **Sh. Khilanda Ram @ Khilanda Ram Bhugra S/o Late Sh. Tara Chand.**

Sh. Khilanda Ram @ Khilanda Ram Bhugra was the owner of the subject cited property to the extent 100% share as per record has died on 24.09.2011 and he had execute a registered WILL in favour of Sh. Surender Kumar Bhugra (Son), & Dheeraj Kumar Bhugra @ Avinash Kumar Bhugra vide document no. 495 dt. 19.12.2005 registered in the office for Sub Registrar Faridabad. & Leaving behind the following legal heirs :- Yashpal Bhugra (Son, Died on 22.05.2013), Surender Kumar Bhugra (Son), Kanchan Lata Malik (Daughter), Seema Amar Dudeja (Daughter) and there are no other legal heirs.

Sh. Surender Kumar Bhugra S/o Late Sh. Khilanda Ram & Sh. Avinash Kumar Bhugra @ Dheeraj Kumar Bhugra R/o House No. 601, Sector 19, Faridabad intends to apply for the transfer of the said property in their favour on the basis of regd. will being legal heirs. If any person is having objection against the transfer of plot/house, he/they can submit objections in writing to the Estate officer, HSVP Faridabad. Along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice. Otherwise the Estate officer may sanction mutation of the property as per HSVP policy and may not entertain subsequent claim if any.
Legal Heirs : Surender Kumar Bhugra
Avinash Kumar Bhugra @ Dheeraj Kumar Bhugra

PUBLIC NOTICES

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्री साबिर खान पुत्र श्री सद्दीक खान निवासी मकान नं0 बी0ई0–एस0टी0 जामिया मॉडल स्कूल के पास, बडखल कॉलोनी फरीदाबाद हरियाणा का रहने वाला हूँ और ब्यान करता हूँ कि मेरे पिताजी स्व0 श्री सद्दीक खां पुत्र श्री अब्दुल हफीज की मृत्यु दिनांक 22.01.2024 को हो चुकी है। यह कि मेरे पिताजी स्व0 श्री सद्दीक खां पुत्र श्री हफीज अपने जीते जी मेरे नाम पर वाका मौजा बडखल तहसील बडखल जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित मु0 नं0 67, कीला नं0 8/3(3–17) 13(8–0) व 14(3–19), 17(7–19), 18(5–17) व कीला नं0 17 व 14/1 में से टुकडा नं0 18 व 19 बारकबा 100 वर्गगज बापेमाईश 20 फुट जरब 45 फुट जिसके पूर्व में बकाया हिस्सा प्लाट नं0 19 का, पश्चिम में प्लाट नं0 18 का बकाया हिस्सा उत्तर में प्लाट नं0 24–25 व दक्षिण में रास्ता 18 फुट लगता है की बाबत वसीयतनामा शुदा वसीका नं0 574 दिनांक 08.12.2021 कार्यालय सब रजिस्ट्रार बडखल में पंजीकृत करवाया था। अब उक्त इंतकाल/विरासत मेरे नाम दर्ज व मंजूर किया जाये।

शपथी श्री साबिर खान

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership in respect of one-half share in respect of House 678-P, Sector-37, Faridabad, upon the death of Shri P.K. Kodnani son of Shri Kundo Mal Kodnani, Residents of House No. 678-P, Sector-37, Faridabad.Shri P.K. Kodnani, who was the joint owner of the above cited property, along with Smt. Jasota Kodnani, as per record had died intestate on 11.12.2023. His wife Smt. Parmeshwari Kodnani had expired intestate long before him on 09.09.2019. Shri P.K. Kodnani left behind only two legal heirs namely 1. Smt. Pooja (daughter) and 2. Shri Rajesh Kodnani (Son). Now Shri Rajesh Kodnani son of Shri P.K. Kodnani intend to apply for the transfer of one-half share of his father-Shri Shri P.K. Kodnani, in the said property in his favour being the legal heir of the deceased. The other legal heir Smt. Pooja, daughter of Shri P.K. Kodnani has no objection if one-half share of her father in the above said property is transferred to her above named brother namely, Shri Rajesh Kodnani. If any person is having objection against the transfer of ibid plot/house, he/she can submit objections in writing to the Estate officer, HUDA Faridabad, along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice. Otherwise the Estate officer may sanction mutation of the property as per HUDA policy and may not entertain subsequent claim if any.
legal heir Rajesh Kodnani

PUBLIC NOTICE

Subject: - Transfer of Plot no 2114, Sector 16, Faridabad in respect of 100% share upon the death of **Late Krishan Dutt Sharma son of Late Shri Lekh Ram Sharma.**

Late Krishan Dutt Sharma son of Late Shri Lekh Ram Sharma was the Owner of the subject cited property to the extent of 100% share. As per the record had died on 21-08-2022 and he had not registered/Un-Registered any Will. Leaving behind the Following Legal heirs (1.) Manish Gautam (Son) (2.) Ruchi (Daughter) (3.) Ritu Gautam (Daughter). That there are no other legal heirs. **Shri Manish Gautam S/o. Shri Krishan Dutt Sharma** resident of House No. 2114, Sector 16, Faridabad, Haryana intends to apply for transfer of the said 100% share of said property in his favour as per legal heirs. If any person is having objection against the transfer of ibid plot/ Plot. He/she can submit objections in Writing to the Estate Officer, HSVP, Faridabad, along with supporting documents within 30 days from the date of publication of this notice. Otherwise the Estate Officer may sanction mutation of the property as per HSVP Policy and may not entertain subsequent claim, if any.
Legal Heir: Manish Gautam

PUBLIC NOTICES

PUBLIC NOTICE

I, Tejpal Singh S/o Sh. Surat Singh R/o H.No.-326, Housing Board Colony, Sector-7 Extn., Gurugram, Haryana declare that my wife Late Smt. Sushma W/o Sh. Tejpal Singh passed away on 16.09.2014 at Gurgaon & leaving behind the following legal heirs:- 1. Tejpal Singh-59 Yrs (Husband) 2. Himanshi Singh-25 Yrs. (Daughter) 3. Yougank Singh- 23 Yrs. (Son). There are no other legal heirs of my wife except the above mentioned legal heirs. If anyone has any objection regarding this, then he/she can raise objections within 30 days from the date of this publication in the office of Tehsildar, Gurugram, Haryana.

PUBLIC NOTICE

It is for the information of the General Public that House/Shop No. 2335/MIG, HBC, Sector-28, Faridabad was transferred / allotteed in the name of **Sh. Sudershan Lal Bhatia S/o Sh. Firaya Lal Bhatia** vide letter No. 515 dated 03.05.1997 Now above allottee transferee / Sale deed holder **Smt. Gurbachan Kaur W/o Sh. Chanan Singh** has expired on 05.02.2011.

Now **Sh. Raj Kumar Anand S/o Late Sh. Chanan Singh** R/o House No. 2335/MIG, HBC, Sector-28, Faridabad has submitted a Will executed by the allottee in her name registered in the office of sub registara, Faridabad vide documents No. 1015, dated 19.03.2009 and has requested to transfer the allotment of the above mentioned house in her name on the basis of the Will. Now by the present Public Notice, it is informed to all public in General that in case anybody has objection to the above said transfer of allotment of House/Shop No. 2335/MIG,(1/5 Share) HBC, Sector-28, Faridabad in the name of **Sh. Raj Kumar Anand S/o Late Sh. Chanan Singh** He/She can file the objection within 30 days from the publication of the notice after that necessary action for the transfer of the above mentioned house will be taken by this office as per Rules and no objection will be entertained after 30 days from the date of publication of this notice.
Estate Manager HBC, Sector 7A, Faridabad

PUBLIC NOTICE

Transfer of ownership of constructed/ unconstructed Property/ Plot No. 500 P, Sector 22B Urban Estate Gurgaon consequent upon the interstate death of allottee/Co-allottee Shri Ved Parkash.

Shri Ved Parkash who was the allotte/ Co-allottee of the subject citied property as the record has died on 24th May 2014 has no registered or un-registered will, leaving behind following legal heirs:

1.Satya Vati (Wife)
2.Alok Kaushik (Son)
3.Kirti Kaushik (Daughter)

Shri Alok Kaushik S/O Late Shri Ved Parkash R/O Hno 500 P, Sector 22B, Gurgaon intend to apply for the transfer of the said property in his name being the legal heir and request for the allotment in his name.

If any person is having any objection against the transfer of the ibid plot/house he/she can submit the objection in writing to the Estate Officer-1 HSVP, Sector 14, Gurgaon along with the supporting documents within 30 days from the date of the publication of the notice, otherwise the Estate Officer may accord permission to transfer /re-allotment of the said property as per HSVP Policy and may not entertain subsequent claim, if any.
Alok Kaushik
Legal heir
On behalf of Estate Officer-1, HSVP, Sector 14, Gurgaon

PUBLIC NOTICE

Subject: Transfer of ownership in respect of Flat No. B-45, Sai Park Apartmetns, Sector 87, Faridabad, area 1110 Sq. feets, upon the death of Shri Gaurav Vatsa, son of Shri Bal Mukund Prasad Singh, 56, Prithwi Singh Market, Patna, Bihar.Shri Gaurav Vatsa, who was unmarried, the joint owner of the above cited property, as per record had died intestate on 08.02.2021. Shri Gaurav Vatsa left behind his mother as her only legal heir namely Smt. Pratibha Rani Singh. Now Smt. Pratibha Rani Singh intend to apply for the transfer of the said property in her favour being the legal heir of the deceased. If any person is having objection against the transfer of ibid flat, he/she can submit objections in writing to the Municipal Corporation of Faridabad, within 30 days. Otherwise any claim may not be entertained thereafter. legal heir Pratibha Rani Singh

PUBLIC NOTICE

PROPERTY NO. B-479, NEW FRIENDS COLONY, NEW DELHI-110025

Be it known to all concerned that (1) Mrs. Madhu Khanna, wife of Late Col. Vinod Kumar Khanna, (2) Mr. Shravan Khanna, son of Late Col. Vinod Kumar Khanna and (3) Ms. Shruti Khanna, daughter of Late Col. Vinod Kumar Khanna, who are representing themselves as the absolute / lawful owner(s) and in exclusive possession of the Subject Property, free from all encumbrances, charges, lien, mortgages, disputes etc., have agreed to get the said property re-constructed/ re-developed through my Client at my Client's cost and in lieu thereof, my Client is getting the exclusive ownership rights of the Entire First Floor and 25% share/ portion of the Entire Stilt Area alongwith 22.5% undivided share in the land underneath the Subject Property measuring about 300.4 square yards, subject to fulfillment of all the contractual obligations by my Client on his/ her part as mutually agreed between them.

Any person(s), Association, Company, Firm, Bank, Financial Institution and any Legal Entity having any sort of right, claim, title or interest in the Subject Property, may put forth his/ her/ its claim to the undersigned with supporting documentary proof, within 15 (*fifteen*) days from the publication of this notice, failing which it shall be presumed that the Subject Property is free from all sorts of encumbrances, charges, claims, lien etc. and my client shall proceed to complete the transaction, free from all encumbrances and further any such claim raised thereafter shall not be binding upon my client in any manner whatsoever.
AMIT V.AWASTHI (Advocate, Supreme Court of India)
D-36, Pamposh Enclave, ND-48
Ph. 011-45532238, 9891317238

HT Classifieds
For Classifieds advertising please call Ad Sales Team on:
NORTH DELHI
Vishal Sachdeva: 9910249013
EAST & CENTRAL DELHI
Sumit Negi: 9899268321
WEST DELHI & FARIDABAD
Ranjeet Singh: 9911819105
SOUTH DELHI & GURGAON
Abhishek Tiwari: 9899865804
NOIDA & GHAZIABAD
Gaurav: 8630242501

Union budget 'betrayed' people of Delhi, says AAP

Alok KN Mishra
alok.mishra1@hindustantimes.com

> In 2023, Delhi paid ₹2,07,000 crore in income tax and ₹25,000 crore in CGST. Delhi's demand was only 0.4% of the total value...Despite that, the Centre did not give a single rupee.
>
> **ATISHI,** Delhi's finance minister

> Delhi government was demanding 10% of direct taxes collected from Delhi, which is around ₹21,000 cr, but the budget gives back almost 30% under various service heads.
>
> **VIRENDRA SACHDEVA,** BJP

NEW DELHI: Delhi finance minister Atishi on Tuesday said the Union Budget 2024-25 "betrayed" the people of Delhi, who pay ₹2.32 lakh crore in tax annually, as they did not get funds for infrastructure development, sanitation and beautification. Leaders of the Aam Aadmi Party (AAP) said the budget appeared to be "saving the BJP government", alleging "it has not been designed for the welfare of the people."

However, Delhi Bharatiya Janata Party unit chief Virendra Sachdeva said that the AAP government was misleading the people of Delhi on budgetary allocations, adding that the Centre has given "much more" than what Delhi government demanded, under various service heads.

Addressing a press conference at the Delhi secretariat, Atishi said: "In 2023, the people of Delhi contributed ₹2,07,000 crore in income tax to the Centre and ₹25,000 crore in CGST. Together, they paid ₹2,32,000 crore in taxes to the Centre. The people of Delhi demanded 5% of the taxes for infrastructure development, and an additional 5% should be given to Delhi for sanitation and beautification purposes. The people of Delhi only demanded ₹20,000 crore from the Centre. Delhi's demand was only 0.4% of the total value of the Union budget. Despite that, the Centre did not give a single rupee."

According to budget documents, Delhi will receive ₹1,168 crore from the Centre in 2024-25 under various heads, such as compensation for the 1984 riots victims, grants in lieu of share in central taxes and duties, contribution to Union Territory Disaster Response Fund and Central assistance for externally aided projects, such as the Chandrawal water treatment plant.

To be sure, the same amount was earmarked for Delhi under similar heads in 2023-24 budget.

"The people of Delhi demanded budgetary allocations for the Municipal Corporation of Delhi in line with the budgetary allocations Centre makes for different urban local bodies of the country. Not even a single rupee has been given to the MCD of the total of ₹82,207 crore earmarked for different urban local bodies," Atishi said.

"The budget document shows that ₹1,24,000 crore would be given to different states as part of devolution of taxes, but not a single rupee has been given to Delhi," Atishi said.

Delhi BJP chief Virendra Sachdeva said that against a demand of 10%, Delhi was getting 30% of its tax share.

"Delhi government was demanding 10% of direct taxes collected from Delhi, which is around ₹21,000 crore, but the budget gives back almost 30% of the tax collected from Delhi under various service heads. The direct budgetary allocation for Delhi is ₹1,168 crore, apart from ₹11,180 crore for operational costs of Delhi Police along with ₹220 crore for infrastructure development of the city," Sachdeva said.

"Other allocations for Delhi come under heads of Delhi Metro, NHAI, RRTS, NDMC operational costs, budgets of various central hospitals of Delhi, such as AIIMS and RML, cost of pensions to Delhi government employees and budgets of central universities. These add up to over ₹50,000 crore, which is around 30% of direct taxes collected," Sachdeva said.

Meanwhile, AAP Rajya Sabha MP Sanjay Singh termed the budget one to "save the government - increase inflation".

"The share market has gone down after the budget was presented. This means that the market did not like this budget. The country's farmers were expecting MSP for their crops to be doubled but the government has not made any provision for it. The budget has also betrayed the youth of the country. Along with the youth, NDA's constituent parties also demanded the abolition of the Agniveer scheme, but the government did not fulfil their demand either," Sanjay Singh said in a press conference at the AAP headquarters.

Humidity high, Delhi sweats



Parts of Delhi recorded isolated light showers on Tuesday, with humidity levels again remaining high. The relative humidity oscillated between 65% and 95% over 24 hours. Delhi's maximum temperature was 36.2°C, which was a degree above normal for this time of the year, while the minimum was 27.4°C. The India Meteorological Department has forecast light to moderate rain in parts of the city on Wednesday. RAJ K RAJ /HT PHOTO

Delhi court grants bail to Atishi in defamation case

NEW DELHI: A Delhi court granted bail to Delhi minister Atishi in a defamation case filed by BJP media head Praveen Shankar Kapoor. Atishi, accused of making defamatory statements against the BJP, was directed to file a ₹20,000 bail bond. The court set the next hearing for August 8. The case arose from allegations of BJP poaching AAP MLAs.

Ggm: DTCP issues notice to 100 plot owners in DLF-5

GURUGRAM: The DTCP's enforcement wing issued show cause notices to around 100 property owners in DLF Phase 5 in Gurugram for illegal construction and commercial activities on their plots. Violations included multi-story buildings and converted stilt parking. Separately, DTCP demolished unauthorised colonies in Wazirpur and Hayatpur villages. Further action, including sealing, is planned for violators, officials warned.

Ggm: Mason dies in cave-in at construction site

GURUGRAM: A 50-year-old mason, Dhuram (went by a single name), a Jhansi, Uttar Pradesh native , died at a construction site in DLF Phase-I, Gurugram, after a mound of soil collapsed on him. The incident occurred around 11am on Monday. Despite efforts to rescue him, he was declared dead on arrival at the hospital, said police. The victim's family ruled out foul play, and an inquiry under section 194 of the BNSS 2023 was launched, police said.

DTC starts trials on two new bus routes

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi government has started trials for two new circulator bus routes in Dwarka Mor and Vasant Vihar to improve public transport facilities, they said in a statement on Tuesday evening. These circular routes are designed to have buses start and end at the same points, covering key locations along the way without terminating anywhere, the Delhi government's statement added.

In response to the development, transport minister Kailash Gahlot said, "The trial of new circulator bus routes in Dwarka and Vasant Vihar is a significant step in our ongoing efforts to improve public transportation in Delhi. By addressing the specific needs of residents and ensuring coverage of important areas, we aim to make daily commutes more convenient and efficient. This initiative reflects our commitment to enhancing the quality of life for Delhi's commuters."

The 23km Dwarka Mor circular route features two 12-meter CNG buses operated by the Delhi Transport Corporation (DTC). These buses will start from Dwarka More and cover locations such as Dwarka Sector-14 Metro Station, Dwarka Sector-21 Metro Station, Apeejay College, NSIT, Guru Gobind Singh University, Vardhman Mall, and various residential areas, with an estimated journey time of approximately 1 hour and 10 minutes.

This new route aims to enhance connectivity within the Dwarka area, making travel more convenient for daily commuters, students, and visitors, the Delhi government said in a statement. The 13.35km Vasant Vihar circular route is serviced by eight electric buses operated by DTC, covering the route in about 45 minutes.

This service connects Vasant Vihar Metro Station and Chhatarpur Metro Station, and the operation of these electric buses began on June 7, 2024.

This development comes after Delhi government started a week-long trial run for the mohalla bus project last week on July 15, with two routes — Akshardham to Mayur Vihar Phase-3 and Majlis Park to Pradhan Enclave in Burari.

CBI TO PROBE DEATH OF MAN DURING DELHI RIOTS, SAYS HC

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Delhi high court on Tuesday transferred to the Central Bureau of Investigation (CBI) the probe into the death of a 23-year-old Muslim man who, along with others, was allegedly assaulted by policemen and forced to sing the national anthem and Vande Mataram during the northeast Delhi riots in February 2020.

"I am allowing the plea and transferring the investigation to the CBI," a bench of justice Anup Jairam Bhambhani said.

The court passed the order while hearing a plea filed by the mother of the victim, Kismatun, seeking probe by a court-monitored special team into her son Faizan's death.

In her petition, the victim's mother claimed that the police illegally detained her son after the incident and denied him critical health care, as a result of which he succumbed to his injuries on February 26, 2020.

The alleged assault took place two days prior to his demise, and a video of it was widely shared online in the days that followed.

Allocation for Delhi Police sees 6% dip

HT Correspondent
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: The central government has allocated ₹11,400.81 crore to the Delhi Police in the budget estimates for the 2024-25 fiscal, representing a 6% reduction equating to ₹728.02 crore from the revised budget estimate of ₹12,128.83 crore granted for the 2023-24 financial year, according to police officers familiar with the details of the Union Budget presented by finance minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Tuesday.

The Union Budget 2024-25 data showed that out of the total allocation of ₹11,400.81 crore, ₹10,291.28 crore is allotted under the "Revenue" category for establishment-related expenditures. In the last fiscal, the government granted ₹11,047.67 crore under the Revenue category, which has now been reduced by ₹756.39 crore. This reduction may impact the hiring of new contractual employees in the city police, some officers said, asking not to be named.

A significant portion of the revenue category budget is used to pay the salaries of around 87,000 police personnel, along with other contractual employees such as multi-tasking staff (MTS), legal and financial advisors, forensic experts, and data entry operators. The procurement of office-related stationery, equipment, and other items is also funded from this allocation, said one of the officers.

The budget estimates allotment to the Delhi Police under the "Capital" category is ₹1,109.53 crore, which is ₹28.37 crore, or 2.62%, more than the previous financial year's revised budget estimate of ₹1,081.16 crore.

"The increased allocation under the Capital section is primarily for improving police infrastructure, such as the construction of police quarters and building of police stations that are still running in rented buildings or temporary structures, traffic-related infrastructure and upgradation of communication system," another officer said.

NORTHERN RAILWAY
Azadi Ka Amrit Mahotsav
NOTICE
E.Tender NRCH-LP2425 are invited for Northern Railway Central Hospital, New Delhi for following work i.e. Empanelment of Local vendor i.e. Firms/Distributors/ Chemist Shops for day to day supply of medicines/surgical items & Consumables etc. to Northern Railway Central Hospital Basant Lane, New Delhi for period of Two Years within distance of 12Km.Estimated value of Rs. 6,33,40,243.00 (approximate) per year Rs. 12,66,80,486.00 for Two years. EMD Rs. 20 Lakh (Max.2% of the estimated value). Last date and time for submission of online Bid 14-08-2024 up to 11.00 AM. Time of opening of Bid soon after closing of Bid on 14-08-2024. Above tender can be seen on website **http://www.ireps.gov.in.** This is e-tender and Authorized Vendor are requested to participate on this website only. Any type of manual Bid will be rejected. **2229/2024**
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

NORTHERN RAILWAY
Azadi Ka Amrit Mahotsav
Tender Notice
Invitation of Tenders through E-Procurement System
Principal Chief materials manager, Northern Railway, New Delhi-110001 for and on behalf of the President of India, invites e-tenders through e-procurement system for supply of the following items:-

Sr. No.	Tender No.	Brief Description	Qty.	Closing Date
01	82244100C	Tab/Cap. Ibrutinib 140mg	2670 Nos	21.08.2024

Note: 1. Vendors may visit the IREPS website i.e. **www. ireps.gov.in** for details.
2. No Manual offer will be entertained
Tender Notice No. Inj. Medicines Dated: 22.07.2024 **2226/2024**
Serving Customers With A Smile

NORTH CENTRAL RAILWAY G20
Tender Notice
Sr. DEE/TRD/Agra for & on behalf of President of India invites "Open Tender" through online only (e-Tendering) for the following work:
Name of work: Provision of Overhead equipment for the development of terminal attention facilities for train sets at Agra Cantt. Station.

Tender No.	Approximate cost	Earnest Money	Period of completion
AGCTRDT202410	10389269.40	202000/-	Six months

1. For full details & submission of the bid please see the Indian Railway website **www.ireps.gov.in**. 2. Tender can only be submitted through web portal **"www.ireps.gov.in"** up to **15.30** Hrs. on date **13.08.2024** 1278/24 FA
North central railways | @CPRONCR | @northcentralrailway | www.ncr.indianrailways.gov.in

SEARCH FOR MISSING

HEMLATA
General Public is hereby informed that one woman **Namely:** Hemlata, **W/o:** Sh. Rajender Kumar, **R/o:** H. No. B-436, Gali No. 2, Adarsh Enclave, Prem Nagar-III, Delhi, **Sex:** Female, **Age:** 32 Years, **Height:** 5'4", **Complexion:** Fair, **Built:** Medium, **Face :** Round, **Wearing:** Khaki Colour Kurta, Black Colour Pajami and Blue Colour Slippers in Feet has been missing since 17.04.2024 from her residence. In this regard **DD No. 40A, Dated: 20.04.2024** has been registered at **P.S.: Prem Nagar, Delhi.**
Sincere efforts have been made by local police to trace out the missing woman but no clue has come to light so far. If anyone have any information about this missing woman. Please inform to the following.
Ph.: 011-24368638, 24368641
Website : http://cbi.nic.in
E-Mail ID: cic@cbi.gov.in
Fax: 011-24368639 **SHO**
DP/9559/RD/2024 **P.S.: Prem Nagar, Delhi**
Ph.: 8750870322, 9873443203

SEARCH FOR MISSING

SHEEBA
General Public is hereby informed that one girl **Namely: Sheeba**, D/o Zakir Ali, R/o R-3, A-3, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi, **Sex:** Female, **Age:** 18 Years, **Height:** 5ft, **Complexion:** Fair, **Face:** Long, **Built:** Medium, **Wearing:** Check Blue colour school dress and Black colour shoes in her feet has been missing from her house since 10.07.2024. In this regard **DD No. 0001A, Dated: 11.07.2024,** has been registered at **P.S.: Ranhola,** Delhi.
Sincere efforts have been made by local Police to trace out the missing girl but no clue has come to light so far. If anyone have any information about this missing girl, please inform to the following.
E-mail: cic@cbi.gov.in
Website: http://cbi.nic.in
Fax: 011-24368639 **SHO**
Ph: 011-24368638, 24368641 **P.S: Ranhola, Delhi**
DP/9616/OD/2024 **Ph.: 7015045790**

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON
See Section 82 Cr.P.C.
Whereas complaint has been made before me that accused **Sohan Lal S/o** Late Puran Mal **R/o** K-3/8 DDA Janta Flat Sector 04 Rohini New Delhi. has committed (or is suspected to have committed) the offence in case **FIR No. NO. 173/2022, U/s 33 Delhi ex. act P.S.: Sagarpur Delhi,** and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said accused **Sohan Lal,** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said accused **Sohan Lal,** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).
Proclamation is hereby made that the said **Sohan Lal,** accused of **FIR No. NO. 173/2022, U/s 33 Delhi ex. act P.S.: Sagarpur Delhi,** and it has been returned to a warrant of arrest thereupon is required to appear before this Court to answer the said complaint on or before **30.08.2024**.
By Order
Ms. Isha Singh
DP/9637/SW/2024 **LD MM-03, Room No. -18**
(Court Matter) **Patiala House Court, New Delhi**

बिहार लोक सेवा आयोग
15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना-800001
आवश्यक सूचना
स्वास्थ्य विभाग, बिहार के अन्तर्गत राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में 23 विभागों (स्पेशलिटी) के अधीन सहायक प्राध्यापक के कुल 1339 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु दिनांक-20.06.2024 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-34/2024 से 56/2024 को विभागीय पत्रांक-649 (17), दिनांक-22.07.2024 के आलोक में तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है।
अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।

CORRIGENDUM
Due to unavoidable circumstances, the last date of submission of e-Tender vide No. 4- 40/STY/TLDA/2023 bearing tender ID No. 2024_ARDD_50571_1 uploaded on 03-07-2024 invited for procurement of 1,80,000 liters of Liquid Nitrogen in phase manner as per requirement along with transportation to Dharmanagar (North Tripura Dist.) and RK Nagar (West Tripura Dist.) during the year 2024-25 and 2025-26 (i.e. till the completion of supply of total bided quantities) has been extended upto 29-07-2024 at 5.00 PM.
The technical bids of said e-Tender will be opened on 30-07-2024. The other contents of the e-Tender will remain unchanged.
(Dr. Neeraj Kumar Chanchal)
Chief Executive Officer
Tripura Livestock Dev. Agency, Astabal, Agartala
ICA/C-965/2024-25

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON
See Section 82 Cr.P.C.
Whereas complaint has been made before me that accused person **Praveen** S/o Sh. Manohar Lal R/o C-2/61, Nand Nagri, Delhi has committed (or is suspected to have committed) the offence case FIR No. 363/2008 u/s 325/34 IPC, P.S. Nand Nagri, Delhi and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said **Praveen** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **Praveen** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant). Proceeding u/s 82 Cr.P.C. has been initiated in the case. Proclamation is hereby made that the said **Praveen** accused of FIR No. 363/2008 u/s 325/34 IPC, P.S. Nand Nagri, Delhi is required to appear before this Court to answer the said complaint on **17.09.2024.**
By Order: Ms. Deepakshi Rana,
Metropolitan Magistrate-03,
Shahdara Court No.-19,
DP/9554/NE/2024 **Karkardooma Courts, Delhi**

COMMON MANAGEMENT ADMISSIONS COMMITTEE- 2024
(www.cmacadmissions.com)
BBA Admission (2024-25)
Admission Announcement for BBA Program 2024-25
Indira Gandhi Delhi Technical University for Women (IGDTUW), Delhi Technological University (DTU) and Netaji Subhas University of Technology (NSUT) invite online applications for the common admission process of full-time Bachelor of Business Administration (BBA) Program offered at the following Universities/Institutes established by Govt. of NCT of Delhi:
- **Department of Management, IGDTUW — 75 Seats (Only for Female Candidates)**
- **Department of Management Studies, NSUT — 120 Seats**
- **University School of Management & Entrepreneurship, DTU — 180 Seats**

Eligibility Conditions: The candidate must have scored at least 60% marks for NSUT and 50% marks for DTU and IGDTUW, in the 12th board examination (from a recognized board) and must also have passed English (Core/Elective/Functional) as a subject in the 12th Board Examination. The reserve category candidates are eligible for relaxation in minimum marks as per applicable norms.
Selection Criteria: The merit list shall be drawn on the basis of CUET UG 2024 performance in paper 1A (English Language, Code 101) and paper 3 (General Test, Code 501). For detailed information please refer admission brochure of the participating Universities.
Apply online on www.cmacadmissions.com
Opening Date: 27.06.2024 **Closing Date: 25.07.2024**
www.igdtuw.ac.in **www.dtu.ac.in** **www.nsut.ac.in**
Helpdesk Email ID: cmacbba@igdtuw.ac.in
DIP/Shabdarth/Classified/0121/24-25

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF ACCUSED PERSON
See Section 82 Cr. P. C.
Whereas a complaint has been made before me that accused person namely **Md Mustak S/o Md. Hamid** R/o Jhuggi No. 113, C-4 Ki Jhuggi, Lawrence Road, Keshav Puram, Delhi, have committed (or is suspected to have committed) the offence under **FIR No. 624/21 U/s 324 IPC.,** has been registered at **P.S. Keshav Puram, Delhi** and it has been returned to a warrant of arrest there upon issued that the said **Md Mustak** cannot be found and whereas it has been shown to my satisfaction that the **Md Mustak** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warrant).
Proclamation is hereby made that the said accused of **Md Mustak of FIR No. 624/21 U/s 324 IPC., registered at P.S. Keshav Puram, Delhi** is required to appear before this court to answer the said complaint on or before **18.09.2024.** **By Order**
DP/9268/NW/2024 **Ms. Divya Arora, MM,**
Room No.112, Rohini Court, Delhi

NORTHERN RAILWAY
Azadi Ka Amrit Mahotsav
E-TENDER NOTICE
For & on behalf of the President of India, Chief Workshop Manager, N. Rly. C&W workshop, Jagadhri Workshop/Yamuna Nagar invites open e-tender on short notice for the following work:

1	Name of work	**Work of Work of Supply, Installation, Commissioning of "Stainless Steel RPF Maingate (Workers) of Northern Railway, Jagadhri Workshop (On Turnkey Basis) (As per Drg No. JUDW/MECH./21-763) with 01 year Warranty.**
2	Location	Northern Railway, Carriage & Wagon Repair Shop, Jagadhri Workshop, Yamuna Nagar, Haryana-135002
3	Tender Value	**Rs. 8,98,570/-**
4	Quantity	As per scop of work
5	Cost of Tender form	Rs. 0/-
6	Earnest money amount	**Rs. 18000/-**
7	Completion period of the work	03 months from the date of issuance of Letter of Acceptance
8	Date & Time for submission of tender form	19.08.2024 till 15.30 hrs.
9	Opening of tender 19.08.2024 till 15.35hrs.	Tender opening will be done any time after the tender closing time. The tenderers are not required to be present during the opening. Railway reserves the right to open the tender any time after closing of tender.
10	Website particulars	www.ireps.gov.in

No.: 6-S/67/Tender/2023-24/Pt-II dt. 22.07.2024 2232/2024
SERVING CUSTOMERS WITH A SMILE

COALITION ECONOMIX

efforts to fulfil the commitments in the Andhra Pradesh Reorganisation Act. Recognising the state's need for capital, we will facilitate special financial support through multilateral agencies," Sitharaman added.

The Opposition flayed the budget, pointing out that not only did it not contain specific schemes for other states but also held little for Maharashtra and Haryana, two states ruled by the Bharatiya Janata Party (BJP) that are slated to go to the polls later this year. The Congress also alleged that two of the five schemes announced for young people were lifted from its manifesto.

"Kursi Bachao [save your chair] Budget. Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states. Appease Cronies: Benefits to AA with no relief for the common Indian. Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets," Leader of the Opposition Rahul Gandhi said on X.

But NDA members welcomed the announcements. "From the beginning, we had requested special assistance for Bihar. In response, they have announced help in several areas. We are doing a lot of work, and we will receive additional support in many aspects, which will be beneficial," said a beaming Bihar chief minister, Nitish Kumar.

This was the first budget presented by the third iteration of the NDA, mere weeks after the BJP suffered a setback in the general elections and failed to garner a simple majority in the Lok Sabha. The party won 240 seats in the 543-member House, giving space to allies to make greater demands for their respective states.

The BJP's sobering performance was attributed to slipping support among key demographics such as young people, women, marginalised castes and rural poor over bread-and-butter issues such as a crippling lack of jobs.

The budget sought to address this lacunae by unveiling nine priority areas for the government – productivity and resilience in agriculture; employment and skilling; inclusive human resource development and social justice;manufacturing and services; urban development;energy security;infrastructure; innovation, research, and development; and next-generation reforms – while maintaining fiscal prudence.

The sharpest focus was on young people. The government announced five schemes with an aggregate spend of around ₹2 lakh crore for roughly 41 million people – it will pay one month's wage up to ₹15,000 in three instalments to every new person entering the workforce, incentivise employers up to ₹3,000 a month for two years towards their EPFO contribution for new employees, offer a direct incentive to both employer and employee for their EPFO contribution for the first four years, skill two million people over five years, and offer internship opportunities at 500 top companies for 10 million people over five years. The focus was on generating employment, a key grassroots grievance that hurt the BJP in the recently concluded polls. In addition to the five schemes listed above, the government also announced upgradation of 1,000 Industrial Training Institutes, government-backed skilling loans up to ₹7.5 lakh and financial support for loans up to ₹10 lakh for higher education in domestic institutions, making up its second thrust area -- jobs.

Sitharaman made further commitments to women, including working women's hostels and cheap loans.

"For promoting women-led development, the Budget carries an allocation of more than ₹3 lakh crore for schemes benefitting women and girls," she said.

A third priority of the budget was maintaining fiscal discipline. It lowered its fiscal deficit target for the current year to 4.9% of the Gross Domestic Product, from the 5.1% target set in the interim budget in February and from 5.6% in the previous year. It lowered its gross borrowing target to ₹14.01 lakh crore rupees but said it still plans to spend a record ₹11.11 lakh crore rupees in capital expenditure on long-term infrastructure.

"The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach a deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavour will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government debt will be on a declining path as a percentage of GDP," Sitharaman said.

A revenue windfall this year has boosted the government coffers, giving it ample resources to boost spending while narrowing the fiscal deficit. The Reserve Bank of India paid the government a record ₹2.1 lakh crore dividend this year, while tax revenues surged on the back of a stronger economy.

Taxes were a fourth key area. The government raised the short-term capital gains tax – on stocks held for less than one year – to 20% from 15%, and the long-term capital gains tax – for stocks held for over one year – to 12.5% from 10%. The step was seen as an effort to arrest the frenzy that has propelled the markets to record highs, a day after the economic survey sounded a word of caution on galloping markets. It caused a temporary slide in India's benchmark indices but they recovered shortly after and ended the day flat.

Sitharaman reduced customs duties on items ranging from cancer drugs, mobile phones, chargers, seafood, gold, critical minerals and seafood. She also tweaked the new tax regime slabs and raised the standard deduction limit from ₹50,000 to ₹75,000.

"As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to ₹ 17,500 in income tax," she said.

There were a string of other announcements – more funding for agricultural research, a movement towards small nuclear reactors and solar power for energy security, credit guarantee schemes and cheap loans for micro, small and medium enterprises, expanded urban housing, a new scheme for tribal people, and digitised land records – that hinted that the government was thinking about initiating next-generation reforms and a simplification of the tax framework.

But the four main priorities outlined the government's immediate and medium-term outlook – resolve the lingering problem around too few new jobs, win back key demographics such as young people disillusioned over bread-and-butter issues, shun populism as much as possible by training focus on fiscal prudence, but also ensure that allies critical to its survival remain in good humour.

{ FROM PAGE 1 }

NO NEET RETEST

take time, the final conclusions must be recorded at the present stage "since there is an urgent need to provide certainty and finality to the dispute which has occurred and affects the careers of over 2 million students".

The NEET-UG was conducted at 4,750 centres across 571 cities in India and 14 cities overseas, with over 2.3 million students competing for 108,000 seats. The CJI noted the severe consequences that ordering a fresh NEET-UG would have, including disruptions to the admission schedule, cascading effects on medical education and disadvantages to marginalised groups benefiting from reservation policies.

"This court realises that directing a fresh NEET-UG for the present year would be replete with serious consequences which will be for over 23 lakh students who appeared in this exam. It will cause disruption of admission schedule, cascading effects on the course of medical education, impact on availability of qualified medical professionals in the future and seriously disadvantageous for the marginalised group for whom reservation was made in allocation of seats," the bench said.

Highlighting the inadequacy of evidence before it to buttress the claims of massive leaks or widespread malpractices, the bench added in its order: "We are of the view that ordering cancellation of the entire exam is neither justified on application of settled principles propounded by this court nor on the basis of the material on record."

It also addressed discrepancies in the answer key for one question, initially deemed to have two correct options -- 2 and 4. Following the receipt of an expert committee's report, led by the IIT Delhi director, the bench noted that only one option (4) was correct, directing the National Testing Agency (NTA) to re-tally the NEET-UG results accordingly.

The court order would entail a complete re-evaluation of NEET ranks and scores for all 2.3 million students. The scores of at least 420,000 students, including 42 of the 61 who achieved perfect marks of 720, will decrease by five points with the court invalidating the disputed marks that they received for answering option 2, according to the old NCERT textbook. The directive would ripple through the entire ranking system, significantly altering the standings of students nationwide.

The court also recorded the Centre's submission that a seven-member expert committee, headed by Dr K Radhakrishnan, former chief of ISRO, and chairman, board of governors, IIT Kanpur, has been constituted to strengthen the medical examination process. Solicitor general Tushar Mehta appeared for the Centre in the matter.

"This committee will follow further directions from the court to strengthen the NEET-UG exam process, aiming to prevent future issues similar to those raised in the current petitions," directed the bench, clarifying it would issue a detailed order soon.

Noting that the NTA conducted a special test for 1,563 candidates, giving them the option to either appear for a retest or forego grace marks that were awarded to them for loss of time, the bench clarified that students with individual grievances could approach competent jurisdictional high courts under Article 226.

The Supreme Court verdict brings closure to a contentious chapter, ensuring that the NEET-UG 2024 results largely stand, barring further findings by the CBI. For millions of aspiring medical students across India, this decision provides much-needed relief and certainty, allowing them to move forward with their academic and professional aspirations without the looming uncertainty of a retest.

The NEET-UG 2024 paper leak controversy had quickly morphed into a significant political issue, with Opposition parties seizing the opportunity to criticise the government. The Opposition accused the ruling coalition of failing to ensure the sanctity of one of the country's most critical entrance examinations, thereby jeopardising the futures of millions of aspiring medical students.

On Monday, the first day of the monsoon session, the NEET controversy dominated discussions, with Opposition leaders, including Leader of the Opposition (LoP) Rahul Gandhi and Samajwadi Party (SP) MP Akhilesh Yadav vociferously attacking the government. They called for the resignation of Union education minister Dharmendra Pradhan. The uproar forced the government to defend its position and the measures it had taken to address the situation. Pradhan rejected allegations that widespread paper leaks had vitiated the exam, asserting that there was no evidence of paper leaks in the last seven years.

Pressing for a retest, the petitioners argued that the integrity of NEET-UG 2024 had been severely compromised due to a widespread paper leak. They contended that the leak, which occurred in Hazaribagh and Patna, was not an isolated incident but indicative of systemic deficiencies in the examination's conduct. According to them, the scope of the leak, coupled with structural flaws in the administration of the exam, necessitated a retest to ensure fairness and uphold the exam's sanctity. The petitioners were led by senior counsel Narender Hooda and Sanjay Hegde, and advocates Mathews J Nedumpara and Charu Mathur, among others.

Highlighting the extent of the issue, the petitioners emphasised that the leak could have potentially impacted the scores of numerous candidates, creating an uneven playing field. They argued that the results from 4,750 centres in 571 cities, including 14 overseas locations, could not be considered valid until a thorough investigation was completed. The involvement of the CBI in probing the leak underscored the seriousness of the situation, as multiple FIRs had been transferred to the agency from states such as Delhi, Gujarat, Rajasthan, Bihar and Jharkhand, they pointed out.

Moreover, the petitioners brought to the court's attention that the initial findings from the CBI's investigation indicated that at least 155 students had benefited from fraudulent activities.

This, they claimed, was a clear sign of a larger conspiracy that compromised the exam's credibility. The petitioners argued that without a retest, many deserving candidates who had studied diligently would be unfairly disadvantaged, and those who had resorted to dishonest means would gain an undue advantage.

In response to the petitioners' claims, the Centre and the NTA staunchly defended the integrity of the examination process. They argued that the alleged leaks, although unfortunate, were limited to specific locations and did not reflect a systemic breach that would justify a nationwide retest. They contended that the incidents in Hazaribagh and Patna were isolated, affecting only a minuscule fraction of the total candidate pool.

The Centre, in its July 10 affidavit, provided detailed data analytics conducted by IIT-Madras to support its stance that the overall results were not compromised. This analysis showed no significant anomalies in the results from the affected centres compared to the national average, thereby indicating that the leak did not have a widespread impact. The Centre also pointed out that the NTA had taken immediate corrective measures by conducting a special test for 1,563 candidates, offering them the option to either appear for a retest or accept grace marks, thereby addressing individual grievances without the need for a blanket retest.

The CBI's involvement came after FIRs filed in Delhi, Gujarat, Rajasthan, Bihar and Jharkhand were transferred to it on June 22. During four days of arguments, the court heard from multiple parties, including an additional director of the CBI who has been heading the probe into the alleged paper leaks in Hazaribagh and Patna.

While delivering the order on Tuesday, the bench underscored the need to provide certainty and finality in the dispute. While recognising that leaks occurred in Hazaribagh and Patna, the bench noted the CBI's status reports, which indicated that 155 students from these centres were the likely beneficiaries of the fraud. Even as it noted that the investigation was ongoing, the court found no conclusive evidence of a systemic leak or a breach that would justify annulling the entire exam.

About the petitioners' opposition to the IIT-Madras report, the bench said that it has "independently scrutinised" the data of candidates and found no evidence of any widespread malpractice.

WARRANT AGAINST MARATHA QUOTA ACTIVIST IN 2013 CHEATING CASE

PUNE: A local court on Tuesday issued a non-bailable warrant (NBW) against Maratha quota activist Manoj Jarange-Patil in connection with a 2013 cheating case after he failed to appear before it, his lawyer said.

"A hearing was scheduled today before the judicial magistrate here in the case, but as Jaranage is currently on hunger strike, he could not be present," said advocate Harshad Nimbalkar, representing Jarange-Patil.

A case under Indian Penal Code (UOC) section 420 (cheating) and 406 (criminal breach of trust) was registered against Jarange-Patil and two others in 2013. Jarange-Patil and co-accused had in 2012 approached the complainant, who stages plays on Chhatrapati Shivaji Maharaj and Chhatrapati Sambhaji Maharaj, for six shows of "Shambhuraje" play in Jalna district and offered him ₹30 lakh.

While ₹16 lakh were paid, there was some dispute over the remaining money, leading to a complaint.

The court then ordered the police to register a case. **PTI**

18-MONTH-OLD AMONG SIX KILLED IN ASSAM ACCIDENT: POLICE

KARIMGANJ: Six people, including an 18-month-old child, were killed and another was injured when an auto-rickshaw they were travelling in collided with a car in Assam's Karimganj district on Tuesday, police said.

The accident occurred in the Nilam Bazar area of the Karimganj district.

According to officials, the victims were travelling in an autorickshaw when it collided with a car, leaving six of them dead.

Karimganj superintendent of police (SP) Partha Protim Das told ANI that the accident took place in the Nilam Bazar area of the district.

"Six people, including an 18-month-old child, died in the accident. One person was seriously injured in the incident and referred to Silchar Medical College & Hospital," SP Das said. **HTC**

HT Unforgettable



In the memory of
Smt Maya Bhattacharya
(1932-2005)

On her 92nd Birth Anniversary
Deeply remembered by
Chatterjees and Bhattacharyas

GOVERNMENT OF ODISHA **B-104**
OFFICE OF THE CHIEF
CONSTRUCTION ENGINEER
KEONJHAR (R&B) CIRCLE, KEONJHAR
No. 3145 / Date : 22.07.2024
ORDER
The tender for the work "Improvement to Udayapur — Saharpada Road (ODR) from Ch. 0/000 km to Ch. 4/600 km in the District of Keonjhar for the year 2024-25" invited vide Bid Identification No CCEKC - 03/ 2024-25 is hereby cancelled due to being single tender in First time tender call as per Works Department office Memorandum No. 16 date 01.01.2015.
Chief Construction Engineer
Keonjhar (R & B) Circle, Keonjhar
OIPR - 34033/11/0019/2425

GOVERNMENT OF ODISHA **B-103**
OFFICE OF THE CHIEF
CONSTRUCTION ENGINEER
KEONJHAR (R&B) CIRCLE, KEONJHAR
No. 3154 / Date : 22.07.2024
ORDER
The tender for the work "Construction of E-Type staff quarters for ICDS Officials under W and CD Department at Sundargarh for the year 2023-24" invited vide Bid Identification No C.C.E.K.C., Keonjhar No. 01 / 2024-25 is hereby cancelled as per Letter No. 5390 dt. 06.03.2024 of Additional Secretary to Govt., Department of Women & Child Development, Odisha
Chief Construction Engineer
Keonjhar (R & B) Circle, Keonjhar
OIPR - 34033/11/0017/2425

GOVERNMENT OF ODISHA **A-169**
OFFICE OF THE CHIEF CONSTRUCTION ENGINEER , UPPER INDRAVATI PROJECT
AT/PO: MUKHIGUDA DIST:KALAHANDI , ODISHA, PIN: 766026
e-mail address : cceuip1987@gmail.com / louiipbbsr@gmail.com

1. Type of Work : Canal structure Work
2. Total No. of Works : 02 nos
3. Approximate value of work : Rs 92.53 lakhs to Rs 113.01 lakhs (Excluding GST)
4. Tender Paper Cost : Rs. 10,000/- (online) of Each work
5. Bid Security / E.M.D : Rs.92,600/- & Rs.1,13,100/-(Online)
6. Period of Completion : 09 (Nine calendar months).
7. Class of Contractor : A & B Class

Procurement Officer	e- procurement Notice No.	Bid Amount	Availability of online viewing of Tender prior to Bidding		Period for seeking tender clarification	Submission & Availability bid on-line	Date & time of opening of Technical Bid	Date & time of opening of Financial Bid
			From	To				
1	2		3	4	5	6	7	
Chief Construction Engineer, Upper Indravati Project, AT/PO - Mukhiguda, Dist - Kalahandi, Odisha, Pin - 766026	CCE, UIP - 01 (02)/2024-25, Dt. 22.07.2024	1) Rs 92.53 lakhs 2) Rs 113.01 lakhs (Excluding GST)	29.07.2024 (10.00 AM)	16.08.2024 (up to 5.00 PM)	06.08.2024 to 08.08.2024 during office hours.	29.07.2024 (10.00 AM) to 16.08.2024 (up to 5.00 PM)	20.08.2024 at 11.00 AM	To be initimated to qualified bidders after evaluation of the technical bid.

Date of opening of technical bid : Dt-20.08.2024 at 11.00 AM in the O/O the Chief Construction Engineer, UIP, Mukhiguda, Kalahandi, Odisha, PIN-766026. Date of opening of financial bid : To be decided after finalization of Technical Bid. Further details can be seen from the Govt. Website www.tendersorissa.gov.in
Chief Construction Engineer, Upper Indravati Project, Mukhiguda
OIPR - 32352/11/0002/2425

Maharashtra Rural Road Development Association
Superintending Engineer, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Chhatrapati Sambhajinagar Region, Chhatrapati Sambhajinagar
e-Tender Notice 14/ 2024-25
The Superintending Engineer, PMGSY, Chhatrapati Sambhajinagar Region, Chhatrapati Sambhajinagar on behalf of Government of Maharashtra invites the rate bids in electronic tendering system published on **http://pmgsytenders.gov.in** for construction & five year maintenance of **MH-2290 Bridge** works under **Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana** in the Purna Block districts of **PARBHANI**. Date of Sale & Submission start from 19-07-2024 11.00 am to 26-07-2024 till 05.00 pm. Further notification & Clarification will be published on website.
Sd/- (K. T. Wagh) Executive Engineer Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana MRRDA District: Parbhani
Sd/- (V. H. More) Superintending Engineer Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Chh.Sambhajinagar Region, Chh.Sambhajinagar
DGIPR/2024-25/ROC 1132

MAHATRANSCO Maharashtra State Electricity Transmission Co. Ltd.
NOTICE INVITING TENDER CPD/30-2024-25
The due Date and Time of submission and opening of following SRM e-tender is extended as follows:

Tender No. & Description of Material	Estimated Amount (in Rs. Lakhs) / Tender Fee (in Rs.)	Due Date & Time (Hrs.) for Submission & Opening of Tender
SP/T-0819/0724 [2nd call] [RFX No.5000001255] (Two Bid System) Procurement of 400 KV, 220 KV & 132 KV (Normal) & (Antifog) type Porcelain long rod insulators for all EHV PCC O&M Zones of MSETCL on Rate Contract Basis -2nd Call	5451.61 / 25000.00	05.08.2024 Up to 17:00 Hrs. / 05.08.2024 at 17:30Hrs

Contact Person: Office of the Executive Engineer (P&C)
Tel. No.022-26474211/022-26472131 Extn.2491/2493.
Email:eegrp8@mahatransco.in, aegrp8@mahatransco.in
For further details visit our website http://www.srmetender.mahatransco.in
Any further amendments will be published on the MSETCL website www.mahatransco.in.
So bidders are requested to check the website.
Sd/-
Executive Engineer (P&C)

Prayagraj Nagar Nigam
1, Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001, Uttar Pradesh
NIT NO 258 ENV/2024-25 DATE 23.07.2024
E-TENDER NOTICE, 3rd Call
This is to inform to all prospective bidders having the required qualification mentioned in the RFP document that Municipal Corporation Prayagraj invites Selection of Agency for Development and Maintenance of Miyawaki Forest in Prayagraj Municipal Corporation (Year 2024-25)
Schedule for Tender

S. No.	Activity	Date	Time
1	Tender Document Availability	24/07/2024	14:00 hrs onwards
2	Last date of Bid submission	03/08/2024	up to 15:00 hrs
3	Technical Bid opening Date	03/08/2024	16:00 hrs onwards

For more details, please visit the website at http://www.etender.up.nic.in
पत्रांक : संण्डी-258/पर्या0/2024, दिनांक 23.07.2024
(Uttam Kumar Verma) Environment Engineer Prayagraj Nagar Nigam

कार्यालय निदेशक आयुर्वेद सेवायें उत्तर प्रदेश लखनऊ
संख्या–1063 / एच / ए / 489 / 2021 / शिक्षा दिनांक–22.07.24
—:: विज्ञप्ति ::—
उत्तर प्रदेश राज्य के निजी क्षेत्र के एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं हॉस्पिटल, समसपुर, हवेली, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (उ0प्र0) के छात्र / छात्राओं को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या–सी –16008 / 2022 में पारित आदेश दिनांक–01.07.2024 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के निजी क्षेत्र के एन.सी.आई.एस.एम. भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा सत्र 2020–21 के लिए मान्यता प्राप्त आयुर्वेदिक कालेजों के यू.जी. पाठ्यक्रम (बी.ए.एन.एस.) में सत्र 2021 में रिक्त सीटों के विरुद्ध मेरिट के आधार पर समायोजित किये जाने के निमित्त निम्नांकित विवरणानुसार काउन्सलिंग / पुनरावंटन की प्रक्रिया सम्पादित की जानी है, जिसमें एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एवं हॉस्पिटल, समसपुर, हवेली, चुनार, जनपद–मिर्जापुर (उ0प्र0) के शैक्षणिक सत्र 2018–19 के सभी सम्बन्धित इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित मूल अभिलेखों सहित निम्न वर्णित स्थान / तिथि / समय के अनुसार काउंसिलिंग / पुनरावंटन में प्रतिभाग करें।
वांछित अभिलेख :–
1– हाईस्कूल अथवा समकक्ष एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष का अंकपत्र एवं प्रमाण–पत्र।
2– नीट 2018 का स्कोर कार्ड।
3– आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र।
4– पूर्व में निर्गत आवंटन पत्र।
5– पूर्व में निर्गत आवंटन पत्र।
6– पूर्व कालेज में प्रवेश का साक्ष्य व जमा शुल्क रसीद।
काउन्सिलिंग का स्थान – राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधि निर्माणशाला, गोहान रोड, लखनऊ।
काउन्सिलिंग की तिथि – 30.07.2024 (काउन्सिलिंग की प्रक्रिया प्रातः 10:00 बजे से प्रारम्भ होगी।)
अभिलेखों का सत्यापन – दिनांक–30.07.2024 को प्रातः 10:00 बजे से मध्याह्न 12:00 बजे तक।
सीटों का आवंटन – दिनांक–30.07.2024 को अपरान्ह 01:00 बजे से सीटों की आवंटन प्रक्रिया समाप्त होने तक।
उ0प्र0: 217608 दिनांक: 22.07.2024
Website: www.upgov.nic.in
(डा0 पी0 सी0 सक्सेना) निदेशक

Government of Uttarakhand
Office of the Director General, Information & Public Relation Department, Uttarakhand
Suchna Bhawan, Ladpur Ring Road, (Near Commercial Tax Department), Dehradun
(Read all the terms and conditions carefully before filling the e-tender form)
Letter No: 25/I&PRD(Elec.mtr)/16/2021 Dated: 22 July, 2024
E-Tender Invitation for Listing of Online Radio/Digital Radio/Internet Radio
Various public welfare policies, schemes and other important information of the Uttarakhand Government is publicized by The Department of Information and Public Relation, Uttarakhand through various mediums in public interest. The department has proposed to enlist online radio/digital radio/internet radio for publicity through various mediums for 01 year.
The department invites e-tender from the owners of online radio/digital radio/internet radio operating in the state of Uttarakhand under the following terms and conditions. The details of e-tender are as follows:-

S. No.	Particular	Date & Time
1.	Date of availability of Tender Document on Website	24 July, 2024, 11:00 AM
2.	Pre Bid meeting Date	03 August, 2024, 11:00 AM
2.	Bid Submission Start Date	10 August, 2024, 11:00 AM
3.	Venue for Tender Related Work	Information & Public Relation Department, Suchna Bhawan, Ladpur Ring Road, Dehradun, Uttarakhand.
4.	Tender Document is also available at	http://www.uktenders.gov.in
5.	Last Date of Bid Submission	17 August, 2024, 04:00 P.M
6.	Date of Opening of Technical Bid	19 August, 2024, 11:00 A.M
7.	Date of Opening of Financial Bid will be intimated separately	-------
8.	Tender Document Cost	Rs. 500/-

Note: If any date mentioned above is declared public holiday, that will be shifted to the next working day without any change in other parameters such as Venue etc.
Sd/- Director General
Information and Public Relation Department,
Dehradun, Uttarakhand
DIP No Memo dt 23.07.2024

C-253
WATCO
OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER, WATCO.
Ground Floor, Unnati Bhawan,
H.B. Colony, Satyanagar, Bhubaneswar-751007,Odisha, India
Telefax: - +91-674-2391444 / E-mail — ceowatcoodisha@gmail.com
INVITATION FOR BID (IFB)
Bid Identification No. WATCO (W) — 03 /2024-25 Dtd.22.07.2024
WATCO No. 4533 Date: 22.07.2024

1. Name of the work :- " Procurement of ISI marked DI K-9, socket & spigot pressure pipes of different diameters for Different works in WATCO Division, Rourkela
2. Types of Bid :- Double Cover (Technical & Financial)
3. Estimated cost : :- Rs.783.00 Lakh
4. Period of Completion : 2 (Two calendar) Months.
5. Class of Contractor :- Manufacturer
6. Date & time of availability of bid document in the portal :- From 11.00 AM of Dt.29.07.2024 to 5.00 PM of 12.08.2024
7. Last date & time of receipt of bids in the portal :- 5.00 PM of 12.08.2024
8. Date & time of opening of technical bids : 11.00 AM of 13.08.2024
9. Name and address of the Officer Inviting Bid :- CEO, WATCO, Telefax:- 0674-2391444 E-Mail: ceowatcoodisha@gmail.com
10. The bidders have to participate in ONLINE bidding only.

Further details can be seen from the web site www.tendersodisha.gov.in
(CEO) WATCO
OIPR - 13194/11/0006/2425

WORST-EVER LANDSLIDE IN ETHIOPIA KILLS 229, RESCUE ON

Agence France-Presse
letters@hindustantimes.com

ADDIS ABABA: Using shovels or their bare hands, local residents on Tuesday searched desperately for survivors after a landslide in a remote area of southern Ethiopia killed at least 229 people, the deadliest such disaster recorded in the Horn of Africa nation.

Crowds gathered at the site of the tragedy in an isolated and mountainous area of South Ethiopia regional state as some people clawed through mounds of red dirt, according to images posted on social media by the local authority.

So far, 148 men and 81 women are confirmed to have lost their lives after the disaster struck in the Kencho-Shacha locality in the Gofa Zone on Monday, the local Communications Affairs Department said in a statement.

Five people had been pulled alive from the mud and were receiving treatment at medical facilities, the government-owned Ethiopian Broadcasting Corporation reported earlier.

"Initially, four households were affected by the landslide, and later households in the area were mobilised to save lives," Firaol Bekele, early warning director at the Ethiopian Disaster Risk Management Commission (EDRMC), told AFP.

"But they too perished when the landslide engulfed them," he said, adding that the disaster was caused by heavy rains that had battered the area on Sunday night. EBC quoted local administrator Dagemawi Ayele as saying that among the victims were the locality's administrator as well as teachers, health professionals and agricultural professionals who had rushed to help.

Images posted on social media by the Gofa authority showed residents carrying bodies of the dead on makeshift stretchers, some wrapped in plastic sheeting.

Ethiopia, with a population of around 120 million people, is highly vulnerable to climate disasters including flooding and drought.

Harris secures majority Dem delegates, nomination in Aug

Prashant Jha
letters@hindustantimes.com

WASHINGTON: US vice president Kamala Harris has secured the support of a majority of Democratic delegates, and is poised to become the party's nominee for president after a virtual roll call of the delegates by early August. This will confirm her as the candidate before the party convention in Chicago scheduled from August 19.

On Monday, Harris also visited her campaign headquarters in Delaware where she leaned into her past as a public prosecutor to frame the battle with Republican nominee Donald Trump as one between a prosecutor and a felon. President Joe Biden, recovering from Covid-19, called in and told what was his campaign team till he dropped out on Sunday, "Embrace Kamala. She is the best".

Harris has also mounted a massive fundraising operation, raising over $100 million since she entered the race on Sunday.

Amid uncertainty after Biden's withdrawal weeks before the convention, the Democratic National Committee (DNC) released draft rules allowing anyone to file for candidacy with the support of 300 delegates, not exceeding 50 from one state. "The process is going to be fair, open, transparent but fast," Jaime Harrison, the DNC chair said.

The impetus for a quicker process before the convention comes from the fact that the deadline to get on to the ballot for the presidential election in Ohio was earlier slated for August 7, a deadline Democrats want to meet to avoid future legal challenges.

"If we are going to be on 50 ballots, we have got to have all that done and locked up by August 7," Harrison added.

But with a majority of delegates already pledging their support to Harris, and no one else announcing their intent to seek the nomination, a virtual roll call is likely to seal her nomination as the Democratic presidential candidate in the first week of August.

Harris will have to pick her running mate before that. Among the names being most widely discussed are Pennsylvania governor Josh Shapiro, Kentucky governor Andy Beshear, North Carolina governor Roy Cooper and Arizona senator Mark Kelly.

In a statement after she became the presumptive nominee, Harris said she was proud to have secured the broad support needed to win the nomination, with her home state of California putting her over the line. "This election will present a clear choice between two different visions.

Donald Trump wants to take our country back to a time before many of us had full freedoms and equal rights.

I believe in a future that strengthens our democracy, protects reproductive freedom and ensures every person has the opportunity to not just get by, but to get ahead."

Harris also visited what is now her campaign headquarters in Wilmington, Delaware, the home state of Biden, where she addressed and reassured campaign staffers who have gone through weeks of uncertainty, seen their leader at the top of the ticket drop out, and have felt uncertain about their own prospects.

In a message to boost staff morale and sustain enthusiasm for Harris's candidacy, Biden called in to address his team. He acknowledged that Sunday's news of his decision to drop out was surprising and hard for them but said it was the right thing to do. He emphasised that while the name at the top had changed, the mission remained the same.



Vice President Kamala Harris at a convention in Dallas on Wednesday. AP

US Secret Service chief resigns after Trump assassination bid

Agence France-Presse
letters@hindustantimes.com

WASHINGTON: US Secret Service Director Kimberly Cheatle resigned on Tuesday, a day after acknowledging that the agency failed in its mission to prevent an assassination attempt against Donald Trump.

Cheatle was facing bipartisan calls to step down after a 20-year-old gunman wounded the former Republican president and current White House candidate at a July 13 campaign rally in Butler, Pennsylvania.

"It is overdue, she should have done this at least a week ago," Mike Johnson, the Republican Speaker of the House of Representatives, told reporters. "I'm happy to see that she has heeded the call of both Republicans and Democrats."

President Joe Biden thanked Cheatle for her nearly three decades in the Secret Service and said she had "selflessly dedicated and risked her life to protect our nation throughout her career." "We all know what happened that day can never happen again," Biden said in a statement.

"As we move forward, I wish Kim all the best, and I will plan to appoint a new director soon."

Cheatle appeared before a congressional oversight committee on Monday and said the attack on Trump, who was slightly wounded in his right ear, represented a failure by the Secret Service. She called it "the most significant operational failure of the Secret Service in decades." Both Republicans and Democrats called on Cheatle to resign during a tense hearing.

She drew the ire of lawmakers from both parties by refusing to provide specific details about the attack, citing the existence of multiple active investigations.

The gunman opened fire on Trump with an AR-style assault rifle just minutes after he began speaking at the campaign event.

Perched on the roof of a nearby building, he was shot dead by a Secret Service sniper less than 30 seconds after firing the first of eight shots. Investigators have concluded the young man, who lived in a town about 80 kilometres from Butler, acted alone, and have not been able to identify any strong ideological or political leanings. Two rally attendees were wounded and a 50-year-old firefighter, Corey Comperatore, was shot dead.

{ IN BEIJING } AMID PALESTINE CONFLICT

Hamas, Fatah sign unity deal

Sutirtho Patranobis
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Over a dozen Palestinian factions including Hamas and Fatah have agreed to end their differences and signed a unity deal in Beijing, Chinese state media said on Tuesday as Beijing continues its push to play a global peacemaker.

Gathering rival Palestinian factions to sign a deal comes over a year after Beijing brokered an unexpected deal between Iran and Saudi Arabia.

"Representatives of 14 Palestinian factions, including Fatah and Hamas, on Tuesday, jointly pledged to end their divisions and strengthen Palestinian unity by signing the Beijing Declaration," state-run China Central Television (CCTV) said in a brief statement. The representatives agreed to form an "interim national reconciliation government" to administer Gaza after the Israel-Hamas war ends.

The unity deal, called the 'Beijing Declaration' was signed at the closing ceremony of what Chinese state media termed as "reconciliation dialogue" held in Beijing between from July 21 and 23, the CCTV report said.

The announcement of the Hamas-Fatah deal came as Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu is scheduled to visit Washington amidst the nine-month Israel-Hamas conflict, which has resulted in nearly 40,000 Palestinian casualties. Netanyahu is expected to meet President Joe Biden and the US Congress on Wednesday. Fatah controls parts of the West Bank, while Hamas controls Gaza.

Beijing Declaration

Chinese foreign minister Wang Yi hosted senior Hamas official Musa Abu Marzouk, Fatah's Mahmud al-Aloul, and representatives from a dozen other groups for three days of negotiations. "This marks the first time representatives from 14 Palestinian factions have gathered in Beijing for reconciliation dialogue, bringing valuable hope to the long-suffering Palestinian people," said Chinese foreign ministry spokesperson Mao Ning.

"It (the declaration) emphasises the need to convene a broad and fully authorised international conference under the auspices of the UN, with regional and international participation," Mao was quoted as saying in Chinese state media.

"The most prominent highlight is the consensus reached on post-war governance of Gaza and establishment of a provisional national reconciliation government.

The strongest call is to achieve true independence for Palestine in accordance with relevant UN resolutions," Mao said.

Netanyahu hints at truce deal with Gaza

Associated Press
letters@hindustantimes.com

TEL AVIV: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has signalled that a ceasefire deal that would free dozens of hostages in Gaza could be taking shape. Netanyahu is in Washington, where he is to address Congress.

The Israeli military has ordered the evacuation of part of a crowded area in the Gaza Strip it had designated a humanitarian zone. Egypt, Qatar, and the US are pushing Israel and Hamas toward a phased deal to stop the fighting and free remaining hostages.

Netanyahu's office said a negotiating team will be sent to continue talks on Thursday.

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES DEOGHAR
(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान)
(An Institution of National Importance under Ministry of Health & Family Welfare)
भारत सरकार/Government of India
Website-www.aiimsdeoghar.edu.in

No.-AIIMS/DEO/RECT.CELL/2024-25/1903 Date- 16.07.2024

7th ROLLING ADVERTISEMENT

Advt. No.:-AIIMS/DEO/RECT.CELL/2023-24/1894/Phase I

Offline applications are invited for the medical faculty posts on direct recruitment/ deputation basis in various departments at All India Institute of Medical Sciences, Deoghar Jharkhand.

Next cut off date for receiving Soft copy of application is 10.08.2024 and 17.08.2024 for hard copy of application.

For further information candidates are requested to visit the website of institute- **www.aiimsdeoghar.edu.in** on regular basis.

Recruitment Cell
AIIMS Deoghar

REGIONAL CENTRE FOR BIOTECHNOLOGY
An Institution of National Importance
Established by Dept. of Biotechnology, Govt. of India
under the auspices of UNESCO
Faridabad-Gurgaon Expressway, Faridabad-121001

Advt. No. RCB/BSU/03/2024/Rectt./HR

Regional Centre for Biotechnology (RCB) invites online applications from suitably qualified applicants for contractual position of Application Developer under the project **"BSU – Phase-II"**. For details, visit website **www.rcb.res.in**. **Last date** for receipt of online application is **16.08.2024**.

Controller of Administration

Have fun with facts on Sundays
Catch the latest column of
HT TWTW THE WEEK THAT WAS
A quiz on the week's development.
HT FIRST DRAFT. LAST WORD.

SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
E-TENDER NOTICE FOR VARIOUS ELECTRICAL TRD RELATED WORKS

1. Tender Notice No.: TRD_NGP_Tender_24-25_2R2 Dtd: 17.07.2024
Name of the Work: Rectification of critical implantation (implantation between 2.45 mtr. To 2.49 mtr.).
IRPSM ID.: 13.02.36.23.3.51.003,
Tender Cost: ₹ 1,84,60,668.20
Earnest Money: ₹ 2,42,300.00

2. Tender Notice No.: TRD_NGP_Tender_24-25_06R1 Dtd: 19.07.2024
Name of the Work: Outsourcing of maintenance activities of PSI assets of Itwari-Chhindwara section for 24 months.
Tender Cost: ₹ 2,83,70,884.64,
Earnest Money: ₹ 2,91,900.00
Last Date of Submission of Electronic Offers (On-line) - Both up to 15:00 Hrs.:
Tender No. 1: On date **12.08.2024**
Tender No. 2: On date **19.08.2024**
For further details of above tenders, visit website: **www.ireps.gov.in.**

Sr. Div. Elect. Engineer - TRD,
South East Central Railway,
Nagpur
AIM/18-65

स्वच्छ भारत अभियान
एक कदम स्वच्छता की ओर

NORTHERN RAILWAY
Azadi Ka Amrit Mahotsav
E -Tender Notice

Sr. Divisional Electrical Engineer/Traction Distribution, DRM's Office, State Entry Road, New Delhi for & on behalf of President of India, invites open e-tender for the under noted work:

Name of work with its location	Augmentation/Replacement of Catenary wire over Delhi Division.
Approx. Cost of work	Rs.3,25,21,714.62/-
Earnest Money Deposit	Rs.3,12,600/-
E-Tender Bid Online Submission period	02.08.2024 (00.00 Hrs.) to 16.08.2024 (15.00 Hrs.)
E-Tender Bid Submission End Date & E-Tender Open Date & Time	16.08.2024 (15.00 hrs)
Fund Allocation	Capital & DRF (PH-36)
Website particulars where complete details of tender documents can be seen	**www.ireps.gov.in**

E-Tender No.: 24-TRD-NDLS-2024-25 Dated : 23.07.2024 2236/2024

Serving Customers With A Smile

Jharkhand Council of Educational Research & Training (JCERT), Ranchi

TENDER NOTICE FOR PRINTING AND SUPPLY OF ATLAS, DICTIONARY, GRAMMAR AND GENERAL KNOWLEDGE BOOKS

Bid No: JCERT/NPP10-07/2024/2664

Jharkhand Council of Educational Research & Training (JCERT) invites e-bids in two bids system (Technical & Financial) from reputed and eligible printers for the printing and supply of Atlas, Dictionary, Grammar and General Knowledge books to student of Class IX, XI and XII for three years i.e. 2024-25, 2025-26 and 2026-27 studying in Government Schools under State government scheme.
Important dates/details are as under:

Sl. No.	Activity	Start Date	Time	End Date	Time
1	Online availability of bid document	24.07.2024	10.00 am	21.08.2024	06.00 pm
2	Pre-Bid Meeting	31.07.2024	04.00 pm	-	-
3	**Online Bid Submission**	24.07.2024	10.00 am	21.08.2024	06.00 pm
4	Submission of Paper Sample	21.08.2024	10.00 am	22.08.2024	06.00 pm
5	Opening of Technical Bid	23.08.2024	03.00 pm	-	-
6	Opening of Financial Bid	To be announced after the technical evaluation			

Interested eligible bidders may view and download bid documents from the websites http://jharkhandtenders.gov.in.

PR 330307 Jharkhand Council of Educational Research and Training(24-25)#D

Sd/-
(Aditya Ranjan, I.A.S)
Director, JCERT, Ranchi

PSPCL Punjab State Power Corporation Limited
Powering Punjab, Connecting Lives

Regd. Office:- PSEB H.O. Building, The Mall, Patiala
Corporate Identification Number (CIN): U40109PB2010SGC033813
Contact No. 96461-18773

TENDER ENQUIRY No.: QQ- 1332/PO/C&S dt 23.07.24

Chief Purchase Officer/MM, Central Purchase Organization, PSPCL, 2nd floor, Multistorey Building, The Mall, Patiala, invites e-Tender for procurement of 1Cx95 sq.mm-180KM and 4Cx95 sq.mm - 220Km LT XLPE insulated, PVC sheathed, Aluminum Conductor, unarmoured cable, ISI marked as per tender specification no. QQ-1332/PQ/C&S dated 23.07.2024. For detailed NIT & tender specification please refer to **https://eproc.punjab.gov.in** from 23.07.2024 (5.00 PM) onwards.

NOTE: Corrigendum and addendum if any will be published online at **https://eproc.punjab.gov.in**

C476/24 35958

GOVERNMENT OF CHHATTISGARH, WATER RESOURCES DEPARTMENT
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER
MAHANADI PROJECT, RAIPUR (CHHATTISGARH)

e-PROCUREMENT TENDER NOTICE
ePrucurement Portal : https://eproc.cgstate.gov.in
(Tender Cancelation Notice)

S. No.	Name of Work	NIT No./ System Tender No./ Dated	Probable Amount of Contract	Reason for Cencellation of Tender
1.	Lining and Repair work from R.D. 10000 m to 15000 m of Mahanadi Main Canal under Mahanadi Reservoir Project of Block Dhamtari, District- Dhamtari (G.No. 08081)	14/SAC/2023-24/ 153217/ Dated - 23.02.2024 (First Call)	Rs. 193.18 Lakhs	Cancel due to Single Tender Received.

Executive Engineer
M.R.P. Dam Division No. 2, Rudri
For, Chief Engineer, Mahanadi Project, Raipur (C.G.)

G-242501264/4

GOVERNMENT OF ASSAM ::ASSAM INLAND WATER TRANSPORT DEVELOPMENT SOCIETY

E-PROCUREMENT NOTICE:: NATIONAL OPEN COMPETITIVE BID FOR PROCUREMENT OF GOODS

Name of Project : Assam Inland Water Transport Project (AIWTP)

RFB Reference No. : IN-IWT-394222-GO-RFB

Loan Credit No. / Grant No : IBRD/9026-IN

Assignment Title: Providing Basic Amenities at 2 (two) important ferry Ghat points with HDPE material, as floating pontoon.

The Government of India has obtaining financing from the World Bank towards cost of the Assam IWT Project. Under the project, State Project Director, Assam Inland Water Transport Development Society (AIWTDS) invites Request for Bid (RFB) through National Open Competitive bidding process from reputed manufacturer or their authorize dealer/supplier having requisite eligibility for "Providing Basic Amenities at 2(two) important ferry Ghat points (Rajaduar at North Guwahati and Kamalabari at Majuli) with HDPE material, as floating pontoon". Complete documents of the RFB shall be available on website www.aiwtdsociety.in and www.assamtenders.gov.in. Intending bidders are required to register at e-tender portal of the Assam Govt. www.assamtenders.gov.in and participate through e-tender portal only. The last date and time for online submission of bid is on 21/08/2024 at 14:00 Hrs IST.

Sd/-
Additional State Project Director
Assam IWT Development Society
Ulubari, Guwahati-781007
email: dir.iwtds-as@gov.in

Janasanyog /CF/816/24/24-Jul-24

कार्यालय नगर निगम, बरेली ।

पत्रांकः 198/प्र०अधि०/NCAP/2024–25 दिनांकः 23 जुलाई 2024

TENDER NOTICE

Online bids are invited for following Work. Tender forms may be purchased online by the bidders, having relevant experience.

Work Description	Tender & EMD Fee	Work Period
Selection of NGO/Agency to undertake various Information, Education and Communication (IEC) activities to achieve the objectives of National Clean Air Programme (NCAP) in Bareilly municipal area	The EMD & Tender Fee shall be submitted online in the account mentioned below. Bank Details for online payment - Account Number: 3647000100980707 Bank Name: Punjab National Bank Branch: Patel Chowk, Bareilly IFSC: PUNB0364700	01 Year (May extend for Further 01 Year upon the approval of Municipal Commissioner)

Event of Calendar:

S.N.	Events	Date & Time
1.	Date of downloading tender document	24/07/2024 from 12.00 PM
2.	Last date for seeking clarification, if any	26/07/2024 up to 02:00 PM
3.	Start date for uploading of proposal on e-Procurements platform	27/07/2024 from 02:00 PM
4.	Last date for uploading of proposals (both Technical & Financial) in e-Procurements platform.	31/07/2024 up to 04.00 PM
5.	Time and date of opening of Technical proposal	31/07/2024 at 05.00 PM
6.	Time and date of Opening of Financial proposal	to be intimated later

The tender document can be downloaded from https://etender.up.nic.in. "Corrigendum if any. Would appear only on the https://etender.up.nic.in site and not to be published in any News Paper."

प्रभारी अधिकारी (NCAP)
नगर निगम बरेली।

कार्यालय नगर निगम, बरेली।

पत्रांकः 199/प्र०अधि०/उ०वि०/2024–25 दिनांकः 23 जुलाई 2024

TENDER NOTICE

Online bids are invited for following Work. Tender forms may be purchased online by the bidders, having relevant experience.

Work Description	Tender & EMD Fee	Work Period
RPF for Selection of Agency for Annual Maintenance Contract (AMC) for various Horticulture Works at Bareilly Nagar Nigam Area.	The EMD & Tender Fee shall be submitted online in the account mentioned below. Bank Details for online payment - Account Number: 3647000100980707 Bank Name: Punjab National Bank Branch: Patel Chowk, Bareilly IFSC: PUNB0364700	24 months (Further expandable for 12 months upon the approval of Municipal Commissioner)

Event of Calendar:

S.N.	Events	Date & Time
1.	Date of downloading tender document	24/07/2024 from 12.00 PM
2.	Last date for seeking clarification, if any	27/07/2024 up to 02:00 PM
3.	A pre-proposal meeting will be held on.	29/07/2024 at 01:00 PM
4.	Start date for uploading of proposal on e-Procurements platform	30/07/2024 from 02.00 PM
5.	Last date for uploading of proposals (both Technical & Financial) in e-Procurements platform.	05/08/2024 up to 04.00 PM
6.	Time and date of opening of Technical proposal	05/08/2024 at 05.00 PM
7.	Time and date of Opening of Financial proposal	to be intimated later

The tender document can be downloaded from https://etender.up.nic.in. "Corrigendum if any. Would appear only on the https://etender.up.nic.in site and not to be published in any News Paper."

प्रभारी अधिकारी उद्यान विभाग
नगर निगम बरेली।

Sable hopes tactical switch pays off at the Paris Games

India's top track star for the last many years is determined to get his plans right after past setbacks

Avishek Roy
avishek.roy@htlive.com

NEW DELHI: Avinash Sable didn't let his disappointment of last year's Budapest world championships linger on for long. The Hangzhou Asian Games was less than two months away and the 3000m steeplechase champion needed to get on with preparation.

He didn't go back with the Indian team to their base at Colorado Springs, United States. Instead, he opted to train in Bengaluru and striking gold in China restored his belief. But Sable did take a hard look at his preparation for major events. In the 2022 Eugene Worlds, he qualified for the final, but got sucked into a slow race, finishing 11th clocking a pedestrian 8:31.75. At Budapest, another tactical and slow preliminary heat caught him off guard, finishing seventh (8:22.24) to be eliminated.

"This year the focus has been on preparation, so that I don't run behind but run shoulder to shoulder with the front group. That's why I started late. I want to cover all the bases in training," a relaxed Sable told HT.

The conversation was free-flowing at the Inter-State meet in Panchkula last month. It was only his second competition this year, but Sable eagerly awaited the Paris Diamond League a week away on July 7. That was going to tell him about his preparation. "I got invitations from Diamond Leagues, but refused. My focus is on preparation for Olympics. I know what it is to compete in international events. I don't have a fear of international competition anymore.

"Earlier, I used to think how will I enter among a pack of runners... There will be so many athletes – taller, smaller. How will I spot the hurdle? All that fear has gone. I thought I am consistently competing in DL, breaking national records, but have not been able to deliver at world championships in the last two years.

"I know people might think why is Sable not running (but) I have learnt to back my decisions. I've not thought about results in the preparation phase. I told myself I will accept all that comes my way, but whatever has to happen should happen before Olympics, not during it. This has been my mentality this year."

The Paris Diamond League was ideal preparation for the Olympics because the top runners were there.

The Paris DL seemed to vindicate his approach. Fourth at the start of the final lap, Sable finished sixth, but broke his national record clocking 8:09.91. Kenyans Abraham Kibiwot and Leonard Kipkemoi, who will compete in the Olympics, were in the race. Ethiopian Sime Abrham won clocking 8:02.36.

The national record came, but Sable would have studied other minute details as he headed to St Moritz in the Swiss Alps for his current final preparation with US coach Scott Simmons.

"Last year, the target was to get good timing; this year it is the opposite – keep doing your best in training – speed, endurance, final kick."

Having broken the national record multiple times, Sable says his obsession with timing is over. "I was running for timing and if I didn't get it in one race, I would call up Scott that I want to enter this Diamond League or some other competition. I would want to have another race quickly and set that timing. But I was losing crucial time to train and it was affecting my preparation for major championships.

The 2022 Commonwealth Games was the first race which gave Sable belief that he is world class. Running against three Kenyans, he snatched silver clocking a national record 8:11.20 secs. Sable wants the Paris race to be like Birmingham.

"I think my best chances will be if it is a race like athletes running single file. You are clear about your position. You are able to see others, not like a bunch till the last lap and then there is a burst. In such races anything can happen, even a runner with not very good endurance can win with a last kick. In 8:10, 8:11 races you know whoever is best in the field in recent times will come through."

That didn't happen in the last two Worlds. Moroccan Olympic and world champion Soufiane El Bakkali trumped all tactics with his pace in the last two laps, be it a slow or fast race. In 2022 Eugene, he won a slow race clocking 8:25.13; in Budapest he killed it with a fast 8:03.53s.

Sable admits the pace in the last two laps has become important and everyone is preparing for that. "I am prepared for everything."

"Kuch bhi ho jaaye, jaise bhi race jaaye, uske liye prepare raghenge. (Whatever the race throws up, I will be ready)."



3000M STEEPLECHASE

How the top 7* have fared

1	Lamecha Girma (ETH)	OLYMPICS AND WORLDS SILVER MEDALLIST (2022, 2023), WORLD RECORD HOLDER (7:52.11). SEASON'S BEST 8:01.63 (Stockholm Diamond League)
2	Soufiane El Bakkali (Mor)	OLYMPICS AND WORLD CHAMPION (2022, 2023). SEASON'S BEST 8:09.40 (Stockholm Diamond League)
3	Abraham Kibiwot (KEN)	WORLDS BRONZE MEDALLIST, 2023. SEASON'S BEST 8:06.70 (Paris Diamond League)
4	Simon K Koech (KEN)	WORLD U-20 BRONZE MEDALLIST, 2021. SEASON'S BEST 8:18.45 (Paris Diamond League)
5	Samuel Firewu (ETH)	U-20 WORLDS MEDALLIST 2022. SEASON'S BEST 8:05.78 (Stockholm Diamond League)
6	Leonard Kipkemoi (KEN)	U-20 WORLDS MEDALLIST 2018. SEASON'S BEST 8:12.97 (Paris Diamond League)
7	Getnet Wale (ETH)	DIAMOND LEAGUE CHAMPION 2019. SEASON'S BEST 8:09.69 (Doha Diamond League)

*Those who have qualified for the Olympics

SABLE IN THE PARIS LEAD UP

- Avinash Sable competed in four races this year and broke his national record at Paris Diamond League (8:09.91) on July 7. His timing is 10th best of the season. He is 9th (qualified steeplechaser) in Road to Paris rankings.
- He won the Asian Games in Hangzhou 2023 with a timing of 8:19.50
- He won silver at the Commonwealth Games in Birmingham 2022 with a timing of 8:11.20

Panghal eyes redemption after tumultuous build-up

Shantanu Srivastava
sportsdesk@hindustantimes.com



Boxer Amit Panghal (C) leaves for Paris from New Delhi. TWITTER

NEW DELHI: A lot has changed for Amit Panghal since the Tokyo Olympics. He fell in the pecking order before reclaiming his spot, for one. The image of his late grandfather, Captain Jagram Panghal, has been tattooed on his left scapula (shoulder blade). One underlines determination and the other inspiration.

"It ensures he is always around me. I draw a lot of peace and confidence from it," the 28-year-old says. Jagram earned his fame at the dangals in and around Rohtak's Mayna village. He is said to have been unbeaten across seven neighbouring villages, and became Panghal's hero since childhood.

"We are five brothers, and me being the youngest my grandfather adored me. He wanted me to win an Olympic medal. 'Dil khol ke khel' (play with freedom) was his only advice.

"Now is the time to realise his dream, which is my dream too."

Having fluffed his chance in Tokyo – as world No.1 he crashed out in the opening bout – the 51kg boxer's resilience has helped get a second shot at the one major medal missing from his cabinet.

It has not been easy though. Panghal spent much of the three years leading up to Paris on the sidelines, repeatedly failing to make it to the national side. The turnaround began in February with victory at the Strandja Memorial in Sofia. The Indian boxers' failure at the first Olympic World Qualifiers in Busto Arsizio, Italy the next month was followed by Panghal topping the evaluation criteria at the national camp, paved the way for his return to the team.

Panghal, who with Nishant Dev (71kg) made the cut at the second World Qualifier in June, says he is "in the best shape of my life".

He trained for a month at Sports Authority of India's (SAI) high-altitude centre in Shilaroo, Himachal Pradesh, opting not to travel with the rest of the boxers to India's pre-Games base at the southwestern German city of Saarbrucken.

"It has done wonders to me," Panghal says about his Shilaroo stint. "My endurance has improved a lot. Initially, I would lose steam after a bit of brisk walking at this altitude (8,000 feet), but now I feel fresh throughout the bout. The lungs and legs don't give way, the mind is focussed. I am in a great space."

Panghal's sparring partners in Shilaroo included 2019 Asian Championships silver medallist Kavinder Singh Bisht, former national champion Rohit Mor and the talented Sachin Siwach.

"I had boxers across age-groups, styles, techniques and weights to spar with. Just staying in altitude helped improve the endurance and stamina," said Panghal, whose regimen included weekly cross-country runs and occasional treks.

Supervised by two coaches, including long-time personal coach Anil Dhankar, Panghal worked on his starting problems. Known to be a sluggish starter, he paid the price against Colombia's Yuberjen Martinez in Tokyo, and survived a close bout against Mexico's Mauricio Ruiz at the second World Qualifier.

"The solution is to go on early attacks and land a few punches to impress the judges. I have changed my reactive strategy and have decided to be proactive, from the opening round of the opening bout."

For that, his opening rounds in practice were reduced from the regulation three minutes to one. "The idea was to put all my energy in the opening exchanges and assert myself. With improved stamina, I know I can finish off the opponent in the next two rounds."

"I know this is my second Olympics, but in my head it still feels like my first. Tokyo was over in a blink. I am no longer world No.1 but want to show the world what I am capable of."

The 2019 World Championships silver medallist counts Cuban Alejandro Carlo and Uzbekistan's 2016 Olympics champion Hasanboy Dusmatov as his major threats in Paris. "I have not fought against the Cuban, so will have to rely on video analysis. Dusmatov is always a threat."

Technically, Panghal will continue to rely on his pacy in-out style to counter taller opponents. "It's the style that has worked best for me. I feel the endurance work will enable me to pull this off against the best."

HT OLYMPIC TRACKER

GAMESWATCH



Table tennis player G Sathiyan with Carlos Alcaraz at the Games Village. UTT

IOC MULLS PALESTINIAN CALL FOR ISRAEL BAN

The International Olympic Committee was Tuesday weighing a Palestinian call for Israeli athletes to be barred from the Games over the war in Gaza, three days before the Opening Ceremony in Paris. As the Israeli Olympic team settled into the Athletes' Village, IOC was studying a letter sent by the Palestine Olympic Committee to president Thomas Bach asking him to ban the Israelis, citing the bombings of the besieged Gaza Strip as a breach of the Olympic truce. The letter sent on Monday "emphasised that Palestinian athletes, particularly those in Gaza, are denied safe passage and have suffered significantly due to the ongoing conflict". It said "approximately 400 Palestinian athletes have been killed, and the destruction of sports facilities exacerbates the plight of athletes who are already under severe restrictions". The IOC is likely to reject the Palestinian call but it highlights how the rising death toll and growing humanitarian crisis in Gaza is impacting the Paris Games.



Runners Avinash Sable and Parul Chaudhary in St. Moritz, Switzerland. SAI

ANDY MURRAY TO RETIRE AFTER OLYMPICS

Andy Murray confirmed on Tuesday that he will retire after the Paris Olympics, closing another chapter in tennis' golden age. The 37-year-old, a two-time Olympic champion, is planning to play in the singles and doubles at his fifth Games. "Arrived in Paris for my last-ever tennis tournament @Olympics," the three-time Grand Slam champion and former world number one posted on social media. "Competing for Great Britain has been by far the most memorable weeks of my career and I'm extremely proud to get to do it one final time."

Murray has been ravaged by injuries in recent years, slumping to 121st in the world. The Scot has played with a metal hip since 2019 and suffered ankle damage earlier this year before undergoing surgery to remove a spinal cyst, which ruled him out of singles at Wimbledon. Murray famously ended Britain's 77-year wait for a men's champion at Wimbledon when he triumphed in 2013, defeating career-long rival Novak Djokovic in the final.



Table tennis player Ayhika Mukherjee with Rafael Nadal at the Games Village. UTT

India thrash Nepal to qualify for semi-finals

Agencies
sportsdesk@hindustantimes.com



Shafali Verma. PTI

DAMBULLA: Shafali Verma slammed a career-best 48-ball 81 as defending champions India thrashed Nepal by 82 runs in their final group match to confirm their semi-final spot at the Women's Asia Cup T20.

With India shuffling the batting order, Shafali and Dayalan Hemalatha (47) opened the innings and gave India a flying start after stand-in skipper Smriti Mandhana opted to bat.

The opening duo smashed its way to 122 in 14 overs to lay the foundation. Jemimah Rodrigues then hit unbeaten 28 off 15 balls, including three fours in the final over, to take India to a solid 178/3. Nepal needed to achieve the target in or under 10 overs to surpass Pakistan on net run rate and qualify for the semi-finals but they could only manage 96 for nine in their 20 overs, thanks to some superb bowling from the in-form Indian attack.

Deepti Sharma (3/13) was the most successful bowler for India as she snapped three wickets, while her spin colleague Radha Yadav (2/12) and seamer Arundhati Reddy (2/18), playing in place of a rested Pooja Vastrakar, snapped two each.

Pakistan, thus, became the second team to qualify for the semifinals from group A.

It proved to be a tough chase for Nepal as they kept losing wickets at regular intervals to slip to 52/4 in 10.2 overs with seamer Arundhati cleaning up both the openers — Samjhana Khadka (7) and Sita Rana Magar (18).

Earlier, Shafali literally toyed with the bowlers, using her flicks to good use as 12 fours and a maximum flew from her blade.

Brief scores: India 178/3 (Shafali Verma 81, Dayalan Hemalatha 47). Nepal 96/9 (Arundhati Reddy 2/28, Deepti Sharma 3/13, Radha Yadav 2/12). **India won by 82 runs.**

Gaikwad, Abhishek and a problem of plenty

Sanjjeev K Samyal
sanjjeev.samyal@htlive.com

MUMBAI: Waiting in the wings is never easy. You may be racking up the numbers but it's just not enough to breaking into the team because the place you desperately need is being occupied by someone else.

It becomes a battle of attrition. Those who witnessed cricket during the era when Sachin Tendulkar, Rahul Dravid, VVS Laxman and Soura Ganguly know precisely what it means to wait and hope, sometimes without end.

India's T20 talent pool is overflowing thanks to the Indian Premier League and that has meant that there are many takers for the spots that have become available with the retirement of Rohit Sharma and Virat Kohli.

However, there are just too many candidates for those openings. Just ask Ruturaj Gaikwad and Abhishek Sharma.

The two had good reasons to be optimistic about their selection for the Sri Lanka series after a good run in the IPL and against Zimbabwe.

Mahendra Singh Dhoni chose the 27-year-old Gaikwad to succeed him as the captain of Chennai Super Kings and that alone should perhaps warrant a serious look by the selectors. Earmarked as the player to keep an eye on ever since he made his IPL debut in 2020, the opening batter has truly lived up to expectations, delivering blockbuster performances season after season in the T20 league. His aggregate of 2380 runs in just five seasons (64 innings) at an average of 41.75 (SR 136.86) shows just how consistent he has been.

Despite not getting to bat in his favoured opening position during the Zimbabwe tour, Gaikwad adjusted well at No. 3 and No. 4. He made runs consistently, and also scored them at a brisk strike rate of 158.33, hitting a 47-ball 77* and 28-ball 49.

Abhishek, too, gave a good account of himself in his debut series in Zimbabwe with both bat and ball. Playing in his fearless, eye-catching style, he smashed a hundred in his second international game and bowled tidy spells of left-arm spin as well.

India has long been desperate to have a top-order batter who can bowl and when that rare commodity comes along, one expects the selectors to jump at the first opportunity to get him on board. Abhishek seems a perfect fit for that role but for now, it seems he must wait a while longer.



India batter Abhishek Sharma poses with fans. AP

Opening the batting for Sunrisers Hyderabad, he took the 2024 IPL by storm by smashing 42 sixes while scoring 484 runs at a strike-rate of 204.44. The IPL show had come after a solid display for Punjab in the national T20 championship, the Syed Mushtaq Ali Trophy, where he powered his state side to their maiden title with 485 runs, with two hundreds and three half-centuries while striking at over 180.

While speaking to the reporters ahead of departing for Sri Lanka, chief selector Ajit Agarkar mentioned how they can only pick 15 players in the squad.

"Every player who's left out feels hard done by. Our challenge is to pick only 15. You try and get the best balance possible. So, someone's likely to miss out. Sometimes, they have had decent performances in recent times but you've got to see who is picked ahead of them. Are those guys not deserving of their place? If that's the case, then there are things to discuss," said Agarkar.

Agarkar gave the example of Rinku Singh who was omitted from India's squad for the T20 World Cup 2024 squad despite playing exceptionally well in the lead up to the tournament.

"Any player who is dropped will feel hard done by. Look at Rinku (Singh), he performed really well ahead of the T20 World Cup, but couldn't make the cut. We can only pick 15," the chief selector said.

It is understood that both Abhishek and Gaikwad are on the selection radar for the future. In the Punjab player's case, he has time on his hand but at 27, things are getting a bit tight for the Maharashtra batter as the wait to find a permanent spot in the team gets longer.

One thing is for sure, their run of form will keep all the batters in the squad on their toes. Slip up and you know who is waiting in the wings.

Dujardin pulls out of Paris Games

LONDON: Charlotte Dujardin, Britain's joint-most decorated female Olympian, has pulled out of Paris 2024 after a video emerged showing her "making an error of judgement". The six-time dressage medallist said she is under investigation from the FEI and will "withdraw from all competition".

Pogacar too tired for the Olympics

LJUBLJANA: Tour de France winner Tadej Pogacar pulled out of the Paris Olympics citing "tiredness", his Slovenia team announced. "Unfortunately Tadej Pogacar has cancelled his participation because of a state of extreme fatigue," Slovenian cycling coach Uros Murn said in a statement. Pogacar won a third Tour de France title in Nice on Sunday. Victory also gave him the first Giro d'Italia-Tour de France double since Marco Pantani in 1998.

To Get All The Popular Newspapers.
Type in Search Box of Telegram
@sharewithpride

If You Want to get these Newspapers Daily at earliest

English Newspapers»»

Indian Express, Financial Express, The Hindu, Business Line, The Times of India, The Economic Times, Hindustan Times, ET wealth, Business Standard, First India, Mint, Greater Kashmir, Greater Jammu, The Himalayan, The Tribune, Brill Express, The Sikh Times, Avenue Mail, Western Times, Millennium Post, The Statesman, State Times, The Pioneer, Hans India, Free Press, Orissa Post, Mumbai Mirror, Mid-Day, Deccan Chronicle, Deccan Herald, Telangana Today, Financial Times, The Asian Age, The Telegraph, Oheraldo, Gulf of Times, The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, USA Today, The Wall Street Journal, The Guardian, The Times

Hindi Newspapers»»

दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, दिव्यभास्कर, हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, बिज़नस स्टैंडर्ड,

अमर उजाला, जनसत्ता, द पायोनीर, राष्ट्रीय सहारा, प्रभातखबर, लोकसत्ता

Others»»

Hindi & English Editorial, Employment News, Malayalam Newspapers, Tamil, Telugu, Urdu, Gujarati

Type in Search box of Telegram https://t.me/Magazines_8890050582 And you will find a Channel named @Lalit712 join it and receiv daily editions ofall popular epapers at the earliest

Or

you can click on this link

https://t.me/sharewithpride